

लेखक की अंगरेजी पुस्तक Education in New India  
का हिन्दी अनुवाद  
बापी रोडट जार्ज एलन एण्ड अनविन लि० लंदन  
अनुवादक विराज एम० ए०

मूल्य  
छीसरा संस्करण  
प्रकाशक  
मुम्बई

पाच रुपये पचाम नये पसे  
मार्च १९६०  
राजपाल एण्ड मज्ज दिल्ली  
बेगम ब्यारी प्रस दिल्ली

मौलाना अबुल कलाम आजाद को—

जिन्होंने रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी के  
साथ मिलकर भारत के लिए  
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का  
स्वरूप तयार करने में  
सहायता दी।



## विषय-क्रम

भूमिका	७
१ भारत में शिक्षा की स्थिति विहगावलोकन	६
२ बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत और व्यवहार	३६
३ माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन	६०
४ समाज शिक्षा की धारणा	१०७
५ भारतीय विश्वविद्यालयों के विषय में	१३५
६ अग्रजों का अध्ययन	१६१
७ सांस्कृतिक गतिविधियाँ और राज्य	१८६
८ छात्रों में अनुशासनहीनता	२०५
९ शिक्षा का नियत कर्तव्य	२५१



## भूमिका

अपने प्रजातन्त्रीय आदर्शों के अनकूल ही भारत ने अपने यहाँ शिक्षा सुविधाओं का इतना विस्तार करने का निश्चय किया है कि जिससे उसके सामाजिक और उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही उसने अपने शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन का विद्यार्थी नाम भी अपने हाथ में लिया है जिससे यह शिक्षा देश की नई आवश्यकताओं और नई महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अधिक उपयुक्त साधन बन सके। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो काम उठाए गए हैं उनका संक्षिप्त—परन्तु सार्थक है कि बहुत अपर्याप्त नहीं—विवरण भाग के अध्यायों में दिया गया है।

स्वाधीनता प्राप्ति के समय भारत में शिक्षा की क्या अवस्था थी और उसके बाद से अब तक क्या प्रगति की गई है इसका एक उदात्त-सा परिमाण (सर्वे) करने के बाद इस अध्ययन में मुख्यतया उन परीक्षाओं का वर्णन किया गया है जो भारत में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। प्रारम्भिक स्तर पर भारत में बुनियादी शिक्षा प्रणाली का विकास किया जा रहा है जिसमें बड़ी उत्साहजनक सम्भावनाएँ भरी हैं और जिसमें सम्मेलन सारे सार के शिक्षाशास्त्रियों की रुचि होगी। इसी प्रकार एक नए ढंग की वपस्क-शिक्षा के सम्बन्ध में किए गए भारत के परीक्षण अन्य देशों के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी ओर प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत मुख्यतया उगी की पुनरावृत्ति कर रहा है जो कुछ अन्य देशों में किया जा चुका है। इसलिये यद्यपि प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत अधिक प्रगति हुई

है, फिर भी मैंने जगका कोई अलग अध्याय इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया है।

इस पुस्तक को लिखने में जिन लोगों ने मेरी सहायता की है उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उन सबके प्रति व्यक्तिगत आभारप्रदर्शन कर पाना सम्भव नहीं है। भारत सरकार के गिना मन्त्रालय तथा राज्य-सरकारों के गिना विदेशालयों में कार्य कर रहे अपने सहकारियों का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने गिना (डाटा) और अनन्त बहुमूल्य सुझाव मुझ दिए। मैं उन परिवारों के सपादकों और संगठनों के सदस्यों का भी कृतज्ञ हूँ जिनके आग्रह ने मुझ इन विचारों को लेख्यबद्ध करने के लिए विवश कर दिया। परन्तु इस पुस्तक में व्यक्त की गई सब सम्मतियाँ मेरी अपनी हैं और उनके लिए केवल मैं ही उत्तरदायी हूँ—विशेष रूप से उन सम्मतियों के कारण भारत सरकार या विदेशविशालय अनुदान-आयोग किसी भी प्रकार बचनबद्ध नहीं है।

मैं समय-समय पर भारत यूरोप तथा अमेरिका की परिवारों तथा अन्य प्रकाशनों के लिए भारतीय गिना के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में जो लेख लिखता रहा हूँ उनका मत इस पुस्तक में भी काफी उपयोग किया है। परन्तु प्रत्येक लेख को मत संगोषित किया है और कुछ लेखों को तो बिल्कुल नये सिरे से लिखा है। इसलिए यह कहना सत्य होगा कि इस पुस्तक में एक भी ऐसा लेख सम्मिलित नहीं किया गया है जो इस वर्तमान रूप में कहीं अन्यत्र छप चुका हो। इससे प्रतिरिक्त इन सब लेखों को एक जगह समूहीत कर देने से वे इस प्रकार एक-दूसरे के समर्थक और सहायक बन गए हैं जैसे कि पुष्प पुष्प प्रकाशित दस्त में नहीं हो सकते थे। यदि इस पुस्तक का पढ़कर पाठकों को भारत के गिना-सम्बन्धी प्रयत्न की प्रगतिवृत्ति, सजीवता और विविधता की कुछ भसक मिल सके तो मैं अपना प्रयत्न सफल समझूँगा।

सन्धन

—हुमायुन कबिर

४ जुलाई १९५५

## अध्याय १

# भारत में शिक्षा की स्थिति • विहगावलोकन

स्वाधीनता प्राप्त करने के तत्काल बाद भारत के सामने जो अनक समस्याएँ उपस्थित थीं उनमें एक सबसे बिकट समस्या अपनी शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करने और विस्तार करने की समस्या थी। ऐसी व्यवस्था की जान की आवश्यकता थी कि जिससे पाठ्यासा जान योग्य भाषा बाल सब बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हो सके और इस बात का भरोसा रहे कि उन्हें शिक्षा-सम्बन्धी वे सुविधाएँ अवश्य प्राप्त हो जाएगी जो उनके माता-पिता को प्राप्त नहीं थी। इसके साथ ही साथ निरक्षर ब्यस्क लोगों की शिक्षा के लिए भी एक विनाल कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता थी। एक और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का नय सिरे से पुनर्गठन करने की आवश्यकता थी और दूसरी ओर उद्योग तथा कृषि के विकास के लिए आवश्यक वैज्ञानिक तथा प्राविधिक (टेक्निकल) शिक्षा का तन्ही से विस्तार किया जाना अभीष्ट था। राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन को समुन्नत करने के कार्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसके लिए यह आवश्यक था कि राज्य विभिन्न प्रकार की कलाओं को अधिकाधिक प्रथम दे। साथ ही यह भी आवश्यक था कि अपने पूव तथा पश्चिम के पड़ोसा देशों के साथ पुराने सम्बन्धों को फिर ताजा किया जाए और जिन देशों के साथ पहले भी कभी सम्बन्ध नहीं रहे उनके साथ नये सम्बन्ध स्थापित किए जाएँ। लगभग दो सौ वर्षों तक भारत के सांस्कृतिक सम्बन्ध लगभग केवल इण्डस तक ही सीमित हो गये थे। स्वतन्त्र भारत इस निरन्तर संकुचित क्षान हुए संसार में अन्य देशों से अछूता या अलग-बलग नहीं रह सकता था।



भारत के संविधान में यह कहा गया है कि इस संविधान के लागू होने के दस वर्ष के अन्दर अन्दर चौदह वर्ष तक की आय वाले बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जानी चाहिए। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि स्वाधीनता प्राप्त होने के समय देश में इन २५ प्रतिशत बालकों के लिए भी शिक्षा-व्यवस्था नहीं थी तो यह भावना महत्त्व की दृष्टि से एकत्रित प्रतिकारी समझा जाना चाहिए। यह काम अपने आप में ही बहुत कठिन था उस पर यह उन अनर्थ घटनाओं के कारण और भी दुष्कर हो गया जिनके कारण स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत में भारी उपलब्धता हुई। स्वाधीनता प्राप्ति का मूल्य देश के विभाजन द्वारा चुकाना पड़ा था और दुर्भाग्य से इस विभाजन के फलस्वरूप लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। जनसंख्या का स्थानान्तरण इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। केवल दो राज्यों के बीच ही लगभग एक करोड़ लोगों की अदल-बदल हुई। भारत में उपलब्ध जन धन और सामग्री के सम्पूर्ण साधना का एक बड़ा भाग इन विस्थापितों के पुनर्वास के विनाश काय का पूरा करने के लिए लगा देना पड़ा। अभी यह समस्या पूरी तरह हल भी नहीं हुई थी कि विश्व-शक्तियों के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय मुद्रा का विमूल्यन (डिफ्ल्यूएशन) हो गया जिसके साथ-साथ मुद्रा प्रसार (इनफ्लेशन) हुआ और वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। स्वाधीनता के पहले पाँच वर्ष देश के कुछ भागों में अनावृष्टि तथा कुछ भागों में बाढ़ों के कारण भी बड़ी कठिनाई के वर्ष थे। विश्व में इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा जितना भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अतः यह कुछ धाँचक की बात नहीं कि देश के साधना पर यह सब अनिवार्य बोझ पड़ने के कारण शिक्षा का विभाग हाताक्षि यह कम नहीं है उतना नहीं हो पाया जितनी कि लोगो को चाहिए।

इन सब राजनीतिक, आर्थिक और प्राकृतिक बाधाओं के प्रतिकूल एक तथ्य ऐसा भी था जिनके देश में शिक्षा की प्रगति में सहायता दी और जो प्रायः अधिकाधिक सहायता देता रहेगा। यह तथ्य था भूतपूर्व दोगे राज्यों का भारतीय संघ में मिल जाना। इस विसर्जन के कारण गारा देश एक एके रूप में मिलकर एक हो गया है जैसा कि पहले कभी नहीं था। दोनों राज्यों तथा पहले के अलग-अलग राज्यों का साथ-साथ अस्तित्व केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से

ही बाधक नहीं था अपितु देश की सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक प्रगति की दृष्टि से और भी बड़ी बाधा बना हुआ था। केवल चाड़े-से प्रचलित अपवादों को छोड़कर य दंगी राज्य शिक्षा की दृष्टि से और इमान्ति, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और सम्पूर्ण भारत की प्रगति में बाधा डाल रहे थे। विमर्श की प्रक्रिया और उसका विकास हुए पूर्ण एकाकरण के फलस्वरूप अब ये राज्य भारत के अंग बन गए हैं। जलोरी की मजबूती उसका सबसे कमजोर कड़ी द्वारा ही आका जाता है। अब हम यह विश्वास रख सकते हैं कि एक बार पिछली रमिया को पूरा कर लेने के बाद भारतीय शिक्षा की शुद्धता की मनी कदियाँ समान रूप से मजबूत होंगी।

इसी सत्य का पूरा करण के लिए एक और कदम यह उठाया गया है कि समाज में पिछड़े हुए वर्गों के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। संविधान में यह धारणा का गई है कि सब नागरिकों की सामाजिक प्रतिष्ठा समान होगी और सबका उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे और संविधान में राज्य पर यह दायित्व डाला गया है कि वह उन वर्गों के हितों को बनाने की ओर विशेष ध्यान दे जा जब तक सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक बाधाओं के कारण पिछड़े रहे हैं। समाज शिक्षा के विस्तृत कार्यक्रम जिनके द्वारा उन बाधाओं को हटाने का यत्न किया जा रहा है जिनसे अनिश्चित ब्यस्त लोगों का हानि उठानी पड़ सकती है अवसर के प्रजातन्त्रीकरण की ओर की जा रहा इस प्रगति के ही अंग है। बालिकाओं और स्त्रियों का उपलब्ध सुविधाओं में और अधिक वृद्धि करण के लिए भी विशेष प्रयत्न किए गए हैं। विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा पा रही छात्रा की संख्या दुगुनी हो गई है। १९४७-४८ में यह ३५ लाख थी और बड़कर १९५४ में ७० लाख से भी अधिक हो गई है।

शैक्षणिक उन्नति के अवसर का समान बनाने के लिए एक और साधन के रूप में छात्रवृत्तियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। केवल योग्यता के आधार पर ही जान वाली बहुत-सी छात्रवृत्तियों के अनिश्चित समाज के अपेक्षाकृत गरीब या पिछड़े हुए वर्गों को महामता देने के लिए भी विशेष योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं जिससे वे भी देश में उपलब्ध शिक्षण की सुविधाओं से लाभ उठा सकें। विधान के स्तर पर राज्य-सरकारों ने अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित आदि

भारत के संविधान में यह कहा गया है कि इस संविधान के लागू होने के दस वर्ष के अन्तर अन्तर चौदह वर्ष तक की आयु वाले बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जानी चाहिए। जब हम इस बात पर ध्यान देने हैं कि स्वाधीनता प्राप्त होने के समय देश में इन २५ प्रतिशत बालकों के लिए भी शिक्षा-व्यवस्था नहीं थी तो यह धारणा महत्व की दृष्टि से एकदम जातिवारी समझा जाना चाहिए। यह काम अपने आप में ही बहुत कठिन था उस पर यह उन अनेक घटनाओं के कारण और भी दुष्कर हो गया जिनके कारण स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत में भारी उपलब्धता हुई। स्वाधीनता प्राप्ति का मूल्य देश के विभाजन द्वारा चुकाना पड़ा था और दुर्भाग्य से इस विभाजन के फलस्वरूप लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। जनसंख्या का स्थानान्तरण इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। केवल दो राज्यों के बीच ही लगभग एक करोड़ लोगों की बदल-बदल हुई। भारत में उपलब्ध जन धन और सामग्री के सम्पूर्ण साधनों का एक बड़ा भाग इन विस्थापितों के पुनर्वास के विनाश काय का पूरा करने के लिए लगा देना पड़ा। अभी यह समस्या पूरी तरह हल भी नहीं हुई थी कि विश्व-शक्तियों के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय मूल का विमुक्तन (डिबस्यूण्डन) हो गया जिस के साथ-साथ मुद्रा प्रसार (इनफ्लेशन) हुआ और वस्तुओं की कमी हो गई। स्वाधीनता के पहले पाँच वर्ष देश के कुछ भागों में अनावृष्टि तथा कुछ भागों में बाढ़ों के कारण भी बड़ी कठिनाई के वर्ष थे। शिक्षा से इतनी बड़ी मात्रा में छात्रान्नों का आयात करना पड़ा जितना भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अतः यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं कि देश के साधनों पर यह सब अनिवार्य बोझ था पड़ने के कारण शिक्षा का विकास हालांकि यह कम नहीं है उतना नहीं हो पाया जितनी कि लोगों की चाहत थी।

इन सब राजनीतिक आर्थिक और प्राकृतिक बाधाओं के प्रतिकूल एक तथ्य ऐसा भी था जिसने देश में शिक्षा की प्रगति में सहायता दी और जो प्राग भी अधिकाधिक सहायता देता रहेगा। यह तथ्य था भूतपूर्व देशी राज्यों का भारतीय संघ में मिला जाना। हम विस्तार के कारण सारा देश एक जैसे रूप में मिलकर एक हो गया है जैसा कि पहले कभी नहीं था। देशी राज्यों तथा परदेस के अग्रणी प्रांतों का साथ-साथ अस्तित्व केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से

## भारत में शिक्षा की स्थिति विहंगावलोकन

ही बाधक नहीं था अपितु देश की सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक प्रगति का दृष्टि से घोर भा बड़ी बाधा बना हुआ था। कवन बाद-से प्रगतिशील प्रपवादों से घोर भा दली राज्य शिक्षा की दृष्टि से घोर इसीलिए सामाजिक दृष्टि से पिछड़ हुए थे और सम्पूर्ण भारत का प्रगति में बाधा डाल रहे थे। विलयन की प्रक्रिया और उसके बाद हुए पूर्ण एकीकरण के फलस्वरूप अब ये राज्य भारत के घन हूँ भाग बन गए हैं। जखीर का मजबूती उसका सबसे कमजोर बड़ी द्वारा ही भाकी जाता है। अब हम यह विश्वास रख सकते हैं कि एक बार पिछड़ा कमिया का पूरा कर लेने के बाद भारतीय शिक्षा का श्रुतला का सभी बढियाँ समान रूप से मजबूत हानगी।

इसी समय का पूरा करने के लिए एक और काम यह उठाया गया है कि समाज में पिछड़ हुए वर्गों के लिए प्रपसाहन अधिक सुविधाओं का व्यवस्था की गई है। संविधान में यह घोषणा की गई है कि सब नागरिकों की सामाजिक प्रतिष्ठा समान होगी और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे और संविधान में राज्य पर यह दायित्व डाला गया है कि वह उन वर्गों के हितों को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दे जा अब तक सामाजिक धार्मिक या शैक्षणिक बाधाओं के कारण पिछड़ रहे हैं। समाज शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम जिनके द्वारा उन बाधाओं का हटाना कायम किया जा रहा है जिनमें अशिक्षित बयस्क लोगो को हानि उठानी पड़ सकती है। अवसर के प्रजातन्त्रीकरण का और का जा रहा इस प्रगति के ही भाग हूँ। बातिबाधों और स्थिया का उपलब्ध सुविधा में और अधिक बृद्धि करने के लिए भी विविध प्रयत्न किए गए हैं। विभिन्न प्रकार की शिक्षण मस्थाओं में शिक्षा पा रही छात्राओं की सख्या दुगुनी हो गई है। १९४७-४८ में यह ३५ लाख थी और बढकर १९५४ में ७० लाख से भी अधिक हो गई है।

शैक्षणिक उन्नति के अवसर का समान बनाने के लिए एक और साधन के रूप में छात्रवृत्तियाँ का भी प्रयोग किया जा रहा है। केवल साम्यता के आधार पर ही जाने वाली बहुत-सी छात्रवृत्तियों के अनिश्चित समाज के प्रपेक्षावक तरीके या पिछड़े हुए वर्गों को सहायता देने के लिए भी विविध योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं जिनमें वे भी देश में उपलब्ध शिक्षण की सुविधाओं से लाभ उठा सकें। विचारालय के स्तर पर राज्य-सरकारों ने अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जाति

वासियो तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देन और अधिकाधिक छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की है। ये कम जसा कि इनके नाम से ही ध्वनि होता है भारतीय जनता के ये भाग्य हैं जो ऐतिहासिक कारणों से उन्नति का अवसर पान में सबसे अधिक पिछड़े रहे हैं। महाविद्यालय के स्तर पर भारत सरकार उन्हें मट्रिक परीक्षा के पश्चात् अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ देने की योजना बनाकर उनकी सहायता करने का प्रयत्न कर रही है। १९४७ और १९५४ के बीच इस योजना में ३४ गुने से भी अधिक विस्तार किया गया है। १९४७-४८ में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों पर तीन लाख रुपये व्यय किए गए थे जबकि १९५३-५४ में यह राशि ६२ लाख रुपये थी। १९५४-५५ में इन जातियों के विद्यार्थियों के लाभ के लिए एक करोड़ से भी अधिक रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया गया था।

इस बात को भी अधिकाधिक अनुभव किया जा रहा है कि शिक्षण की सारी प्रगति अन्तर्गत शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है। पिछले लगभग ५० वर्षों में इन शिक्षकों के सामाजिक और आर्थिक स्तर का निरन्तर पतन होता गया है। युद्ध के वर्षों और उम्र भर तरबास बान के समय में उनकी दशा पतन के निम्नतम बिंदु तक जा पहुँची थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अध्यापन केवल उन लोगों का पेशा रह गया था जो अन्य सब क्षत्रों में अग्रगण्य रहे होते थे। देश के शैक्षणिक नक्शों में इस बात को अनुभव किया कि राष्ट्र का भविष्य नई पीढ़ियों की योग्यता पर निर्भर है और नई पीढ़ी की योग्यता अध्यापकों की योग्यता पर निर्भर है। परन्तु १९४७ से पहले शैक्षणिक नक्शा इतना असमर्थ था कि जो कुछ आवश्यक था उसे वे कर ही नहीं सकते थे।

१९४७ के बाद स्थिति बदलने लगी। वेतन त्रय में सुधार किया गया और कुछ मामलों में तो वेतन-वृद्धि चार या पाँच गुनी तक कर दी गई। फिर भी अभी तक वेतन त्रय इतना अच्छा नहीं है कि जिससे टीक डग के पुरुष और स्त्रियाँ अध्यापन के पेशे की ओर आकृष्ट हो सकें। अध्यापकों के आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी कुछ काम उठाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए विशय स्वागत समारोहों का आयोजन किया गया जिसमें भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा शिक्षामंत्री उपस्थित हुए। माध्यमिक विद्यालयों के कुछ निर्वाचित प्रधान

ध्यापकों के लिए मुख्य पवतीय प्रदेशों में सेमिनार तथा शीप्स कम्पों की व्यवस्था की गई। असिल भारतीय भाषार पर कई सम्मेलन बिय जा चुके ह जिनमें पाठ्यक्रम और अध्यायन-विधियों का पुनर्गठन करने की समस्याओं पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक एकत्र हुए ह। सक्षप में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि समाज की शिक्षा की नीति और कुछ मामलों में सामाजिक नीति के निर्धारण पर सभी स्तरों पर अध्यापकों का सहयोग प्राप्त किया जाए। परन्तु यह स्वीकार करना उचित होगा कि वस्तुतः सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक वर्ग की रचना के लिए अभी काफी कुछ करना शय है।

१९२१ के बाद से शिक्षा एक प्रान्तीय विषय रहा है जो सीधा एक निर्वाचित शिक्षामन्त्री के अधीन था और यह शिक्षामन्त्री राज्य के विधान-मण्डल के सम्मुख उत्तरदायी होता था। स्वतंत्र भारत के संविधान में भी यह स्थिति पहले जैसे ही है। केवल दो महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़कर शय सब दशाओं में शिक्षा अब भी राज्य का विषय है। ये दो अपवाद विश्वविद्यालय की शिक्षा और प्राविधिक (टेक्निकल) शिक्षा ह। उपलब्ध सुविधाओं का समन्वय करने और उच्चतर स्तर पर उचित प्रमाणों का बनाए रखन की दृष्टि से इन मामलों में संविधान ने जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर डाल दी है। वशानिक और प्राविधिक शिक्षा पर होन वाले भारी खर्चों को देखते हुए यह आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में दोहराव न हो। इसलिए उच्चतर वशानिक और प्राविधिक शिक्षा का विकास केन्द्रीय सरकार ने जिम्मे डाल दिया गया है।

इन प्रकार यह ठीक है कि शिक्षा राज्य-सरकार का विषय है और केन्द्रीय सरकार पर न तो इसने लिए कोई प्रत्यक्ष दायित्व है और न उसे इस सम्बन्ध में कोई वशानिक या सांविधानिक अधिकार ही है फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह शिक्षा के प्रत्यक्ष पहलू में अधिक से अधिक दिनचरसी ले। भावी सन्ततियों की मनोवृत्ति का निर्माण शिक्षा द्वारा ही होता है और यह आवश्यक है कि हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्य सक्षम और प्रमाण राष्ट्रीय दृष्टि से सब जगह एकरूप ह। तीन बातें ह जिनके कारण केन्द्रीय सरकार एक सलाहकार और समन्वय स्थापित करने वाली संस्था के रूप में अपने कार्यक्रमों को विस्तृत कर सक्ती है। लगभग सभी राज्यों के प्राथमिक साधन अपने शिक्षण-सम्बन्धी कार्यक्रमों को पूरा

करने के लिए अर्पण है। इसलिए अपनी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) को पूरा करने के वास्ते धनदान और सहायता के लिए व केन्द्रीय सरकार पर ही निर्भर रहते हैं। केन्द्रीय सरकार के पास सब राज्यों के सम्बन्ध में जानकारी भी सङ्गृहीत रहती है और वह प्रायः इस जानकारी से रोयनगृह (मिनिस्ट्रिंग हाउस) के रूप में भी कार्य करती है। इस तथ्य के कारण भी कि वही राजनीतिक दल राज्य-सरकारों का भी नियन्त्रण कर रहा है जो केन्द्र में सत्तालब्ध है और विभिन्न रूप में राष्ट्रीय जीवन में पङ्क्तिबद्ध की प्रमुख स्थिति के कारण भी काफी सहायता मिलती है।

परन्तु अध्यापक रूप से केन्द्रीय सरकार केवल आग्रह धनरोष कर सकती है राज्य सरकारों को बिना नहीं कर सकती। यदि कोई राज्य-सरकार केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता के बिना काम चलाय का शयार हो तो वह अपने साविधानिक अधिकार का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार की सलाह का अवहेलना कर सकती है। इस कारण कुछ ऐसे विविध साधनों का विकास किया गया है जिनमें शिक्षा में एकरूपता बनी रहे और ठीक-ठीक समन्वय होता रहे। इन साधनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सदल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन) है। जसा इसका नाम से स्पष्ट है यह एक सलाहकार निगम (बोडी) है। परन्तु क्योंकि बोर्ड-में विविधता के अनिश्चित इतरों सब राज्य के शिक्षामंत्री सम्मिलित होते हैं और केन्द्रीय शिक्षामंत्री इसका सभापति होता है इसलिए इसके नियम केन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारों को मानने ही होते हैं। क्योंकि इसकी सिफारिशों संप्रभुता ही सबसे अधिक से होती है—पिछले सात वर्षों में केवल एक समस्या का नियम मतदान द्वारा किया गया—इस कारण भी इसको और भी अधिक अधिकार (अधिकारिता) प्राप्त है।

अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (आस एडिटा कॉमिल फार टेक्निकल एजुकेशन) और हाल ही में निर्मित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) भी प्राविधिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्रों में इसी कार्य को पूरा करते हैं। जसा पहले उल्लेख किया जा चुका है इन दो क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार को अध्यापक और साविधानिक अधिकार भी प्राप्त हैं। इसके अनिश्चित इन दो निगमों की सलाह से ही बड़े-बड़े अनुमान

धीर सहायता रागियाँ शिक्षा संस्थाओं को दी जाती ह। इसलिए इन दो संस्थाओं का वही अधिक सोचा और सुनिश्चित प्रभाव है और य भारत की शिक्षा के सम्पूर्ण ढांच में सुदृढ़ बनाने वाले मामूले का-सा काम करती ह।

शिक्षा-सम्बन्धी प्रमाणा और नीतियों में एकरूपता बनाए रखने के लिए काम कर रहे इन उपकरणों को भारत सरकार द्वारा आयोजन आयोग (प्लानिंग कमिशन) की स्थापना से और भी अधिक प्रबल प्रोत्साहन मिला। आयोजन आयोग की नियुक्ति यह मानकर की गई थी कि यदि जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना और संविधान के प्ररक्त सिद्धान्तों को क्रियान्वित करना अभीष्ट है तो केन्द्रीय और राज्य-सरकारों के प्रयत्न का ठीक-ठीक समन्वय किया जाना आवश्यक है। क्योंकि आयोग का वाय यह था कि वह देश के भौतिक, मानवीय और पूँजी-सम्बन्धी साधन का आकलन (एन्मीनट) कर और ऐसी योजना बनाए जिससे उनका सबसे अधिक प्रभावशाली और मनुजित उपयोग हो सके इसलिए आयोग का राष्ट्रीय गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में भागे तीर पर एक निश्चित नीति निर्धारित कर देनी पड़ी। इन की आवश्यकताएँ अधिक थी और तुलना में साधन कम थे इसलिए यह आवश्यक था कि एक भार तो भ्रष्टाचार (प्रामोरिटी) का समुचित निर्धारण कर दिया जाए जिससे उपलब्ध साधन का सबसे अधिक प्रभावपूर्ण उपयोग किया जा सके और सबसे अधिक तीव्र आवश्यकताओं का सबसे पहले पूरा किया जा सके और दूसरी ओर सब स्तरों पर कार्यक्रमों का उचित समन्वय किया जाए जिससे दुर्घटक और अप्रत्याशित से बचा जा सके।

शिक्षा के क्षेत्र में आयोग ने प्रजातन्त्रात्मक राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सर्वांगीण कार्यक्रम तैयार किया। यह स्पष्टतया मान लिया गया कि शिक्षा भी विभिन्न स्थितियों एक-दूसरे से अनिच्छित रूप से सम्बद्ध ह और इसलिए किसी एक क्षेत्र में सब तक उन्नति नहीं हो सकती जब तक उसमें सम्बद्ध अन्य सब क्षेत्रों में भी उन्नति न हो जाए। यह भी स्वीकार कर लिया गया कि देश के विभिन्न भागों की आवश्यकताएँ और उनके साधन भिन्न भिन्न हैं और उन भागों के सामान्य तथा सौदागिक विकास में भी भिन्न ह। इसलिए प्रस्तावों और सन्धियों का निर्धारण करने में नरमी से काम लिया जाना चाहिए। फिर भी यदि राष्ट्रीय प्रयत्न का प्रभावपूर्ण



हो तो यह आवश्यक था कि मोटे सौर पर भ्रष्टताओं का निर्धारण कर दिया जाए और कुछ समय नियत कर दिए जाएं। इस प्रकार पंचवर्षीय आयोजन सारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों, लक्ष्यों और प्रमाणा में एकरूपता लाने की दृष्टि से अधिकारिक सहायक सिद्ध होगा।

## १

अब यहाँ संक्षेप में उस प्रगति पर दृष्टि डाल लेना उचित होगा, जो भारत में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में की है। १९४७ में प्राथमिक स्तर पर ६ से ११ वर्ष तक की आयु के बालकों में से मुखिल से ३० प्रतिशत किसी न किसी प्रकार के विद्यालय में पढ़ने जात थे। ५ वर्ष के अन्दर यह प्रतिशतता बढ़कर ४० प्रतिशत हो गई और उसके बाद इसमें और भी वृद्धि हुई है। ३१ मार्च, १९४८ को उन सब बड़े राज्यों में जो अब भारतीय संघ के क' क्षेत्रों के राज्य कहनाते हैं प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या लगभग १४० ०० थी। ३१ मार्च १९५३ को यह संख्या बढ़कर लगभग १८० ०० हो गई। इन राज्यों में विद्यालयों की संख्या में ४६ लाख से भी अधिक की वृद्धि हो गई है। यद्यपि अन्य राज्यों के सम्बन्ध में आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं—१९४७ से पहले कई देशी राज्यों में कोई सुसंगठित शिक्षण प्रणाली ही नहीं थी फिर शिक्षण-सम्बन्धी आँकड़ों का तो कहना ही क्या? फिर भी यह अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है कि इन राज्यों में भी शिक्षा की वृद्धि इसी अनुपात में या इससे भी काफी अधिक ही हुई होगी। ३१ मार्च १९५३ को सम्पूर्ण भारत में प्रारम्भिक विद्यालयों की संख्या २२० ०० से अधिक थी और उनमें शिक्षा पा रहे छात्रों की संख्या १ करोड़ ९० लाख से भी अधिक थी।

इस प्रकार केवल शिक्षा के परिमाण में ही अत्यधिक विस्तार नहीं हुआ बल्कि शिक्षा की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पुराने ढंग की शिक्षा के स्थान पर जो मुख्य रूप से साहित्य-सम्बन्धी और पितावी गिना थी अब प्रारम्भिक स्तर पर धीरे-धीरे राष्ट्रीय मूल्यवादी शिक्षा की प्रणाली प्रारम्भ की जा रही है। मूल्यवादी शिक्षा का धारणा में सबसे महत्वपूर्ण मान यह है कि शिक्षा का सम्बन्ध जीवन से होना चाहिए और शिक्षा किसी

सामाजिक दृष्टि से उपयोगी गतिविधि जैसे कोई नसा-बीजत, के साथ मिली जुली होनी चाहिए। विद्यालय के पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को धसल-धसल एक-दूसरे से पृथक समझने के बजाय ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए जिससे उन सब विषयों का एक दूसरे से सम्बन्ध और उनकी एकता स्पष्ट हो जाय। साथ ही विद्यालयों को चाहिए कि वे बच्चा को बचपन से ही यह सिखायें कि एक सहकारी समाज के संस्थ के रूप में किस प्रकार जीवन बिठाना उचित है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने बुनियादी शिक्षा के भिन्नान्तों को स्वीकार कर लिया है और इस प्रणाली को अपनाने के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम और मागदर्शक (माया-निर्देश) परियोजनाएँ शुरू की जा चुकी हैं जिससे उनका ध्यान विस्तार करने में सहायता रहे। बुनियादी विद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है परन्तु यह प्रगति उनकी तीव्र नहीं हुई जिससे हमें हानी चाहिए और इसका कारण समुचित रूप में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी रही है।

१९४७ में प्राथमिक विद्यालयों में ५६१००० अध्यापक काम कर रहे थे जिनमें से केवल ५८२ प्रतिशत प्रशिक्षित थे। उस समय प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रतिवर्ष ४०००० से कम लोग भरती होते थे। १९५५ में प्रशिक्षण विद्यालयों में हान बारी यह भरती प्रतिवर्ष ७०००० से भी अधिक हो गई। पहले से विद्यमान प्रशिक्षण विद्यालयों में स अनवर को बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों में परिवर्तित कर लिया गया है। कई जगह प्रशिक्षण की अवधि घटाकर कम कर दी गई है और हमारे साथ यह व्यवस्था की गई है कि नियत अवधि के बाद अध्यापन कार्य कर रहे अध्यापकों का बाच-बीच में प्रशिक्षण दिया जाता रहे। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि देश की आवश्यकताओं को देखते हुए ये प्रशिक्षण संस्थाएँ और इनमें प्रशिक्षण पान वाले व्यक्तियों की संख्या अब भी अपर्याप्त है।

इस समय विद्यमान प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों में बदलने पर परिवर्तित करने का काम ऐसा है कि इसमें काफी समय लगगा। इसलिए कुछ अन्तर्जातीय एम. एम. उठाए गए हैं जिससे प्राथमिक शिक्षा के विषयों का बच्चे के रूप में सुधार हो सके। उन सबमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि साथ-साथ उन विषयों को बुनियादी शिक्षा में परिवर्तित कर

हो तो यह आवश्यक था कि मोटे तौर पर भ्रष्टताभा का निर्धारण कर लिया जाए और कुछ सक्षम नियत कर दिए जाएं। इस प्रकार पंचवर्षीय आयोजन सारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों, सक्ष्यों और प्रमाणों में एकत्वता लाने की दृष्टि से अधिकधिक सहायक सिद्ध होगा।

## १

अब यहाँ सक्षप में उस प्रगति पर दृष्टि डाल लेना उचित होगा जो भारत ने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में की है। १९४७ में प्राथमिक स्तर पर ६ से ११ वर्ष तक की आयु के बालकों में से मुदिकल से ३० प्रतिशत बिली न बिली प्रकार के विद्यालय में पढ़ने आते थे। ५ वर्ष के अन्दर यह प्रतिशतता बढ़कर ४० प्रतिशत हो गई और उसके बाद इसमें और भी वृद्धि हुई है। ३१ मार्च १९४८ को उन सब बड़े राज्यों में जो अब भारतीय संघ के क' श्रेणी के राज्य कहलाते हैं प्राथमिक पाठशालाभा की संख्या लगभग १४०० ० थी। ३१ मार्च १९५३ को यह संख्या बढ़कर लगभग १८० ० हो गई। इन राज्यों में विद्यार्थियों की संख्या में ४६ लाख से भी अधिक की वृद्धि हो गई है। यद्यपि अन्य राज्यों के सम्बन्ध में अधिक उपलब्ध नहीं है—१९४७ से पहले कई देशी राज्यों में कोई सुसंगठित शिक्षण प्रणाली ही नहीं थी फिर शिक्षण-सम्बन्धी आवश्यकता का तो कहना ही क्या? फिर भी यह अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है कि इन राज्यों में भी शिक्षा की वृद्धि इसी अनुपात में या इससे भी काफी अधिक हो गई होगी। ३१ मार्च १९५३ को सम्पूर्ण भारत में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या २२०००० से अधिक थी और उनमें शिक्षा पा रहे छात्रों की संख्या १ करोड़ ९० लाख से भी अधिक थी।

इस प्रकार केवल शिक्षा का परिमाण में ही अत्यधिक विस्तार नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पुराने ढंग का शिक्षा के स्थान पर जो नव्य रूप से माहिर-अभ्यन्धी और पितामी शिक्षा थी अब प्राथमिक स्तर पर धीरे-धीरे राष्ट्रीय अनुियानी शिक्षा की प्रणाली प्रारम्भ की जा रही है। अनुियानी शिक्षा की धारणा में राजने महत्वपूर्ण भान यह है कि शिक्षा का नव्य जीवन न होना चाहिए और शिक्षा विगी

सामाजिक दृष्टि से उपयोगी गतिविधि जब कोई बच्चा-बालक के साथ मिली जुली होती चाहिए। विज्ञान के पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का अलग-अलग एक-दूसरे से पृथक् समझने के बजाय ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए जिससे उन सब विषयों का एक दूसरे से सम्बन्ध और उनकी एकता स्पष्ट हो जाय। साथ ही विज्ञानियों को चाहिए कि वे बच्चों को बचपन से ही यह सिखायें कि एक सहकार सम्प्राज के सम्यक् रूप में किस प्रकार जीवन बिताना उचित है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने बुनियादी शिक्षा के विद्यालयों की स्वीकार कर लिया है और इस प्रणाली का अन्तर्गत के विषय परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम और माध्यम (पाठ्य-नियम) परिष्कारनाएँ शुरू की जा चुकी हैं जिससे उनका आगे विस्तार करने में सरलता रहे। बुनियादी विद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है परन्तु यह प्रगति उतना तीव्र नहीं हुई जितना कि हानी चाहिए और इसका कारण समन्वित रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों का कमी रहा है।

१९७३ में प्राथमिक विद्यालयों में ५६१०० अध्यापक काम कर रहे थे जिनमें से केवल ५८२ प्रतिशत प्रशिक्षित थे। उस समय प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रतिवर्ष ४०० से कम लोग भर्ना होत थे। १९७५ में प्रशिक्षण विद्यालयों में हाल वाली यह भरती प्रतिवर्ष ७००० से भी अधिक हो गई। पहले से विद्यमान प्रशिक्षण विद्यालयों में सन्तान का बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों में परिवर्तित कर लिया गया है। बड़े जगह प्रशिक्षण का अवधि घटाकर कम कर दिया है और उसके साथ यह व्यवस्था की गई है कि नियत अवधि के बाद अध्यापन कार्य कर रहे अध्यापकों का बाध्य-बीच में प्रशिक्षण दिया जाता रहे। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि देश की आवश्यकताओं का दायित्व हुए ये प्रशिक्षण संस्थाएँ और इनमें प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों का संख्या अल्प भी अल्प है।

उस समय विद्यमान प्राथमिक विद्यालयों का बुनियादी विद्यालयों में बड़े पैमाने पर परिवर्तित करने का काम ऐसा है कि इसमें बाकी समय लगना। इसलिए कुछ अन्तर्विज्ञान एवं काम लगाए गए हैं जिससे प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों के स्तरों में सुधार हो सके। उन सबमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि छात्रों के उन विषयों का बुनियादी शिक्षा में परिवर्तित कर

पाना आसान रहे। इस प्रकार पाठ्यक्रम को और प्रच्छन्न बनाने के लिए उसमें कुछ दस्तकारीयों तथा अन्य कई प्रकार की सृजनात्मक गतिविधियों को स्थान देने का प्रयत्न भी किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा पर होन वाले व्यय में हुई वृद्धि से भी यह बात सूचित होती है कि देश सविधान में बननाय हुए सक्षम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिये कितना विनित है। ३१ मार्च १९४८ का १<sup>वाँ</sup> अधी के राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों पर होन वाला कुल व्यय १८ करोड़ ७० लाख रुपये प्रतिवर्ष था। १९५३ में ३१ मार्च का यह व्यय बढ़कर २४ करोड़ ९० लाख रुपये प्रतिवर्ष हो गया था। ३१ मार्च १९५३ को सम्पूर्ण भारत में प्राथमिक विद्यालयों पर होन वाला कुल व्यय ४३ करोड़ ७० लाख रुपये प्रतिवर्ष था।

यदि दो अन्य महत्वपूर्ण तत्वा का उल्लेख न किया जाय तो भारत में प्रारम्भिक शिक्षा में हुई वृद्धि का यह चित्र न तो स्पष्ट ही हो पायगा और न सम्पूर्ण ही होगा। स्वाधीनता के आगमन के फलस्वरूप अब लोग अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए उसे उन्मुख हो उठे हैं। जैसे कि वे पहले कर्मी नहीं हुए थे और वे अपने बच्चा को उचित शिक्षा दिवान के लिये अधीर हैं। सारे देश में लोग न गावों में विद्यालयों के बनना के निर्माण के लिए जमीन देता और शारीरिक श्रम खुले जिल में प्रदान किया है। केवल एक जिले में ही स्थानीय सागा ने विद्यालयों के लिए ६०० अकान तमार दिये। जिल धन्ना में १९४७ से पहले शिक्षण की सुविधाएँ थी ही नहीं या बहुत अल्प थी उनमें शिक्षा पाने की उन्मुखता और सेवा की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट होत पड़ती है। उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी के बकाइली इलाके में जो लगभग ००० वर्ग मील में फैला हुआ है १९४७ से पहले एक भी विद्यालय नहीं था। १९५३ में इस एजेंसी में लगभग १९०० विद्यालय बन चुके थे।

## २

राष्ट्र के साधनों का सवप्रथम उपयोग बालकों की शिक्षा के लिये किया जाना चाहिये। परन्तु बालकों के बड़े होने में समय लगता है और इस बीच में संसार का घटनाक्रम दबा नहीं रहेगा। १९३७ में प्रान्तीय स्वाशासन प्रारम्भ होने और देशी इलाकों में अग्रधिकार का फैलाव हो जाना स वयस्ता की

शिक्षा की बहुत बड़ा और प्रत्यक्ष प्रभाव प्राप्त हुआ। बसन्त शिक्षा के इस आन्दोलन के फलस्वरूप साक्षरता में काफी वृद्धि हुई। किन्तु उसके बाद भी ॥ वर्ष से अधिक धातु की कुल जनसंख्या में से १०४१ में साक्षरता का बचन १४६ प्रतिशत था। १०५१ तक यह संख्या बढ़कर १८ तक पहुँच गई थी। परन्तु केवल इन दो संख्याओं का जान लेना ही मात्रा वृत्तान्त स्पष्ट नहीं हो जाता। १०७ में बसन्त शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ी मात्रा में गतिविधि प्रारम्भ हुई थी उसमें दूसरा विन्दु यह है कि जो बड़ी मात्रा में पढ़ गये होंगे कि विन्दु का पूरा प्रभाव भारत में १९४१ के बाद ही अनुभव होना शुरू हुआ। यह काल में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि तो बड़ी मात्रा में हुई है। बड़े पैमाने पर बनी हो गई। बहुत-से विद्यालय बन्द कर दिए गए और बसन्त शिक्षा की गतिविधियाँ समग्र रूप से हो गई। १४६ में साक्षरता की वृद्धि के कारण शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रारम्भ किया जा सका। १०४६ और १९४७ के वर्षों में जो बड़ा संकाय और अनिश्चितता थी उसी के कारण यह प्रकार का रचनात्मक कार्य रखा-सा रहा और इस संकाय का परिणाम अन्त में देना विचारों के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए यह सचमुच निश्चित ही है कि स्वाधीनता प्राप्ति के समय से साक्षरता के आंकड़े १९४१ के अन्त में कुछ कम ही रहेंगे। इसलिए साक्षरता में १४६ प्रतिशत से १८३ प्रतिशत की वृद्धि धीरे-धीरे स्वाधीनता के पञ्चाब्द के काल में प्राप्त संभवता समझी जानी चाहिए।

सुविधाओं में आर्थिक विस्तार के अतिरिक्त विद्यालयों में नई-नई संस्थाएँ पाठ्य गुणों में भी अधिक हो गई हैं—भारत में बसन्त शिक्षा के कार्यक्रमों में उन्नतता का दृष्टि से भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वाधीनता से पहले बसन्त शिक्षा के कार्यक्रमों का मुख्य केवल पठना-लिखना सिखाना मात्रा मात्रा मात्रा करता था। परन्तु अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि केवल मात्रा मात्रा प्राप्त करने से बसन्तों का शिक्षा के प्रति वह उन्माह जो धुन में बड़ा तीव्र होता है धीरे-धीरे घटता जाता है। इसलिए नये कार्यक्रमों में ऐसा पद्धतिपूर्ण और निवासन पर आरम्भ किया गया किनसे लोगों की शिक्षा में रुचि बनी रहे और साथ ही यह शिक्षा उन लोगों को पूरा करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जो उन शिक्षा प्राप्त करने वाले बसन्त लोगों का करने से पड़ता है।

भारत सरकार ने वयस्क शिक्षा की जो नई धारणा बनाई है उसमें इन दोनों बातों को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। इस धारणा में साक्षरता के महत्व को स्वीकार आवश्यक किया गया है किन्तु साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि यदि किसी शिक्षावादी का कार्यक्रम को सफल बनाना है तो उसमें वयस्क लोगों की विविध रुचियों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इसलिए सामाजिक शिक्षा का एक संशुद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें (क) साक्षरता (ख) आरोग्य और स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का ज्ञान (ग) आर्थिक दशाभा की मुधारण का प्रदर्शन (घ) नागरिक शिक्षा और नागरिकता की शिक्षा तथा (ङ) शिक्षा के मनोरंजनात्मक पहलुओं पर विशेषित बल दिया गया है।

यह स्पष्ट करने के लिये कि ये नये कार्यक्रम केवल साक्षरता के पुराने कार्यक्रमों में मिलाए हैं और इस बात पर जोर देने के लिए कि वयस्कों को दी जाने वाली शिक्षा सामाजिक विषयों से सम्बद्ध होनी चाहिये इन नये कार्यक्रमों को 'सामाजिक शिक्षा' नाम दिया गया है।

१०३७ ३९ के दिनों में बनाया गए वयस्क शिक्षा आन्दोलन के अनुभवों से यह बात भी सामने आई कि यदि नवमाछर लोगों की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान पर्याप्त मात्रा में पाठ्य सामग्री विद्यमान न हो तो साक्षरता भी दर दर बनी नहीं रह सकता। लोग क्या सिखा सब भूल जाते हैं। १९५० के प्रारम्भ में यह निश्चय किया गया था कि इन विभिन्न विषयों पर जिनमें सामाजिक मनन्य को निम्नस्वी होती है छोटी-छोटी पुस्तिकाओं की एक माला प्रकाशित की जाय। अब तब हिन्दी में १६० पुस्तिकाएँ प्रकाशित की जा चुकी हैं और उसके सम्बन्ध में सबको यह खुसी अनुभवित है कि वे किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित की जा सकती हैं। हाथ ही में एक और योजना प्रारम्भ की गई है जिसका अन्तर्गत किसी भी भारतीय भाषा में छठी नवमाछर के लिए उपयोगी स्वीडन पुस्तक की एक सूची तैयार की जायेगी। इन पुस्तिकाओं पर प्रतिक्रिया पुरस्कार भी दिया जायेगा। केन्द्रीय सरकार ने सरल हिन्दी भाषा में जनता के लिए ज्ञान बाग (ज्ञान सरोवर) का पहला भाग भी तैयार कर दिया है। यह जलद्वेय पाँच भागों में प्रकाशित होगा। नवमाछरों के

लिए उपयोगी साहित्य के सत्रन के सम्बन्ध में विविध प्रशिक्षण देने के लिए कुछ साहित्यिक वर्गों को भी स्थापना किया जा चुका है। कई राज्य सरकारों ने भी विभिन्न भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के साहित्य का सत्रन करने के लिए प्राथमिकीय कार्य किया है।

किन्तु भारत का सामान्य का प्रसार करने का प्रथम कदम अपनी समस्याओं तक ही सीमित नहीं रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी राज्य विकसित देशों में जावन के स्तर को ऊँचा उठान में शिक्षा का महत्वपूर्ण हाथ होता है भारत ने शिक्षा में सामान्यीय कार्यवाही के लिए देशी बयस्का की शिक्षा के बारे में युनस्को के सह समन्वय का आयोजन किया। भारत ने 'मूलमूल' शिक्षा के सम्बन्ध में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए भी मुविषाए प्रशान की हैं। सामाजिक शिक्षा में दृश्य-श्रव्य (छात्रों को विद्युत्) उपकरणों का अधिकधिक प्रयोग करने के लिए भी काम उठाया गया है। इस कार्य-योजना को पूरा करने के लिए समय-समय पर कार्यकर्ताओं के लिए विविध प्रशिक्षण के माध्यमों का आयोजन किया गया है।

समाज शिक्षा के सम्बन्ध में हुई प्रगति का धनमान इस तथ्य में मगाया जा सकता है कि १९४७ से लेकर १९५४ तक की अवधि में एक पराई स अधिक निरन्तर लोगों को सागर बनाया गया। यह बात विविध रूप में प्रस्तुत की है कि महिलाओं ने भी इन कार्यक्रमों में बड़ा उम्माह में भाग लिया है और नवमानव लोगों में उनका अनुपात भी काफी अधिक है।

### ३

प्राथमिक शिक्षा का पुनगठन या बयस्कों की शिक्षा का विस्तार सब तरफ समभव है जब तक उसी अनुपात में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार और पुनगठन न हो जाय। प्राथमिक शिक्षा और बयस्क शिक्षा दोनों के लिए ही अध्यापक मन्त्रालय ने माध्यमिक विद्यालयों द्वारा तयार किए जाने हैं। साथ ही उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों का भी माध्यमिक विद्यालय ही तैयार करने हैं। इस प्रकार समाज की शिक्षा के कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु यह बात सचरिणि है



कि भवतः भारतीय शिक्षा की शृंखला में माध्यमिक शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी रही है। परिमाण की दृष्टि से यह माध्यमिक शिक्षा ११ से १७ वर्ष की आयु के बालकों में से केवल १० प्रतिशत को पढ़ने की सुविधा प्रदान कर पा रही है। बढ़ते हुए प्रजातन्त्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह संस्था विल्कुल ही अपर्याप्त है। इसके प्रतिरिक्त य १० प्रतिशत बालक भी योग्यता के आधार पर नहीं चुने जाते बल्कि इस आधार पर चुने जाते हैं कि किस बालक का परिवार विद्यालय की फीस का खर्चा उठा पाने में समर्थ है। गुण या उत्कृष्टता (क्वालिटी) की दृष्टि से इस माध्यमिक शिक्षा की अपनी कोई विशेषता नहीं है। इसे एक ऐसा निश्चित पड़ाव भी नहीं माना जा सकता जहाँ पर एक नियत स्तर तक की औपचारिक (फार्मल) शिक्षा समाप्त हो जाती है। माध्यमिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा की सबसे तैयारी मात्र समझा जाता है और लगभग वे सभी बालक जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं विश्व विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने पहुँच जाते हैं। एक बात और यह शिक्षा बहुत अधिक बिनाबी शिक्षा है और विभिन्न अभिरूचि (एप्टिट्यूड) वाले छात्रों को अनलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ है।

इसलिए परिमाण और उत्कृष्टता दोनों की ही दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन एक तात्कालिक आवश्यकता है। एक ओर तो १९४७ के पहले विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की अपेक्षा वहीं अधिक संख्या वाले छात्रों को शिक्षा देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है और दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि विभिन्न अभिरूचि वाले छात्रों के लिए अलग अलग प्रकार के विभिन्न विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाय। साथ ही यह भी आवश्यक है कि देशी और गहरी क्षत्रों की अनलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये ढंग के व्यावसायिक विद्यालय (वोकेशनल स्कूल) तैयार किए जायें।

१९४७ के बाद माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में परिमाण की दृष्टि से कुछ प्रगति हुई बार माध्यमिकता कहा जाता है और यह कहना निराधार नहीं है। १९४८ में उन प्रान्तों में जिन्हें यह बंधन था कि वे राज्य कहा जाता है, माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या त्रिगुणित स्कूल और हाई स्कूल दोनों ही सम्मिलित थे १२५० से कुछ ही अधिक थी। पाँच वर्ष बाद १९५१ में

यह संख्या बढ़कर १८५०० हो गई। यदि केवल हाई स्कूलों (उच्च विद्यालयों) और हायर सेकेंडरी स्कूलों (उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों) पर ही ध्यान दिया जाय तो प्रगति और भी अधिक आश्चर्यजनक प्रतीत होती। १९४८ में ऐसे विद्यालयों की संख्या ४० ० से भी कम थी और १९५४ में यह बढ़कर लगभग १० ०० तक जा पहुँची।

इन विद्यालयों में यही हान वाले छात्रों के आंकड़ भी इतने ही विस्मयजनक हैं। १९४८ में क' अणी के राज्य में विद्यमान मिडिल स्कूलों में छात्रों की संख्या १० लाख से कुछ ही अधिक थी। १९५३ में यह संख्या बढ़कर १५ लाख हो गई थी। उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में १९४८ में छात्रों की संख्या १८ लाख थी जो १९५३ में बढ़कर लगभग ३० लाख हो गई। सब प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा पा रहे छात्रों की कुल संख्या १९५४ में ६ लाख से अधिक थी। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या १९४८ से १९५३ तक बढ़कर दुगुनी से भी अधिक हो गई।

माध्यमिक शिक्षा के ऊपर होने वाले व्यय में हुई वृद्धि भी चौंकाने वाली है। १९४८ में क' अणी के राज्य में माध्यमिक शिक्षा पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय १३ करोड़ ४८ लाख रुपये था। १९५३ में यह अंक बढ़कर २८ करोड़ ६८ लाख रुपये हो गया। सम्पूर्ण भारत में १९५३ में माध्यमिक शिक्षा पर ३६ करोड़ ८५ लाख रुपये व्यय हुए।

इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा के गणात्मक सुधार अर्थात् शिक्षा की किस्म के सुधारों के लिए भी अनवरत प्रयत्न किया गया। अनेक राज्यों ने इस सम्बन्ध में विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अपनी अपनी समितियाँ नियुक्त की। परन्तु यह भी अनुभव लिया गया कि माध्यमिक शिक्षा स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं को ठीक ठीक रूप से पूरा कर सके इसके लिए यह आवश्यक है कि इस भारी समस्या का अखिल भारतीय पैमाने पर परिणाम (सर्वे या सर्वेक्षण) किया जाय। इसलिए १९५२ में एक आयोग की नियुक्ति की गई जिसके अध्यक्ष डा. लक्ष्मण स्वामी मुन्तलियार थे। इस आयोग का काम सम्पूर्ण भारत में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना था। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) १९५३ में प्रस्तुत कर दिया।

यहां इस आयोग द्वारा की गई केवल थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी सिफारिशों का ही संकेत कर देना उचित होगा। इस आयोग ने सिफारिश की है कि माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में एक वर्ष और बढ़ा दिया जाय जिससे माध्यमिक शिक्षा पूर्ण हो जाय और उसे भी अपने आपमें एक पूरी मजिद समझा जा सके। आगा की जाती है कि इससे विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर ऊंचा हो जाएगा और विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायों में ज्ञान के लिए तैयार हो सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि सारे पाठ्यक्रम का नया सिरे से पुनर्गठन किया जाय जिससे विद्यार्थियों के ऊपर और अधिक भार डाले बिना पाठ्य विषयों में और अधिक विविधता लाई जा सके। ऐसा करने के लिए यह चल किया जा रहा है कि सारे पाठ्यक्रम का कुछ बड़ी सावधानी के साथ चुने हुए महत्वपूर्ण विषयों के आधार पर और उनमें सम्बद्ध रूप में तैयार किया जाय। एक तीसरी महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि बड़ी संख्या में बहुप्रयोजन विद्यालय (मल्टीपरपज स्कूल) खोले जाय। परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में भी बहुत बड़े पमाने पर सुधारों की सिफारिश की गई है।

आयोग की कुछ सिफारिशों तो ऐसी हैं जिन्हें राज्य सरकारें विद्यमान ७ वर्षों में पहले ही चपताना प्रारम्भ कर चुकी थीं। दोष सिफारिशों पर तत्परतापूर्वक काम किया जा रहा है। बहुत-से माध्यमिक विद्यालयों में नागरिक शास्त्र, संगीत, कला-कौशल और कृषि जैसे विषय प्रारम्भ करने पाठ्यक्रम में सुधार कर दिया गया है। नये प्रकार के उच्च विद्यालय भी खोले गए हैं जिनमें कृषि, गिर्य और व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। हमने भी वहीं अधिक महत्वपूर्ण एक नये प्रकार के उच्च माध्यमिक विद्यालय का विकास है जिसका स्वरूप उत्तर बुनियादी विद्यालय (पोस्ट सेनिअर स्कूल) का होगा।

यहां इस बात का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उत्कृष्टता के सुधार के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं। प्रशिक्षण की सुविधाओं में बहुत अधिक वृद्धि की गई है और सेवा काल में ही प्रशिक्षण के लिए कम पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। राष्ट्रीय सरकार ने सत्तारूढ़ होने के बाद महीने के छह-आठ दिनों में केन्द्रीय शिक्षा प्रशिक्षण (सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन) की स्थापना की जिसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण

को नया रूप दिया जा सके और शिक्षण सम्बन्धी अनुसंधान के कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा सकें। यह प्रतिष्ठान इस समय ऐसी बुनियादी शिक्षा का ढग मात्र निकालन का मूल भर रहा है जो गहरी इलाका के लिए उपयुक्त है। साथ ही विद्यार्थियों में इस्तेमाल होने वाले सस्ते और उपयोगी फर्नीचर तयार करके और नये और मितव्यय-पूर्ण दुग्ध-शुद्ध उपकरण तयार करने के सम्बन्ध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। अपने सात वर्ष के छोटे-से जीवन-काल में इस प्रतिष्ठान ने इतनी प्रगति की है कि उसमें भारत और भारत में बाहर के अनेक प्रमुख विद्वानों का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ है।

#### ४

विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में देश की सबसे प्रमुख आवश्यकता यह है कि इस समय विद्यमान सुविधाओं को पक्का किया जाय और उनमें सुधार किया जाय। फिर भी इस क्षेत्र में परिमाण की दृष्टि से भी काफी विस्तार हुआ है। १९६७ से पहले अविभक्त भारत में २१ विश्वविद्यालय थे। विभाजन होने के बाद भी केवल भारतीय संघ में ही विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर ३१ हो गयी है। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो १४८ में २०५०० तक बढ़ी १९५३ में बढ़कर ४६५०० से भी अधिक हो गयी। १९४८ में भारतीय संघ के ११ राज्यों में विश्व विद्यालयां सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या २७०० थी १९५३ में यह बढ़कर ५००० हो गयी।

विश्वविद्यालया तथा उच्चतर शिक्षा देने वाली अन्य संस्थाओं पर होने वाला व्यय जिसमें प्राविधिक शिक्षा का व्यय सम्मिलित नहीं है—१९४८ में १ करोड़ के राज्यों में ७ करोड़ ६२ लाख रुपये था १९५३ में यह बढ़कर १६ करोड़ ४० लाख रुपये हो गया। १९५३ में सम्पूर्ण भारत में उच्चतर शिक्षा पर होने वाले व्यय की राशि २१ करोड़ १६ लाख रुपये थी।

परन्तु विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्या शिक्षा की उत्तुङ्गता की है। १९४७ से पहले भी यह शिक्षावस्तु थी कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। विश्वविद्यालयों में छात्रों की बहुत भीड़ और केवल मर्यादित विषयों का बहुत अधिक ध्यान दिया जाने की आलोचना शिक्षाशास्त्रियों और मातृ

यहां इस आयोग द्वारा की गई केवल थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी सिफारिशों का ही संकेत कर देना उचित होगा। इस आयोग ने सिफारिश की है कि माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में एक वर्ष और बढ़ा दिया जाय जिससे माध्यमिक शिक्षा पूर्ण हो जाय और उस भी अपने-आपमें एक पूरी मजिल समझा जा सकें। आगा की जाती है कि इससे विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर ऊंचा हो जायगा और विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायों में जाने के लिए तैयार हो सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि सारे पाठ्यक्रम का नया सिलेबस पुनर्गठन किया जाय जिससे विद्यार्थियों के ऊपर और अधिक भार डाले बिना पाठ्य विषयों में और अधिक विविधता लाई जा सके। ऐसा करने के लिए यह यत्न किया जा रहा है कि सारे पाठ्यक्रम को कुछ बड़ी सावधानी के साथ चुने हुए महत्वपूर्ण विषयों के आधार पर और उनसे सम्बद्ध रूप में तैयार किया जाय। एक तीसरी महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि बड़ी संख्या में बहुप्रयोजन विद्यालय (मल्टीपरपज स्कूल) खोले जाय। परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में भी बहुत बड़ा पैमाने पर सुधारों की सिफारिश की गई है।

आयोग की कुछ सिफारिशें तो ऐसी हैं जिन्हें राज्य सरकारें पिछले ७ वर्षों में पहले ही अपनाना प्रारम्भ कर चुकी थी। शेष सिफारिशों पर तत्परतापूर्वक काम किया जा रहा है। बहुत-से माध्यमिक विद्यालयों में नागरिक शास्त्र, संगीत, कला-कौशल और कृषि जैसे विषय प्रारम्भ करके पाठ्यक्रम में सुधार कर दिया गया है। नये प्रकार के उच्च विद्यालय भी खोले गए हैं जिनमें कृषि, शिल्प और व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। हमने भी बड़ी अधिक महत्वपूर्ण एक नये प्रकार के उच्च माध्यमिक विद्यालय का विकास है जिसका स्वरूप उत्तर बनिपादी विद्यालय (पोस्ट ब्रिज स्कूल) का होगा।

यहां इस बात का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उत्कृष्टता के सुधार के लिए क्या प्रयत्न किये गए हैं। प्रशिक्षण की सुविधाओं में बहुत अधिक वृद्धि की गई है और सेवा काल में ही प्रशिक्षण के लिए नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गए हैं। राष्ट्रीय सरकार ने सत्तास्पर्द्धा होने के चार महीने के अन्दर अन्दर दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा प्रशिक्षण (सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन) की स्थापना की जिसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण

को नया रूप दिया जा सके और शिक्षण सम्बन्धी अनुसंधान के कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा सकें। यह प्रतिष्ठान हम समय ऐसी अनियामी शिक्षा का तग तान निकालन का प्रयत्न कर रहा है जो पहरी इलाका के लिए उपयुक्त न। साथ ही विद्यालयों में इस्तेमाल होने वाले सम्म और उपयोगी पर्नोंवर तयार करन और नये और मितव्यय-पूर्ण दृश्य-श्रव्य उपकरण तयार करन के सम्बन्ध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। अपने साथ वष के छोटे-से जीवन-काज में इस प्रतिष्ठान ने इतनी प्रगति की है कि उसने भारत और भारत में बाहर के प्रमुख विद्वानों का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ है।

## ४

विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में देश की सबसे प्रमुख आवश्यकता यह है कि इस समय विद्यमान सुविधाओं को पक्का किया जाय और उनमें सुधार किया जाय। फिर भी इस क्षेत्र में परिमाण की दृष्टि में भी काफी विस्तार हुआ है। १९४७ में पहले अविकसित भारत में २१ विश्वविद्यालय थे। विभाजन होने के बाद भी केवल भारतीय संघ में ही विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर ३१ हो गयी है। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जा १९४८ में २२५००० से कम थी १९५३ में बढ़कर ४६५००० से भी अधिक हो गयी। १९४८ में भारतीय संघ के ७ देशी के राज्या में विश्व विद्यालयों में स्नातक होने वाले छात्रों की संख्या २७००० थी १९५३ में यह बढ़कर ५०००० हो गयी।

विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा देने वाली अन्य संस्थाओं पर होने वाला व्यय जिसमें प्राध्यापक शिक्षा का व्यय सम्मिलित नहीं है—१९४८ में 'क' देशी के राज्या में ७ करोड़ ६२ लाख रुपये था १९५३ में यह बढ़कर १६ करोड़ ४ लाख रुपये हो गया। १९५३ में सम्पूर्ण भारत में उच्चतर शिक्षा पर होने वाले व्यय की राशि २१ करोड़ १६ लाख रुपये थी।

परन्तु विश्वविद्यालयों की शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्या शिक्षा की उत्कृष्टता की है। १९४७ में पहले भी यह निकायत थी कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। विश्वविद्यालयों में छात्रों की बहुत भीड़ और केवल मैट्रिकुलेशन क्रिया का बहुत अधिक ध्यान न्यि जान की आलोचना शिक्षाशास्त्रियों और मान

जनिक नताभा दोनों ने ही की थी। इस बात की ओर भी ध्यान खींचा गया था कि विश्वविद्यालय केवल शहरों की आवश्यकता को पूरा करते हैं और ग्रामों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। १९४७ में यह अनुभव किया गया कि विश्वविद्यालय की शिक्षा की समूची समस्या की नम सिर से पड़ताल होनी चाहिये। तदनुसार १९४८ में प्रोफसर सचपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गयी और इस आयोग ने १९४९ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया।

इस आयोग का कथन है कि विश्वविद्यालयों को न केवल राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में ही नतुत्व प्रदान करना चाहिये अपितु विभिन्न पेगों उद्योगों और वाणिज्य के क्षेत्र में भी नतुत्व प्रदान करना चाहिये। उन्हें हर प्रकार की उच्चतर शिक्षा की साहित्यिक और वैज्ञानिक प्राविधिक और व्यावसायिक उच्चतर शिक्षा की बढ़ती हुई माँग को पूरा करना चाहिये। विस्तृत उदार अर्थात् साहित्यिक शिक्षा के महत्व का स्वीकार करते हुए भी आयोग ने भारतीय विश्व विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा और कृषि की शालाओं (फैकल्टीज) को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग की सम्मति में भारत जैसे देश के लिए कृषि शिक्षा का विस्तार ऐसी वस्तु है जिस सबसे अधिक अग्रता दी जानी चाहिए। आयोग का सुझाव है कि कृषि महाविद्यालय यथासम्भव देहाती क्षेत्रों में बनाये जाने चाहिये इससे छात्रों को देहाती जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर मिलेगा और वे देहाती परिस्थितियों के सम्बन्ध में सीधा और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इससे शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के सम्बन्ध में की जाने वाली इस आलोचना का भी निराकरण हो जायगा कि इस शिक्षा प्रणाली में देहाती क्षेत्रों की आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है।

स्वाधीनता प्राप्त होने से पहले सब भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। परन्तु अब प्रमुख शिक्षा-शास्त्रियों का विचार था कि इसके कारण अधिकांश विद्यार्थियों पर एक अनावश्यक और अनुचित बोझ पड़ जाता है और यथासमय अंग्रेजी का स्थान किसी न किसी भारतीय भाषा को लेना होगा। १९४७ के बाद अंग्रेजी को हटाने की माँग बहुत प्रबल हो उठी। इस

मार्ग के उपसिद्धान्त (कोरोसरी) के रूप में कई प्राग्दिन विन्विद्यालय स्थापित किये गये और यह कहा जा सकता है कि १९५२ तक भारत का कोई ऐसा प्रमुख भाषा प्रयोग नहीं रहा था जिसका अपना विन्विद्यालय न हो। साथ ही शिक्षा-शास्त्रियों का यह भाव था और सामान्यतया सारा देश इससे सहमत था कि शिक्षण के माध्यम के परिवर्तन की प्रगति शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिये किन्हीं बाह्य कारणों के आधार पर नहीं। इस सम्बन्ध में प्रायोगिक सिफारिशों से जनमत को सुनिश्चित बनाने और शिक्षा के प्रभावा को कायम रखने में सहायता मिली है।

इस आयोग की सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण एक सिफारिश यह थी कि जब श्रुत शिक्षण में विश्वविद्यालय अनुदान समिति है उसी दृष्टि पर भारत में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का जाय। इस सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने पहले एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की। पहले यह बताया जा चुका है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावा को यथाचित रूप में बनाये रखना और उपलब्ध सुविधाओं का समन्वय करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। यह बात सामान्यतया स्वीकार कर ली गयी थी कि इस जिम्मेदारी का विश्वविद्यालय अनुदान समिति को सन्धान बनाकर सबसे अधिक प्रबल रूप में निवाहा जा सकता है। हाल ही में इस समिति का स्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ले लिया है जिसके अधिकार और कार्य समिति का अपेक्षा अधिक कर लिये गये हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में वित्त के लिए बड़ा धनराशिया इस आयोग को दी गयी है। आगे की जाती है कि यह आयोग अपने स्वयं की परीक्षा प्रभाव द्वारा विश्वविद्यालयों में कहीं अधिक प्रबल समन्वय (कोऑर्डिनेशन) स्थापित कर सकना और उत्तमतर शिक्षा के लिए प्रभावपूर्ण और मितव्ययी प्रसार के लिए परिस्थितियों तयार कर सकेगा। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद अपनाया गयी नीति के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान की प्रगति का भी बड़ा प्रोत्साहन मिला है। आगे की जाती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस प्रगति का न केवल बनाये रखना अपितु इस और भी सबसे बनायेगा।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश के अनुसार छात्रों को सुबह और यद्यपि का उत्तमतर शिक्षा प्राप्त करने तथा अनुसन्धान



करने में समर्थ बनाने के लिए विज्ञान तथा अन्य कलाएँ—साहित्य, धर्मशास्त्र राजनीति इत्यादि—के लिए अनुसंधान-छात्रवृत्तियाँ देना शुरू की गयी है। अनुसंधान का उत्तम कार्य करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में सुविधाओं में बहुत वृद्धि कर दी गयी है। इन प्रयोगशालाओं की स्थापना स्वाधीनता के बाद प्राप्त हुई वही महत्वपूर्ण सफलता है। टीक-ठीक कहा जाय ता ये शिक्षण सम्पादने नहीं हो सके, अपितु उच्चतर अध्ययन और अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये वैज्ञानिक शिक्षा के प्रमाणा में सुधार करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण योग दे सकती हैं।

### ५

द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की अनेक बड़ी बड़ी मुश्किलें सामने आयीं। युद्ध की आवश्यकताओं के कारण औद्योगिक और प्राविधिक क्षेत्र में निम्नवर्ग वृद्धि प्रगति हुई परन्तु यह प्रगति राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को बनाय रखने के लिए किसी सुधायोजित कार्यक्रम के अनुसार न होकर केवल सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गयी कुछ कामचलाऊ ढंग की प्रगति थी। लड़ाई बन्द होने के बाद देश में बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण प्रारम्भ किया गया परन्तु यह उद्योगीकरण तब तक सफल नहीं हो सकता था जब तक कि देश में इंजीनियरिंग और प्राविधिक शिक्षा का बिल्कुल नये सिरे से पुनर्गठन न किया जाय। इस समस्या को हल करने के लिए अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षण परिषद् (आल इण्डिया कौमिल फार टेक्निकल एजुकेशन) की स्थापना की गयी जिसका काम सब स्तरों पर प्रमापों को सुधारने और गिनत सम्बन्धी शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि करने के उपाय सुझाना था।

स्वाधीनता मिल जाने के बाद इस कार्य को और अधिक प्रावधिकता दी गयी। यह अधिकाधिक अनुभव किया गया कि सारी औद्योगिक प्रगति प्रविधि तथा विज्ञान ज्ञान वाली जनशक्ति पर निर्भर है। दूसरी ओर देश में इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक शिक्षा के लिए विद्यमान सुविधाएँ उत्पन्नता की दृष्टि से और परिमाण की दृष्टि से आवश्यकताओं की अपेक्षा वहीं कम थीं। १९४७-४८ में भारत में इंजीनियरिंग में केवल लगभग ९० स्नातक हुए और प्रविधि विज्ञान

में गिना की स्थिति विहयावलोकन

तोलोजी) में केवल ३००। स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसंधान करने और प्रशिक्षण के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सुविधाएं बहुत ही कम थीं। प्रविधि विज्ञान के क्षेत्र में तो लगभग थीं ही नहीं। इसलिए प्राविधिक शा का क्षेत्र ऐसा था जिसमें न्यूनतम समय में अधिकतम प्रगति की जान आवश्यकता थी।

जिस प्रकार इस क्षेत्र में आवश्यकता तीव्रतम थी उसी प्रकार हमें प्रगति की आवश्यकता तेजी से हुई है। इंजीनियरिंग और प्रविधि विज्ञान दोनों में स्नातका की संख्या तिगनी से भी अधिक हो गई है। सारे देश में कुछ चुनी हुई संस्थाओं का अपनी इमारतों प्रयोगशालाओं और उपकरणों को सुधारने के लिए बड़े-बड़े अनुदान दिए गए हैं। इन संस्थाओं के गिनक वर्ग को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। गरीब होनहार विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि कर दी गयी है। अतीत में प्राविधिक गिना (टैक्निकल एजुकेशन) की एक कमजारी यह थी कि यथोचित व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाओं का अभाव था। इस कमी को पूरा करने के लिए उद्योगों के सहयोग से औद्योगिक प्रशिक्षण छात्रवृत्तियों की एक योजना चालू की गयी है।

भारतीय प्राविधिक गिना के क्षेत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना १५१ में बनारस के पास लखनपुर में भारतीय प्रविधि विज्ञान प्रतिष्ठान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) की स्थापना है। मुख्य रूप से इस प्रतिष्ठान का उद्देश्य यह है कि इसमें स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान का प्रबंध हो। इसलिए इस संस्था में उच्चतम स्तर तक गिनक विज्ञान के गिनक और अनुसंधान की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। अन्त में जाकर यह प्रतिष्ठान इंजीनियरिंग और प्रविधि विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान कर सकेगा। यहां पर विनाय रूप से यह उल्लेख कर देना भी उचित होगा कि सम्बंधन इंजीनियरिंग उत्पादन मध्यम गिनक विज्ञान नौनिर्माण गिनक (नवन प्राक्किक्कर) मशीना का बनाने और सम्भालने तथा औद्योगिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम इस समय तक शुरू भी हो चुका है।

वयनौर में स्थित भारतीय विज्ञान प्रतिष्ठान की पुराना शालाओं (फैक्ट्रीज) को परिवर्धित किया गया है और कुछ नई शालाएं भी बनायी गयी हैं।

१९४७ से पहले भी इस प्रतिष्ठान ने विगुप्त तथा मूल विभागों के सम्बन्ध में अनुसन्धान केन्द्र के रूप में अच्छी भ्याति प्राप्त कर ली थी। १९४७ और १९५२ के बीच इस प्रतिष्ठान ने प्राविधिक विकास के लिए बनायी गयी योजनाओं के कारण जो अब लगभग पूरी होन वाली है यह प्रतिष्ठान प्राविधि विज्ञान में भी स्नातकोत्तर गिम्ना और अनुसन्धान की उच्चतम कोटि की स्थापना कर गया है।

अब तक प्राप्त सफलता का कुछ आभास देने के लिए कुछ आंकड़ों को चर्च कर देना उचित होगा। १९४७ में विद्यालय के स्तर पर विज्ञान विषय करने वाले विद्यार्थियों की संख्या २ लाख थी जो बल्कर १९५३ में ११॥ लाख हो गयी। इस अवधि में उस प्रकार की शिक्षा पर होने वाला व्यय २२ लाख ५० हजार रुपये से बढ़कर ६५ लाख ५० हजार रुपये हो गया। महा विद्यालय के स्तर पर भी इस शिक्षा का विस्तार इसी प्रकार उल्लेखनीय था। यहाँ १९४७ में चर्चा होन वाले छात्रा की संख्या ४६० थी जो १९५३ में ११५००० हो गयी। इस स्तर पर १९४७ में होन वाला व्यय २ करोड़ रुपये था जो १९५३ में ६ करोड़ रुपये हो गया।

## ६

भारतीय गणतन्त्र के शिक्षात्मक कार्यक्रम का यह मोटा और सर्वांगिक चित्र भी अब तक अपूर्ण ही रहेगा जब तक जनता के साम्प्रतिक जीवन को विकसित करने के लिए उठाये गये कदमों का यहाँ कुछ उल्लेख न कर लिया जाय। न केवल भारत में बल्कि आधुनिक संसार के अनेक भागों में भी गिम्ना में जोर इस बात पर रहता है कि बाल्य और भावनाओं की बलि देकर बुद्धि को सीधे दिया जाय। मानव प्रकृति के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की इस प्रकार उपेक्षा कर देने से सम्भोद समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं और आन्तरिक यूरोप और अमेरिका के शिक्षाशास्त्री इसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए असन्तुलन को सुधारने के लिए उपाय खोजने में जुटे हुए हैं।

भारत इस प्रकार की समस्याओं से बहुत कुछ इसलिए बचा रह गया क्योंकि उसके यहाँ ओव संस्कृति की बहुत प्राचीन परम्परा थी जिसमें बुद्धि सबल्य और भावनाओं का साथ-साथ विकास होता था। आनन्दपूर्ण समारोहों

भारत में गिन्या की स्थिति विहायबलावन

के कारण कस्यना को खुसकर खसने का अवसर मिलता था। महाकाव्या की कथाओं से लोग को ननिक गिन्या प्राप्त हुनी था। दान और धर्म के मन्व ध में मौलिक प्रवचनों में बुद्धि व मन्वार में सहायता मिलता थी। प्राचीन प्रयाए और दन्तकथाए कहावतें और कहानियां पुराण और स्मृतिया य सभी विभिन्न स्तर पर लोक गीतो लोक नाटका और लोक कलाओं के रूप में एक पाग से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होत रह ह। कला प्रेम का परम्परा हमारे यहां निरन्तर लोग तक में रमा हुई है। जसा कि कस्यनाया (घाट और हुन्दा से जमीन पर की गया चित्रकारी) और ग्रामीण स्त्रिया गारा का गयी सजावट में तथा ग्रामाण लोगों द्वारा किये जान वाले नाटका नृत्त और कस्यना में स्पष्ट है। इस परम्परा का बनाय रखने और कला व विकास का प्रामाह्न देने के लिए भारत सरकार ने असाधारण मनोनीता व लिए राष्ट्रपति का घर में पुरस्कार दन की व्यवस्था का है और गुणा कलाकारों को छात्रवतिया अथवा सहायता या उनकी कला के प्रसापत्र दन का भा व्यवस्था का है। अन्य कलाओं की प्रदर्शनिया तथा नृत्य-मण्डलिया व अभिनयों की व्यवस्था अपन देण में आ गयी है और उह विधियों में आ भजा गया है। दूसरे ग्ना से भी इस प्रकार की नृत्य-मण्डलिया और प्रदर्शनिया का भारत में आन क लिए प्रासाहन दिया गया है।

दण की सस्मृति का साहित्य वास्तुकला (आर्किटेक्चर) मूर्तिकला चित्र कला संगीत नाट्यकला (ड्रामटिक आर्ट) और नृत्य कला व अध्ययन और विकास द्वारा उन्नत करन व लिए राष्ट्रीय अकादमिया स्थापित की गयी हैं। संगीत-नाट्य अकादमी का उद्घाटन जनवरी १९५० में किया गया था। इस अध्ययन नाट्य और संगीत में अपनी प्राचीन परम्पराओं को बनाय रखने और उनकी समृद्ध करना है। साहित्य के क्षेत्र में इसी लक्ष्य को पूरा करने लिए माघ १९५४ में साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया गया। ल कला अकादमी जिसकी स्थापना अगस्त १९५४ में की गयी थी चित्र मूर्तिकला वास्तुकला तथा अन्य व्यावहारिक कलाओं व क्षेत्र में अध्ययन अनुसंधान को प्रासाहन तथा सहायता दणा।

जिन ७ वर्षों का हम विहायबलावन कर रहे हैं उनमें एक उत्तम सफलता यह थी कि भारत सरकार की देख रेख में एक पुस्तक 'प्र

पश्चिमी दान का इतिहास' (ए हिस्ट्री ऑफ फिसासफ्री ईस्टन एण्ड वेस्टन) नामक ग्रन्थ का प्रकाशन किया गया (प्रकाशक जाय एलन एण्ड सनथिन सहन)। यह पुस्तक कई दृष्टियों से अनुपम है। इसमें विस्तृत रूप से मानव जाति के दार्शनिक विकास का एक साफ उत्तराधिकार के रूप में परिमाण (सर्वे मा सर्वेक्षण) किया गया है और पूर्व तथा पश्चिम के दशन शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस परिष्करण के लिए प्रेरणा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा-मन्त्री प्रबुल कलाम आजाद से प्राप्त हुई। श्री आजाद का कथन था कि पूर्वी और पश्चिमी दान का ऐसा इतिहास अवश्य लिखा जाना चाहिये क्योंकि यूरोपियन लेखकों द्वारा लिखे गये अधिकांश दार्शनिक इतिहास इस क्षेत्र में भारत की देन की या तो विसृज्य ही उपेक्षा कर जाते हैं और या उसका केवल उल्टा-सा जिक्र करके छोड़ देते हैं और दूसरी ओर भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गयी अधिकांश पुस्तकें में केवल भारतीय दर्शन पर ही विचार किया गया होता है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग मानवीय विचारधारा के विकास की निरन्तरता को अनुभव नहीं कर पाते। इसी प्रकार भारत से बाहर रहने वाले बहुत-से लोगो का इस बात का कुछ अनुमान ही नहीं होता कि आधुनिक दर्शन के विकास में भारत की देन कितनी मूल्यवान रही है। दार्शनिक जगत में भारत के स्थान का ठीक-ठीक मूल्यांकन न केवल ज्ञान के दृष्टिकोण से आवश्यक है बल्कि इसलिये भी आवश्यक है कि आधुनिक संसार में भारतीय मर्मता और संस्कृति का भी यथोचित आदर हो सके। यह पुस्तक १९५२ में प्रकाशित हुई थी और इसका बहुत ही शानदार स्वागत हुआ है।

भारत में लोगों की रूचि दूसरे देशों के साथ सम्पर्क बढ़ाने के लिए तीव्रतर होती जा रही है और दूसरे देशों में भी भारत से सम्पर्क बढ़ाने की इच्छा बढ़ रहा है। यह बात स्वाधानता के बाद के ७ वर्षों में दी गयी छात्रवृत्तियों की संख्या या यात्रा अनुदानों से स्पष्ट है। भारत सरकार सांस्कृतिक छात्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष ३४ देशों के नागरिकों का १०० छात्रवृत्तियाँ देती है। एक और धन्य यात्रा के अन्तर्गत उन देशों के निवासियों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं जो भारतीय नागरिकों को अपने देश में छात्रवृत्तियाँ देते हैं। छात्रवृत्तियों की एक और विषय योजना हाल ही में शुरू की गयी है जिससे अनुसार भारतीय नागरिकों का अरबी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानी

फारसी तथा लैटिन और सुर्की जसा विन्गी भाषाभाषा का सीखन के लिए प्रात्याहृत किया जाता है। १९५० में एक स्वायत्त (योग्यनीमस) संगठन स्थापित किया गया जिसका नाम भारतीय साम्प्रतिक सम्प्रदाय परिषद (इंडियन कॉमिनिटी ऑफ़ इन्टरनल रिलीजियस) है। इसका ध्येय भारत तथा दूसरे देशों के मध्य एक दूसरे के सम्बन्ध में ज्ञान की वृद्धि करने और उनका भाषा साहित्य और कलाका का अध्ययन करके और विविधताओं तथा साम्प्रतिक सम्प्रदायों के मध्य घनिष्ठ सम्प्रदाय स्थापित करके पारस्परिक सम्बन्ध को पुनर्जीवित करने और सुदृढ़ बनाना है।

यूनस्को के जम्मावाता सम्प्रदाय में से एक के रूप में भारत न १९५० में एक अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की थी और १९५२ में एक स्वायत्त आयोग की स्थापना कर दी गई। इस आयोग के सन्वाधान में अनेक महत्वपूर्ण सम्मेलन हो चुके हैं। १९५९ में साम्प्रतिक आयोग के लिए देशांतर व्यवस्थापिका के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन मद्रास एगिया में से निरक्षरता और अज्ञान के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम तयार करन और दगाभा का परिमाण (मर्ब) करन के सम्बन्ध में किया गया पहला प्रयत्न है। १९५१ में एक और सम्मेलन हुआ जिसका नाम 'पूर्व तथा पश्चिम में मानव की धारणा और शिक्षा के दान शास्त्र के सम्बन्ध में मानविकी कायम' (राइट टबल कान्फ्रेंस आन द कान्फ्रेंस आफ मैन एंड दी फिनायली आफ एजुकेशन इन ईस्ट एंड वेस्ट) था। १९५३ में विभिन्न देशों के मध्य अथवा किसी देश के अन्दर ही विद्यमान अज्ञान का समाप्त करन के लिए गांधीवाणी विधिया के प्रयोग के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वायत्त भारतीय राष्ट्रीय आयोग के पहले सम्मेलन में जो जनवरी १९५४ में हुआ था एगिया तथा अजीबा के देशों से भाईभार के मान प्रतिनिधियों को निमन्त्रित किया गया था और परमाणु ऊर्जा (एनर्जिक एनर्जी) के सम्भावित उपयोगों अन्तर्राष्ट्रीय अज्ञानों का समाप्त करन के लिए गांधीवाणी विचारधारा की देन एगिया और अजीबा की सस्थाओं के विस्तृत प्रचार को आवश्यकता और विभिन्न विचार और प्रणामिया के शान्तिपूषक सह अस्तित्व के सम्बन्ध में सम्बन्धपूर्ण मिश्रितों की गई थी।

इस प्रकार स्वाधीनता के सात वष भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रयत्न और विस्तार के सात वष रहे । स्वाधीनता की प्राप्ति के फलस्वरूप लोगों के सम्मुख नय सक्षम बन और लोगों के ऊपर नयी जिम्मेदारियाँ आ पड़ी । ऊपर दिय गए संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि अनेक विद्यमान त्रुटियों को हटा दिया गया है और नव जाग्रत भारत की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के लिए आधार गिलाएँ रख दी गई हैं ।

इन वर्षों में शिक्षा पर हुए कुल व्यय को देखने से यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि अब तक कितनी सफलता प्राप्त कर ली गई है और अभी जो कुछ करने को बाय है वह कितना महान् बाय है । १९४६-४७ में शिक्षा के ऊपर किया गया कुल सरकारी व्यय २ करोड़ ५० लाख रुपये था । इसमें से केन्द्रीय बजट २ करोड़ रुपये से भी काफी कम था । हाल के तीन वर्षों १९५१-५२ १९५२-५३ और १९५३-५४ के आँकड़ों से पता चलता है कि इन वर्षों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने कुल मिलाकर अपने धन-व्यय में शिक्षा के लिए क्रमशः ७४ करोड़ १० लाख रुपये ८२ करोड़ ६ लाख रुपये और ९३ करोड़ ४० लाख रुपये की व्यवस्था की । शिक्षा के ऊपर सरकारी तथा सरकारी मजदूरी से हुए राष्ट्रीय व्यय में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई है । १९४६-४७ के वर्ष में शिक्षा पर होने वाले इस कुल व्यय की राशि ४१ करोड़ १० लाख रुपये थी । १९५२-५३ में यह राशि बढ़कर एक अरब ३५ करोड़ रुपये हो गई । १९५४-५५ के वर्ष में शिक्षा पर होने वाला यह कुल अनुमानित व्यय १ अरब ५ करोड़ रुपये था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिक्षा पर सरकार की ओर से किया जाने वाला व्यय तो बीगुन से भी अधिक बढ़ गया है परन्तु ग्राम स्तरों की ओर से होने वाले व्यय में इस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है ।

फिर भी इस विषय में डीन देन के लिए कोई कारण नहीं । अभी तक जो सफलता प्राप्त हुई है वह हमारी महत्वाकांक्षाओं से तो बहुत कम है ही वह नायद भारतीय जनता के सामर्थ्य से भी अभी बहुत कम है । यदि इसी प्रकार की दशा में विद्यमान अन्य देशों के आँकड़ों के साथ तुलना की जाय तो

इतनी छोटी अवधि में इतनी सफलता पर भारत को लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु हम यह नहीं भूल सकते कि यदि हमें देश की परम्पराओं और देश की आगाओं के अनुकूल एवं सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को चलाना है, तो हमें शिक्षा पर प्रतिवर्ष लगभग ४ अरब रुपये व्यय करने होंगे और इसके लिए हमें शिक्षा पर इस समय होने वाले व्यय को लगभग तिगुना बढ़ा देना होगा।



## अध्याय २

# बुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त और व्यवहार

शिक्षा की कोई भी राष्ट्रीय प्रणाली सदैव उस देश के राष्ट्रीय भावनों की प्रणाली का प्रतिबिम्ब होती है। बल्कि और भी ध्यान बढ़कर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का रूप व्यक्तियों और समूहों के जीवन के लक्ष्यों द्वारा नियत होता है और उसके द्वारा वह शिक्षा ही व्यक्तियों और समूहों के जीवन के भक्ष्यों को नियत करती है। यह बात केवल मानव प्राणियों पर ही लागू नहीं होती बल्कि उन जीवों पर भी लागू होती है जिन्हें हम सृष्टि के निम्न कोटि के प्राणी कहते हैं। इस प्रकार पशुओं के बच्चे बड़े पशुओं की गतिविधियों को नकल करके अपने आपको मावी जीवन के लिए तैयार करते हैं। मनुष्य के मामले में इस प्रकार की नकल या अनुकरण प्रक्रिया की एक सचेत प्रक्रिया के रूप में होती है जिससे वह व्यस्त जीवन की जिम्मेदारियाँ को पूरा कर सके। मनुष्य का यह ज्ञान ही वह वस्तु है जो मानवीय शिक्षा प्रणाली को पशु जीवन की अतिचारित ढंग से अभिगत (एक्वायर्स) आदतों और दशावस्थाओं से पृथक् करती है।

यदि किसी भी प्राणिवर्ग को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो यह आवश्यक है कि आसपास की परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के बाद उन परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति के प्रतिग्रह (रिस्पांस) में भी परिवर्तन हो जाय। जहाँ भी यही किसी प्राणिवर्ग के सदस्य उत्तम कारणों से परिवर्तन होने के बाद उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन करने में असफल रहते हैं वहीं वह प्राणिवर्ग विनाश के पथ पर चल पड़ता है। विनाश की सारी कहानियाँ अपने

आपको अपनी आसपास की परिस्थितियों के अनुकूल अधिकाधिक ढालते जानने के प्रयत्न का अभिलेख मात्र है। परन्तु मानव प्राणी अब एक ऐसी रास्ता तक पहुँच गए हैं जहाँ वे केवल अपने आसपास की परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रतिग्रह का ढालकर ही सन्तुष्ट नहीं हैं बल्कि अब वे अपने आसपास की परिस्थितियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढालने के लिए प्रयत्नशील हैं। क्योंकि मोक्ष-विचारकर नियत किए गए लक्ष्य का प्रभाव मानवीय गतिविधि के निरन्तर विस्तृत होत हुए क्षेत्र पर पड़ता है इसलिए सामाजिक लक्ष्य में कोई भी परिवर्तन करने के लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है और ऐसा परिवर्तन निरपवाहक रूप से हासिल हो रहा है।

अब समाज-सुधारका की भाँति महात्मा गांधी भी इस बात का भवनामानि जानते थे कि शिक्षा में सुधार बिना वह अपने सामाजिक लक्ष्यों तक नहीं पहुँच सकते। किसी भी समाज की उत्कृष्टता या निहृष्टता उसके मूल्यों की उत्कृष्टता या निहृष्टता पर निर्भर होता है। इसलिए यदि समाज को सुधारना अभीष्ट हो तो उसका केवल एक ही उपाय है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सुधार किया जाय। गांधी जी ने इस बात को अनुभव किया कि नागरिक के भविष्य को उसके जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में जबकि वह निर्माण की दशा में होता है सबसे अच्छी तरह ढाला जा सकता है। इसीलिए उन्होंने सर्वोच्च के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शिक्षा की धारणा तैयार की। उनके अपने शब्दों में 'इस शिक्षा के पीछे मुख्य विचार यह है कि शरीर, मन और आत्मा की सम्पूर्ण शिक्षा उस दस्तकारी द्वारा दी जाय जो बच्चे को सिखाई जा रही है। आपको बच्चे के अन्दर विद्यमान सब योग्यताओं को इस दस्तकारी की सब प्रक्रियाओं को मिखाते हुए ही विकसित करना होगा और आपके इतिहास, भूगोल और गणित के सब पाठ उस दस्तकारी से ही सम्बद्ध होंगे।'

मनुष्य मूलतः सामाजिक प्राणी है और उसे अवश्य ही समाज में रहना होता है। अनिवार्य शिक्षा में यह मानकर चलता जाता है कि बच्चा एक सहकारी समूह का सदस्य है। विद्यालय समाज का ही एक छोटा-सा नमूना है और वस्तुतः प्रत्येक बच्चा अपने आपमें एक छोटा-सा समाज है। इस प्रकार विद्यालय को एक समाज के रूप में स्थापित करने का परिणाम यह होता है कि नाग

## अध्याय २

# वुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त और व्यवहार

शिक्षा की कोई भी राष्ट्रीय प्रणाली सदैव उस देश के राष्ट्रीय आदर्शों की प्रणाली का प्रतिबिम्ब होती है। बल्कि और भी आगे बढ़कर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का रूप व्यक्तियों और समूहों के जीवन के लक्ष्यों द्वारा नियत होता है और उसके बाद वह शिक्षा ही व्यक्तियों और समूहों के जीवन के लक्ष्यों का नियत करती है। यह बात केवल मानव प्राणियों पर ही लागू नहीं होती बल्कि उन जीवा पर भी लागू होती है जिन्हें हम सृष्टि के निम्न कोटि के प्राणी कहते हैं। इस प्रकार पशुओं के बच्चे बड़े पशुओं की गतिविधियों को नकल करके अपना आपका भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं। मनुष्य के मामले में इस प्रकार की नकल या अनुकरण प्रशिक्षण की एक सचेत प्रक्रिया के रूप में होती है जिससे वह व्यक्त जीवन की जिम्मेदारियाँ का पूरा कर सके। लक्ष्य का यह ज्ञान ही वह वस्तु है जो मानवीय शिक्षा प्रणाली को पशु जीवन की अवधारित ढंग से अधिकृत (ऐकवायक) आदत और दशतामा से पृथक् करती है।

यदि किसी भी प्राणिवर्ग को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो यह आवश्यक है कि आसपास की परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के बाद उन परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति के प्रतिग्रह (रिस्पान्स) में भी परिवर्तन हो जाय। जहाँ भी कहीं किसी प्राणिवर्ग के सदस्य उत्तम प्रकार से परिवर्तन होने के बाद उनके प्रति अपनी प्रतिनिष्ठा में परिवर्तन करने में असफल रहते हैं वही वह प्राणिवर्ग विनाश के पथ पर चल पड़ता है। विनाश की सारी कहानी अपने

आपको अपनी भासपास की परिस्थितियाँ के अनुकूल अधिकाधिक ढालते जान के अविरोध प्रयत्न का अभिलेख मान है। परन्तु मानव प्राणी अब एक ऐसी दशा तक पहुँच गए हैं जहाँ वे केवल अपने भासपास की परिस्थितियों के अनुकूल अपने प्रतिग्रह को ढालकर ही मनुष्य नहीं हैं बल्कि अब वे अपने भासपास की परिस्थितियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढालने के लिए प्रयत्नशील हैं। क्योंकि सोच-विचारकर नियत किए गए सन्धियों का प्रभाव मानवीय गतिविधि के निरन्तर विस्तृत होने हुए क्षेत्र पर पड़ता है इसलिए सामाजिक लक्ष्यों में कोई भी परिवर्तन करने के लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है और ऐसा परिवर्तन निरपवाद रूप से होकर ही रहता है।

अब समाज-मुधारकों की भाँति महात्मा गांधी भी इस बात का भलीभाँति जानते थे कि शिक्षा में सुधार किया बिना वह अपने सामाजिक सन्धियों तक नहीं पहुँच सकते। किसी भी समाज की उत्कृष्टता या निम्नता उसके सन्धियों की उत्कृष्टता या निम्नता पर निर्भर होती है। इसलिए यदि समाज को सुधारना अभीष्ट हो तो उसका केवल एक ही उपाय है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सुधार किया जाय। गांधी जी ने इस बात को अनुभव किया कि नागरिक के भविष्य को उसके जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में जबकि वह निमाण की दशा में होता है सबसे अच्छी तरह ढाला जा सकता है। इसीलिए उन्होंने सर्वोदय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी शिक्षा की धारणा तैयार की। उनके अपने शब्दों में इस शिक्षा के पीछे मुख्य विचार यह है कि गरीब मन और आत्मा की सम्पूर्ण शिक्षा उस दस्तकारी द्वारा दी जाय जो बच्चे को सिखाई जा रही है। आपकी बच्चे के अन्दर विद्यमान सब योग्यताओं को इस दस्तकारी की मदद प्रक्रियाओं को सिखाते हुए ही विकसित करना होगा और आपके इतिहास भूगोल और गणित के सब पाठ उस दस्तकारी से ही सम्बद्ध होंगे।

मनुष्य मूलतः सामाजिक प्राणी है और उसे अवश्य ही समाज में रहना होता है। बुनियादी शिक्षा में यह मानकर चला जाना है कि बच्चा एक सहकारी समूह का सन्ध्या है। विद्यालय समाज का ही एक छोटा-सा नमूना है और वस्तुतः प्रत्येक बच्चा अपने आपमें एक छोटा-सा समाज है। इस प्रकार विद्यालय को एक समाज के रूप में स्वीकार कर लेने का परिणाम यह होता है कि नागरिक

रिक्तता के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त वातावरण तैयार हो जाता है। बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वे अपने को समाज का एक सदस्य समझें और इस प्रकार एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करें। दूसरों के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य भी उसने ही महत्वपूर्ण है जितने उसके अपने अधिकार। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा भाषाश्रम की व्यक्तिगत स्वाधीनता के नाम पर पारिवारिक और सामाजिक बंधन का सिधिल करते जाने की प्रवृत्ति को सुधारने का प्रयत्न करती है। अधिकारों पर आवश्यकता से अधिक बल देने का फल यह होता है कि मानव व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। इस प्रकार की विकृति के परिणाम कुसाम्यस्थापित या कुसमजित (मैल ऐडजस्टिड) व्यक्तियों और विभक्त समाजों में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।

गांधी जी ने इस बात को तीव्रता से अनुभव किया कि शिक्षा का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह व्यक्ति का नये सिरे से समेकन (इंटीग्रेशन) करे और उस एक सजीव समाज के सन्ध्य के रूप में परिपुष्ट करे। सहकारी समूह के सदस्य के रूप में बालक की सभी गतिविधियाँ सामाजिक ढंग की होनी चाहियें। बुनियादी शिक्षा इस तथ्य को मानकर ही चलती है और उनका लक्ष्य यह होता है कि इस प्रकार की मान्यता बड़े होत हुए बालकों की मानसिक रचना का ही एक भाग बन जाय। न केवल सब सामाजिक गतिविधियों को समूहों के रूप में आयोजित किया जाता है बल्कि उनको इस रूप में भी आयोजित किया जाता है कि उनकी तात्कालिक सामाजिक उपयोगिता स्पष्ट हो। इनका उद्देश्य यह होता है कि बालक में बिल्कुल प्रारम्भ से ही सहकारिता की भावना और उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाय।

इस सम्बन्ध में सभी शिक्षा-मनोवैज्ञानिक एवम्मत हैं कि अध्यापक द्वारा दी गई शिक्षा को निष्क्रिय रहकर ग्रहण करने की प्रक्रिया की प्रेरणा किसी भी काम में हिस्सा बटान की प्रक्रिया के द्वारा बालक बातों को कहीं अधिक जल्दी सीख पाते हैं। बालक सब चीजों को करक देवना चाहता है। स्वभाव से ही वह क्रियाशील होता है और उसकी चञ्चलता उसकी अत्यधिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्र होती है। उसे बिना हिल जुड़े बहुत लम्बे समय तक धुपचाप बिठाये रखना जसा कि पुराने परम्परा के विद्यालयों में प्रायः किया जाता है उसने ऊपर प्रभावकार करना है। जब उस समय के सिवाय जबकि वह किसी

बात को बड़ी समझता स सुन रहा हो, उदाहरण के लिए किसी परिणाम का कहानी या किसी माहस-यात्रा के वणन को सुन रहा हो वह हमारा जान करने रहता या खुद कुछ न कुछ करते रहना प्रसन्न करता है।

यदि ठीक-ठीक देखा जाय तो यह कोई नई बात नहीं है। स्पष्ट रूप में गतिविधि के सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत न किये जाने पर भी वस्तुतः यह गतिविधि न जाने कब से बालक की शिक्षा का एक भाग बनो रही है। तथैवी माना भी बहुत जल्दा यह जान आती है कि अपने बच्चा की समझ के एक मात्र तरीका यही है कि उन्हें कुछ न कुछ काम करने का दिया जाय क्योंकि इसमें एक ओर तो उनकी निपुणता का विकास होता है और दूसरी ओर वे प्रसन्न बन रहते हैं। इस मातृ-बुद्धि का औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश मिला है काफी विलम्ब में हुआ है परन्तु अब यह सिद्धान्त शिक्षा के क्षेत्र में पहुँच चुका है। कम से कम गत दशकों के उत्तरार्ध में यूरोप और अमेरिका जगत् में शिक्षा का क्षेत्र अधिकारिक गतिविधि को बनाने का ही प्रयत्न रही है। इन में लगभग ५० वर्ष पूर्व श्री रबीन्द्रनाथ ठाकुर ने बालक की स्वाधीनता और गतिविधि पर जोर देने हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपना महान् प्रयोग प्रारम्भ किया। यदि यह समझा जाय कि बाल्यापी शिक्षा का सार गतिविधि पर जोर देना है तो स्वीकार करना होगा कि इसके आधारभूत सिद्धान्त भारत के लिए भी नये नहीं हैं।

पिछला विद्यालयी संस्था में गतिविधि की धारणा में बुनियादी शिक्षा में एक और नया तत्व मिला दिया है। बुनियादी शिक्षा में बालक के प्रशिक्षण के लिए जा भी गतिविधि चुना जाय वह सादे-सम सृजनात्मक और सामाजिक दृष्टि में उपयोगी गतिविधि होना चाहिये। जब कोई भी अपने बच्चे को किसी गतिविधि में लगाती है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका भी कोई न कोई उद्देश्य होता है। परन्तु उस समय यह धारणा नहीं होती कि बच्चे को भी उस उद्देश्य का ज्ञान हो। इसी प्रकार बच्चे का गतिविधि में सृजनात्मक या उपयोगी भी नहीं होना। इसी तरह यूरोप और अमेरिका के विद्यालयों में जिन गतिविधियों पर जोर दिया जाता है उनमें यह ध्यान नहीं रखा जाता कि उनका कोई सामाजिक उद्देश्य भी है या नहीं। बच्चे की गतिविधि के सम्बन्ध में सामाजिक उपयोगिता के इस तत्व की अपेक्षा

युनियादी शिक्षा की गतिविधि पर केन्द्रित शिक्षा के अन्य प्रकारों से पृथक् करती है।

सामाजिक उपयोगिता और उद्देश्य पर यह ध्यान केवल समांगता या एकस्मात् नहीं दे दिया गया है। वस्तुओं का उत्पादन मुसगठित मानव जीवन का मेरुदण्ड है। क्योंकि कोई भी समाज अपने सदस्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने के सामर्थ्य द्वारा ही जीवित रह पाता है। वस्तुओं के उत्पादन का स्तर भव लोगों के सहकारिता पूरा प्रयत्न द्वारा ही पर्याप्त बनाए रखा जा सकता है। युनियादी शिक्षा में बालक को अपने शिक्षा-काल के प्रारम्भ से ही समाज का एक मन्स्य मान लिया जाता है और इसलिए सामाजिक दृष्टि से उपयोगी गतिविधि पर जोर दिया जाता है।

जहाँ भारत में और विदेशों में शिक्षण-क्षेत्र के विचारक गतिविधि और स्वतन्त्रता के महत्त्व पर अधिकाधिक ध्यान दे रहे थे वहाँ भारत में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में अधिकाधिक ध्यान पुस्तकों पर दिया जा रहा था। बच्चा के मामले में भी स्थिति यह थी कि बड़ों की आज्ञाओं और चरित्र के विकास की अपेक्षा स्मृति का व्यायाम—(तोता रटने) अधिक कराया जाता था। पुस्तकों के ऊपर आवश्यकता से अधिक ध्यान देने का परिणाम यह हुआ कि शिक्षा भारतीय जीवन की वास्तविकताओं से दूर हटने लगी। प्रायः शिक्षा पाकर बालक अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से दूर हटता चला जाता था और उसके मन में शारीरिक व्यय के प्रति यदि घणा नहीं तो अरुचि अवश्य उत्पन्न हो जाती थी। इसका परिणाम यह हुआ है कि पुरानी परम्परागत पद्धति में शिक्षा पाया हुआ बालक एक खास प्रकार की नीचरी पर ही निभर रहने लगा है। यदि उसे उसी एक विशिष्ट दिशा में अवसर प्राप्त न हो सके तो वह प्रायः असहाय और निराश हो जाता है। इसके फलस्वरूप भारत में अशिक्षित व्यक्ति में आत्मविश्वास और पहल करने की शक्ति का प्रायः अभाव होता है और जब उसके सामने नई और परिवर्तनशील स्थितियाँ आती हैं तो वह निराश होकर छटपटान-सा समता है।

जीवन के लिए तयारी कराने में अग्रफल रहने के अतिरिक्त पुरानी शिक्षा प्रणाली विपुल शिक्षणात्मक दृष्टिकोण से भी सन्तोषजनक नहीं है। व्यक्ति के सन्तुलित विकास करना अपना उद्देश्य मानने की बजाय यह बुद्धि पर

अनुचित जोर डालती है। इसमें सकल और कल्पना का उपयोग कर दा जानी है और बढि क भी अवन पहलुओं में से तक और निगम का अपसा स्मरण गति पर वही अधिक जोर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बुद्धि भी पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाती। बालक को जानकारी का प्राप्त हो जानी है परन्तु वह एक व्यक्त मानव प्राणी के रूप में विकसित नहीं हो पाता।

गांधी जी के मन में इस प्रचलित गिना प्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई हालांकि वह स्वयं भी इसी गिना प्रणाली की उपज थे। उनका विश्वास प्रारम्भ से इसलिए हुआ था कि यह प्रणाली गिना की दृष्टि से अपर्याप्त थी परन्तु धीरे धीरे चलकर वह इसलिए और भी प्रबल हो गया क्योंकि जिस दूसरी वैकल्पिक प्रणाली को विकसित करने में उन्होंने सहायता दी थी उसके आर्थिक वा सामाजिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए यहाँ सबसे पहले कुछ उन महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख कर देना अच्छा रहेगा जिसकी दृष्टि से बुनियादी गिना हाल के दिनों में भारत में प्रचलित गिना के प्रकार में मिल्न है। पुरानी परम्परागत प्रणाली की एक मूलभूत त्रुटि यह है कि उसमें माध्यमिक और उच्चतर गिना को एक सुझावित और सर्वांगसम्पूर्ण प्रारम्भिक गिना प्रणाली पर आधारित करने के बजाय माध्यमिक और प्राथमिक गिना को उच्चतर गिना के लिए सहायक और उसकी तुलना में गौण बना दिया गया था। प्रारम्भिक और माध्यमिक गिना अपने आप में स्वयं न होकर बस उच्चतर गिना प्राप्त करने के लिए साधन मात्र थी। एक दृष्टि से गायब यह बात धनिदाय भी थी। पिछले केवल १०० वर्षों से ही यह स्थिति आई है कि गायब यह स्वीकार कर लिया है कि सावजनीन (बुनियादी) गिना प्रणाली की व्यवस्था करना भी उसकी एक जिम्मेदारी है। जब राष्ट्रीय सरकार का यह हाल था तो एक विदेशी सरकार ने यह धाना करना कठिन था कि वह अपना प्रयास के लिए गिना की इस प्रकार का सुविधाएँ प्रदान करेंगी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में पश्चिमी गिना मध्य रूप में उपयोगिता की दृष्टि से प्रारम्भ की थी। यह गिना इतनी पचाप सख्या में भारतीयों को अग्रणी मिलान का साधन थी कि जिससे गैर का प्रवासन करने का काम आसान हो जाय। यह ठीक है कुछ ईमाई पादरियों और



जायत भारतीय नेताओं ने इससे भिन्न उद्देश्या से शिक्षा का प्रचार किया था। स्वयं सरकार में भी मैकॉन्टे जिस व्यक्ति भी यजिनका यह मत था कि पश्चिमी विज्ञान और राजनीतिक विचारों के सम्पर्क में भ्रान से भारतवासियों का लाभ होगा। फिर भी शिक्षा के ऊपर मुख्य रूप से जोर उपयोगिता की दृष्टि में ही रहा। इसका फल यह हुआ कि प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा मुख्य रूप से छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार करने की नींव की मजिदें भर ही समझी जाने लगी। इन सब परिस्थितियों में यह भी अनिवार्य ही था कि दहाती क्षत्रों को जहाँ भारत की अधिकांश जनता निवास करती है आवश्यकताओं को बहुत अधिक उपेक्षा की गई। बनियादी शिक्षा इन दोनों ही दृष्टियों में देश को सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें दहाती आवश्यकताओं पर कहीं अधिक जोर दिया गया है और बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य यह है कि वह भीसत नागरिक के लिए शिक्षा की एक अपन भाषा में पूरा मजिद बन सके।

अग्रजों ने जो शिक्षा प्रणाली जारी की थी उसकी एक और त्रुटि यह थी कि यह मूलतः व्यक्तिवादी (इंडिविजुअलिस्टिक) प्रणाली थी। लगभग एक शताब्दी तक इस शिक्षा प्रणाली में व्यक्तियों और समाज के पारस्परिक सहयोग के बजाय प्रतियोगिता पर धन दिया गया। यह कुछ छात्रों का बात नहीं थी क्योंकि उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटन की पथदर्शक शिक्षण की विचारधारा की भाँति यह भी विकासवाद की सिद्धान्त को मूल रूप में समझने पर आधारित थी। यद्यपि ससार में जीवित रहने के लिए सहयोग का भाँ कम से कम उतना ही महत्व है कि त्रितना कि प्रतियोगिता का। फिर भाँ उम समय लोगों की यह प्रवृत्ति थी कि विकासवाद को इस रूप में प्रस्तुत किया जाय कि यह अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए व्यक्तिवाद और समूहों में हानि हुए सघर्ष का परिणाम हो। उस समय की शिक्षा प्रणाली में भी यह प्रवृत्ति प्रतिक्रित हुई और इसका फलस्वरूप व्यक्ति को सामान्य हित की उपेक्षा करके धीरे-धीरे भाँ भाँ बढ़ जाने की भावना को प्रोत्साहन मिला। इस विचारधारा के समर्थकों का विश्वास था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य की धार ही बढ़ता चला जाय तो उसमें किसी न किमा प्रकार सामान्य हित की सिद्धि भाँ हाँगी हो।

बनियादी शिक्षा इस समय प्रचलित शिक्षा से इस दृष्टि से भी भिन्न है कि इसमें किसी स्पष्ट दोस पढ़ने वाला काम को पूरा करने और उम प्राप्त होने

बाल भ्रान्त पर कहीं अधिक जोर दिया जाता है। परम्परागत शिक्षा में विषय रूप से जब कि वह निष्कम्भ अभ्यासका द्वारा दिलवाई जा रहा हो सारी शिक्षा केवल एक बौद्धिक कवायद-मी बनती चली जाती है। इस शिक्षा के विषय अध्ययन (एन्मट्रन्) होते हैं। इसीलिए वे प्रायः समझ में नहीं आते और इस कारण विद्यार्थियों का वे बहुत ही नीरस और अरुचिकर लगते हैं। विद्यार्थियों का जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे वे समझ नहीं पाते। वे उन मशीन की तरह बसल पाठ करने लगते हैं। इस प्रकार जानकारी निर्जीव बस्तु की भाँति पड़ी रह जाती है और वह उनके मज्जीब विचार के तान-बान का हिस्सा नहीं बन पाती। क्योंकि बालक का जो शिक्षा मिल रही होती है उसके सत्य को वह नहीं देख पाता इसलिए वह बिल्कुल निष्क्रिय और बहुत बार तो अति-छक्का पान बना रहता है जो शिक्षा का ग्रहण नहीं कर रहा होता बल्कि उसने सामने सिर झुकाकर हार मान रहा होता है। इससे विपरीत किसी दस्तकारी को केन्द्र बनाकर ही जान वाला शिक्षा में बालक का अपने परिधम का परिणाम तुरन्त अनुभव हो जाता है। उस दस्तकारी द्वारा तयार की गई बस्तु उसके लिए सफलता का साकार प्रतीक होती है और इससे उसके मन में सफलता की अनुभूति जाग उठती है। बालक और बालिका को मालूम है कि हम जीवन में अपने आप स्वाकार किये हुए कार्य का सफलतापूर्वक समाप्त कर डालने में बड़बड़ और कोई भ्रान्त नहीं है। मगर ही यह भ्रान्त बालिकों और बालिकों की तुलना में कुछ हज़ार किम्ब का हा फिर भी जब बच्चे अपने धर्म की उपज को देखते हैं तो उनके मन में भी भ्रान्त की दम ही अनुभूति होती है।

शारीरिक परिधम पर जोर देकर बालिका शिक्षा उस एक और बालक का तान में महापता दे रही है जिसने बहुत लम्बे समय में भारतीय समाज की विमर्श किया हुआ है। प्रारम्भ में जाति या वर्ण-व्यवस्था धर्म के विभाजन की आवश्यकता के कारण स्थापित हुई थी। यह भी माल्य है कि एक समय यह जाति या वर्ण-व्यवस्था कम पर आधारित थी और इसमें काफी सफल थी। परन्तु यह सफल बहुत दीर्घ हो जाती रहा और इस प्रणाली में बढ़ाव भ्रान्त जान के साथ-साथ बौद्धिक और शारीरिक धर्म में बहुत बड़ा अन्तर हो गया। समय बीतने पर शारीरिक धर्म का सामाजिक दृष्टि से हीन समझा जान

लगा। ब्रिटिश लोग ने सम्पर्क का प्रभाव भी धारीरिक श्रम के प्रति घृणा को समाप्त करने में सहायक नहीं हुआ। अंग्रेज लोग धर्मों की ऊँच-नीच में विश्वास रखते थे और भारतीय जाति की ऊँच नीच में। इन दोनों के मिल जान के परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें समाज के भलग भलग स्तरों के बीच में विद्यमान खाई पहले की अपेक्षा भी कहीं अधिक चौड़ी और गहरी हो गई। साथ ही भाषा भाषिक और राजनीतिक दशाभा के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी जिसमें हम प्रकार की सामाजिक विषमता टिक नहीं सकती थी। फिर भी तत्कालीन बौद्धिक वर्ग के साथ जुड़ा हुआ प्रतिष्ठा का भाव बना ही हुआ था। ऐसी दशा में यह अनिवार्य था कि भारत में विद्यमान शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से विज्ञानी (शास्त्रीय तकटमिक) और साहित्यिक ही होती। शिक्षा का धारीरिक श्रम और धारीरिक गतिविधियों के साथ घनिष्ठ सह-सम्बन्ध (कोरिलेशन) स्थापित करके बनियादी शिक्षा धारीरिक श्रम के कार्य के प्रति घृणा को समाप्त करने में सहायता दे रही है और बालकों के मन में श्रम व शारीरिक श्रमभाव करने का भाव जगा रही है।

सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य पर जोर देने का ध्यान दिनाम्नो में भी अच्छा परिणाम हुआ है। बालक उन स्तंभकारियों में जगे रहते हैं जिनके फलस्वरूप भौतिक वस्तुएं पैदा होती हैं। इस प्रकार उन्हें अपने परिश्रम का परिणाम लगभग तत्काल ही देखने लगता है। अपनी स्पष्ट सफलता को देख कर उन्हें सतोष होता है और इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। यह सर्वविदित है कि आत्मविश्वास बढ़ने से योग्यता में भी वृद्धि हो जाती है। इसके साथ ही अपने साथियों के साथ सहयोगपूर्वक मिलकर काम करने में बालकों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो जाती है। उत्तरदायित्व के फलस्वरूप अनुशासन का भाव उत्पन्न होता है और यह अनुशासन ऊपर से थोपा हुआ अनुशासन नहीं होता बल्कि अपने काम को पूरा करने के प्रयत्न में बालका द्वारा स्वयं विकसित किया हुआ अनुशासन होता है। इसलिए बनियादी विद्यालयों के बालकों में दीख पड़ने वाला धन साधारण विद्यालयों के बालकों की अपेक्षा अधिक आत्मविश्वास और अनुशासन का भाव आत्मिक या सायागिक नहीं है। जहाँ तक महज (इन्ट) वर्गों का सम्बन्ध है यह मानने के लिए कोई कारण नहीं कि इन में असम-भलग प्रकार के विद्यालयों के

मानकों में कोई भी अन्तर क्या होना चाहिए। व सभी मानक उस एक ही समाज से आए होते ह और सम्भव उन सबकी सामाजिक पृष्ठभूमि एक-सी ही होती है। अन्तर केवल विद्यालय के वातावरण और शिक्षण की पद्धति में है। पुराने ढंग के विद्यालय में बालक ऊपर से चापे गए अनुशासन के अधीन होते ह जबकि बुनियादी विद्यालय में उन्हें स्वयं द्वारा नियत सीमाओं के अन्दर रहते हुए गतिविधि की स्वाधीनता रहती है। दोनों प्रकार के विद्यालयों में बालकों में पाए जाने वाले स्वभाव के अन्तर की व्याख्या केवल इस तथ्य द्वारा ही की जा सकती है कि पुराने परम्परागत विद्यालयों में बालक सारे समय आश्रित ही आश्रित कर रह होते ह समाज को कुछ प्रदान नहीं कर रह होते जबकि बुनियादी विद्यालयों में बालक कुछ न कुछ वस्तु उत्पन्न कर रहे होते ह और उन्हें इस तथ्य का ज्ञान भी होता है।

परम्परागत शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध किये जाने वाले आश्रितों में सबसे मजबूत आशय यह है कि इस प्रकार के विद्यालयों में पाठ्य विषय भी ही बिना किसी योजना के चुन लिए जाते ह और प्रायः उन विषयों में परस्पर कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं होता जो समझ में आ सके। इस प्रकार यह सम्भव है कि कोई बालक इतिहास, गणित-विज्ञान और किसी प्राचीन भाषा का अध्ययन कर रहा हो और न तो उस ही में पता हो और न उसके शिक्षक को ही कि ये भाग विषय उसके अध्ययन के लिए क्या चुन गए ह। बुनियादी गिम्ना में इस श्रुति को सुधारन का बल किया गया है और विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में परस्पर सम्बन्ध (आर्गेनिक) सह-सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है और यह सम्बन्ध किसी एक चुनी हुई दस्तकारी के सम्बन्ध में उन विषयों का लागू करके स्पष्ट किया जाता है। एक घण्टा में यह सह-सम्बन्ध की धारणा भी नहीं करी है। मिल्कुल विभिन्न विषयों द्वारा भाषा के पद-शोषक गिम्ना-साम्प्रदाय न भी मानसिक जागृता की एकता का पुष्ट करने के लिए पाठ्य विषयों के सम्बन्धों की आवश्यकता पर जोर दिया है। व्यक्ति का जीवन विभिन्न दृष्टियों और आवश्यकताओं के मध्य निरन्तर होता हुआ साम्य-स्थापन (एन्जस् मेट) भर है। ऐसा साम्य-स्थापन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि विभिन्न गतिविधियों का परस्पर सह-सम्बन्ध स्थापित न कर दिया जाय। यह आवश्यक है कि बालक को अपने प्रारम्भिक ज्ञान से ही अपनी रुचियों को सह-सम्बन्धित

करना और उनका समन्वय करना भिन्नाया जाय। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियाँ में सह-सम्बन्ध स्थापित करने पर जोर देकर शिक्षण सम्बन्धी एक स्वस्थ सिद्धांत का पालन कर रही होता है।

परन्तु यहाँ एक शतावली दे देना उचित होगा। जहाँ बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत—किसी दस्तकारी के माध्यम से बौद्धिक विषयों का प्रामाण्य की परिस्थितियों के साथ सह-सम्बन्ध—के समर्थन में सब कुछ कहा जा सकता है वहाँ यह भी ठीक है कि हमें इस सिद्धांत को इतनी दूर तक नहीं घसीटना चाहिये कि यह विस्मय से बेहूदा प्रतीत हो न सके। किसी भी क्षेत्र में प्रागे बढ़ने वाले पथ-दर्शक लोग बहुत बार अपने उत्साह के कारण सही रास्ते से भटक जाते हैं। बुनियादी शिक्षा के ऐसे भी अनेक समर्थक हुए हैं जिनका यह दावा है कि मामूली गिनती से लेकर 'परमोद्भावनिक' तक सब विषय किसी एक ही दस्तकारी के माध्यम से पढ़ाए जा सकते हैं। स्पष्ट रूप से ही इस प्रकार के दावे बहुत प्रतिरजित हैं और थोड़ा-सा विचार करने से ही यह स्पष्ट हो जायगा कि सह-सम्बन्ध का भी कुछ अपनी सीमाएँ हैं। बीजगणित—विद्यालय के स्तर का एक विषय यदि उदाहरण के लिए चना जाय—बिना अस्वाभाविक और सीख-तान के उपायों का अवलम्बन किए किसी भी दस्तकारी के माध्यम से नहीं सिखाया जा सकता। जहाँ तक उच्चतर स्तर पर सैद्धान्तिक विषयों के अध्ययन का प्रश्न है चाहे वह भौतिकी शास्त्र हो या अध्यात्म शास्त्र चाहे वह रसायन शास्त्र हो या एक शास्त्र सह-सम्बन्ध की पद्धति से पढ़ाए जा पाते और भी कठिन है। यह ठीक है कि हैगल ने कहा है कि संसार में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से सम्बद्ध है परन्तु यह कहना कि जब भी कोई एक व्यक्ति छीकता है तो उसके साथ ही सृष्टि के परम तत्व (एम्मास्यूट) में भी कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है हैगल के सिद्धांत की हँसी उठाना ही है। यदि भावधान न रहा जाय तो बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत पर भी ऐसी ही बहूदली की सीमा तक घसीटा जा सकता है।

सह-सम्बन्ध के सिद्धांत का उस समाज से भी सम्बन्ध होना चाहिये जिसकी सेवा करने के लिए विद्यालय खोला गया है। अर्थात् विद्यालय का सम्पूर्ण समाज के जीवन को प्रतिबिम्बित करना है इसलिए विद्यालय में ऐसी दम्तकारी चुनी जानी चाहिये जो स्थानीय परिवेश (ऐनवायरनमेंट) के साथ सम्बद्ध हो। चाहे यह कहना पिछलेपण ही जान पड़े फिर भी इस बात पर जोर देना आवश्यक

है कि यदि कोई ऐसी दस्तकारी बुनियादी शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में चुना जाय जिसका उस प्रदेश के साथ सम्बन्ध न हो तो बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य शिक्षणामक सामं जाता रहता है। बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य यह है कि किसी परिचित दस्तकारी के साथ जुड़ी हुई गतिविधियाँ का वाक्यात्मक और धीरे-धीरे बालक को द्वारा बालक की साम्यताओं का परितुष्ट किया जाय। यदि दस्तकारी परिचित नहीं है तो वह बालक की ऊर्जा और रुचि पर एक अनुचित बोझ बन देगी। इसलिए विद्यालय के लिए चुनी जान वाली दस्तकारी ऐसी होनी चाहिये जिसका अपने परिवार के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध हो। यदि ऐसा न हो तो दस्तकारी पर दिया जान वाला जोर बालक के व्यक्तित्व का समकल (इंटीग्रेशन) करने में सहायक हान के बजाय समक व्यक्तित्व में एक गहरे स्तर पर टालने का कारण बन सकता है।

किसी परिचित दस्तकारी का चुनाव एक और दृष्टि में भी बहुत सम्बन्धी है। सभी स्तरों में छात्रों में मान बाली पीढ़ियों में मानसिक और साम्यात्मिक दृष्टि से अपने से पहली पीढ़ियों से दूर हान जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। उपवासकारों और नाशकारों ने अनेक बार पिताओं और पुत्रों के मध्य हान वाले संघर्ष का बड़ा सर्वांग चित्रण किया है। एक देश में जहाँ पुराना पाठ्य निरक्षर है और नई जवान पीढ़ी मात्र इस दूर और संघर्ष की भाँसा और भी अधिक है। यह संघर्ष तब और भी अधिक उग्र बन जाता है जबकि देश सामुनिकाकरण की तात्प्रक्रिया में अगुजर रहा हो। ऐसा देश में सम्भव है कि बालकों के मन में अपने आपको अपने बड़ा से ऊँचा सम्मान की प्रवृत्ति जाग उठे। दूसरी ओर बड़ा लोग में तो एक दामोदरी प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण एक ओर तो वे नये सौदरसौकों का सन्तुष्टि की दृष्टि से देखने लगे और दूसरी ओर उन वस्तुओं की प्रशंसा और भाँसा की दृष्टि से देखने लगे जिन्हें वे समझ नहीं पाते। यह तो सम्भव है कि वे साम्यता से बहुत अधिक भाँगाण बाँध बैठें। बुनियादी शिक्षा की आधारभूत धारणा शिक्षण का प्रक्रिया का किसी परिचित दस्तकारी पर आधारित करने द्वारा यह संकट काफ़ी सीमा तक कम हो सकता है और यह विश्वास किया जा सकता है कि पिताओं और पुत्रों के बीच का खाई बहुत बरी नहीं हो पाएगी।

बुनियादी विद्यालय के लिए किसी दस्तकारी के चुनाव के प्रश्न पर कुछ

अध्यापक और छात्र यह देखें कि उनके परिश्रम का फल फिर उहीका प्राप्त हो रहा है तो उन्हें नया उत्साह और प्रेरणा प्राप्त होगी और उन्हें एक ऐसी अनुभूति होगी कि जमे उठेन कोई अड़थका काय पूरा कर लिया है। यदि छात्रों और अध्यापकों की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी कुछ उपज बची रह जाय तो उसका उपयोग विद्यालय में हानि वाले कुछ घमघमाईय खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

बुनियादी शिक्षा के अथर्गत को बड़ी सावधानी के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिये। केवल इसके इस दावे की परीक्षा के लिए नहीं कि इस प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा सुगम बनाई जा सकती है बल्कि इसमें भी अधिक दृष्टि में कि बुनियादी शिक्षा में शिक्षण का महत्व कम न हान पाय। यदि उत्पादन पर आवश्यकता में अधिक बन् दिया जाय तो उसमें यह अंतरा रहेगा ही कि विद्यालय एक ऐसा कारखाना न बन जाय जिसमें बालकों के श्रम का शोषण किया जा रहा हो। यह अंतरा इस तथ्य के कारण और भी अधिक बढ़ जाता है कि बुनियादी शिक्षा में पुराने ढंग के विद्यालयों की संख्या गिराव के तिर पर अधिक बौद्धिक रहता है। हम पहले सचेत कर चुके हैं कि बुनियादी शिक्षा में विद्यालय के काम में बिबिधता होने के कारण और पढ़न सिखन की एकरमता को बीच-बीच में उत्पादनगोत्र श्रम द्वारा तोड़ देने के कारण विद्यार्थी का भार बहुत हल्का हो जाता है। परन्तु छात्रों को एक निर्धारित पाठ्यक्रम में छटकाना दे देन का परिणाम यह होता है कि अध्यापक व तिर विद्यालय की सब गति विधियाँ का समन्वय करन का बोझ आ पड़ता है। इसके फलस्वरूप उसके ऊपर निरन्तर एक बोझ बना रहता है क्योंकि उस मग उन समस्याओं का समाधान ढोजते रहना होता है जो इस पाठ्यक्रम में उत्पन्न हू। पुराने ढंग के अध्यापकों को यह सुविधा थी कि वे बड़ी गत से पढ़ते बले जाते थे परन्तु बुनियादी विद्यालयों में ऐसा कोई सरल उपाय नहीं है। जब तक बुनियादी शिक्षा का काय तपस्वी शिक्षक सोच कर रहे हैं तब तक इस बात का कुछ बड़ा सबट नहीं है। परन्तु जब इस प्रणाली का विस्तार होगा और प्रारम्भिक सेवा भावना वाले अध्यापकों का स्थान पेशेवर आदमी ले सेंगे जिनमें से सबस यह धाया नहीं को जा सकती कि वे अपने काय के सिध अपना जीवन समर्पण कर रह होंगे, उस समय इस बात का वास्तविक संकेत उपस्थित होगा कि अध्यापक

सोच बुनियादी शिक्षा के केवल उन पहलुओं पर ही ध्यान दें जिनमें सफलता या असफलता का आभासी भेद नापा जा सके। क्योंकि शिक्षा के रचनात्मक पहलू अभ्यस्त होत हैं और उनका नाप नहीं जा सकता। इसलिए यह बड़ा स्पष्ट स्रोत है कि बुनियादी शिक्षा का प्रसार बढ़ान पर वही अध्यापक लोग अपनी सफलता का एकमात्र नाप उत्पादन बढ़ान का ही न समझ बैठें। यह पता करना बिल्कुल सरल है कि किसी विद्यालय में निर्धारित परिमाण में वस्तुएं तैयार हुई हैं या नहीं। किन्तु यह जांच पाना उतना सरल नहीं कि किसी विद्यालय में छात्रों का चरित्र परिपुष्ट हुआ है या नहीं और उन्हें जीवन के मूल्यों का उचित ज्ञान हो गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः यह बात स्पष्ट है कि पहले दो या तीन वर्षों में बालका द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का आर्थिक मूल्य बहुत थोड़ा ही हो सकता है। ज्यों-ज्यों बालक बड़े हुए और अभिव्यक्ति निपुणता प्राप्त करते जाएंगे त्यों-त्यों उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की किस्म भी सुधरती जायगी। प्रभाव (स्टैण्डर्ड) ऊँचा बनाए रखने का आग्रह भी शिक्षा का एक अंग होना चाहिये। यदि बच्चों का प्रशिक्षण ठीक ढंग से किया गया हो और वे अपना काम निपुणता सावधानी और ईमानदारी के साथ कर लें तो कोई कारण नहीं कि उनकी तैयार की हुई वस्तुएँ क्यों अत्यंतोपजनक या घटिया हों। यदि कोई काम करना ही है तो यह ठीक ढंग से किया जाना चाहिये। अधिक-करेपन या निपुणता के अभाव को कोई भला गुण नहीं माना जा सकता। इसलिए अच्छी किस्म की चीजों का उत्पादन उन प्रशिक्षण का ही एक अंग है जो बालका का विद्यालय में प्राप्त होना चाहिये।

फिर भी इस बात पर जितना जोर दिया जाय वह कम है कि विद्यालय अभिप्रेत वे मागरिणों के प्रशिक्षण का केन्द्र है तात्कालिक उपभोग के लिए वस्तुएँ तैयार करने का कारखाना नहीं है। जिस भी दस्तकारी को केन्द्र बनाकर शिक्षा दी जा रही हो उनके द्वारा बालक की योग्यताएँ निखरनी चाहियें और उन उस दस्तकारी के अर्थ विषयों के साथ सह-सम्बन्ध द्वारा समाज के सार्वजनिक स्वरूप का ज्ञान हो जाना चाहिये। यह ठीक है कि बालका द्वारा तैयार की गई वस्तुओं में वे बहुत-सी विषय योग्य होनी चाहियें और वे होंगी भी परन्तु इस बात का प्रयत्न नहीं होना चाहिये कि उनका काम का एकमात्र कमोटी उन



का विसाई-सर्वा काम से कम इतनी राशि अध्यापक और छात्रों द्वारा किये जाने वाले काम से अवश्य निबल सकती चाहिये। यदि इतना भी न निकल सके तो यह अध्यापक की योग्यता में कमी का सूचक समझा जाय। नसी प्रकार एक ऊपरी सीमा भी नियत कर दी जानी चाहिये और यह सीमा विद्यालय पर होने वाले कुल व्यय का २० से लेकर ४० प्रतिशत तक होनी चाहिये। यदि इस सीमा से भी अधिक भाग विद्यालय में तयार वस्तुओं से हो रही हो तो स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि विद्यालय में दस्तकारी के शिक्षणात्मक पहलु की अपेक्षा उत्पादन के पहलु पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय बोर्ड (सप्टिम एडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन) ने इस समस्या पर काफी विस्तार से विचार किया है। बोर्ड ने एस नोगो के भी विचार सुने हैं जिन्होंने प्रारम्भ में यहाँ तक दावा किया कि विद्यालय पूषणता आत्मनिर्भर होना चाहिये और वह सबकुछ आत्मनिर्भर हो सकता है। परन्तु विचार विमर्श के बाद उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि यदि सब मामलों में बालक आत्मनिर्भर होना सीखे जाय तो इतना ही काफी समझा जाना चाहिये। भावधानी के साथ विचार करने के बाद बोर्ड ने विद्यालयों में तैयार की जाने वाली वस्तुओं से प्राप्त श्रम वाली भाग के सम्बन्ध में कोई अनुपात नियत करने से इनकार कर दिया और केवल इतनी सिफारिश की कि यदि बुनियादी शिक्षा प्रणाली का सफल बनाना अभीष्ट है तो इसके शिक्षणात्मक और उत्पादनात्मक पहलुओं पर समान ध्यान दिया जाना चाहिये।

इस प्रकार किसी दस्तकारी के उत्पादनात्मक पहलु पर आवश्यकता से अधिक बल देना एक ऐसा सतर्क है जिससे बुनियादी शिक्षा को बचना ही चाहिये। परन्तु इनका यह अर्थ नहीं है कि यह बात इस प्रणाली की कोई निन्दा या घालोचना है क्योंकि समार में ऐसी कोई भी प्रणाली नहीं है जिसमें दोष न ढूँढे जा सकें। अनेक प्रकार की दस्तकारियों की व्यवस्था का हम दृष्टि से भी विरोध महसूस है। अनेक दस्तकारियों का अर्थ यह होगा कि छात्रों और अध्यापकों दोनों के लिए ही बहुत प्रकार की विविधता बनी रहे और इसमें बुनियादी शिक्षा के शिक्षणात्मक पहलु पर अधिक पहलु की अपेक्षा अधिक जोर देने में सहायता मिलेगी। साथ ही अनन्योन्या बुनियादी शिक्षा देना का अधिक उन्नति में भी सहायता देगी। भारत जैसे देश में दस्तकारियों की वृद्धि

का विग्रह स आवश्यकता है क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत अधिक फैला हुई है। धनक प्रकार की दस्तकारियाँ बाजार बुनियादी विद्यालय उद्योग और व्यापार के विस्तार की आधारशिला बन सकेंगे। माविमत्र रूप में प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा के अनुभव के आधार पर इस प्रकार की शिक्षा का जा सकता है। जब शिक्षा का विभिन्न दस्तकारियाँ के आधार पर प्रारम्भ किया गया तो वही साक्षरता शिक्षा का प्रगति का बड़ा प्राप्ताह्न मिला। बालक और किशोर सभी का अपनी निपुणता और अर्थोपाजन का दक्षिण का बचन का समय प्राप्त हुआ। विद्यालयों को बहु गिन विद्यालयों के रूप में परिवर्तित करने का द्वार यह पहला बंदन था और बहु गिन विद्यालयों की स्थापना हा बहु आधारशिला थी जिसके ऊपर साक्षरता इस न अपने उपयोगीकरण और विकास का महत्त्व लगा किया। भारत में भा बुनियादी शिक्षा का प्रकार इस प्रकार के बहु गिन विद्यालयों का स्थापना का प्रारम्भ समझा जा सकता है।

स्वतंत्रता और संगठन य वे दो सिद्धान्त हैं जिनके आधार पर कार्य समाज प्रगति कर सकता है और जीवित रह सकता है। इसलिए बालक में हा संभावना हा स्वतंत्रता का भावना और संगठन के प्रति निष्ठा का भावना उत्पन्न की जाना चाहिये। इसीलिए बुनियादी विद्यालयों में यह एक मुख्य लक्ष्य रखा गया है कि बालक में स्वतंत्रता (स्पोन्टाइटी) और सामाजिकता का भावना का विकसित किया जाय। स्वतंत्रता के अन्वयार्थ बालक का मन साम्यताएँ पनप उठता है। सामाजिकता का भावना के अन्वयार्थ उसमें जिम्मेदारता का भाव जाग उठता है और वह हम बात को धनमय करने लगता है कि वह स्वयं भा समाज का एक उत्पन्नशील अंग है। कक्षाओं के मन्त्रिमा और बावकारिणी समितिवा की प्रणाली के द्वारा उसमें पालन करने का दक्षिण और उत्तराधिकारी का भावना परिपुष्ट हो जाती है। सामूहिक गतिविधियाँ में सहकारिता के महत्त्व पर बल दिया जाता है। य सब चीजें मिलकर बालक के लिए शिक्षा को एक वास्तविक रूप दे देता है क्योंकि इनमें बालक यह धनमय बचन समझ है कि वे समाज के साम्य हैं। हमारे शिक्षा की इन समय प्रवर्तित पद्धति में बालक को समाज के अन्वयार्थ में बतसाया जाता है और उन बताया जाता है कि उन क्या करता चाहिये। बुनियादी शिक्षा में बालक को समाज के एक अन्वयार्थ के रूप में जीना सिखाया जाता है। इनमें स पहला पद्धति बचन

वास्तविक शिक्षा की है और इसीलिए यह जीवन में बहुत दूर हटती हुई है। दूसरी पद्धति सामाजिक जीवन में वास्तविक रूप में भाग लेने की पद्धति है और इसलिए यह नागरिकता की भीषी शिक्षा है।

इसलिए बनियादी विद्यालय को प्रजातन्त्र का व्यावहारिक उदाहरण बनना चाहिये। यह उद्देश्य सफल होता है या नहीं यह बात मुख्य रूप से अध्यापक की योग्यता पर निर्भर है। सब प्रजातन्त्रों की भाँति विद्यालय के समाज में भी प्रजातन्त्र सभी सफलतापूर्वक काम कर सकता है जब कि वहाँ बुद्धिमत्तापूर्ण और उचित नृत्व प्राप्त हो सके। मन पहले ही यह सचेत कर दिया है कि पाठ्य पुस्तकों और निर्धारित पाठ्य विषयों से छटकारा मिला देने के साथ-साथ बनियादी विद्यालयों में अध्यापक के ऊपर काफी अधिक बोझ भी पड़ता है। मने एस भी बनियादी विद्यालय देखें जहाँ भौतिकी विज्ञान या रसायन विज्ञान को बताई की दस्तकारी के साथ मिलाकर पढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा था परन्तु वहाँ के बालकों को अपने बच्चा भवन के क्षमता या लम्बाई चौड़ाई तक का कुछ ध्यान न था और वहाँ तक कि उन्हें अपने भार और अपनी ऊँचाई तक का भी कुछ अनुमान न था। इसके विपरीत मन कुछ एम बुनियादी विद्यालय भी देखें जहाँ पढ़ाई बालकों द्वारा निरन्तर बड़े जोर और उत्सुकता के साथ अपने परिवेग (एनवायरनमेंट) की ओर और जीव-मंडल के रूप में चल रही थी। वैसे तो अन्तर्गतवा हर एक प्रणाली में ही अध्यापक का सबसे अधिक महत्व होता है परन्तु बुनियादी विद्यालय में उसका महत्व सामान्य विद्यालयों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है।

एक दृष्टि से सम्पूर्ण मानवीय गतिविधि का सत्य प्रानन्द है। वस्तुतः कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना की परिभाषा किसी भी कृत्य की सन्तुष्टिपूर्ण समाप्ति के रूप में की है। पुस्तकों और निर्जीव दिग्दर्शकों को बालकों के ऊपर घाप देने के कारण उन्हें बहुत लम्बे समय तक निष्क्रिय बैठ रहना पड़ता था और इससे बालकों को बहुत चोट होता था। बुनियादी शिक्षा में बालकों को स्वतंत्र और स्वच्छन्द स्निग्ध साथ ही सोद्देश्य और उपयोगी गतिविधियाँ का प्रवर्तन देकर इस घाप को हटाने का प्रयत्न किया गया है। विद्यालय में दस्तकारीयों प्रारम्भ करने के फलस्वरूप विद्यालय बालकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक जीवनप्रद और राक्षस बन जाता है और इसके फलस्वरूप बेचस वितावी (शान्तीय) या

साहित्यिक काम का नीरसता भय ही जाती है। परन्तु यदि विद्यालयों के धार्मिक दष्टि से आत्मनिर्भर बनाने पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाय तो दस्तकारी बालक के लिए एक आनन्दपूर्ण मजनात्मक गतिविधि न रहकर एक घबरात वाला बोझ बन जायगी।

लगभग सभी देशों में शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि अध्ययन की प्रक्रिया को आनन्दपूर्ण बनाया जाय। घबरात और एकरमता का हटाना और छात्रों की निरक्षरता को दूर करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। भारत में भी हम स्वस्थ प्रवृत्ति का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। भारत के विषय में हम बात का और भी अधिक जोर देकर कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत बार हमारे देश में कुछ महान् का बहुत प्रभाव पड़ा है। जिस कुछ महान् धर्म आप में कोई बड़ी अच्छी बात है। बहुत-से भारतीयों को उसका भी भावना बहुत प्रिय जान पड़ती है। जिन मार्गों में धर्म का भावना बड़ी उत्पन्न है वे यह धनप्रवृत्ति करते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धर्म को त्याग देना उनकी विश्वासपरायणता की बुराई है। किसी धर्म के लिए कुछ महान् करने से कोई व्यक्ति धष्ट बन सकता है परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि धर्म का धर्म आप में कोई महत्व नहीं है और उसे उसी उक्ति कहा जा सकता है जब कि वह किसी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में सहा जा रहा हो। बुनियादी विद्यालयों के कुछ अध्यापकों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे धर्म-महान् या लक्ष्य का इस रूप में प्रभाव करते हैं कि जो वे अपने आप में कोई अच्छा वस्तु है। यदि हम प्रकार की प्रवृत्तियों को न रखा गया तो यह भय है कि बुनियादी शिक्षा न पढ़ाई की मजनात्मक गतिविधि का उभरकर बनने वाली सिद्ध न होकर बनी एक बाधक और भयावह वस्तु न बन जाय।

सही अर्थों में समझ ली गई बुनियादी शिक्षा मानसिक और शारीरिक कार्यों को मिश्रित और किताबी (प्राचीन) विषयों को किताब दस्तकारी की गतिविधियों के आधार पर मिश्रित बालक को एकरमता और नारमता में लाने का प्रयत्न है। यह शिक्षा विद्यालय में स्वतंत्रता और आनन्द का वातावरण उत्पन्न करना चाहती है। जो बुनियादी शिक्षा बालक के लिए इस प्रकार अच्छा है क्योंकि यह बालक के व्यक्तित्व को उन गतिविधियों पर

सांख्यिक शिक्षा की है और इसीलिए वह जीवन से बहुत दूर हटी हुई है। दूसरी पद्धति सामाजिक जीवन में वास्तविक रूप में भाग लेने की पद्धति है और इसलिए वह नागरिकता की सीधी शिक्षा है।

इसलिए धनियादी विद्यालय की प्रजासत्तव या व्यावहारिक उदाहरण बनना चाहिये। यह उद्देश्य सफल होता है या नहीं यह बात मस्य रूप से अध्ययन की योग्यता पर निर्भर है। सब प्रजासत्तवों की भाँति विद्यालय के समाज में भी प्रजासत्तव सभी सफलतापूर्वक काम कर सकता है जब कि वहाँ बुद्धिमत्तापूर्ण और उचित नम्रत्व प्राप्त हो सके। मन पहले ही यह संकेत कर दिया है कि पाठ्य पुस्तकों और नियमित पाठ्य विषयों से छटकारा देना इन के साथ-साथ धनियादी विद्यालयों में अध्यापक के ऊपर काफी अधिक बोझ भी पड़ता है। मन ऐसे भा धनियादी विद्यालय स्थापित ह जहाँ भौतिकी विज्ञान या रसायन विज्ञान को बतार्ई की दस्तकारी के साथ मिनाकर पढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा था परन्तु वहाँ के बालकों को अपने बसा भवन के मरुफल या लम्बाई चौड़ाई तक का कुछ धन्य न था और यहाँ तक कि उन्हें अपने मार और अपनी ऊँचाई तक का भी कुछ अनमान न था। इसके विपरीत बने कुछ ऐसे बुनियादी विद्यालय भी देख ह जहाँ पन्नी बालकों द्वारा निरन्तर बड़े जोर और उत्सुकता के साथ अपने परिवे (एनवायरनमेंट) की आज और जीव-मृदता के रूप में चल रही थी। बसे तो भूतलोगका हर एक प्रणाली में ही अध्यापक का सबसे अधिक महत्व होना है परन्तु बुनियादी विद्यालयों में उसका महत्व सामान्य विद्यालयों की अपेक्षा बड़ी अधिक होता है।

एक दृष्टि से सम्पूर्ण मानवीय गतिविधि का सत्य ध्यान है। वस्तुतः कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ध्यान की परिभाषा किसी भी कृत्य की सन्तोषपूर्ण समाप्ति के रूप में की है। पुस्तकों और निर्जीव दिनचर्या के बालकों के ऊपर घाप देने के कारण उन्हें बहुत लम्बे समय तक निष्क्रिय बैठ रहना पड़ता था और इससे बालकों को बहुत नष्ट होता था। धनियादी शिक्षा में बालकों को स्वतंत्र और स्वच्छन्द स्तिन साथ ही सोच्य और उपयोगी गतिविधियों का ध्वसर देकर इस क्षति को हटाने का प्रयत्न किया गया है। विद्यालय में दस्तकारियों प्रारम्भ करने के फलस्वरूप विद्यालय बालक के लिए अपेक्षाकृत अधिक जीवनप्रद और रोचक बन जाता है और इसके फलस्वरूप केवल विनावी (घाम्नीय) या

साहित्यिक कार्य को नारसत्ता भग हो जाती है। परन्तु यदि विद्यालय का प्राथिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाय तो दम्भकारी वास्तव के लिए एक आनन्दपूर्ण सजनात्मक गतिविधि न बनकर एक बहाने वाला बाध बन जायेगी।

समयमयी देना में शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि अध्ययन की प्रक्रिया को आनन्दपूर्ण बनाया जाय। बचान और एकरमता का हटान और छात्रों की निरक्षरता को बचान के लिए निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है। भारत में भी इस स्वस्थ प्रवृत्ति का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। भारत के विषय में इस बात का और भी अधिक जोर देकर कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत बार हमारे देश में कष्ट सहन का बहुत प्रयोग किया जाता है जैसे कष्ट सहना अपने आप में कोई बड़ी अच्छी बात हो। बहुत-से भारतीयों को तपस्या की भावना बहुत प्रिय जान पड़ती है। जिन लोगों में आनन्द की भावना बढ़ा उठे है वह अनुभव करते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आनन्द को त्याग देना उनकी विश्वासपरचमणता की कसौटी है। किसी आनन्द के लिए कष्ट-सहन करने से कोई व्यक्ति झूठ बन सकता है परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि कष्ट का अपने आप में कोई महत्व नहीं है और उसे तभी उचित कहा जा सकता है जब कि वह किसी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामान के रूप में सह्य हो रहा हो। युनियानी विद्यालयों के कुछ अध्यापकों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे कष्ट-सहन या तपस्या का इस रूप में प्रयोग करते हैं कि उस के अपने आप में कोई अच्छी वस्तु है। यदि इन प्रकार की प्रवृत्तियों का न राखा गया तो यह भय है कि युनियानी शिक्षा न पौड़ी की सजनात्मक गतिविधियों को उत्पन्न करने वाली सिद्ध होकर बनी एक बाधक और भयावह वस्तु बन जाय।

सही अर्थों में समझ लो यदि युनियानी शिक्षा मानसिक और नारीरिक कार्यों को मिलाकर और निम्नो (नास्त्रीय) विषयों को किसी दम्भकारी की गतिविधियों के आधार पर निम्नो बालक को एकरमता और नारमता में छत्रकारा दिया गयी है। यह शिक्षा विद्यालय में स्वतन्त्रता और आनन्द का सातावरण उत्पन्न करना चाहती है। यह युनियानी शिक्षा बालक के लिए नम कारण अच्छी है क्योंकि यह बालक के व्यक्तित्व को उन गतिविधियों पर

परिपुष्ट करन में सहायता देगी है, जिन्हें उस बालक न स्वयं स्वतंत्रतापूर्वक चुना है और जिनमें उसका स्वयं पहल की है। जो थोड़ा बालक के लिए भ्रष्टा है वही समाज के लिए भी भली है। समाज को होना चाहे एक लाभ का ऊपर उन्नत कर लिया गया है। सार्वजनिक शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली पर होना चाहे धन का कम से कम कुछ भण्ड पुरा करने यह शिक्षा को समके लिए सुलभ बनान में सहायता देती है। बुनियादी शिक्षा उन लोगों के भाग्यो का भी समाधान कर देती है जो सब मानवीय गतिविधियों का सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि में भी मूल्यांकन करना चाहते हैं। इस बात पर सब सहमत है कि मन्त्री अवधि में शिक्षा उत्पादनशील सिद्ध होती है परन्तु अल्प अवधि में अर्थात् तत्काल सामान्य मान वाली कठिनाइयों के कारण सम्बन्धी अवधि में अर्थात् २२ से होना वाले लाभों को प्राप्त कर पान में रुकावट पड़ जाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उचित रूप से किया गया विनियोग आग बलकर मनाफा देना है। परन्तु यदि किसी के पास विनियोग करन के लिए पूँजी ही न हो तो वह क्या करे? यह है वह प्रश्न जिसका उत्तर बुनियादी शिक्षा देना का प्रयत्न करती है। बुनियादी विद्यालयों का लक्ष्य यह सिद्ध करना है कि शिक्षा आवश्यक रूप से ऐसा विनियोग नहीं है जो बहुत देर में और केवल परीक्षा रूप से ही मुनाफा देता हो बल्कि ऐसा विनियोग है जिसमें लाभ तुरन्त और प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त हो सकता है।

इस विवेचन को समाप्त करन से पहले अन्त में एक शतावली दे देना आवश्यक है। इस सारे मामले की प्रकृति को देखते हुए पुराने परम्परागत विद्यालयों को बुनियादी शिक्षा के विद्यालयों में परिवर्तित करन का काम क्रमशः और धीरे-धीरे ही होना चाहिये। दो लाख से मा अधिक विद्यालयों का बुनियादी विद्यालयों में परिवर्तन और लगभग १० लाख अध्यापकों का नये सिरे से प्रशिक्षण ऐसा कार्य है जिसे कई वर्षों में पूँजाकर करना ही आवश्यक होगा। क्योंकि इस सक्रमण काल में दोनो प्रणालियों जारी रहेगी इसलिये इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उन दोनों में परस्पर विरोध भाव उत्पन्न न हो। इसलिये हमें इस विचार को नहीं पनपना देना चाहिये कि इन विद्यालयों के रूपांतरण का अर्थ यह है कि अपने अतीत का एकदम छोड़ दिया जाय बल्कि हमें इस परिवर्तन का हम रूप में देखना चाहिये कि हम अब फिर उसी पुराने मूल्यों पर फिर से आ

दन नग ह जा बीच में कुछ समय तक अनक कारण म भुसा लिए गए थ या उभेभित हा गए थ । छोट बासनों का गतिविधिया के द्वारा गिष्ठा नी जानी चाहिये विद्यालय के सब विषय एन समबित (इंटग्रलिटि) रूप में पशाय जान चाहिये और गिष्ठा साहय होनी चाहिये । य एम सत्य ह जिह सिद्ध करन क लिए किमी प्रमाण की आवश्यकता नही । इन सिद्धान्तो का व्यवहार म सभा अन्ध गिष्ठागास्त्रियों न स्वीकार किया है अन्धे ही उहान इन बातो का मुम्पत् सिद्धान्तो का रूप न भी दिया हा । फिर भी इन सिद्धान्तो का समम बुझकर स्वाकार करना हम दुष्टि न काफी महत्वपूर्ण है कि समम प्रारम्भिक गिष्ठा को बुनियादी गिष्ठा की पद्धति में परिवर्तित करन क भारताय निम्बर का प्रातिकारी महत्व स्पष्ट हा जायगा ।



## अध्याय ३ माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन

कई बार यह कहा जाना है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये है जिनका सम्बन्ध प्रारम्भिक शिक्षा या वयस्क शिक्षा में नहीं किया जा सकता। पहली बात तो यह है कि शिक्षा की विभिन्न दशाओं के बीच सीमा की कोई पक्की रखा खींच पाना सम्भव नहीं है क्योंकि ये दशाएँ परस्पर एक दूसरे से इस प्रकार घुस भिन्न गई हैं कि उन्हें पहचान पाना कठिन है। एक और बात यह है कि प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा के लिए प्राप्त होन वाले सब अध्यापक माध्यमिक विद्यालया में ही तयार होते हैं। इसलिए यदि माध्यमिक शिक्षा का विस्तार और पुनर्गठन न किया जाय तो प्रारम्भिक शिक्षा का पुनर्गठन या वयस्क शिक्षा का प्रसार असम्भव हो जायगा। इससे प्रतिरिक्त राष्ट्रीय नीति का निर्धारण बहुत सीमा तक राष्ट्रीय नेताओं के निश्चय पर निर्भर रहता है। ये राष्ट्रीय नेता मुख्यतया उस ढंग में सहाते हैं जिससे उच्चतर शिक्षा प्राप्त की हुई है। परन्तु इस उच्चतर शिक्षा का पूरा लाभ तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि माध्यमिक शिक्षा का ढंगा में की जान वाली तयारी अपूर्ण या दायपूर्ण हो। इसलिए समाज के शिक्षा के विगी भी वायव्य में माध्यमिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण स्थान होना है। यह माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा दोनों के लिए ही अध्यापक प्रदान करती है। यह छात्रों के

विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर अध्ययन की दूसरी सम्प्राप्ति के लिए तैयार करती है। इससे प्रतिरिक्त यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर समा दशा में विद्यार्थियों की अनिश्चित संख्या अपनी शिक्षा समाप्त न करती है। विद्यार्थियों की वह अन्य समस्या भी जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे जाती है, वह तब विश्वविद्यालय में प्राप्त होने वाले अध्ययन का पूरा लाभ नहीं उठा सकता जब तक कि माध्यमिक शिक्षा की स्वस्थ प्रणाली द्वारा उसका आधार प्रकट न कर दिया जाय। यदि और कोई कारण न भी हो, तो भी कबल इन कारणों की दृष्टि में खतम हुए यह आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा उच्चतम कोटि की हो। तभी यह आधुनिक युग की आवश्यकताओं का पूरा कर सकेगी।

माध्यमिक शिक्षा को उत्कृष्ट कोटि का बनाने के लिए एक और भी कारण दिया जाता है। समा समाज में अधिकतर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई प्रारम्भिक शिक्षा का समाप्ति पर ही खतम कर देते हैं। वह थोड़ी-सी अन्य समस्या जो माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को पार करके उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, दश का अच्छा मतलब प्रदान कर सकती है। परन्तु यदि उन नवज्व कल्पना का प्रभाव (एफिजेंस) बादतमा में प्रियान्वित करना अभीष्ट हो तो हम लोग भी काफी बड़ा समस्या में हान चाहिये जो ज्ञान प्रणिष्ठा और चरित्र का दृष्टि से इसका लिए समर्थ हो। कुछ बाइबल सर्वोच्च नता नीति का निश्चय कर सकते हैं परन्तु उन नीतियों को प्रियान्वित कर पाना उन मध्यम स्तर के लोग पर ही निर्भर है जिनमें नताओं के उद्देश्य का ठोस-ठीक समझ पाने का ज्ञान और मूर्धन्यता हो।

माध्यमिक शिक्षा इन मध्यवर्ती लोगों का प्रणिष्ठा दे सकती है और उन दत्ता का चाहिये। ये प्रणिष्ठित लोग उच्चतम स्तर पर नियत गत नीति सम्बन्धी निश्चय का प्रियान्वित कर सकेंगे। इसलिए जो लोग अपनी पढ़ाई माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाप्त करें उन्हें ज्ञान और सत्यमता (कीम्नीटन्स) का प्रान्त करनी हो चाहिये साथ ही उनमें नतस्व का गुण और चरित्र भी विकसित हो पाना चाहिये। इनमें से कुछ लोग और आगे जा सकेंगे और वे उच्चतर नताओं की रक्षा में पहुँचेंगे परन्तु सब लोगों को भी कम से कम मध्यवर्ती स्थिति के कृत्यों को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिये। ये मध्यवर्ती लोग सामान्य जनता के सम्मुख नताओं के अनिश्चितता का स्पष्टकरण कर सकेंगे।

इस बात पर साधारणतया सब लोग सहमत हैं कि माध्यमिक शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य यह भी है कि छात्रों में जनत्व के उन गुणों का विकास हो जाय जिनकी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ती है। प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य आधारभूत जानकारी और वह निपुणता प्रदान करना होता है जिसके सहारे मनुष्य सरलता से जीवन-यापन कर सके। उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करना होता है और वह (उच्चतर शिक्षा) प्रायः अपने आप में एक लक्ष्य होती है। माध्यमिक शिक्षा इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है और यह उन लोगों का चुनाव करने में सहायक होती है—या कम से कम इसे सहायक होना चाहिए—जिन्हें समाज में उच्चतर नता बनना है।

यह स्पष्ट है कि यदि प्रजातन्त्र को वास्तविक बनाना है तो शिक्षा को अधिकाधिक मुक्त बनाना होगा। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिये कि शिक्षा में केवल मात्रा का विस्तार काफी नहीं है। जब तक शिक्षा की विस्म में भी सुधार न हो तब तक केवल सागरता के प्रचार से उससे कहीं अधिक नई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनकी विचाररता द्वारा हल होगी। शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार का एक और भी पहलू है जो सारे समाज में शिक्षा शास्त्रियों के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। शिक्षा की मात्रा में विस्तार करने के साथ यह खतरा मग्न जुड़ा रहता है कि उससे शिक्षा की विस्म बिगड़ती चली जाय अर्थात् शिक्षा घटिया दर्जे की होती जाय। शिक्षा की विस्म में सुधार न होने की दशा में केवल सागरता का प्रचार करते जान से यह खतरा है कि इस प्रकार की शिक्षा से मनुष्य की केवल विनाशात्मकता में ही वृद्धि न हो जाय। अतीत काल में मुद्द प्रायः सङ्कुचित भावना के प्रभावों के कारण होते रहे हैं। परिमित बर्णानिवर्तन और सीमित संचार साधना के कारण इस प्रकार के मुद्दों के प्रभाव भी परिमित ही रहते थे। परन्तु मात्रा के प्रसार में मुद्द का अर्थ यह है कि लगभग निश्चित रूप से उन सब वस्तुओं का विनाश हो जाय जिनका मनुष्य प्रतिनिधि है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार का परिणाम यह न हो कि शिक्षा के प्रसार (स्ट्रेण्ड) नीचे गिर जाय। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों के सामाजिक मूल्यों को रखा करत हुए मनुष्य में स्वतंत्र और सृजनात्मक भावना परिपुष्ट कर सके। अतीत में इन सामाजिक मूल्यों की रक्षा

### माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन

नवन कुछ धो-अ छम सोय हा करल रह है जिनकी पत्रच पान और मोहन  
 क उज्जतर धून्यों सब थी । परन्तु गिला के प्रसार के माय-भाय प्रपक व्यक्ति का  
 पत्रच इन तक हो सकता है और इसका माय ही यह सनरा ॥ कि कहा जीवन  
 क य मत्प अष्ट न हान चर जाए ।

इमें एक और गतने से भी बचाव करना है। गिना की मुविधाया के विस्तार का परिणाम मनीकीकरण (रजामन्तन विचारों पर अत्यधिक नियंत्रण) भी हो सकता है। जब भी कभी हम बहुत अधिक सस्या वाले सागा के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं तो हम इस बात का प्रलाभन होता है कि काम की एमा गिना अपनाई जाय जिसमें सागा का प्रतिराय कम से कम हो और समस्याया के एम समाधान दूँ जायें जा मोर तोर पर मारा जनता पर लागू हान हों। परन्तु जीवन के उच्चतम मूल्या का उपलब्धि एकान्त या मनुष्या की पुषकता में हो होनी है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना मुक्ति का उपाय स्वयं ढूँढना होता है। गिनात व्यक्तिता का मर्या में बढि हान के कारण हम इस मध्य की भूल जा सकते हैं। सम्भव है कि हम मुविधाया के विस्तार और व्यक्तिता की सम्मलता में घपना कर बैठें। प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर मनीकीकरण की समस्या इतनी गम्भीर नहीं है। इसके कम से कम तान कारण हैं। इसमें मन्त्र नहीं कि प्रारम्भिक आयु में बातका पर प्रभाव बहुत आसानी से और बग्न अधिक डाला जा सकता है परन्तु वे बातें अत्यधिक स्थिति-सम्पन्न (अपान फिर अग्नी पुरानी दगा की धार बापम सौट धान वाले) और व्यक्तिता प्रधान हान हैं। उनकी व्यक्तितागिना और स्थिति-सम्पन्नता उन्हें बानी हन नक किमा बघा गत पर कमत जान से बचानी है। बिन्तु मनीकीकरण के स्तर से उनकी रना का सबसे बड़ा कारण प्रारम्भिक गिनाक्रम का अवधि का स्वतन्त्रता है अथान् यह कि प्रारम्भिक गिनाका बान बन्त थोड़ा होता है। यह अवधि इतनी कम होती है कि न तो इसमें कार् एमा जान ही गिया जा सकता है जा प्राय चलकर उनका जीवन में काम आये और न उनमें कुछ एमी धान्ते हो डाली जा सकती है जो स्वायी बन जायें और बभी बानें नहीं। कर्नाति प्रारम्भिक गिना में बबल आधारमूत जानकारों और निपुणा मित्राना ही प्रयोजन होता है इसलिए यह गिना सबसे लिए एक जगो ही हानी चाहिए। परन्तु जब हम प्रारम्भिक स्थिति से प्राय बडत हैं तो गिना की एक न्य रनने

का यह प्रयत्न दिगङ्घर सन्निहीकरण के रूप में प्रकट हो सकता है। यदि ऐसा हो तो बवल इतना ही खतरा नहीं है कि छात्रों की उत्कृष्टता का प्रभर समाप्त हो जायगा बल्कि यह खतरा है कि छात्रों के लिए अपने भविष्य जीवन का चुनाव कर पाना और भी अधिक कठिन हो जायगा। इसमें भी बुरी बात यह सम्भव है कि हमसे समाज में एक ऐसा विचित्र स्वभाव उत्पन्न हो जाय जिसके कारण या तो जीवन के सब यत्नमान मूल्यों का प्राप्ति भीतर स्वीकार कर लिया जाये या ठीक उसी तरह प्राप्ति भीतर स्वीकार कर दिया जाय।

२

इस प्रकार जहाँ किसी प्रजातन्त्रीय समाज में माध्यमिक शिक्षा का महत्व अमन्य है वहाँ यह भी स्वीकार करना होगा कि भारतीय शिक्षा की श्रृंखला में यह माध्यमिक शिक्षा ही सबसे कमजोर कड़ी समझा जाती रही है। विश्व विद्यालयों का निर्माण है कि माध्यमिक विद्यालयों से आने वाले छात्र प्राप्ति नुसल स्तर के नहीं होते। शिक्षण सम्बन्धी प्रशासकों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त इन छात्रों की प्रारम्भिक शिक्षण या समाज-शिक्षण के रूप में सेवा करने की क्षमता में बड़ा सन्देह है। जन्ता यह अनुभव करती है कि माध्यमिक शिक्षा अपने इस मुख्य उद्देश्य को पूरा नहीं करती कि वह छात्रों में नेतृत्व के उन गुणों को परिपुष्ट कर सके जिनकी जीवन के विभिन्न क्षणों में आवश्यकता पड़ती है। माध्यमिक शिक्षा अन्ततः प्रगतियों की ही हानि पहुँची है। शिक्षा और उच्चतर शिक्षा दोनों को ही हानि पहुँची है।

सावजनिक जीवन या औद्योगिक क्षेत्र के किसी भी भाग पर दृष्टि डालते ही भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की दुबलता स्पष्ट होकर आती है। सावजनिक जीवन में नेताओं और अनुयायियों के बीच अन्तर देश के विभाजन के बाद हुई उच्च-मध्यम में बड़े ही दुर्लभ रूप में दृष्टिगोचर हुआ था। ज्ञान और उद्योग के क्षेत्रों में हमारे पास उच्च योग्यता वाले वैज्ञानिक, इंजीनियरों की संख्या बहुत थोड़ी है। हमारे देश में एक बारीक-देना के बारीकरी की अपेक्षा किसी प्रकार पढ़ाई नहीं है। फिर भी एक भारतीय

कारागर का उत्पादनगोलता उसी कार्टि के अमरिकन या युरोपियन कारागर की अपेक्षा सामान्यतया कम होती है। इसका कारण केवल यंत्रीकरण की मात्रा का अंतर ही नहीं है। ठीक एक हा डंग की मशीना पर भी भारतीय कारागर मूकावल स कम काम कर पाता है। इस अन्तर का एकमात्र युक्तिमयत व्याख्या यहाँ है कि हमारे यहाँ कम मुनिमित और कायक्षम मध्यवर्ती नतामो का अभाव है जो किसी कारखान में कारमें या वाजमन के पं पर हात ह।

हमारी माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य दोषों में स एक यह भी है कि इसका उद्देश्य और वायमय की काई स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई। सामान्य तया ये प्राथमिक शिक्षा का भाग जारी रखन जमा ही समझा जाता है या केवल कागजा और विबविद्यालय की शिक्षा के लिए तैयारी के रूप में समझा जाता है। क्योंकि इसे प्रारम्भिक शिक्षा का ही और भाग विस्तार समझा जाता है इसलिए बालक माध्यमिक विद्यालय में हमलिए नहीं जाठ क्योंकि उनमें काई विषय वाय्यता होनी है बल्कि हमलिए जाने ह। क्योंकि उनके पास अपनी पढाई का जारी रखन के लिए प्राथिक साधन होन ह। इही कारण से विगार वय के बालक भी अपनी पढाई माध्यमिक शिक्षा स भाग हमलिए जारी नहा रखन क्योंकि उनमें उम पढाई के लिए प्रावश्यक वाय्यता होना है बल्कि हमलिए प्राग पठत ह। क्योंकि उनके पास प्रावश्यक वित्तीय साधन होत्र हैं। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा को अगन आप में एक ऐसा निश्चिन मजिल नहीं समझा जाता जिसकी अपनी हो कुछ नाम विषयताण हा। हमलिए दंग में माध्यमिक शिक्षा का सारा डीबा ही बरत बरना और अस्पष्ट-सा है।

माध्यमिक शिक्षा का कायक्षम और इसके कायकलाप (पवान) की स्पष्ट परिभाषा उम तरह नहीं की गई जिस तरह प्रारम्भिक और उच्चतर शिक्षा की की गई है। इसका कुछ इतिहासीय कारण ह। अतीत काल में शिक्षा केवल बाइ-म गिन-बुन लागों का विषयाधिकार थी और स भोग जिनता भी सम्भव हा अधिक स अधिक ज्ञान प्राप्त करन की चेष्टा करने से। हमें अभी अभी प्राक्षर हाता है कि उम समय के न केवल विगान् धनितु राजा और हमरे के माग भी जिनका पास कुछ खाली समय होना था जिस प्रकार इतना विषयाग जमा गान प्राप्त कर लेत्र थ। उन्हें विभिन्न विषया या ज्ञान के बमित स्तर में अंतर करन का प्रावश्यकता हा नहीं पडती थी और वे सब

प्रकार के ज्ञान का ग्रहण करने में जुट रहते थे। क्योंकि उस समय गिना को मर्यादी स्तर के रूप में समझा जाता था और इस बात का विचार नहीं किया जाता था कि इसने क्या-क्या व्यावहारिक उपयोग सम्भव हैं। इसलिए वे गिन-बुने लोग जो इस प्रकार के बौद्धिक विकास में रुचि रखते थे अपने ज्ञानवर्धन के लिए किसी प्रकार की मर्यादा (हदबंदिया) को स्वीकार नहीं करते थे। वे सब प्रकार का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने की चেষा करते थे। दूसरी ओर अधिकांश जनता अपने वेगों के लिए आवश्यक निपुणता मात्र प्राप्त करके सन्तुष्ट रहनी थी और इस प्रकार की निपुणता प्राप्त करना सामान्यतया शिक्षा प्राप्त करना ही समझा जाता था। इसलिए शिक्षा का प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के रूपों में विभाजन अपेक्षाकृत बहुत हाल की चीज है। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या लगभग सभी देशों में माध्यमिक शिक्षा की सीमाएँ अनिश्चित-सी हैं। आजकल समुक्त राज्य अमेरिका में माध्यमिक शिक्षा के वाय-वीर और वायकनाप के सम्बन्ध में काफी विचार चल रहा है। कुछ विद्वानों का विचार है कि माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक (व्यावहारिक) है और इसका ध्येय यह है कि यह मनुष्य की अपनी रोजी बर्मान में समर्थ बनाए। इसके विपरीत दूसरे विचारकों का क्याल है कि यह माध्यमिक शिक्षा भी एक प्रकार की सामान्य शिक्षा ही है जिसका उद्देश्य समाज का अर्थ नर और नारी प्रदान करना है।

भारत में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और कार्यक्रम की परिभाषा कर पाना और भी अधिक कठिन क्यों रहा इसके कुछ विशेष कारण हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे देश में उन्नीसवीं शताब्दी की प्रारम्भिक दशकियों में ही मुख्य उद्देश्यों की दृष्टि में रखकर प्रारम्भ की गई थी। कुछ प्रयोजन शिक्षा शास्त्री और सुधारक ऐसे थे जिनका विचार था कि पश्चिमी विज्ञान और राजनीतिक विचारों के सम्पर्क में आने से भारत का पुनरुत्थान होगा। साथ ही कुछ ऐसे प्रशासक भी थे जिनका उद्देश्य यह था कि देश में एक शिक्षित वर्ग तैयार किया जाय जो अगली विचारों के अनुसार देश के प्रशासन को चलाने में सहायता करे। यह स्पष्ट था कि बहुत बड़े पैमाने पर अफसर इकट्ठा करना भारत में नहीं लाए जा सकते थे। उच्चतम पद अग्रेसरों के लिए सुरक्षित रखे गए, परन्तु प्रशासन के लिए दूसरे और तीसरे स्तर पर भी काम करने के

लिए बहुत बड़ा मय्याम नमचारिया का आविर्भाव था। प्रगामकों की इस  
 थी कि इस प्रकार के मय्याम का भरण के लिए भारतीया का प्रगिष्ठन नि  
 जान। इस प्रकार दोना वगैरे के उद्देश्य निम्न-मिन थ किन्तु वे दोना एक  
 उत्पत्ति का प्रारम्भ और प्रसार। इस पश्चिमी गिष्ठा के प्रसार में कु  
 पद्धति का प्रारम्भ और प्रसार। इस पश्चिमी गिष्ठा के प्रसार में कु  
 भारतीय नतामान भा बड़ा लितवस्था थी। क्योंकि उन्हें यह भागा थी कि इनम  
 दश के पुनर्निर्माण में और भी को स्वाधीन करान में सहायता मिदगा। भारतीय  
 नतामो के इस उत्साह से भी पश्चिमी गिष्ठा के प्रसार में बड़ा सहायता  
 मिली।

इन सब योगों के उद्देश्य भले हैं किन्तु जो कि

व सब एक ही सत्य तक पहुँचने के लिए हैं।

इस सब योगा के उद्देश्य भले हा किन्तु ही भिन्न क्या न रहे हों परन्तु  
 व सब एक हा सत्य तब पहुँचन के लिए प्रयत्न कर रहे थे। उनका विचार  
 उस वस्तु में भी था जिसे गिटा का अर्थ था सिद्धान्त (परमिणन ध्यारी)  
 कहा जा सकता है। उनका विचार था कि यदि हमें कुछ थोड़े-से अल्पसंख्यक  
 शिक्षित लोग हों तो उनको उद्धारण के रूप में देखकर लोगों को बड़ा सत्या  
 में नये शिक्षण-धाराओं को अपनायन की प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार भाषुनिक  
 गिटा प्रणाली उच्च स्तरा से नीचे की ओर सब तक रिमता चली जायगा  
 जब तक बहु सार समाज में व्याप्त न हो जाय। भविष्य की गिटा-नीति के  
 सम्बन्ध में मैकटि के प्रसिद्ध स्मरण-लेख (मिनिट) के अनुसार उस समय की  
 सरकार न यह धारणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का यह महान् उद्देश्य  
 होना चाहिये कि भारत के दावानिया में यूरोपाय साहित्य और विज्ञान का  
 प्रचार किया जाय और गिटा के प्रचारन से निपट की गई सब निधिया का  
 सर्वोत्तम उपयोग यह होगा कि उनका व्यय केवल अग्रणी गिटा के लिए किया  
 जाय। इस सलाह (रिवाल्सूशन) में यह भी कहा गया था कि इस प्रकार  
 के विद्यालयों और काल्जा को जारी रखन की भी व्यवस्था की जानी चाहिये  
 जहाँ पुरानी देशी ढंग का गिटा भी की जाती हो। परन्तु बहुत शीघ्र हा यह  
 बात उनकी केवल एक धुम कामना का प्रदान मात्र बनकर रह गई। क्योंकि  
 अग्रणी विद्यालयों की गिटा सरकारी और ध्यारी नौकरिया में प्रवेश के लिए  
 तय्यार-ना बन गई थी इसलिए इन विद्यालयों में गिटा प्राप्त करने के लिए  
 न वाले विद्यापिया की सत्ता निरन्तर बढ़ती गई। अन्तु इन नवगति



भारतीयों में से कुछ के मन में तो प्राचीन पौस्तक्य विद्याओं के प्रति मकल्ले जसी ही प्रेमा भी जाग उठी थी।

यह कहा जा सकता है कि जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली १८५७ में विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ प्रारम्भ हुई। क्या-वि विश्वविद्यालय तब तक ठीक ढंग से काम नहीं कर सकते जब तक कि माध्यमिक विद्यालयों से उत्तीर्ण होकर छात्र उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने न आएँ, इसलिए अधिकाधिक मात्रा में माध्यमिक विद्यालय भी खोले गए और अन्त में इन माध्यमिक विद्यालयों के कमस्वरूप प्राथमिक शिक्षा का भी विस्तार हुआ। इस प्रकार यह दोहन लगा कि जैसे अध्यात्म सिद्धान्त (परमेश्वरानुभूति) आध्यात्मिक परिणाम उत्पन्न करने लगा।

अन्त में एक कल यह हुआ कि शिक्षा के सारे क्षेत्र पर विश्वविद्यालयों का प्रभुत्व हो गया। माध्यमिक विद्यालय मात्र ध्यान विश्वविद्यालयों के लिए छात्रों का तैयार करने पर देते थे। शिक्षा के माध्यम तब के रूप में मान्यता की बड़ी उपेक्षा की गई। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत कम प्रयत्न किया गया। पाठ्यक्रम कठोर (शास्त्रीय) हो गए और उनका जीवन से कोई सम्बन्ध न रहा क्योंकि विश्वविद्यालयों में व्यवसाय सम्बन्धी या गिनत-सम्बन्धी पाठ्यक्रमों को कोई व्यवस्था नहीं थी। अन्त में मैट्रिकुलेशन परीक्षा के द्वारा विश्वविद्यालयों ने केवल माध्यमिक शिक्षा पर अपना प्रभुत्व जमा बठे अर्थात् प्राथमिक विद्यालयों में ही प्राप्त की शिक्षा पर भी प्रभाव डालने लग। उन प्रारम्भिक दिनों में विश्वविद्यालयों की उपाधि (डिग्री) सामान्यतः नौकरी पान की लगभग गारंटी ही बन गई थी। इस तथ्य के कारण भी विश्वविद्यालयों का शिक्षा क्षेत्र पर प्रभुत्व और भी पूर्ण हो गया।

माध्यमिक विद्यालयों पर विश्वविद्यालयों का बहुत अधिक प्रभाव होने का परिणाम यह हुआ कि इन विद्यालयों में बुद्धि के परिपोषण (इन्टेल्लेक्ट) पर अनधिकृत रूप से बल दिया जान लगा। बुद्धि का यह परिपोषण भी सम्पूर्ण रूप में नहीं था बल्कि बुद्धि के केवल उमी पहलू पर बल दिया जाता था जो स्मरण शक्ति पर निर्भर रहता है और अपने-आपको भाषा सम्बन्धी योग्यता के रूप में प्रकट कर पाता है। माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन की प्रणाली अन्त

थोड़े-से बालकों की स्थितियों और अभियाग्यताया (एप्टीट्यूड) के अनुकूल होती है। इसमें विभिन्न स्तर पर कल्पना के दार्शनिक और अनुमूर्ति सम्बन्धी निपुणताओं के परिपोषण की धारणा का गई है। कबल उन थोड़े-से अल्प संख्याक बालकों के विवाय जिनमें भाषा का सामान की विशेष योग्यता होती है अल्प बालक प्रायः विद्यालय की शिक्षा का बन्धन ही नाममात्र और मूलनगणना में रहित अनुभव करत हैं। इसविषय विद्यालय उनका सर्वोत्तम साध्यात्मिकता का निवार नहीं पाता। वे विद्यालयों का परागताया का उत्पीड़न प्रत्यक्ष रूप से करत हैं परन्तु इन विद्यालयों में प्राप्त ज्ञान बाह्य अध्ययन परिधि में सुखबनरा का भाव पूरा साम नहीं उठा पाता।

क्योंकि यह साध्यात्मिक शिक्षा जीवन में बहुत दूर हटती गई है इससे यह छात्रों को अपने नित्यप्रति के समार की समझ का धन्यता ही प्राप्त नहीं कर पाती। जब वे पढ़ लिखकर विद्यालय में बाहर निकलत हैं तो वे अपने आप को कुछ बेतुका-सा अनुभव करत हैं और समाज में आसक्ति-वाम और समता के साथ अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाते। जीवन का वास्तविकताया में शिक्षा के इन सम्बन्ध-विच्छेद का एक परिणाम यह हुआ है कि व्यक्ति अपना सामाजिक परिस्थितियों में अपने आपको कुछ अजनबी-सा अनुभव करत लगा है और यह बात बड़ी खतरनाक है। इस शिक्षा के फलस्वरूप एक एमी बनाबटी बाड़ लकी हो गई है जो इन शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों का घर समाज में पथक कर देता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सामाजिकता की भावना भग्न हो जाती है और फलस्वरूप समाज अत्यन्त-अलग बिलर हुए टुकड़ों के रूप में विभक्त हो जाता है। व्यक्ति और समूह दोनों के ही जीवन रहन के लिए समाज की भावना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि समूह उस दशा में रह रहा नहीं सकता, जबकि उसमें सम्पूर्ण यह अनुभव न करे कि इसका उस समूह से सम्बन्ध है या वे उस समूह के आग्राम्य हैं। यह आग्राम्यता या 'सम्बन्ध' होने की भावना व्यक्ति के कल्याण के लिए भी अत्यन्त आवश्यक है। जिस व्यक्ति का समूह का समर्पण प्राप्त न हो उस पर निरन्तर एक बोझ और दबाव बना रहता है और वह बहुत अजीब होना होकर समाप्त हो जाता है। अन्तर्गत इस प्रकार की सामाजिक सहायता के अभाव में फलस्वरूप स्वयं व्यक्ति के अन्दर ही संकीर्णता (प्रेममटन) प्रारम्भ हो जाता है।

भारत में विद्यमान माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के दोषों का विस्तृत विवरण यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से बहुत-से दोष तो सर्वविदित हैं और सबको मापण-मापों से अनवरत बार दोहराया जा चुके हैं। फिर भी यहाँ यह कहना आवश्यक है कि इन सब दोषों के होते हुए भी इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ बड़े शानदार अध्यापन और बहुत-से उत्कृष्ट विद्यार्थी भी तैयार किये हैं। चाहे जो हो वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समुद्देश्य में निन्दा करने का कोई लाभ नहीं है। किसी भी प्रणाली को सुधारने और उसका पुनर्गठन करने के लिए उसके दोषों को ढूँढने और उनको हटाने के उपाय बनाने के लिए बड़ा सावधान अध्ययन की आवश्यकता होती है। यह बात भी ध्यान रखनी चाहिये कि किसी भी शिक्षा प्रणाली को रातों रात नहीं बदला जा सकता। यहाँ कोई साफ सलेट नहीं है जिस पर एकाएक कुछ भी लिखा जा सके बल्कि यहाँ तो कहीं कुछ थोड़ा-सा नया जोड़ना होगा और कहीं कुछ थोड़ा-सा मिटाना होगा और इस प्रकार छोटे-छोटे संशोधनों की प्रक्रिया को जारी रखना होगा। हामाकि भारत में उनका कुल मिलाकर प्रभाव मापें यह हो कि पुरानी प्रणाली इतनी खल्ल जाय कि उसे पहचान पाना ही सम्भव न हो।

### ३

अब हम उन कुछ विविष्ट समस्याओं पर विचार कर सकते हैं जो इस समय भारत में माध्यमिक शिक्षा के सामने उपस्थित हैं। इन समस्याओं के कारण शिक्षा का पुनर्गठन और भी अधिक आवश्यक और माघ ही और भी अधिक कठिन हो गया है। पहली समस्या तो यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध की नयी सिरे से परिभाषा की जाना चाहिये अर्थात् उसे स्पष्ट करने सम्भावना जाना चाहिये। यह समस्या सभी देशों में काफी कठिन बनी हुई है। इंग्लैंड में इन सम्बन्धों में विवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है कि प्रारम्भिक वर्षों में माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा के रूप में हो चलना चाहिये अथवा एक बिल्कुल पृथक् धारा में चल पड़ना चाहिये। एक समय या अब लोगो का ११ योग वर्ष की (इलेवन प्लस) की आयु के जादू में दयनीय रूप से अत्यधिक विश्वास था। मनो-वैज्ञानिकों के एक धरा का समर्थन प्राप्त करने शिक्षा मामलों का यह विश्वास

हा गया था कि ११ वर्ष की आयु में बालका को उन दो वर्गों में बाटा जा सकता है कि उनमें से कौन-से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के योग्य ह और कौन-से नहीं। किंतु अनुभव ने प्रागावाणी लोगो के इस विश्वास की पुष्टि नहीं की बल्कि सूचक शक (इन्टेलीजेंस कोगियट) भाजकल एस नहीं मान जाते कि उनमें गलती हो ही न सक। इसलिए भाजकल लोग पहले की अपेक्षा इस बात को बड़ी अधिक स्वीकार करने लग ह कि प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को विभक्त करने वाले अनिश्चितता के वर्गों में कुछ और ढील दी जान का आवश्यकता है।

भारत में इन लोगो का ठीक-ठीक सीमा-निर्धारण और भी अधिक महत्व पूर्ण हो गया है क्योंकि यहाँ यह निश्चय कर लिया गया है कि प्रारम्भिक दशा में बुनियादी शिक्षा दी जायगी। बुनियादी शिक्षा में अध्यापन किसी दस्तकारी के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार की प्रविधि (टेक्नीक) प्रारम्भिक स्तर पर कितनी ही उचित क्यों न हो परन्तु माध्यमिक शिक्षा की दशा में कितनी ही (गारुमाय) और व्यावहारिक विषयो में परस्पर सह-सम्बन्ध करने में अवश्य ही काफी कठिन समस्याएँ उपस्थित हानगी। इसके अतिरिक्त बुनियादी शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के उन प्रारम्भिक भाग को ढाप लेती है जिसमें विविधोक्ति (डाइवर्सीफिकेशन) और विभेदन (डिफरशियेशन) द्वारा शिक्षा में अव्यक्तता (एम्ब्रूकेशन) का सिद्धान्त प्रारम्भ किया जाता है। बुनियादी शिक्षा की एक विस्तृत और सूक्ष्म युक्त धारणा द्वारा उन कठिनाइयो को हल करने में अवश्य ही सहायता मिलेगी। बुनियादी शिक्षा का ध्येय यह है कि वह जीवन का प्रारम्भिक बन जाय। जीवन में विविध प्रकार के तत्व अपन एक-दूसरे से अन्तर को बनाये रखते ह और फिर भी अनुभव की एकता में वे परस्पर सह सम्बद्ध शीघ्र पड़न हैं। इसीलिए बुनियादी शिक्षा जहाँ तक वह जीवन का सच्चा प्रतिबिम्ब है वास्तविकता की विविधताओं को प्रदर्शित करेगी और माध्यमिक शिक्षा के समन्वयक को अपेक्षाकृत सरल बनाएगी कठिन नहीं।

एक विचारक का यह धारणा है कि पहले पाठ वर्ष तक विद्यालय में अध्यापन बुनियादी ढंग पर होना चाहिये और वह सब कामकों के लिए एक ही होना चाहिये। उसका या तीन या चार साल तक माध्यमिक शिक्षा दी जायगी। किन्तु एक अन्य विचारधारा के समर्थको का कथन है कि केवल

पहले ५ साल तक ही सब बालकों को समान ढंग की शिक्षा दी जानी चाहिये। उसके बाद विद्यार्थियों को दो भाग भागों में विभक्त किया जा सकता है। जिन बालकों का इरादा उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का है वे उस विद्यालय में पढ़ेंगे जिसे कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (अनियर सेकेंडरी स्कूल) कहा जा सकता है। जिन बालकों की शिक्षा प्रारम्भिक स्तर के बाद ही समाप्त हो जानी है वे तीन साल तक वरिष्ठ बाल्यादी पाठ्यक्रम (सीनियर बेसिक कोर्स) पूरा करेंगे। एक तीसरी विचारधारा के समर्थक वा कथन है कि इन दोनों वर्गों के प्रतिरिक्त छात्रों का एक तीसरा वर्ग भी बनाया जाना चाहिये। वे अपनी शिक्षा चौदह वर्ष की आयु में समाप्त नहीं करेंगे बल्कि उच्चतर ज्ञान सम्बन्धी पाठ्यक्रम के बजाय वे दो या तीन साल तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।

इस प्रकार के मामलों में जो एकमात्र सुरक्षित सिद्धान्त बनाया जा सकता है वह यह है कि इस बात पर ध्यान रखा जाय कि इन सब विकल्पा में कोई बड़ा पक्का और अचल-अटल विभाजन न कर लिया जाय। यह ध्यान करना कि चौदह वर्ष तक प्रत्येक बालक को ठीक एक ही पाठ्यक्रम पढ़ना होगा अनुचित प्रतीत होता है। इस बात के लिए प्रमाण विद्यमान हैं कि कुछ मामलों में रुचियों और अभियोग्यताओं की पृथक्ता ग्यारह वर्ष की आयु में या कई बार उससे भी पहले दिखाई पड़न लगती है। दूसरी ओर इस बात पर ध्यान करना भी अनचित प्रतीत होता है कि ग्यारह वर्ष की आयु में बालकों को इस प्रकार पृथक्-पृथक् विभक्त कर दिया जाय कि जने य तो रही भई और य रही बकरियाँ। इसलिए ग्यारह वर्ष की आयु के बाद विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था रखनी चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा के इन पिछले वर्षों में माध्यमिक विज्ञान की शिक्षा प्राविधिक (टेक्निकल या शिल्प सम्बन्धी शिक्षा) या व्यावसायिक ढंग के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिये। ग्यारह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के बीच बालकों को किसी भी समय एक पाठ्यक्रम को छोड़कर दूसरे पाठ्यक्रम को ले सकने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। वस्तुतः कुछ और ध्यान बढ़कर यहाँ तक कहा जा सकता है कि यदि किसी बालक या बालिका में चौदह वर्ष की आयु के बाद भी कुछ नई अभियोग्यताएँ या रुचियाँ दीख पड़ें तो उसको एक प्रकार के पाठ्यक्रम से हटाकर दूसरे प्रकार के पाठ्यक्रम की ओर परिवर्तित करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये।

## माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन

जब एक बार बनियानी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का पारस्परिक सम्बन्ध ठीक-ठीक निधारित कर दिया जाय तो उसका नाम माध्यमिक शिक्षा का विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ सम्बन्ध निश्चित कर पाना सम्भव हो सकेगा। माध्यमिक शिक्षा अपने आपमें एक पूर्ण मजिद होना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा का केवल उन व्यवसायों को छोड़कर जिनके लिए ऊँची विश्वविद्यालयी शिक्षा या पत्र सम्बन्धी प्रशिक्षण का आवश्यकता है अन्य सब व्यवसायों के लिए जीवन का तयारी के रूप में स्वाकार किया जाना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न प्रकारों में आपस में समानता हो रहनी चाहिये जिनमें जो विद्यार्थी इच्छा करे और समय हो वे किसी भी तरह पाठ्यक्रम में किसी भी दूसरे पाठ्यक्रम की धार परिवर्तित कर सकें अथवा उच्चतर शिक्षा के लिए उचित मजिद तक पहुँच सकें।

भारत में माध्यमिक शिक्षा के सम्मुख एक और बड़ी समस्या भाषा की विविधता के कारण उत्पन्न हो गई है। अभी हाल तक भी माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की एक मुख्य दुर्बलता यह थी कि इसमें अध्यापन के माध्यम के रूप में अध्यापक का उपयोग किया जाता था। इससे फलस्वरूप अधिकांश विद्यार्थियों पर एक अनुचित बोझ पड़ जाता था और उनके पूर्ण परिपोषण (इवेलपमेंट) में बाधा पड़ती थी। साथ ही इसके फलस्वरूप शिक्षा का अल्पमत्ता और उन लोगों की विद्यालय बहुसंख्या के बावजूद जिन्हें शिक्षा विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था। लाई चौड़ी और चौड़ी होता जाता था। वर्तमान दशक की चौथी दशक के शुरू से अध्यापन के माध्यम के रूप में किसी भारतीय भाषा का प्रयोग करने का और परिवर्तन अधिकाधिक मात्रा में होता गया है। स्वाधीनता के बाद इस प्रक्रिया का गति और तीव्र हो गई है और आजकल माध्यमिक विद्यालयों में लगभग सभी जगह अध्यापन का माध्यम बालक की मातृभाषा ही है। परन्तु इसका कारण दो बड़े समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। पहली समस्या तो यह है कि विद्यालयों में अध्यापन के माध्यम और विश्वविद्यालयों में अध्यापन के माध्यम के बीच अन्तर हो गया है। जो छात्र माध्यमिक विद्यालय में किसी भाषा में भाषा के अध्यापन के माध्यम के रूप में एकान्त अध्यापक का और विश्वविद्यालयों में अध्यापन के माध्यम के रूप में एकान्त अध्यापक का होता है। बहुत बार

वे कालेजों में दिए जाने वाले भाषणा का समझ पाने और वहाँ मिलने वाले शिक्षा से पूरा लाभ उठा पाने में असमर्थ रहते हैं। इसके फलस्वरूप बाधित होकर विश्वविद्यालयों के प्रमापों (स्टैंडर्ड) को भी नीचे गिरा जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि कालेजों के तरुण छात्रों में अनुशासनहीनता का एक कारण यह भी है कि वे उन भाषणा को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं जो उन्हें कालेजों में बिबश होकर सुनने पड़ते हैं।

दूसरी कठिनाई भारतीय भाषाभाषी की अनवस्था के कारण उत्पन्न होती है। संविधान में चौह मापाभाषी को मायता दी गई है। इनमें से तरह भाषाएँ ऐसी हैं जो लाखों लोगों द्वारा बोली जाती हैं और जिनमें साहित्य की सुदीर्घ और समृद्ध परम्परा विद्यमान है। इसलिए अध्यापन के माध्यम के रूप में प्रयोग किये जाने का उनका दावा अन्याय है। परन्तु अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग से जो लाभ होता है वह एक ही देश में अध्यापन के अनक माध्यमों के कारण होने वाली हानियाँ से मन्तुसित होकर बराबर हो जाता है। भाषाभाषी की अनवस्था भारत की राष्ट्रीय एकता की भावना को दुबल कर दे सकती है। इस अनवस्था के कारण अध्यापका और विद्यार्थियों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में स्थानांतरण निश्चित रूप से कठिन हो जाता है। विदेशी भाषा के अनक दोष होने हुए भी अंग्रेजी ने भारत को हा बड़े लाभ पहुँचाए हैं। इस देश में लागू एकता उत्पन्न करने में और उनमें एक सामान्य राष्ट्रीय चेतना जगाने में बड़ी महायत्ना की है। अंग्रेजी के कारण ही यह सम्भव हो सका है कि अध्यापकों और छात्रों को भारत के किसी भी एक कोने से उठाकर दूसरे कोने में भेज दिया जाय और फिर भी उन्हें कोई कठिनाई या अजनबीपन अनुभव न हो।

भाषाभाषी समस्या पर भारतीय शिक्षाशास्त्रियों ने बड़ी मावधानी से विचार किया। माध्यमिक शिक्षा-मायोग ने भी इस समस्या पर बहुत ध्यान दिया था। इस सम्बन्ध में जो कुछ आन-विवाद हो चुके हैं, उनमें निम्नलिखित बातों का समाधान निकलना प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है कि सारे प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापन का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए।  
 में मतभेद है

चारसर हाना जा रहा है। भारत की एकता का बनाए रखन के लिए हिन्दी या हि भारतीय मध्य का अधिकृत भाषा है कनिष्ठ बुनियादी शिक्षाकाल के प्रारम्भ की जानी चाहिए और कम से कम तीन साल तक एक ध्वनिक भाषा के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। इस शिक्षाकाल के बाद भी हिन्दी के अध्ययन के लिए सुविधाएं और वस्तुन प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। प्राथमिक वृत्तान्तिक विचारों की बाह्य और अन्तर्गतोद्योग क्षेत्र में सम्पूर्ण स्थापन के माध्यम के रूप में अक्षरों को भी कनिष्ठ बुनियादी शिक्षाकाल के बाद प्रारम्भ किया जाना चाहिए और इसके लिए सुविधाएँ प्रदान करके अक्षरों का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किन्तु साथ ही यह मिश्रण भी सामन रहना चाहिए कि एक ही रूप में दोन भाषाएँ प्रारम्भ न की जाय। या विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा में भाषाएँ जाना चाहें उनके लिए अक्षरों और हिन्दी दोनो ही ध्वनिक विषय होन चाहिए। इसके अनिश्चित तिन लोगों को भाषाएँ सीखन में विषय रचि हा या तिनकी उममें विषय अभिव्यक्ति हा उन्हें किसी एक प्राचीन भाषा का अध्ययन करन की सुविधा भी हाना चाहिए।

यहाँ यह बतला दना उचित होगा कि इस प्रकार का प्रबंध हान के बाद भाषाभाषा की शिक्षा का नमूना क्या होगा। जो बालक प्राथमिक शिक्षा में भाषा नहा पढ़ना चाहत व सबसे अपना मातृभाषा का अध्ययन करेंगे। या लाग माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहने ह या उसन भाषा जाना चाहने ह उन्हें कम से कम दो ध्वनिक भाषाएँ—हिन्दी या अथवा किसी की मातृभाषा हिन्दी है या उस कोई एक ध्वनिक आधुनिक भारतीय भाषा और अक्षरों ध्वनिक विषय के रूप में सीखनी पड़ेंगी। तिन बातका की भाषाभाषा के अध्ययन में विषय रचि है व अपना इच्छा से शिक्षा अनिश्चित भाषा का भी अध्ययन कर सकेंगे। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा पान बालक अधिकांश विद्यार्थियों को तीन भाषाएँ प्राप्त के लिए मजबूर करना उनके ऊपर अनुचित बोझ डालना होगा। यदि उन बातका का इन तीन भाषाभाषा के साहित्य का अध्ययन करन को विवक किया जाना या सम्मुख हा इस भाषा का उत्तर द पाना सम्भव सम्भव हा जाता। परन्तु स्थिति यह है कि इनमें से अधिकांश विद्यार्थी ता दो भाषाभाषा का बसत नामचमाऊ पान प्राप्त करेंगे। साथ ही



वे बालेजों में दिए जान वाले भाषणों को समझ पाने और वही मिलन वाली शिक्षा से पूरा लाभ उठा पाने में असमर्थ रहते हैं। इसके फलस्वरूप बाधित छावर विद्वविद्यालयों के प्रभाषों (स्टीपेंडर्स) को भी नीचे गिरा जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि कालेजों के तरुण छात्रों में अनुशासनहीनता का एक कारण यह भी है कि वे उन भाषणों का समझ पाने में असमर्थ रहते हैं, जो उन्हें कालेजों में बिबिध होकर सुनने पड़ते हैं।

दूसरी कठिनाई भारतीय भाषाओं की अनेकता के कारण उत्पन्न होती है। संविधान में चौदह भाषाओं को मान्यता दी गई है। इनमें से तरह भाषाएँ ऐसी हैं जो साम्बा लोगो द्वारा बोली जाती हैं और जिनमें साहित्य की सुदीप्त और समृद्ध परम्परा विद्यमान है। इसलिए अध्यापन के माध्यम के रूप में प्रयोग किये जान का उनका दावा प्रबल है। परन्तु अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग से जो लाभ होता है वह एक ही देश में अध्यापन के अनेक माध्यमों के कारण हानि वाली हानियाँ से मनुष्यलित होकर बराबर हो जाता है। भाषाभाषा की अनेकता भारत की राष्ट्रीय एकता की भावना को दुर्बल कर दे सकती है। इस अनेकता के कारण अध्यापकों और विद्यार्थियों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में स्थानांतरण निश्चिन्त रूप से कठिन हो जाता है। विदेशी भाषा के अनेक दोष होने हुए भी अनेक लोग भारत को दा बड़ लाभ पहुँचाए हैं। इसलिये के लोगो में एकता उत्पन्न करने में और उनमें एक सामान्य राष्ट्रीय चेतना जगाने में बड़ी महत्त्वता की है। अंग्रेजों के कारण ही यह सम्भव हो गया है कि अध्यापकों और छात्रों को भारत के किसी भी एक कोने से उठाकर दूसरे कोने में भेज दिया जाय और फिर भी उन्हें कोई कठिनाई या असुविधा अनुभव न हो।

भाषाभाषा की समस्या पर भारतीय विभागाधिकारी न बड़ी सावधानी से विचार किया। माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने भी इस समस्या पर बहुत ध्यान दिया था। इस सम्बन्ध में जो कुछ धारा विचार हुए वे उनसे निम्नलिखित ढंग का समाधान निकलता प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है कि सारे प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा-काल में अध्यापन का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। विद्वविद्यालयों में अध्यापन के माध्यम के सम्बन्ध में मतभेद है परन्तु धीरे धीरे इस माध्यम के लिए प्रायोगिक भाषा का दावा

धारणर हटा जा रहा है। भारत का एकता का बन्धन रखने के लिए शिक्षा जाति भागीय सुष का अधिष्ठित नाग है कनिष्ठ कनिष्ठाना शिक्षाकान के धन में प्रारम्भ का जनी चाहिए और नन न नन तान तान तन एक धनि बाय माया के रूप में पनाई जानी चाहिए। इस शिक्षाकान के बाग ना शिक्षा के अध्ययन के लिए सुविधार्थ और वस्तु प्रान्तरन प्रान्त शिक्षा जना चाहिए। धार्मिक अज्ञानिक विचारों का बाहक और धनराज्य मत्र में समस्त ध्यान के साधन के रूप में अज्ञा का ना कनिष्ठ कनिष्ठाना शिक्षाकान के बाग प्रारम्भ शिक्षा जना चाहिए और इसके लिए सुविधार्थ प्रान्त करके अज्ञा का प्रान्तरन शिक्षा जाना चाहिए। किन्तु माय ही यह निदान ना मानने रहना चाहिए कि एक हा बा में दाना नागा प्रारम्भ का जान। जा विद्यार्थी साधनिक शिक्षा स ना दाना जाना चाहें उनके लिए अज्ञा और शिक्षा नागों हा धनबाय विषय होन चाहिए। इसके अनिरिक्त दिन सागों का भाना नातन में विषय गति हा या दिनका समस्त शिक्षा अनिष्ठाना हा उन्हें शिक्षा एक प्रान्त नाया का अध्ययन करने का सुविधा भी होना चाहिए।

यहाँ यह बताना नन गति हा कि इस प्रकार का प्रबन्ध हन के बाग नागों का शिक्षा का नमूना का हागा। जा बायक प्रारम्भिक शिक्षा म धन नहीं पडना चाहत के कदम दाना नातनाया का अध्ययन करे। जा नाग साधनिक शिक्षा प्रान्त करना चाहत ना समस्त ना दाना जना चाहत हा उन्हें नन म नन ना धन नापना—शिक्षा ना धार शिक्षा का नातनाया शिक्षा है ना उन को एक धन अधनिक नातना नाया और अज्ञा अनिकाय विषयों के रूप में सातना पडेगा। दिन दानकों का नागना के अध्ययन में विषय रति है के धनना इच्छा म शिक्षा अनिरिक्त नाग का ना अध्ययन कर सकें। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार साधनिक शिक्षा पन बाग अधिका विद्यार्थियों का धान नाया साधन के लिए मत्रबुर करना उनके ऊपर अनुचित भार डालना हागा। यदि उन दायका का इन धान नागों के साहित्य का अध्ययन करने का विषय शिक्षा जागा ना मबनुच हा इन धान का उत्तर द पाना सामग्य अनुभव हा जाता। परन्तु स्थिति यह है कि इनमें न अधिका विद्यार्थी ना ना मागों का नवन नातनाका धन प्रान्त करे। नाय हा

भारत की विविध परिस्थितियों में एकमात्र यही समाधान दिखाई पड़ता है।  
बल्कि यम फ्रीस स्विटजरलैंड और रूस जैसे देशों में प्राप्त हुए अनुभव में यह  
बान सिद्ध हो रही है कि जहाँ उचित पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं वहाँ तान  
भापाएँ सीखना कोई अनुचित बोझ नहीं रहता।

भारतीय माध्यमिक शिक्षा की एक और विशेष समस्या है—विद्यालयों के  
पाठ्यक्रम में प्राविधिक (टेक्निकल) और व्यावसायिक (वोकेशनल) विषयों का  
उचित स्थान नियत करना। प्राचीन परम्परा के अनुसार भारत में व्यावहारिक  
पाठ्यक्रम की अपेक्षा बौद्धिक और अव्यक्त विषयों को अधिक ऊँचा स्थान दिया  
जाता रहा है। जातियों का ऊँच-नीच का वर्गीकरण—जिसमें सबसे ऊँचा स्थान  
ब्राह्मण को दिया गया था—इस बात का पर्याप्त प्रमाण है। भारत में शारीरिक  
श्रम के गौरव और प्रतिष्ठा को सदा पूरी तरह अनुभव नहीं किया गया। भारत  
की वर्ण-व्यवस्था के साथ अग्रजों को वर्ण-व्यवस्था के सम्पर्क का प्रभाव भी इस  
मनोबल्लि को सुधारण में सहायक नहीं हुआ। एक समय था जबकि मद्र पुरष  
उस व्यक्ति को कहा जाता था जो अपने हाथ से कोई काम न करता था।  
अग्रजों के शासनकाल में जो बिताबी शिक्षा प्रारम्भ की गई थी उसके फल  
स्वरूप पढ़-लिख लागे को यह निश्चय रहता था कि उन्हें कोई न कोई ऐसी  
नौकरी मिल जायगी जिसमें वे साफ-सफ़द कपड़े पहनकर रह सकेंगे। इसका  
परिणाम यह हुआ कि शारीरिक श्रम के प्रति उनकी अवधि और भी बढ़ गई।  
इस कारण यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है कि भारत में माध्यमिक  
शिक्षा के पुनर्गठन में प्राविधिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उपेक्षा न हो  
पाए।

उत्कृष्टतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों के चुनाव के सम्बन्ध में अपनाय  
जाने वाले सिद्धान्तों पर सभी शिक्षाशास्त्रियों को सम्भीरतापूर्वक विचार करने  
चाहिए। हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि इंग्लैंड में ग्यारह वर्ष की आयु  
बालकों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के समूहों में बाँट देना पर विन्ना ध्यान की  
रही है। भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा की सुविधाएँ आवश्यकता का तुल्य  
में दुर्लभ रूप में उपलब्ध हैं बालकों के चुनाव का प्रश्न विविध रूप से महत्व  
हो जाता है। माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी  
का एक दृष्टि से कष्ट विनोद अधिकार (प्रिविलेज) में प्राप्त हो जाना है।

हमें इस विषय में बड़ा सावधान रहना चाहिए कि यह विशेष अधिकार योग्यता के आधार पर ही दिया जाय। क्योंकि विद्याभ्यास में छात्रा के लिए स्थान बहुत कम होते हैं इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक नियत योग्यता वाले बालक उस अवसर से वंचित न रह जाए जो उन्हें प्राप्त होना चाहिये और हमारे वे बालक जो स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त हैं विद्यालयों में छात्रा के पोट-में स्थानों का घेर कर न बैठ जाय।

यह स्वीकार करना होगा कि अब तक भारत में छात्रा का समुचित चुनाव नहीं होना रहा। विद्यार्थी माध्यमिक विद्यालयों में केवल इसलिए भरती हो जाते थे क्योंकि उनके परिवार उनकी पढ़ाई-लिखाई का आवश्यक खर्चा दे पाने की स्थिति में होने थे और केवल इसलिए वे अपनी पढ़ाई माध्यमिक शिक्षा में भाग भी जारी रख पाते थे। इस प्रकार भारत ऐसे अनक लोग की सेवाभा से वंचित रहा जो पढ़-लिखकर देश के अच्छे नेता बन सकते थे जबकि उनके स्थान पर पढ़िया किस्म के लोग ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे। यह स्थिति और भी दयनीय इसलिए हो उठी है क्योंकि देश में अच्छे विद्यालयों की संख्या बहुत कम है और फिर भी इन विद्यालयों में बालका का प्रवेश केवल सम्पन्न वर्ग तक सीमित है और हम बात का ध्यान वि-कुल नहीं रखा जाता कि विद्यार्थी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता है भी या नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि राष्ट्रीय दुष्टि में हमारा अप्रत्यक्ष हाना है। बड़ि और योग्यता को पनपन का अवसर नहीं मिलता जबकि देश के स्वल्प साधना का वह भाग चान जा रहे होते हैं जो उनका पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकते। अब बिल्कुल हाल में आकर यह प्रयत्न शुरू किया गया है कि शिक्षा प्राप्त करने का अवसर योग्यता के आधार पर दिया जाय।

#### ४

अब यह बात अधिकारिक रूप में स्पष्ट हो चुकी है कि यदि माध्यमिक शिक्षा का अपना उद्देश्य पूरा करना है तो इसका सामूल-मूल पुनर्गठन करना आवश्यक है। इसीलिए कम से कम पिछले ५० वर्षों से इसका सुधार के लिए निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है। अब जाग्रत भारत की आवश्यकताओं के उपयुक्त एक समनात्मक और नये ढंग की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली तयार करने का सबसे

परिमाण नहीं किया गया था। यह परिमाण घन्ट में माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में नियुक्त किए गए लक्ष्मणस्वामी आयोग ने किया जिसने अपनी रिपोर्ट १९५३ में प्रस्तुत की।

इस आयोग ने जो अनक महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी उनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थान बहुप्रयोजन विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का दिया जा सकता है। भारतीय माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए इस सिफारिश का कितना अधिक महत्व है इन सम्बन्ध में जितना कहा जाय कम ही है। जब तक हमारे यहाँ एक विद्यालय न हो जिनमें विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था हो तब तक माध्यमिक शिक्षा अपने मुख्य लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकती। जमा कि हम पहले देख चुके हैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा दोष यह है कि यह केवल एकमुखी है। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों का कुछ कम या कुछ अधिक एक ही नमून की पट्टाई पढ़नी पड़ती है। इससे उनके विकास में बाधा पड़ती है क्योंकि यह स्पष्ट है कि एक ही ढंग की पट्टाई सबके लिए उपयोग नहीं हो सकती। छात्रों का मोट तौर पर इस ढंग से विभाजन किया जा सकता है कि कुछ छात्र ऐसे हों जिनका भविष्य व्यावहारिक विषयों की ओर होगा कुछ की रुचि गणित और विज्ञान में होगी कुछ को क्रीड़ा में किसी कला में रुचि होगी और कुछ का भविष्य साहित्य की ओर होगा। भारत में और अन्य दूसरे देशों में भी माध्यमिक शिक्षा के सामने समस्या यह है कि छात्रों के लिए विविध पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाय और साथ ही कुछ धाड़ से विषय सबका समान रूप से पढ़ाये जायें।

माध्यमिक शिक्षा वालक और यादविकाओं को उस समय प्राप्त हो रही होती है जब कि वे बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं। इस प्रकार बाल्यावस्था की गहरी अवधि माध्यमिक शिक्षा के काल में आ जाती है। बाल्यावस्था के विविध गुण कुल मिलाकर काफी स्पष्ट होते हैं और एकरूप होते हैं। इसलिए बालकों के साथ व्यवहार करना अपेक्षाकृत बड़ी सरल और निरापत्न्य है। उन्हें एक निश्चित मात्रा में ज्ञान या जानकारी दी जानी होती है और विचार तथा क्रिया के सम्बन्ध में कुछ निश्चित आन्तर्गत प्रशिक्षण देना होता है। यह प्रशिक्षणों अर्थात् तत्त्वों व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हुए भी हम अपेक्षाकृत काफी सुनिश्चित रख रख सकते हैं क्योंकि उनकी प्रान्तों और

प्रवर्तियों तुलना में अधिक पक्की हो चुका होती है । परन्तु किंगोर धातु के बालक न तो बालक ही होते हैं और न वयस्क ही । और भी अधिक परेगानों की बात यह होती है कि वे आश्चर्यजनक तीव्रता से एक और से दूसरे दौर में जा रहे होते हैं । उस समय वे ऐसे शारीरिक मानसिक और सवगात्मक परिवर्तनों में से गुजर रहे होते हैं जिनका व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हा बहुत अधिक महत्व होता है । अतः उनके साथ बड़ी सहानुभूति सावधानी और सूक्ष्म-बुद्धि से दृष्टि रक्खी जाना चाहिए । हमलिये माध्यमिक शिक्षा में प्रारम्भिक शिक्षा की पद्धतियों को जारी रखन या विविधविधानय की शिक्षा की पद्धतियों को प्रारम्भ कर देन का प्रयत्न खतरों से खाली नहीं है ।

क्योंकि किंगोरवस्था के प्रारम्भ में ही रुचियाँ और अभियोग्यताओं की विभिन्नता दिखाई पड़न लगनी है, इसलिये माध्यमिक विद्यालयों में किंगोर बालक की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था होनी चाहिए । प्रारम्भिक शिक्षा की प्रणाली काफी कुछ एकरूप रहे इसके लिए कुछ न कुछ उचित कारण बतलाए जा सकते हैं । सभी बालक को सब आवश्यक बनियानी निपुणताएँ प्राप्त करनी ही चाहिए । इसके अतिरिक्त जीवन की इस प्रारम्भिक दशा में सामान्यतया उनकी अभियोग्यताओं में कोई बहुत अन्तर नहीं होता परन्तु जब बालक बड़ होकर किंगोर बन जाते हैं तो इस परिस्थिति में अति बारी परिवर्तन हो जाता है । रुचियों और अभियोग्यताओं में अन्तर होने के साथ ही सब बालकों के लिए एकरूप शिक्षा की बात समाप्त हो जाती है । प्रत्येक किंगोर को विद्यालय में कुछ न कुछ वस्तु ऐसी मिलनी चाहिए जो उसकी सुप्त योग्यताओं को जाग्रत करके बाहर ला सके । ऐसा करन का एकमात्र उपाय यह है कि अधिकाधिक विविध प्रकार का ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाय जिसमें यह भरासा रहे कि विद्यालय के प्रत्येक छात्र को अपनी रुचि की कुछ न कुछ वस्तु मिल सकेगी ।

बहुप्रयोजन-विद्यालय की स्थापना इस विविध आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई है । वैसे तो माध्यमिक विद्यालय के सुधार की आवश्यकता हरएक हालत में होती परन्तु यह आवश्यकता इसलिये और भी तीव्र हो उठी है क्योंकि मारे देश में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए बुनियादी शिक्षा प्रणाली को लक्ष्य स्वीकार कर लिया गया है । बुनियादी विद्यालयों के छात्र शास्त्रीय

(एकैडमिक) निपुणता दूसरी सामाजिक दृष्टि में उपयोगी गतिविधियाँ के सिलसिले में ही प्राप्त करेंगे। इसलिए विविध साहित्यिक ङग की माध्यमिक शिक्षा उनके लिए उपयोग्य नहीं हो सकती। उन्हें यह भासा करने का अधिकार है कि प्रारम्भिक शिक्षा-काल में उन्हें जो सिद्धान्त सिखाए गए थे माध्यमिक शिक्षा-काल की प्रवधि में उहीको कुछ और विस्तृत रूप दिया जाएगा। छात्रों के लिए और अधिक विस्तृत ज्ञान का अवसर होना चाहिए यह हागा कि कुछ चुनी हुई दिशामा में पहले की प्रवेसा और अधिक विकास किया जा सके। केवल इस प्रकार के प्रबंध द्वारा ही किसी विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करने की जिसकी कि हम विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में भागा करते हैं एकही आधारभूत तयार की जा सकती है।

कुछ देगों में विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों की इस आवश्यकता का विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालय स्थापित करके पूरा किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका जम देग तक में भी जहाँ के लोग श्रम के गौरव को पूरी तरह अनभव करते हैं यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा हो। अनक बार ऐसा मुझसे दिया गया है कि अलग विद्यालयों में पण्डित जान वाल प्राविधिक या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कुछ हीनता की दृष्टि से देला जाता है। भारत जैसे देग में जहाँ कि पुरानी परम्परा के अनुसार बौद्धिक श्रम को शारीरिक श्रम की अपेक्षा बहीं ऊँचा माना जाता है विभिन्न विद्यालयों में अलग-अलग प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने का परिणाम यही होता कि शारीरिक श्रम के प्रति सामाजिक अरुचि और भी एकही हो जाती। शिक्षक-सबधौ कृपि-सबधौ या अन्य दूसरे व्यवसायों से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों को उसी विद्यालय में और उर्ध्व स्थाओं में व्यवस्था की जाय जिनमें विविध साहित्य-सम्बधौ पाठ्यक्रमों की व्यवस्था हो। यह बात इन दोनों प्रकार के अनुदानों के समान मूल्य के दृश्यमान प्रतीक बन सकेगी।

बहुप्रयोजन-विद्यालय इस प्रकार तिहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। उनमें विविध अभियोग्यता और रुचियों वाले छात्रों के विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था रहेगी। वे देग के कृषि-सम्बधौ औद्योगिक तथा प्राविधिक कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित और बायसम कमर प्रदान करने में भी मद्दयता देंगे और इन दोनों से भी अधिक महत्वपूर्ण

यह है कि व सामाजिक दृष्टिकोण में एक ऐसा परिवर्तन साम्य जिनमें हम के गौरव का समक्षित सम्मान दिया जायगा।

बहुप्रयोजन विद्यालयों में यह छात्रों का जाता है कि व विविध दृष्टि और अभियोग्यता वाले छात्रों के लिए माध्यमिक गिम्मा को महत्वपूर्ण और सवर्तनीय बना लें। इसी दृष्टि का पूरा करने के लिए एक और आवश्यकता यह है कि विद्यालयों में सह-पाठ्यक्रम (को-क्यूरीकुलर) गतिविधियों को बनाया जाय। इस प्रकार की सह-पाठ्यक्रम-गतिविधियों का गिम्मा पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे नए छात्रों का अनिश्चित ऊर्जा (मरजून एनर्जी) को बाहर प्रकट होने के लिए मृज्जामक माग प्रस्तुत करती हैं। ये गतिविधियाँ तत्काल व्यक्तियों को विविध प्रकार के कारीगरियों और स्तंभकारियों में प्रशिक्षण देने का माधन भी हैं। यह मान सवर्तनीय है कि व्यक्ति अपनी दृष्टि के काम को पूरा करने के लिए जिनका बहिर्नाड उठा सकता है उतनी अपने सामान्य कार्य के लिए काम नही उठा सकता। सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ धरित और ननुत्व के गणा के परिपोषण के लिए भी बन्त प्रच्छ भवमर प्रदान करती हैं। इस प्रकार उनका विद्यालय के अनुशासन पर अनुकरूपों में प्रभाव पड़ता है। अनुशासन की समस्याएँ तभी उठ खड़ा होती हैं जबकि विद्यार्थियों को उस काम में कोई नितबन्धी न हो जा उँ लिया गया है और वे पूरी तरह कायबन्त न हों। विभिन्न प्रकार की सह-पाठ्यक्रम-गतिविधियाँ उह व्यक्त रखेंगी और उन्हें मृज्जनामक आरम अभिव्यक्ति के माग निष्ठाणा और साथ ही साथ विद्यालय का मवाग्ना को मुधारण में भी महत्वपूर्ण सहायता देगा।

पारिपरिक श्रम के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की दृष्टि से बहुप्रयोजन विद्यालय के महत्व का पहल उल्लेख किया जा चुका है। पाठ्यक्रम में किसी दम्नकारी को अनिवार्य विषय के रूप में रखने का उद्देश्य भी इसी लक्ष्य को पूरा करना है। दम्नकारी पर जोर देने का लक्ष्य यह है कि पारिपरिक श्रम के प्रति विद्यमान सामान्य भ्रष्टि समाप्त हो और छात्रों में श्रम के गौरव के प्रति एक नई सम्मान की भावना परिपुष्ट हो। दम्नकारी का प्रशिक्षण दाना दृष्टि ने मूल्यवान है—गिषणात्मक दृष्टि से भी और इस दृष्टि से भी कि यह विद्यार्थी का जीवन के लिए तैयार करने में सहायता देता है। प्रारम्भिक गिम्मा



के काल में दस्तकारी के प्रशिक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से बालक में अनुभूति की सूक्ष्मता और निपुणता को परिपुष्ट करना और स्थापित करना रहता है। उसके थम द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का आधिक दृष्टि से शायद ही कोई मूल्य होता हो परन्तु माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के काम द्वारा उनकी अपनी अनेक आवश्यकताएँ पूरी हो सकनी चाहिए और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुएँ सामान्यतया समाज में स्वीकार की जा सकनी चाहिए। इस प्रकार माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में किसी दस्तकारी को सम्मिलित कर लेने से दुहरा प्रयोजन निम्न होगा। यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व को परिपुष्ट करने में सहायक होगी। साथ ही यह उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी क्योंकि यदि आवश्यकता पड़े तो वह अपनी सीसी हुई दस्तकारी द्वारा भी जीविका उपार्जन कर सकेगा।

आयोग की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों में से कुछ सिफारिशें वे हैं जिनमें विद्यालयों के पुस्तकालयों के सुधार दृश्य-श्रव्य साधनों के प्रयोग परीक्षा प्रणाली में सुधार और गतिविधि-पद्धति को उससे बड़ी अधिक बड़े पैमाने पर अपनाया जा सुझाव दिया गया है जितना कि अब तक अपनाया जाता रहा है। पुस्तकालयों को माध्यमिक शिक्षा के परिपोषण के लिए एक अत्यावश्यक साधन समझा जाना चाहिए और उनका इस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए कि जिससे छात्रों में सामान्य अध्ययन की भाँति का प्रोत्साहन मिले। दृश्य-श्रव्य साधना द्वारा अध्यापन और अधिक स्पष्ट तथा रोचक बन जायगा और इससे अध्यापक और छात्र दोनों में ही प्रारम्भ (इनिशिएटिव) की भावना परिपुष्ट होगी। यह आवश्यक नहीं है कि ये दृश्य-श्रव्य साधन विदेशों से मँगवाई गई महँगी सामग्रियाँ तक ही सीमित रहें। देशों में शिक्षा देने की पुरानी परम्परागत प्रणाली में भी दृश्य-श्रव्य पद्धतियों का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उनका उपयोग विद्यालयों में अपेक्षाकृत अधिक औपचारिक अध्यापन में किया जाय। परीक्षाओं की वर्तमान प्रणाली का बिल्कुल नया विरे स पुनर्गठन करने की द्वाारा मदद बढ़ात रूप आयोग ने यह सुझाव दिया है कि कुछ चुने हुए विद्यालयों को अपना पाठ्यक्रम अध्यापन की पद्धतियाँ और परीक्षा की पद्धतियाँ स्वयं ही नियत करने की स्वतन्त्रता दी जाय। सह-पाठ्यक्रम-नायकत्वों के प्रारम्भ किये जाने

से विद्यालय की गतिविधियों का मात्रा में स्वयं ही काफी बढ़ि हो जायगी । इसके प्रतिरिक्त विद्यार्थियों को कक्षा में होने वाले वास्तविक कार्य में भी कुछ और अधिक भाग लेना चाहिए । इसके लिए उन्हें कुछ पटल स नियन किया हुआ कार्य करने को दिया जा सकता है । या फिर उन्हें अपने अध्ययन का कार्य कम स्वयं तैयार करने की अनुमति दी जा सकती है । बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों का छोटी कक्षा के विद्यार्थियों का पठान के लिए भी उपयोग किया जा सकता है और इसके दो लाभ होंगे । एक तो यह कि अध्यापक और अध्यापित के बीच का अनुपात उपाय अन्धा हो जायगा और दूसरे सब कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय का कार्य और अधिक रोचक बन जायगा ।

लक्ष्मणस्वामी आयोग' द्वारा की गई अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विस्तार से विचार कर पाना यहाँ सम्भव नहीं । जिन लोगों को इस सम्बन्ध में रुचि हो वे आयोग की रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री पा सकते हैं । परन्तु एक और सिफारिश ऐसा है जिसका यहाँ संक्षेप में विचार रूप में उल्लेख कर देना उचित होगा । यह सिफारिश माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक वर्ष की अवधि और बढ़ा देने की है जिससे माध्यमिक शिक्षा अपने भाप में पूरा मजबूत समझी जा सके । इस सिफारिश का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा-काल की समाप्ति पर बालक की योग्यता के प्रमाण (स्टैंडर्ड) को ऊँचा उठाना है । अधिकांश बालकों का शिक्षा-काल माध्यमिक शिक्षा के साथ ही समाप्त हो जाता है । इसलिए इस बात को खूब जोर देकर कहने की आवश्यकता सायद नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा को अपने विद्यार्थियों से मुक्त एक सुनिश्चित मजबूत बनाने के प्रयत्न में कोई कमर नहीं छोड़ी जानी चाहिए । शिक्षा-काल में एक और वर्ष की वृद्धि कर देने से विद्यार्थियों को पहले की अपेक्षा अधिक शारीरिक, मानसिक और सवैचारिक परिपक्वता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा । इससे उनकी योग्यता भी बढ़ जायगी जिससे माध्यमिक शिक्षा विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त प्रमाणपत्र समझी जा सकेगी ।

यह स्पष्ट है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन रातों रात नहीं किया जा सकता । चाहे हमारा मकसद किना ही मिला क्यों न हो परन्तु यह

सम्भव नहीं है कि तुरन्त नये भग्नघोर अपेक्षाकृत विविध प्रकार के माध्यमिक विद्यालय तयार किये जा सकें। भारत में लगभग १८० माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें से लगभग १०००० उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें से लगभग सभी निरपेक्ष रूप से वास्तविक उपयोग (इक्विपमेंट) तथा जोड़ासत्रों की स्वल्पता से ग्रस्त हैं। उनमें अध्यापकों का वेतन अपर्याप्त है और ये अध्यापक भी प्रायः अल्पसंख्यक और अप्रशिक्षित हैं। इन अध्यापकों को अभीष्ट प्रमाण तक उन्नत करने का व्यय बहुत अधिक है और यह सम्भव हमारे देश के वर्तमान सामर्थ्य से परे है। यदि ये वित्तीय कठिनाइयाँ न भी हों तो भी अभीष्ट योग्यता के अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ही नहीं हैं। अपने कार्यक्रम को कई वर्षों की अवधि में फैलाए बिना इस प्रकार के अध्यापकों की भर्ती और प्रशिक्षण करवाना भी सम्भव नहीं है।

नये विद्यालयों की उन्नति एक साथ नहीं की जा सकती। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम अर्धदश के कुछ विद्यालय तयार किये जाएँ। जिस समाज में प्रजातन्त्रात्मक रहन का निश्चय किया है और जहाँ सबको समान अवसर दिया जाना है वहाँ इस प्रकार का काम उठाना सभी उचित कहा जा सकता है जब इन अर्धदश के विद्यालयों में प्रवेश केवल वाग्यता के आधार पर ही हो सके। प्रत्येक राज्य में अधिकांश लोगों का औपचारिक शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा के बान् ही समाप्त हो जाती है। अमेरिका, जर्मनी, जापान और स्विस जैसी देशों में भी मध्यम शैक्षणिक शिक्षा केवल १४-१५ वर्ष की आयु तक ही दी जाती है जबकि माध्यमिक शिक्षा वस्तुतः इस आयु से प्रारम्भ होती है। भारत के संविधान में यह लक्ष्य नियत किया गया है कि नये बालकों को केवल चौदह वर्ष की आयु तक मध्यम शैक्षणिक शिक्षा दी जाए। अभी तक वह लक्ष्य भी पूर्ण नहीं हो सका है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा कुछ छोटे-से अल्पसंख्यक लोगों का ही विषयाधिकार है। ऐसी दशा में कठिण (मुशकिल) कोटि के माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना केवल उन्नीस देशों में उचित कही जा सकती है जब कि ये परम्परागत परिवर्तनाधीन (मोर्जेन्स) के रूप में स्थापित किए जाएँ या अन्तर्लोकता सम्पूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा की विषय की मुधारन में मग्यक हों।

हाल ही में भारत सरकार ने कुछ चुन चुन विद्यालयों के मुधार में कुछ

और अधिक प्रत्यक्ष रूचि इन की आवश्यकता की अनुभव किया है। यह निश्चित किया गया है कि देश के १००० उच्च विद्यालयों में से कम से कम ५ का जुलाई १९५६ तक बहुप्रयोजन-विद्यालयों के रूप में परिवर्तित कर लिया जाय। इसका अर्थ यह होगा कि इन विद्यालयों में कुछ और अधिक अध्यापक रख जायेंगे कुछ और अधिक भवन और उपकरणों की व्यवस्था की जायगी तथा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाएंगे और इस प्रकार के विद्यालयों के पुस्तकालयों की भी काफी उन्नत किया जायगा। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि ठंड हटार अथवा उच्च विद्यालयों को पहले से उच्चतर स्तर पर माना जा प्रवेश किया जाय। इसके लिए इनमें अपेक्षाकृत अच्छे पुस्तकालयों और अच्छी प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जायगी और इनमें विज्ञान तथा अथवा व्यावहारिक पाठ्यक्रम गुरु किए जाएंगे।

देश के विभिन्न भागों में उत्तर बुनियादी विद्यालयों (पोस्ट बसिक स्कूल) की स्थापना का भी यही उद्देश्य है कि समूचे रूप में माध्यमिक शिक्षा को सुवस बनाया जाय। उत्तर बुनियादी विद्यालय अभी तक भी परीक्षाणात्मक दशा में हैं और इन विद्यालयों का सञ्चालन वे ही लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन किसी भांग के लिए समर्पित कर लिया है। अपने प्रबल आदर्शवाद के कारण नम प्रकार के अध्यापक विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं और प्रायः करते हैं कि जिसने शिक्षा के फलस्वरूप विद्यार्थियों में नई चेतना जाग उठता है। अतः उत्तर बुनियादी विद्यालयों की समस्या बढ़ती जायगी तथा तथा उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा का सहृदय की ओर पर्याप्त कम होता जायगा और ऐसे विद्यालयों में दहाता में रहने वाली विज्ञान जनसंख्या के लिए भी नतीजा तयार हो सकेगा।

एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह किया गया है कि देश में कुछ पब्लिक स्कूल स्थापित जाय और उन्हें विकसित किया जाय। जैसा कि अमेरिकन ऐल्फा न अनेक बार कहा है पब्लिक स्कूल एक आमक नाम है क्योंकि जिन विद्यालयों का पब्लिक स्कूल कहा जाता है वे एक विषय प्रकार के गैर-सरकारी विद्यालय होते हैं। सामान्यतया ऐसे विद्यालयों की स्थापना किसी एक गैर सरकारी व्यक्ति या संस्था द्वारा की गई होती है। ये विद्यालय अनिवार्य रूप से न सावस (रेजीडेंटियल) विद्यालय होते हैं और इनके छात्र जनता के अपेक्षाकृत

अधिक सोभाग्यशाली वग में से आते हैं। इन विद्यालयों के पास साधन अधिक होते हैं और इनमें स्वतंत्रता भी अधिक होती है। इसलिए ये बालकों में मनुष्य के गुणों को परिपुष्ट करने पर अधिक जोर देते हैं और अपन छात्रों को अपेक्षाकृत बड़ी अधिक सुविधाएँ प्रदान कर पाते हैं। इन सब सामा के कारण वे माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षण-बन्धो के रूप में अत्यन्त मूल्यवान सिद्ध हो सकते हैं।

कुछ समय पहले भारत सरकार ने दो पब्लिक स्कूल चलाने का निश्चय किया था जिनमें से एक उत्तर भारत में हो और दूसरा दक्षिण भारत में। उस समय इस निश्चय की जानकारी लोगों तक के एक वग न काफी आलाचना की थी। आलाचका का कथन था कि सविधान का उद्देश्य एक वगहीन समाज का निर्माण करना है। इस प्रकार के विद्यालयों को विशय सहायता देना उनकी दृष्टि में सविधान की भावना के प्रतिकूल था क्योंकि इस प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों को जीवन की दौड़ में पहले से ही काफी छूट मिल जायगी। सरकार इन आलोचकों के साथ सहमत नहीं थी। सरकार का विचार था कि क्योंकि सब माध्यमिक विद्यालयों का प्रभाव तुरन्त ऊँचा नहीं किया जा सकता इसलिए अपेक्षाकृत अच्छी माध्यमिक शिक्षा के कम से कम कुछ केन्द्र तो बनाए जाने चाहिए। इस प्रकार के विद्यालय विद्यमान होने से पुराने ढंग के बहुर विद्यालयों को एक चुनौती-नी मिलेगी और ये पब्लिक स्कूल परोक्ष रूप से माध्यमिक शिक्षा का प्रभाव ऊँचा करने में सहायक होंगे।

यह आक्षेप अवश्य सबल था कि अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएँ देना तभी उचित कहा जा सकता है जब कि वे सुविधाएँ अपेक्षाकृत अधिक योग्यता का आधार पर दी जा रही हों। इस आक्षेप का समाधान करने के लिए यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार के विद्यालयों में अर्थात् पब्लिक स्कूलों में प्रवेश माता-पिता की आर्थिक स्थिति के आधार पर न होकर बालक की योग्यता के आधार पर होना चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई विचार ही नहीं उठ सकता कि यह एक ऐसा सिद्धान्त समझा जाना चाहिए जिसका कोई अपवाद न हो। भारत में सब पब्लिक स्कूलों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि एमी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जायें जिनमें अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएँ अपेक्षाकृत अधिक योग्यता वाले बालकों को प्राप्त हो सकें। इसमें कोई मन्देह नहीं कि इस प्रकार

के सिद्धान्त का सत्काल और पूणतया क्रियान्वित करने में अनवर व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। विज्ञान भाषाओं के अनिश्चित छात्र वास्तव की साम्यता का निगम करने में भी कम कठिनाइयां नहीं हैं। विषय रूप में उन मामलों में जहाँ विद्यार्थी सीमांत रेखा के निकट हैं। फिर भी इस प्रकार की काइ पद्धति निकाली जानी चाहिए जिसके द्वारा कम से कम सर्वोत्तम बालक को उसका उचित स्थान मिल सके और जो बालक स्पष्ट रूप में अनुपयुक्त हैं उन पर विद्यालयों में स्थान न मिल सके। पब्लिक स्कूलों में शोषण के आधार पर कुछ छात्रवृत्तियां प्रारम्भ करने का उद्देश्य भी यही है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से केवल इन्होंने वंचित न रह जायें। यह कि उनके पास भाषणों का अभ्यास था।

पब्लिक स्कूलों के विरुद्ध एक और आलोचना यह किया जाता है कि ये साधारण विद्यालयों की अपेक्षा अधिक खर्चीले होते हैं। यह भी कहा जाता है कि पब्लिक स्कूल सामाजिक दृष्टि से विभाजिकार प्राप्त लोगों का एक नया वर्ग उत्पन्न करने लगते हैं। आर्थिक दृष्टि से सम्पत्तिकरित वर्ग में पब्लिक स्कूल का अधिक खर्च केवल अभी उचित ठहराया जा सकता है यदि यह सिद्ध हो जाय कि चरित्र और नेतृत्व को परिपुष्ट करने में पब्लिक स्कूल सामान्य विद्यालय की अपेक्षा बहुत स्पष्ट रूप से अधिक उत्कृष्ट हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में अब तक कोई काम उठाया जाना चाहिए कि जिससे पब्लिक स्कूल एक विभाजिकारयुक्त पथक वर्ग को जन्म न दे सके। उत्कृष्टता के सम्बन्ध में प्रतियोगिता हो सके इस बात पर कोई भी आशय नहीं कर सकता परन्तु यदि पब्लिक स्कूल केवल सम्पन्न परिवारों के बालकों के पोषण-स्थान बन जाय तो वह अवश्य शिक्षावृत्त के लिए पर्याप्त कारण होगा।

पब्लिक स्कूल पर अधिक व्यय होना सामान्य अनिवार्यता है। भारत में सामान्य माध्यमिक विद्यालय जैसा होना चाहिए उससे कहीं अधिक खर्चिया विस्मय का होता है। जिन स्थानों में लड़के अपने जीवन के ऐसे वर्ष बिताते हैं जिनमें कि उनपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है वे मकीण फिर हुए और अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले नहीं होना चाहिए। विद्यालय में उन्हें केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं मिलनी चाहिए अपितु सहकारी और नवजन्मी जीवन की कला का अभ्यास करने का अवसर भी मिलना चाहिए। इसका घय

(१) विद्यालय समाज के जीवन का प्रतिबिम्ब होता है और उसे होना भी चाहिए। इसलिए भारत में पब्लिक स्कूलों को भारतीय जीवन-मूल्य और अधिकाधिक निकट लाया जाना चाहिए। इसका यह अर्थ होगा कि पब्लिक स्कूलों के बाहरी रूप और आन्तरिक विषय-दोनों में ही परिवर्तन किया जाय। विद्यालय-जीवन के प्रमाण और प्रमाणों में काफी सादगी लाई जानी चाहिए। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन करके उन्हें इस ढंग से नया किया जाना चाहिए कि उनमें उन सब परम्पराओं और आदर्शों का समावेश हो सके जो भारतीय संस्कृति के अंग बन गए हैं।

(२) पब्लिक स्कूलों का अपने विशेष गुणों को बिना त्याग देने-दान देना भी सामान्य शिक्षा प्रणाली के अधिकाधिक निकट भी आना चाहिए। इस समय प्रत्येक पब्लिक स्कूल एक स्वतंत्र संस्था के रूप में परिपुष्ट होना चाहता है। जहाँ यह सत्य है कि विद्यालय की स्वायत्तता का बड़ा महत्व है और उसे बनाये रखा जाना चाहिए वहाँ यह भी आवश्यक है कि पब्लिक स्कूल के परस्पर और देश की सामान्य शिक्षा प्रणाली के साथ अधिकाधिक सम्पर्क बढ़ाने के उपाय लाये जाय।

(३) पब्लिक स्कूलों के विशेष गुणों और उनकी विशेषता को पहले जैसा ही बनाये रखते हुए उनपर होने वाले लोच को घटाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। यह ठीक है कि के सामान्य विद्यालयों की अपेक्षा अधिक लक्ष्मण होंगे परन्तु इन दोनों के बीच की विषमता को कम करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाना चाहिए। सादगी को अपनाते ही भी कुछ कमी घटाय होगी परन्तु व्यय और आय के बीच की खाई को कम करने के लिए अन्य उपाय भी सोचे जाने चाहिए। विद्यालय की पीसों में बढ़ि करके इस खाई का नहीं गढ़ा जा सकता क्योंकि ये पीसों इस समय भी इतनी अधिक हैं कि देश की विद्यालय बहुसंख्या के बालक अथवा भी पब्लिक स्कूलों में प्रवेश नहीं पा सकते। गांधीजी के निर्देशों से कुछ सहायता राशि अवश्य मिल सकती है परन्तु पब्लिक स्कूलों को भी बुनियादी विद्यालयों में प्राप्त हुए अनुभव से लाभ उठाना चाहिए जहाँ विद्यालय के व्यय का कुछ अंश छात्रों के दस्तकारी के काम द्वारा पूरा करने की कोशिश की जाती है। सम्भवतः पब्लिक स्कूल इस सिद्धान्त को क्रियान्वित करके लाभ उठा पाने की दृष्टि में कहीं अधिक सज्जद स्थिति में हैं।

पब्लिक स्कूला में अपने सामान्य कार्यक्रमों में ही गतिविधि को काफी स्थान दिया जाता है और योंही ही हैर-फर से इस गतिविधि का सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कामों में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पब्लिक स्कूला के छात्रों की आयु दुनिया के छोटा बालका की दस्तकारी का काम मुख्य रूप से कुछ क्षल का-या काम ही होना चाहिए परन्तु पब्लिक स्कूला में यदि इस प्रकार का दस्तकारी का काम किया जाय तो उनसे कुछ आर्थिक प्राप्ति भी हो सकती है और होनी चाहिए।

(४) सामान्यतया सभी विद्यालयों का और विषय रूप से पब्लिक स्कूला का इस सिद्धान्त का दू-यमान प्रतीक होना चाहिए कि शिक्षा का कार्य समाज में अवसर की समानता उत्पन्न करना है। यह कहा जाता है कि बालक राष्ट्र की सबसे बड़ी निधि होते हैं। इसलिए इस बात की बड़ी सावधानी रखी जानी चाहिए कि राष्ट्र की इन निधियों का उपयोग समाज के अधिकतम लाभ के लिए किया जा रहा हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक बालक का सुविधाएँ उसकी आवश्यकताओं के अनुसार मिलें और उससे उन सेवाओं का भागा भी जाय जो उसके सामर्थ्य में हैं। अथ किसी भी उपाय द्वारा मानव-सामर्थ्य का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा कदम उठान पर भा पूर्ण समानता उत्पन्न नहीं हो सकेगी और उन अर्थों में पूर्ण समानता उत्पन्न करना राज्य का कृत्य भी नहीं कहा जा सकता। अलग-अलग व्यक्तियों की रुचियाँ अभिराम्यताओं और योग्यताओं में अवश्य ही कुछ न कुछ अन्तर होता है। परन्तु राज्य का कृत्य यह अवश्य है कि वह यह देखे कि सब लोगों का समान अवसर प्राप्त हो रहा है और इस प्रकार समाज में प्रजातन्त्रात्मक सुष्ठता और कल्याण की भावना उत्पन्न करे।

## ६

मुयाय्य अध्यापका की कमी और धन के अभाव के कारण यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है कि भारतीय माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन की योजना सभी सावधानी के साथ बनाई जाय। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बाड



न इस समस्या पर कई वर्ष तक विचार करने के पश्चात् जनवरी १९५० में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया था

‘बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक योग्यताओं के सम्बन्ध में बड़ी मासधानी के साथ विचार किया है और वह सर्वसम्मति से निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचा है

(क) पहली उपाधि (डिग्री) का पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होना चाहिए और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए यूनितम आयु १७ वर्ष (१७ वर्ष) होनी चाहिए ।

(ख) १७ वर्ष की आयु में माध्यमिक शिक्षा का समाप्ति के साथ शिक्षा की समाप्ति समझी जानी चाहिए और विद्यार्थी का जीवन के लिए तैयार किया जाना चाहिए । किन्तु यह शिक्षा ऐसे प्रमाण की होनी चाहिए जो उन्हें विश्वविद्यालयों के तीन वर्ष के उपाधि-पाठ्यक्रम (डिग्री कोर्स) का अध्ययन करने में समर्थ बना सके ।

(ग) भारत सरकार से अनुरोध किया जाय कि वह उपरिलिखित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समिति नियुक्त करे जो विद्यार्थी की अन्तिम परीक्षा के लिए एक समेकित (इंटीग्रेटेड) पाठ्यक्रम तैयार करे ।

(घ) माध्यमिक शिक्षाबाल की अन्तिम कक्षा ग्यारहवीं कक्षा कहलानी चाहिए और इस कक्षा में कोई भी छात्र कम से कम १ वर्ष विद्यालय में पढ़े बिना न पहुँच सके । विद्यालय प्रणाली की ठीक-ठीक व्यवधि का निधारण अलग-अलग राज्यों में उन-उन राज्यों की सरकारों द्वारा किया जाय ।

समझ ठीक इसी दिशा में एक और प्रस्ताव पहले उपकृतपत्रियों और माध्यमिक शिक्षाबोर्डों के अध्यक्षों के एक सम्मेलन में भी जो नई दिल्ली में हुआ न पास किया गया था । बाद में उस प्रस्ताव को अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड न जनवरी के अन्त में हुए अपने पटना अधिवेशन में सर्वसम्मति से स्वीकार किया । इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की सामान्य पद्धति और प्रथम उपाधि की रचना (स्ट्रक्चर) के विषय में सब सम्बद्ध अधिकारियों में सहमति है जो आयु पिछले ४ वर्षों में पहली बार हुई है ।

यहाँ यह बात लक्ष्य की जा सकती है कि शिक्षा के जिस समूह को अन्त में गहरा राज्य-भरकारों विश्वविद्यालयों और माध्यमिक शिक्षाबोर्डों ने स्वीकार

## माध्यमिक शिक्षा का पुनगठन

किया है यह नमूना मसूदा ॥ धारा या भिन्न है जिसकी सिफारिश विश्वविद्यालय शिक्षा के मन्त्रालय में नियुक्त किए गए 'राष्ट्रावृत्तान्त-आयोग' या माध्यमिक शिक्षा के मन्त्रालय में नियुक्त किए गए 'सहमणस्वामी-आयोग' ने की थी। राष्ट्रावृत्तान्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि वर्तमान इंटरमीडियेट परीक्षा के दो ३ वर्ष का उपाधि-प्राप्तक्रम होना चाहिए। सहमणस्वामी-आयोग की सिफारिश यह थी कि इंटरमीडियेट परीक्षा का समाप्त कर दिया जाय। और ३ वर्ष का उपाधि-प्राप्तक्रम में पहले ४ वर्ष का माध्यमिक पाठ्यक्रम समा जाय।

राष्ट्रावृत्तान्त आयोग की इस सिफारिश में कि उपाधि-प्राप्तक्रम में प्रविष्ट होने के लिए इंटरमीडियेट परीक्षा पास करने की बात का बनाव रखा जाय समझना सगोचर करना पड़ा क्योंकि केन्द्रीय मलाहकार बाह्य न बसने १० वर्षों की अवधि में दो मावजनित परीक्षाएं करने के विरुद्ध ही गई यक्तिया को मनी माना। यह आम जनमन की बात है कि किसी भी मावजनित परीक्षा में कम से कम दो या तीन महीने पहले करना के नियमित बाय में विद्यार्थियों की रचि समाप्त हो जाती है और वे अपना मारा समय और शक्ति परीक्षा का तयारी में लगाने लगते हैं। इनके शिक्षा-मन्त्रालय में कुछ समय के लिए करना बन्द कर दी जाता है जिसमें विद्यार्थी परीक्षाओं की तयारी और अधिक अच्छी तरह कर सकें। इसके अतिरिक्त जब परीक्षा हो जाती है तो विद्यार्थी तान या चार महीने तक परिणाम का प्रतीक्षा करते रहते हैं। उनके बाय कम से कम एक और महीना नई कक्षा में प्रविष्ट होना और काम शुरू करने-करने बात जाना है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मावजनित परीक्षा में काम के या ३ महीने नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मावजनित परीक्षा के बोझ का प्रभाव भी विद्यार्थियों पर इसका अधिक पड़ता है कि जिन किने वे परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और इस प्रकार विषय हाकर उन्हें विधायन करना पड़ रहा होगा है, उस समय वे कोई या गम्भीर काम शुरू नहीं कर सकते। अन्तिम और पाठ्यक्रम सबसे अधिक निर्णायक युक्ति यह थी कि इंटरमीडियेट परीक्षा शिक्षा की कार्य सुस्पष्ट संक्षिप्त नहीं है इसलिए यह विस्तृत पाठ्यक्रम है और राष्ट्रीय दृष्टि में बचाने आवश्यक मात्र है।

सहमणस्वामी आयोग की इस सिफारिश में कि माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और वर्ष का समा जाय इस कारण सगोचर कर लेना पड़ा क्योंकि

भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि सब बालका का १४ वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसका अर्थ यह था कि यदि माध्यमिक शिक्षाकाल में ४ वर्ष का समेकित पाठ्यक्रम रखा जाता तो विद्यालय-स्थान की आयु बढ़कर १८ वर्ष हो जाती और विद्यार्थी सीधे से सीधे २१ वर्ष की आयु में प्रथम उपाधि प्राप्त कर सकता। लक्ष्मणस्वामी-आयोग ने स्वयं यह उल्लेख किया था कि नानका के मरनक और अध्यापक दोनों ही समान रूप से विद्यालय के शिक्षाकाल का १३ या १७ योग वर्ष से भारी बढान के विरोधी थे। जब केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए राज्य-सरकारों के प्रतिनिधियों से पूछा तो एक भी राज्य विद्यालय-स्थान की आयु को बढ़ाकर १८ वर्ष करने के लिए तैयार नहीं था। सब तो यह है कि सभी राज्यों ने यह कहा कि १३ या १७ योग वर्ष की भी विद्यालय-स्थान की आयु बनाने पर उनके विनीय तथा अर्थ साधना पर काफी भारी बोझ पड़ता।

लक्ष्मणस्वामी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा-काल की समाप्ति से पहले विद्यमान बाल अध्यापन की अवधि के प्रश्न पर कुछ स्पष्ट मांग-पान नहीं किया था। एक ओर तो इसका मुकाब था कि ८ वर्ष के प्रारम्भिक शिक्षाकाल के बाद ४ वर्ष का माध्यमिक शिक्षाकाल होना चाहिए और इस प्रकार विश्वविद्यालय-शिक्षा से पहले की शिक्षा की अवधि १२ वर्ष हो जाती थी। दूसरी ओर इस आयोग ने सितारिया की भी कि जिन राज्यों में इस समय विद्यालय-स्थान का प्रमाण पत्र १० वर्ष के अध्यापन के पश्चात् दिया जाता है, उनमें इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जाए। इस प्रकार विश्वविद्यालय-शिक्षा से पहले का शिक्षाकाल ११ वर्ष का हो जाता था। इस आयोग की ऐसी प्रत्यक्ष सिफारिशों करने का कारण यह था कि अलग-अलग राज्यों में विद्यालय की शिक्षा की संरचना अलग-अलग ढंग की है। कुछ राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ६ वर्ष का है और कुछ में ५ वर्ष का। कुछ राज्यों में माध्यमिक शिक्षा (मिडिल स्टेट) ३ वर्ष का है और कुछ में ४ या ५ वर्ष का। स्वयं माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग अवधि का है।

यह स्पष्ट था कि जब तक अलग-अलग राज्यों में ये विषयगत विद्यमान तो तब तक जब तक माध्यमिक शिक्षा में एक-रूपता को दूर एक-रूपता

स्थापित कर पाना भी असम्भव था। इसलिए एकमात्र उपाय यह प्रतीत हुआ कि यह निश्चय किया जाय कि माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति किम निश्चित आयु में हो जानी चाहिए और साथ ही वह प्रमाण भी निर्धारित कर दिया जाय जिस तक उस आयु में बालक को पहुँच जाना चाहिए। यह सत्य है कि अनन्त यूरोपियन देशों में माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति की आयु १८ वर्ष है परन्तु ऊपर बताए गए कारणों से भारत में माध्यमिक शिक्षा के बाल को बढ़ा कर १८ वर्ष की आयु तक कर पाना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त भारत में लोगों का आयुष्य-काल अपेक्षाकृत कम है और सम्भवतः भारत के लोग यूरोपियनों की अपेक्षा परिपक्व भी कुछ जल्दी हो जाते हैं। इस देश में किंगारा वस्त्रों का समाप्ति १७ या १७ योग वर्ष की आयु समझना और उसीको माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति का बिन्दु नियत करना अनुचित न होगा। सभी राज्यों में निरपवाद रूप से इसका परिणाम यह होगा कि छात्र माध्यमिक विद्यालयों में उसकी अपेक्षा नही अधिक अवधि तक रह सकेंगे जितनी अवधि तक वे इस समय रहते हैं।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अवधि में बढ़ि करने का वित्तीय कारणों से विरोध करते हैं। परन्तु यदि माध्यमिक शिक्षा को अपना उद्देश्य पूर्ण करना हो तो इस अवधि को बढ़ाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। यदि माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा की समाप्ति का एक बिन्दु बनाना है और केवल विविधालय में प्रवेश की तयारी की स्थिति नहीं रखना तो यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि इस शिक्षा-काल की समाप्ति पर अधिकांश बालक और बालिकाएँ सामान्यक काल आरम्भ करने के लिए तैयार हो सकें और प्रजातन्त्रात्मक समाज में प्रभावपूर्ण ढंग से हिस्सा ले सकें। यदि माध्यमिक शिक्षा की आयु को बढ़ाकर कम से कम १७ योग वर्ष तक न किया जाय तो माध्यमिक शिक्षा अपने उद्देश्य का अर्थात् छात्रों की अधिकांश समस्याओं को जीवन के लिए तैयार करने और कुछ पाठ्य-प्रत्यक्ष्यक छात्रों का उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार करने का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकती।

एक बिन्दुस विरोधी दृष्टिकोण से पहले-पहल एक और घासप उन राज्यों में उठाया गया था जहाँ विद्यालय का पाठ्यक्रम ११ वर्ष का था। यह कहा गया था कि इस प्रकार के राज्यों में विद्यालय की अवधि में किसी प्रकार की

वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि इन राज्यों में छात्रों का विश्वविद्यालय की कक्षाओं में भर्ती होने से पहले इंटरमीडियेट कक्षाओं में पढ़ना पड़ता है इसलिए यह युक्ति दी गई कि इंटरमीडियेट पाठ्यक्रम को समाप्त कर देन से शिक्षा के प्रमाण ऊँच होने के बजाय नाबे गिर जाएंगे। यह भासप भी एक गलतफहमी पर ही आधारित है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड न जान-बूझकर ही उस भाग पर अधिक बल दिया है जिस पर कि माध्यमिक शिक्षा समाप्त होगी और उन वर्षों की सख्या पर बल नहीं दिया जो माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ करने से पहले व्यतीत होंगे। उन राज्यों में भी अहाँ छात्रकल मट्रिक परीक्षा से पहले ११ वय विद्यालय में शिक्षा दी जाती है अधिकांश विद्यार्थी १५ या १६ वय की आयु में परीक्षा देने हैं। यह स्पष्ट है कि यदि भ्रम परिस्थितियाँ या की रखा रहे तो छात्रों की योग्यता का प्रमाण १५ या १६ वय की आयु की अपेक्षा १७ योग वय की आयु अधिक होगा। इतना ही नहीं एक माध्यमिक परीक्षा को समाप्त कर देन के फलस्वरूप विद्यालयों में काय की अधि कम से कम ६ मास और बढ़ जायगी। विद्यालय के पाठ्य विषयों की याजना कुछ और बुद्धिमत्तापूर्वक करने तथा अध्यापन का माध्यम मातृभाषा को बनाने से भी अध्यापन तथा विद्यालय के विषयों में योग्यता प्राप्त करने के सामान्य प्रमाण को ऊँचा करने में काफी सहायता मिलेगी। इन सुधारों के साथ-साथ विद्यालय त्याग की न्यूनतम आयु का बढ़ाकर कुछ ऊँचा कर देने से इस बात का निश्चय रहेगा कि विद्यार्थी कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए शारीरिक बौद्धिक तथा सवैगमक दृष्टि से अब की अपेक्षा अधिक योग्य रहेंगे।

वस्तुतः राष्ट्रावृणन-आयोग की इंटरमीडियेट परीक्षा की आवश्यकता या सहमणस्वाभावापान की माध्यमिक शिक्षाकाल की अधि के सम्बन्ध में सिफारिश का उत्संभन दीवता अधि है और वास्तविक कम है। राष्ट्रावृणन आयोग ने इंटरमीडियेट परीक्षा को बनाने रखन की सिफारिश इसलिए की थी क्योंकि उसका विश्वास यह था कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए वर्तमान इंटरमीडियेट परीक्षा से कुछ कम प्रमाण अपर्याप्त रहेगा। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिश में विश्वविद्यालय में प्रवेश की आयु उसा स्तर की रखी गई है जो वर्तमान इंटरमीडियेट की है। परंतु पाठ्य विषयों के पहले की अपेक्षा अधि भन्ने गटन और अध्यापन की पद्धतियों में सुधार द्वारा यह लक्ष्य रखा

गया है कि उतनी ही अवधि में पढ़ाई का अपना प्रमाण कुछ और ऊँचा किया जा सके। यहाँ यह कह देना उचित होगा कि इंग्लैंड या यूरोप में जा वास्तव और वास्तविक विविद्यालय में प्रवेश करने का उचित होत है उनकी योग्यता का प्रमाण १७ वर्ष की आयु में हमारी इंटरमीडियट परीक्षा के प्रमाण से कहीं ऊँचा होता है। यह मानना के लिए कोई कारण नहीं है कि हमारे छात्र यूरोपियन देशों के छात्रों का अपेक्षा कुछ कम बुद्धिमान ह। इसलिए बड़े विश्वास के साथ यह माना की जा सकती है कि पाठ्य विषयों के कुछ और अच्छे गठन तथा कुछ और अच्छे अध्यापन द्वारा हमारे युवक और युवतियाँ १७ योग वर्ष की आयु में उसी प्रमाण तक पहुँच सकेंगे जिस तक उस आयु में पश्चिमी देशों के छात्र पहुँच जाते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि लक्ष्मणस्वामी-आयान न यह मुझाव रखा था कि सर्वोत्तम माध्यमिक शिक्षा-काल की अवधि प्रारम्भिक शिक्षा के बाद ४ साल होनी चाहिए। परन्तु इन ४ वर्षों में स पढ़ाई वर्षों का बहुत कुछ जाँच-पड़ताल का ही रहेगा जिसमें लक्ष्य यह रहेगा कि छात्र की रुचियाँ और अभिमोक्षता का ठीक-ठीक पता किया जाय। परन्तु इस बात के लिए कोई कारण नहीं कि इस प्रकार की जाँच अष्टवर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा-काल के अन्तिम वर्ष में या उससे भी पहले के वर्षों में क्या प्रारम्भ न कर दी जाय? व्यक्तिगत रूप से मैं तो इस मामले में बहुत डील देन के लिए तैयार हूँ और यहाँ तक तैयार हूँ कि विद्यार्थी अपने विद्यालय-जीवन में किसी भी समय एक प्रकार के पाठ्यक्रम को छाड़कर दूसरे प्रकार के पाठ्यक्रम का अपना मके। अधिकांश विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रमों का पुनर्करण १२ या १४ वर्ष की आयु में हो जायगा। इससे जो विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे उनमें से अधिकांश इस माध्यमिक शिक्षा काल में ४ या ५ वर्ष विद्यालय में रह सकेंगे। एस छात्र बहुत याद-स हाँ जा माध्यमिक शिक्षा के लिए इस आयु से कुछ पहले या बाद में माध्यमिक शिक्षा के लिए चुन जाएंगे।

ऊपर बनाए गए कारणों से सप्ताहवार साढ़ न माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति का बिंदु १७ योग वर्ष की आयु नियत किया है और यह सिफारिश की है कि सब राष्ट्रों में विश्वविद्यालय की शिक्षा से पहले की शिक्षा को प्यार हवी कक्षा का नाम दिया जाय। परन्तु सप्ताहवार बोर्ड न असंग-असंग राज्या

में विद्यालय-प्रणाली की वास्तविक श्रवधि का प्रश्न उन-उन राज्यों की सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। यदि किसी कारण कोई राज्य ग्यारहवीं कक्षा से पहले भी विद्यालय में ११ वय की पढ़ाई जारी रखना चाहें तो वह औपचारिक शिक्षा की पाँच वय की आयु से प्रारम्भ करने ऐसा कर सकता है। परन्तु माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति की आयु और उस दशा में योग्यता का प्रमाण सबके लिए एक जैसा ही होगा। इस प्रकार की व्यवस्था कम से कम सत्रमण काल में बहुत आवश्यक है क्योंकि इस व्यवस्था द्वारा वर्तमान समय में राज्यों में विद्यमान विभिन्न प्रणालियों में सबसे कम उलट-फेर होगा। परन्तु इस बात का निश्चय करने के लिए कि विश्वविद्यालय से पूर्व की इस कक्षा में सारे देश में छात्रों की योग्यता का प्रमाण एक जैसा रहे बिल्कुल यह सिफारिश की है कि विद्यालय की अन्तिम परीक्षा के लिए एक समेकित पाठ्यक्रम एक केन्द्रीय मन्त्रिण द्वारा तैयार किया जाए और उसे सब राज्यों पर लागू किया जाए। क्योंकि यह मानने के लिए कोई कारण नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में बालक और बालिकाओं की महज योग्यता में कोई अन्तर है इसलिए माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के लिए सब जगह एक ही आयु नियत कर देना यह आशा की जाती है कि उस समय सारे देश में छात्रों की योग्यता एक समान ही होगी।

भारत में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन का कार्य एक बहुत ही गुह्यतर कार्य है। यद्यपि यह मन्त्र्य रूप में राज्य-सरकारों की जिम्मेदारी का विषय है फिर भी भारत सरकार ने इस बात को अनुभव कर लिया है कि हम कार्य को पूरा करने में उस भी प्रत्यक्ष रूप से रुचि लेनी होगी। पहले यह उल्लेख किया जा चुका है कि लगभग २०० वर्तमान विद्यालयों को उन्नत करने का निश्चय किया जा चुका है। जब यह सब २ विद्यालय भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बन चुकें तब भी वर्तमान विद्यालयों की अधिकांश सख्या मामूली उच्च विद्यालयों के रूप में रहेगी। इस प्रकार इस सत्रमण-काल में यह अन्तिम ही है कि दोनों प्रकार के माध्यमिक विद्यालय साथ-साथ चलते रहें। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र सीधे विश्वविद्यालय में तीन वय के उपाधि-प्राप्त करने में प्रथम वय में भरती होंगे। वर्तमान ढंग के उच्च विद्यालय के छात्र विश्वविद्यालयों में प्रवेश की तयारी के लिए एक और अतिरिक्त वय में

पहला। जिसमें वर्तमान व्यवस्था में कम से कम उत्पन्न करने पर एक उपाय के रूप में यह मुख्य प्रस्तुत किया गया है कि विविधविद्यालय से पूर्व का यह कक्षा उन कालों में ही लगाई जाए जिनमें इस समय दो वर्ष के इंटरमीडियेट के पाठ्यक्रम के बाद से वर्ष का उपाधि का पाठ्यक्रम रहता है। इसके लिए कम से कम इतना परिवर्तन करना आवश्यक होगा कि जहां अब दो वर्ष जमा दो वर्ष का पाठ्यक्रम है वहां एक जमा तीन वर्ष का पाठ्यक्रम कर दिया जाएगा। जिन विविधविद्यालयों में उपाधि का पाठ्यक्रम तीन वर्ष का है उनका लिए भी विविधविद्यालय में पूर्व को इस कक्षा का विद्यालय का प्रथम कालों में रखना अधिक सरल होगा।

परन्तु विचारों का एक वर्ग ऐसा भी है जो यह चाहता है कि यह अनिवार्य रूप की कक्षा विद्यालयों में ही लगाई जाए। इसके लिए उनकी मुख्य युक्ति यह है कि इस अनिवार्य रूप में जा पड़ाई होगा वह विद्यालय की शिक्षण-पद्धति के अनुसार हानी चाहिए। विविधविद्यालय में अध्यापक भी या इसमें भी अधिक छात्रों की कक्षा में भाषण देता है। विद्यार्थियों से यह भाषा की जाती है कि वे अध्यापक के भाषण में से जिन बातों को सगत् और महत्वपूर्ण समझें उन्हें स्वयं ही चुन लें। विद्यालय की अध्यापन प्रणाली में शिक्षक से यह भाषा की जाती है कि वह उसे सीपे गए सब छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देगा और उनका उचित पथ प्रदर्शन करेगा। यही मुख्य कारण है कि विद्यालयों की कक्षा में केवल सीमा या बालास छात्र रहते हैं जबकि कालों का कक्षाओं में संख्या इससे दुगुनी या त्रिगुनी तक होती है। विविधविद्यालय से पूर्व का इस कक्षा की विद्यालय में रखने के पक्ष में एक और युक्ति यह है कि यह कक्षा माध्यमिक शिक्षा-ज्ञान की सबसे ऊँचा कक्षा होगी इसलिए विद्यालय में इस पर जितना ध्यान दिया जा सकेगा उतना कालों में कदापि नहीं दिया जा सकता। इनके अनिवार्य विद्यालय में ही इस कक्षा का लगान से छात्रों में नम्रत्व के गुण परिपुष्ट होने का अधिक अवसर रहेगा और कालों में कम। परन्तु वह एक ऐसा मामला है जिसके निर्णय का भार राज्य-सरकारों पर छोड़ा जा सकता है कि वे अपने सम्बद्ध विविधविद्यालयों से विद्यालयों और कालों में उपलब्ध सुविधाओं की दृष्टि से रखकर परामर्श करने के बाद जा उचित समय में निर्णय कर लें।



## ७

वैसे तो शिक्षा की सभी स्थितियों में अध्यापक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहता है परन्तु माध्यमिक शिक्षा में कुछ ऐसी विशिष्टताएँ हैं जिनके कारण इस शिक्षा-काल में अध्यापक का कार्य और भी अधिक निर्णायक तथा महत्वपूर्ण हो उठता है। प्रारम्भिक विद्यालयों में अध्यापक के मिर पर भारी जिम्मेदारी रहती है क्योंकि वे उन्हीं सौंपे गए छोटे बालकों के परिपोषण का निर्धारित करते हैं परन्तु बालक कुल मिलाकर सत्यवादी होते हैं और शिक्षा ग्रहण करने को तयार रहते हैं। वे हर हालत में अध्यापक द्वारा बनाए अनुशासन को स्वीकार करने के लिए अधिकांश आसानी से तयार हो जाते हैं। दूसरी सीमा पर जिन्हीं विद्यालयों तथा उच्चतर अध्ययन की ध्येय संस्थाओं में विद्यार्थी अध्यापक से बहुत कुछ स्वतन्त्र हो जाते हैं। वे अपनी पढ़ाई अपने आप करते हैं और अध्यापक से केवल सामान्य पथ प्रदान और शिक्षा निर्देशन की ही आशा रखते हैं। साथ ही वे अपेक्षाकृत परिपक्व हो चुके होते हैं और अध्यापक को उन पर निरन्तर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु माध्यमिक शिक्षा-काल में छात्रों-में छात्र बालकों की-सी शिक्षा ग्रहण करने की भावना और अध्यापक पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति तो रहती नहीं और दूसरी ओर कॉलेज के विद्यार्थियों की-सी परिपक्वता और स्वाधीनता की भावना उनमें परिपुष्ट नहीं हुई होती। विद्यमान मध्यम के प्रति विद्यार्थियों का अविश्वाम उनमें भरा हाता है और वे निरन्तर विद्रोह और अमान्यता की मनोदशा में रह रहे होते हैं। उनमें जीवन का अधीर आदर्शवादी भरा हाता है और वे समार को अपने स्वप्न के अनुकूल नय सिरे से नज़र आना चाहते हैं। उनका अध्यापक या तो उनके पूजनीय नायक बन जाते हैं या फिर ऐसे अत्याचारी भयंकर जाने सगते हैं जिनके आदेशों का उल्लंघन हर हालत में किया ही जाना चाहिए। इसलिए शिक्षा की अन्य किसी भी दशा में यह बात इतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि माध्यमिक शिक्षा-काल में कि अध्यापक में नदमिता और धर्म होना चाहिए और उनमें एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए जिम्मेदारी द्वारा वे उन्हीं सौंपे गए छात्रों का उचित पथ प्रदर्शन कर सकें।

इस प्रकार के प्रयत्न में मुख्याध्यापक (हेडमास्टर) को काफी निर्णायक वक्तव्य पूरा करना होगा। विद्यालय की उत्कृष्टता और विद्यालय का वातावरण

मुख्यतया उसके व्यक्तित्व और उसकी रुचियों पर निर्भर है। यदि विद्यालय का अध्ययन सतत कायस्थम और सन्तुष्टिपूर्ण हो तो सारे विद्यालय का वातावरण सुधरा रहता है। परन्तु यदि किसी अच्छे मुख्याध्यापक का समयन प्राप्त न हो तो ऊँचस्वी और भली भाँति प्रशिक्षित अध्यापक भा चाहते हुए भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बहुत-से मुख्याध्यापक बड़े अच्छे विचारों को लेकर अपना कार्य प्रारम्भ करने हैं परन्तु महानुभूतिहीन परिष्कार (एनवायरनमेंट) और दिनचर्या का बोझ का कारण उनका प्रारम्भिक उत्साह धीमे धीमे मल पड़ता जाता है और उस अधिकांश मुख्याध्यापक विद्यालय के काम को बर्बाद गति पर चलाने रहने में ही सन्तोष अनुभव करने लगते हैं।

संज्ञानमूर्तिहीन सामाजिक पट्टभूमि के अतिरिक्त सभी अध्यापक—और मुख्याध्यापक भी इसका अपवाद नहीं हैं—उन एकरमता से ग्रस्त रहने लगते हैं जो कक्षाओं को पढ़ाने के काम में बना रहती है। विश्वविद्यालयों में कक्षा अध्यापन की यह एकरमता इस कारण अत्यंत कम हो जाती है कि वहाँ अपने ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करते जान के लिए निरन्तर प्रेरणा मिलती रहती है। परन्तु विद्यालयों में इस प्रकार का एकरमता से छुटकारा देने वाला कोई उपाय नहीं है। विद्यालयों के अध्यापक सामान्यतया विद्यार्थियों को नवनवीन ज्ञान पाने के लिए सन्तुष्ट हो जाते हैं जितना समाज की प्राचीन परम्परा (विरामन) का भंग बन चुका है। अध्यापक के काम की नवीनता बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है और फिर एक विलुप्त निर्जीव एकरमता ध्यान लगती है। एक बार जब अध्यापक को अपने काम में रुचि न रहे तो फिर वह अपने छात्रों में अध्ययन के प्रति किस प्रकार रुचि जागरित कर सकता है? और किस प्रकार उस रुचि का बनाए रख सकता है? इसलिए यह आवश्यक है कि अध्यापक को हम बड़ी दिनचर्या की एकरमता से छुटकारा पाने में और ऐसे नये अनुभव प्राप्त करने में सहायता दी जाय जिससे कि वह अपने काम को और अच्छे ढंग से कर सकें।

हम ही में भारत में हम समस्या को हल करने का एक प्रयत्न किया गया है। अध्यापक की संख्या इतनी अधिक है—माध्यमिक विद्यालयों में लगभग ७०० ०० अध्यापक हैं—कि सब अध्यापकों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रबंध करना असम्भव है। परन्तु यह अनुभव किया गया कि इस कार्य का

या और मनी निणय प्रोत्साहित कुछ थोड़-भ सोचा द्वारा किया जात थे । इसलिए उस समय समाज के लिए काम कर पाना और यहाँ तक की उन्नति कर पाना उस देश में भी सम्भव था जबकि शिक्षा और उसके फलस्वरूप होने वाला अनुभव का विस्तार सब समाज का प्राप्ति न भु हो सका । परन्तु आजकल स्थिति बिल्कुल भिन्न है । निर्णय करने का समय अब भी थोड़ा-थोड़ा के हाथ में है परन्तु इन थोड़े से लोगों को अपनी गति और अधिकार बहुमत को मनाकर ही प्राप्ति होता है भले ही यह न कहा जा सके कि वह गति और अधिकार बहुमत की स्वेच्छापूर्ण सहमति से प्राप्त होता है । सबसे अधिक शक्तिशाली अधिनायक (मानागाह) भी पूरी तरह और सबदा जनता की इच्छा के प्रतिकूल नहीं आ सकता । कुछ थोड़े-से समय के लिए और कुछ थोड़े-से विविष्ट प्रश्नों पर उसके निणय भले ही मान लिए जाए परन्तु सभी अवधि में उसकी नीति की मुख्य दिशा का निर्धारण उन लोगों के जिनके ऊपर गामन करने का बहुदावा करना है करिय और स्वभाव द्वारा ही निर्धारित होता है और होना भी चाहिए ।

इसलिए भारत जैसे देश में जिसमें अपने लिए प्रजातन्त्र को अपना जीवन पथ के रूप में अंगीकार किया है जनता की शिक्षा अव्यधिक वांछित वस्तु चाहिए । प्रजातन्त्र केवल उसी देश में सफलतापूर्वक काम कर सकता जबकि देश के सब लोगों को सामान्य समस्याओं का कुछ-कुछ ज्ञान हो और , के प्रोत्साहित छोटे-छोटे समूहों को अपने विषय का विचार और गम्भीर ज्ञान हो । ज्ञान की यह गम्भीरता नतुस्व के वर्गोत्तम में उनकी स्थिति के अनुसार ही होनी चाहिए । आधुनिक परिस्थितियों ने सामान्य और विचार दोनों ही प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता को और भी अधिक तीव्र बना दिया है । विज्ञान की प्रगति ने सारे समाज को एक परिवार के रूप में परिवर्तित करके हमारे अनुभव के क्षेत्र को अव्यधिक विस्तृत कर दिया है । साथ ही इस विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में विनाश के ऐसे माधन दे दिए हैं जिनके द्वारा मानव जाति का नाम-विज्ञान मिटाया जा सकता है । सारे संसार में लोगों में परस्पर बढ़त हुए सम्बन्धों के कारण भारतीय जनता पर एक और महान दायित्व इसलिये भी आ पड़ा है कि भारत ने प्रजातन्त्रात्मक जीवन प्रणाली को अपनाया का निश्चय किया है । यदि भारतीय प्रजातन्त्र को वास्तविक बनाना

है तो देश के सभी लोगों का भारत और सत्तार के सम्बन्ध में जानकारी होनी चाहिए ।

हम प्रायः यह समझते हैं कि प्रजातन्त्र और बगलान्न साथ-साथ नहीं रहते । परन्तु प्रजातन्त्र का यह अर्थ नहीं है और हो भी नहीं सकता कि यह सब लोगों का सामन है । अर्थात् हमका केवल इतना अर्थ होता है कि इसमें सब लोगों का सामन करने का अवसर रहता है । प्रजातन्त्र में भाई-भाई एक-दूसरे या नानाओं का एक-दूसरे दस्त हाना चाहिए जो राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न स्तरों पर नियंत्रण करने में समर्थ हो । पुराने समाज के वर्ग-आत्मक रूप में नस्ल-जनन या साम्यवाद का एक आकस्मिक संयोग मात्र हो जाता था । प्रत्येक वर्ग में यह नस्ल-अपेक्षाएँ पाई जाती थीं और सामन वर्ग के लोगों के हाथों तक ही रहता था । आज सब स्तरों तक नस्ल-अपेक्षा समाज के सब भागों के लिए खुली है । प्रजातन्त्र में सब लोगों का नस्ल-अपेक्षा करने का अवसर प्राप्त रहता है वास्तविक नस्ल-अपेक्षा प्राप्त नहीं रहता ।

प्रजातन्त्र में समाज के जीवन में शिक्षा विस्तृत रूप में व्याप्त रहनी चाहिए । इसके लिए यह आवश्यक है कि नई पीढ़ी के लिए सबजनों निःशुल्क अन्विष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाय । यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि सबजनों निःशुल्क शिक्षा की धारणा का विकास भाषा-जनता में मतभेद के विस्तार के बाद ही हुआ है । बालिका की शिक्षा अधिकाधिक ऐसी होती जा रही है कि सबसे पहले उनके लिए राष्ट्र के भाषा का उपनाम दिया जाना चाहिए । परन्तु बच्चा के बड़ा होने में समय लगता है और इस बीच के समय में समाज की घटनाएँ दृष्टि नहीं रहती । इस प्रकार उन लोगों में जहाँ शिक्षा का प्रसार नहीं है और जिन्होंने प्रजातन्त्र-आत्मक जीवन प्रणाली का अपना लिया है वे सब लोग निरन्तरता का समाप्त करने के लिए विविध कार्यक्रमों का प्रारम्भ करना आवश्यक हो गया है । केवल इसी उपाय से शिक्षा की सुविधाओं का प्रभाव के फलस्वरूप अतीत में उत्पन्न कमियाँ पूरी किया जा सकता है ।

समाज की शिक्षा के कार्यक्रमों पर विशेष रूप से बल देने का एक और भी कारण है । बालकों की अन्विष्ट सबजनों शिक्षा का बाँट मो कार्यक्रम चाहे समाज की सच्चे सहायता के बिना सफल नहीं हो सकता । राज्य शिक्षा का अन्विष्ट बनाने के सम्बन्ध में कानून पास कर सकता है परन्तु अब

सोच हम प्रकार के बानूनों को स्वीकार न करें तब तक कोई भी राज्य या पुलिस की सहायता में हम प्रकार के बानूना को लागू नहीं कर सकता। बात भी ध्यान रखन योग्य है कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए देश आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े होते हैं। ऐसी दशा में परिवार की आय में थोड़ी-सी वृद्धि ने से भी काफी फर्क पड़ जाता है और बालकों को छोटी उम्र में ही कुछ न कुछ कमाई का धंधा शुरू कर देना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में बालक को विद्यालय भेजना का निश्चय करना परिवार की धोर से जानते-बूझते कुछ बलिदान करने जसा ही होता है। यदि बच्चों को इस प्रकार के बलिदान की आवश्यकता अनुभव करानी हो तो उसके लिए वयस्क-शिक्षा का एक विभाग कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है।

२

१९४७ में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब मुद्रिकल से यहाँ की १५ प्रति जनता साक्षर थी। यदि केवल वयस्कों के ही ह्रास में होता है—तो साक्षर नियम बनाने का अधिकार केवल वयस्कों के ही हाथ में होता है—तो साक्षर लोगो की प्रतिधत्ता और भी कम थी। दूसरे शब्दों में प्रजातन्त्रात्मक गणतंत्र में जिन लोगो न प्रभुसत्ता के अधिकार पर प्रयोग करना था उनमें से ९० प्रतिशत में अपने देश और देश से बाहर की दंगाओं के सम्बन्ध में जानकारी सग्रह करने के साधन अर्थात् शिक्षा का अभाव था। साथ ही यह बात भी स्वतः मिथ है कि आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र में कुछ भी नियम बनाने के लिए इस प्रकार की जानकारी का होना अनिवार्य है। एक कहावत है कि लोगो को उसी प्रकार का शासन प्राप्त होता है जिनके बिना योग्य होत हैं। यह इतिहास का एक चमत्कार ही है कि भारत न जिसकी जनता का ९० प्रतिशत भाग विन्ध की समस्याओं से अनभिज्ञ था एवं एनी सरकार जनी जो आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील थी और विश्वशांति स्थापित करने के लिए बटिबद्ध थी। इसका एक कारण यह है कि साक्षरता के अभाव के बावजूद हमारे देश में सौवर्ण्य शिक्षा काफी व्यापक रही है जो मुख्यतया मौलिक रही है। विन्धों से भ्रान्त बाले लोग प्रायः निरक्षर भारतीयों तक में पाई जाने वाली संस्कृति की

भावना और सम्पत्तायुक्त व्यवहार का प्रसन्नकर बहुत प्रभावित हुए ॥ और जब भारतीय लोग भी इस सम्भव में विचार करने लगे तो वे भी कम प्रभावित नहीं होत। पहला दुष्टि में निरक्षरता और मस्तिष्क एक-दूसरे की विराधा जान पड़ती है परन्तु इस विरोध का समाधान तब हो जाता है जब हम यह स्मरण करते हैं कि भारत में मौखिक शिक्षा का परम्परा बहुत प्राचीन काल से बना आ रही है। पुराना प्रथाएँ प्राचीन विचारों कहावतों और कहानियाँ पुराण और स्मृतियाँ कण-परम्परा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती बना आ रही है और किसी सीमा तक उच्चान धर्मर ज्ञान द्वारा से जान जाती गिणा व प्रभाव का प्रसार कर दिया है।

इस प्रकार की मौखिक शिक्षा प्राचीन काल में व्याप्त समझी जा सकती थी जबकि उससे एक-दूसरे मनुष्य के मन में समाज में बड़ा रूपा था। मनुष्य-सम्पत्ति की कठिनाइयों के कारण प्रत्येक समाज कुछ कम या कुछ अधिक अपन-आप तक ही सीमित रहता था। उन समाजों में जो समस्याएँ बना उठ खड़ा होती थी उनका समाधान के लिए पुरानी रीतियाँ और कृतियाँ और परम्परागत विचारों पर्याप्त जान थे। आजकल जबकि प्रत्येक प्रत्येक दुष्टिकाओं और पक्ष-भूमियों वाले समाज एक-दूसरे के घनिष्ठ सम्पर्क में आ रहे हैं और उससे नित नित प्रतिक्रियाएँ एक-दूसरे जा रहा है यतियाँ और परम्परागत विचारों नई परिस्थितियों का अनुकूलता का सामना करने में और नई समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ हैं। एक बात तो यह है कि एक-दूसरे से मिलने रीतियों और विचारों के प्रभाव के कारण उनमें से प्रत्येक का प्रभाव उनके मानने वालों पर कम और कम होता जाता है। दूसरी बात यह है कि एक समाज के विचारों और प्रथाएँ, चाहे वे कितने ही बढ्दमूल क्यों न हों वे नित नित समाज के सघर्ष से उत्पन्न हुई समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। एसी स्थिति में यह आवश्यक है कि परम्परागत विचारों को विवेक का आग्रह करके बदल बनाया जाय। मौखिक शिक्षा का स्थान भी अधिकाधिक लिखित शिक्षा का देना चाहिए। मौखिक शिक्षा का बाह्य स्मृति है। आजकल लोगों की चेतना इतनी अधिक बढ़ गई है और वे इतने पथीने हो गए हैं कि केवल स्मृति उन सबका भार नहीं ा सकती। जो शिक्षा आधुनिक मनुष्य का प्राकृतिक शक्तिमा पर विचार पान में सहायता देती थी उसे आज विभिन्न सामाजिक

अक्षियों और विचारों के संपर्क से उत्पन्न समझा-प्राप्त पर विजय पान में सहायता दनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की संभव भी बढ़नी चाहिए, जिससे मनुष्य विदेशों से पान वाली नई-नई बातों को उस सीमा तक ग्रहण कर सके जहाँ तक कि वे मानव-संस्था में सहायक ह।

भारत के मौलिक से यहाँ का सामाजिक वातावरण शिक्षा के लिए सदा अनुकूल रहा है। प्राचीन भारतीय परम्परा में शिक्षा का जो मुख्य रूप से अध्यापक होता था स्थान सामाजिक बगल में सबसे ऊपर था। मध्ययुग में भी मुस्लिम मौलविया को इसी प्रकार का आदर प्राप्त था। इस समय शिक्षा को पहले जैसा ध्यान तो प्राप्त नहीं था परन्तु उसे समाज के अग्र वर्गों की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था। आधुनिक भारत में यदि कोई बात हुई है तो वह यह कि शिक्षा के लिए सामान्य साक्षरता और अधिक तीव्र हो गई है। जो वयस्क स्वयं निरक्षर ह वे भी अपने बच्चों को शिक्षा-विज्ञान और स्वयं शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्कण्ठित हैं। इस कारण प्रशासकों का कार्य काफी सरल हो जाता है। वस्तुतः भारत में स्थिति यह है कि राज्य जितनी जल्दी और जितनी शिक्षा देने की व्यवस्था कर सकता है सोच समझ कभी अधिक जल्दी और नहीं बड़ पमान पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए लागू किया है।

राजनीतिक चेतना की वृद्धि और जनता को सत्ता की प्राप्ति के साथ साथ 'सा-ज्या सब स्त्रो पर शिक्षा मे वृद्धि हुई है तथा-यों सभी क्षेत्रों में और विशेषरूप से वयस्क-शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की माँग बहुत बढ़ी है। १९३७ में लेकर बहुत कुछ प्राथमिक आधार पर और १९४८ के बाद से सम्पूर्ण राष्ट्रीय पमान पर वयस्का की निरक्षरता को समाप्त करने के लिए महान् प्रयत्न किया जा रहा है। अब निनोदिन यह भी बात स्वीकार की जा रही है कि भारत की गरीबी के मुख्य कारणों में से एक यह भी है कि यहाँ शिक्षा का अभाव है। यह कहा जाता है कि कोई भी देश प्रगति सम्पन्न या दरिद्र नहीं होता। जिस देश में देश के साथ वहाँ विद्यमान साधना का जसा उपयोग करते ह वह देश बसा हा हो जाता है। जापान जसा देश जो प्राकृतिक साधना की दृष्टि से सम्पन्न नहीं है मगर के अत्यधिक उद्योगीकृत और समृद्ध देश में से एक गिना जाता है क्योंकि वहाँ के लोग न अपने प्रयत्न में उसे बसा बनाया है। इसके विपरीत

एगिया और अमीबा व उष्ण-वटिबन्ध के देश विनाश प्राकृतिक सम्पत्ति के होने हुए भी दक्षिण और दोन दशा में पड़ है । भारताय जनता न भी इस बात का अनुभव कर लिया है कि आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक प्रगति के लिए भा व्यापक शिक्षा बहुत आवश्यक है ।

१९३७ के दशक में वयस्क शिक्षा के प्रान्तात्मकता की सफलताओं और असफलताओं का विहंगावलोकन काफी मनोरंजक और शानवधक रहेगा । प्रान्ताय स्वशासन और दहाता क्षेत्रों में मताधिकार व प्रचार के फलस्वरूप वयस्क-शिक्षा को तात्कालिक और बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला । परन्तु यह जो बहुत दूर तक बना न रह सका । अगले इसका कारण यह था कि १९३९ में दूसरा विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया । पर इससे भी बड़ा कारण यह था कि वयस्क-शिक्षा की धारणा ही अपर्याप्त थी । उस समय सारा जोर केवल सामरता पर दिया जाता था और इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था कि वयस्का और बालका की रुचियों में अन्तर होता है । इसका परिणाम यह हुआ कि वयस्का को पढ़ने के लिए जो वास्तविकता की किताबें दी जाती थीं उनमें व बहुत जल्दी ऊब उठने लगे । इसका प्रतिक्रिया यह होती थी कि वे सामरता के महत्व को बहुत कम समझने लगे । कुछ ऐसे भी कार्यक्रम तैयार किए गए जिनका उद्देश्य पढ़ाई और लिखाई के माध्यम के बिना ही वयस्कों को शिक्षा देना था । इस प्रकार के परीक्षणों की सफलता स्वभावतः सीमित ही हो सकती थी । बिना अन्तर ज्ञान के शिक्षा अतीत के सीधे-नाले जमान में उपयोगी हो सकती थी परन्तु आजकल की पेचीदा परिस्थितियों में सामरता शिक्षा का अनिवार्य भग बन गई है ।

साक्षात् विचार करने से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वयस्क-सागरता व कार्यक्रमों की अपनी कुछ खास समस्याएँ हैं । जिन लोगों ने सामरता का अभ्यास बचपन में किया होता है वे प्रायः उन विशिष्ट कठिनाइयों का अनुभव नहीं कर पाते जो वयस्क विद्यार्थी के सम्मुख उपस्थित होती हैं । बालक की स्मृतिशक्ति बहुत कुछ फाटो के कमरे जैसी होती है । उसका धनमव का कोण परिमित होता है परन्तु उसकी जिज्ञासा और उत्सुकता असीम होती है । हम लिए उसका वास्तव पढ़ना सीखना एक साहस-यात्रा जैसी और आनन्द की वस्तु होती है । वयस्क व्यक्ति इतना कुछ ज्ञान और अनुभव प्राप्त किए होता है जो



सामान्यतया उसकी अधिकांश आवश्यकताओं के लिए काफी होता है। इस प्रकार उसे घटकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई तात्कालिक प्रेरणा नहीं रहती। वस्तुतः इनके मामला में तो उसे पढ़ना सीखने के लिए अपनी जड़ता की भावत धीरे-कुछ सीखने के विषय आंतरिक विरोध पर विजय प्राप्त करनी होती है।

अक्षर ज्ञान कथन की विधि का विकास बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। बालक वयमाना का चित्र या कविता का सहारे सीखता है। अक्षर सीखने के लिए किए गए प्रयत्न का प्रतिफल उसके लिए तब और तुक मात्र (अल्पानुप्रास) प्रायः पर्याप्त रहता है। साहित्य की कहानियाँ उसकी और अधिक अनुभव प्राप्त करने की भूमिका को उसे जित करती हैं। परन्तु वयस्क के साथ यह बात नहीं है। इसलिए उनकी कठिनाइयों को हल करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय अपनाने की आवश्यकता होती है। एक उपाय यह है कि किसी अक्षर को मिलाव के लिए उन पदार्थों के नाम चुने जाएँ जिनकी भावना उस अक्षर की बनावट से मिलती-जुलती हो जिसमें वह शब्द प्रारम्भ होता है। कुछ अन्य लोगो का विचार है कि वयस्का की पढ़ाई का प्रारम्भ यदि वाक्या में न भी किया जाय तो कम शब्दों से तो अवश्य ही होना चाहिए क्योंकि उनका स्थान है कि यदि वयस्को से एक-एक अक्षर सीखने को कहा जाय तो उनका ध्यान केन्द्रित नहीं हो पाता। इन सब पद्धतियों का प्रयोग किया गया है और इनमें कहीं कम और कहीं अधिक सफलता मिली है। किन्तु अब तक प्राप्त सारे अनुभव के आधार पर इनमें से किसी भी एक प्रविधि (टेक्नीक) का दूसरी की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जा सकता। सच तो यह है कि सामान्यता सफलता का मुख्य कारण अध्यापक का उत्साह और सूझ-बूझ ही होती है।

अक्षर ज्ञान की समस्या के साथ ही सम्बद्ध एवं और समस्या वयस्का के लिए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की समस्या है। यह बात तो विनोदस्पष्ट है कि वयस्का का काम बालकों के लिए तैयार की गई पुस्तकों से नहीं चलेगा। वयस्क निरोधक भले ही हों परन्तु उनका मास्तिष्क बिलकुल परिपक्व होता है। उनकी रचियाँ और शब्दावली भी बालकों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत होती है। इसलिए उनके लिए तैयार की गई पुस्तकें गामभी की दृष्टि

से वयस्कचित्त होना चाहिए किन्तु उनमें प्रयुक्त किए गए पाठों में यथासमय समुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में भी अनेक पद्धतियों के प्रयोग किए गए हैं। अधिकांश भारतीय धनमात्राओं में समुक्त अक्षर होते हैं जो वास्तव के लिए भी सीख पान कठिन होत हैं और वयस्क नव-सामर को तो उन्हें देखकर और भी अधिक डर लगता है। कुछ पाठ्य पुस्तकों में समुक्त अक्षरों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इससे उन पुस्तकों में अधिक सचक पा जाता है क्योंकि उनमें वयस्क की रुचि के विषय भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। एक और पद्धति यह अपनाई गई है और इसमें काफी सफलता भी मिली है कि वयस्क के लिए पाठ्य-पुस्तकों के रूप में सामान्य ज्ञान या इतिहास की पुस्तकें प्रयोग में लाई जाएं। इस पद्धति का यह लाभ हुआ है कि वयस्क का अपने परिपक्व मस्तिष्क के अनुकूल सामग्री मिल जाती है और जहाँ वह पढ़ने का अभ्यास कर रहा होता है वहाँ साथ साथ उसे नया ज्ञान भी प्राप्त होता जाता है।

एक दृष्टि से वयस्कों के लिए पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण समस्या उनका लिए जहाँ में पढ़ने योग्य साहित्य उपलब्ध करने की है। बालक भी यदि अपनी पढ़ने रहने की शान्त न बनाए रखें तो कुछ समय बाद फिर निरुत्तर हो जाते हैं। वयस्क लोग भी पढ़ना-लिखना भूल जान की यह प्रवृत्ति और भी अधिक होती है इसलिए वयस्क के पढ़ने के उपयुक्त साहित्य की रचना को अत्यधिक अग्रता (प्रायोरिटी) दी जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि इस प्रकार का साहित्य उच्चकटि का हो। यह ठीक है कि राज्य इस प्रकार का साहित्य तैयार नहीं कर सकता परन्तु वह ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में सहायता प्रदान कर सकता है जिनमें कि स्वयं और उत्कृष्ट साहित्य की अधिकाधिक बिक्री हो सके।

अनुभव और वयस्क-शिक्षा के विषय पर अधिकाधिक विचार के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वयस्क-शिक्षा की एक नई धारणा सामने आई है। इस धारणा में यह स्वीकार कर लिया गया है कि यदि वयस्क-शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाना है तो वयस्कों की विभिन्न रुचियों को पूरा सुलभ करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत एक पञ्चमूनी कार्यक्रम में निहित है जिसका उद्देश्य वयस्क की आवश्यकताओं को यथासम्भव अधिकतम रूप में पूरा करना

है। इस कार्यक्रम में पाँच वस्तुओं—(१) साक्षरता (२) स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान (३) वयस्कों के आर्थिक स्तर का उन्नत करने का प्रशिक्षण (४) अपने कृत्यों और अधिकारों के प्रति सजगता के साथ-साथ नागरिकता की भावना और (५) समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुकूल मनोरंजन के स्वस्थ रूपा का ज्ञान देने की व्यवस्था की गई है। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उन सब सामानों की सहायता भी गई है जो आधुनिक विज्ञान द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्ति को समाज का पहले की अपेक्षा एक अच्छा सदस्य बनाना है और साथ ही साथ सारे समाज के जीवन के स्तर को ऊँचा करना है इसलिए पुराने केवल साक्षरता के कार्यक्रमों में जोड़ करके लिए इनका नाम समाज-शिक्षा रखा गया है।

इस प्रकार समाज-शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि यह वह पाठ्यक्रम है जिसके द्वारा लोगों में नागरिकता की घटना उत्पन्न की जाती है और उनमें सामाजिक सुसंगठितता (सोसियलिटी) की भावना की वृद्धि की जाती है। समाज शिक्षा बड़ी आयु के लोगों को केवल भ्रष्ट ज्ञान कराकर ही संतुष्ट नहीं हो जाती बल्कि स्वयं सभ्य सामान्य जनता में एक सुशिक्षित मन का निर्माण करना चाहता है। इसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में समाज-शिक्षा का लक्ष्य यह रहता है कि लोगों में व्यक्तिगत रूप में और समाज के एक सदस्य के नाते अपने अधिकारों और कृतव्या की सचेष्ट भावना उत्पन्न की जाए।

### ३

स्वतंत्र भारत को सारे देश में फैली हुई वयस्क-निरक्षरता की बाधा पर विजय प्राप्त करनी है। इस का जनता के अधिकारों में पहुँचने की अपेक्षा अधिक अच्छा जीवन बिताने की भाषाशा भी उत्पन्न की जाती है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अभी बिल्कुल हाल तक भी हमारे अधिकांश गाँव मृतप्राय थे। मिथान—और यही भारतीय जनता का आधुनिक शिक्षा भाग है—वर्तमान में बिना किसी सुविधा के, और अधिक के लिए बिना किसी भाग के जीवन बिताता था। अनवरत बार तो उसे इस बात का मान तक भी नहीं होता था कि उसकी वर्तमान दशा में कोई सुधार हो सकता है। भारत के चार प्राचीन भाग में विश्वास और समझ के सिद्धान्त के कारण उसने

उन परिस्थितियों के साथ भी कुछ समझौता-सा कर लिया था जो कभी-कभी तो झगड़ा हो उठती थी।

लोगों की राजनीतिक गति में वृद्धि हान के साथ गाँवा में एक नई जागृति प्रारम्भ हुई। मतदाधिकार का दहाती दावा में प्रसार होने का परिणाम यह हुआ कि गाँवा में वे लोग भी ध्यान भग जिनकी गतिविधि पहले केवल बाहरा तक ही सीमित रहती थी। जब गराब और निरन्तर क्रिमान न देखा कि तथा कथित समाज के बड़े लोग उनके दरवाज पर याचक बनकर आते हैं तो उनके मन में आत्मगौरव का एक नई भावना परिपुष्ट होन लगी। यह ठीक है कि गुरु-गुरु में उन अपने मतदाधिकार के महत्व का पूरा पान नहीं था और कुछ लोग तो मत का एक विनम्र-नाम्य पनाय तक भी समझन । और अधिक से अधिक जो बीमल मिल सकें उनसे बच्चे अपना मत दे दन थे। परन्तु अब वह किसान इन बातों को अविकाशित समझना जा रहा है कि मतदान का अधिकार केवल एक विभागाधिकार ही नहीं है बल्कि यह एक उत्तरदायित्व मा है। १९४७ के बाद और विंगप रूप में पिछले तीन वर्षों में जनता के सना वगैरे में सावजनिक चेतना बहुत अधिक जाग उठी है। १९४८ में समाज निष्ठा की जो नई धारणा बनाई गई था वह इसी परिपुष्टि की प्रत्यागा (एगीति वेधन) मात्र थी।

समाज-निष्ठा की इस नई धारणा की महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है— नागरिकता का भावना का परिपोषण (इवलपमेट)। इसके लिए यह आवश्यक है कि लोगों का अपने देश के इतिहास और भूगोल का और इस देश का सामाजिक दशाभा का पान हो। इस धारणा में यह भी निहित है कि उन्हें राज्य की काम प्रणाली का और विंगपरूप से अपने मन भयान् बोट के अर्थ और मूल्य का ठाक-ठीक ज्ञान हो। मन को एक विनम्र-नाम्य पनाय समझन की गुरु-गुरु की प्रवृत्ति के स्थान पर एक यह नई चेतना उत्पन्न करनी होगी कि यह मत एक उत्तरदायित्व है और व्यक्ति की नागरिकता का प्रतीक है। किसी भी प्रजातन्त्रात्मक समाज में नागरिकता का अर्थ जनता की प्रमुखता में हिंसा लेना होता है। इसलिए मन (वोट) उम प्रमुखता में व्यक्ति के भाग का प्रमाण है।

मह स्पष्ट है कि सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में

इस प्रकार की शिक्षा स्थानीय स्वाशासन की कार्यविधि के तान में प्रारम्भ होनी चाहिए। यही कारण है कि समाज शिक्षा के सब कार्यक्रमों में इस बात पर बड़ा बल दिया गया है कि नागरिक का अपने अधिकारों और कर्तव्यों का तान केवल राज्य के सम्मुख के रूप में ही न कराया जाय अपितु उन अनन्य छोटे छोटे समुदायों के सदस्य के रूप में भी कराया जाय जिनमें राज्य समीक्षित है। १९५० के बाद सामुदायिक विकास-परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कही जाने वाली गतिविधियाँ का बड़ा विकास हुआ है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में तन्मय यह है कि किसी एक समूह देहाती-क्षेत्र का उन अनन्य सेवाओं में व्यवस्था करके विकसित किया जाय जो अब तक केवल शहरों में ही उपलब्ध थीं। राष्ट्रीय विस्तार-कार्यक्रम का लक्ष्य भी इसी प्रकार की सेवाओं की व्यवस्थापन के कुछ छोटे पैमाने पर करना है और इस सामुदायिक परियोजना के अन्तर्गत कुछ छोटे पैमाने पर करना है। जहाँ इन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और पथप्रदर्शन दिया जाता रहा वहीं मध्यम से इस बात पर बल दिया गया कि इसे पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित किया जाय। इसके फलस्वरूप उन क्षेत्रों में नरत्व और पहल करने (प्रारम्भ) का गतिविधि जाग्रत हो जाती है। यह प्रस्ताव दिया गया है कि समाज शिक्षा के सब कार्यक्रमों को इन राष्ट्रीय विस्तार-सेवाओं के साथ सम्बद्ध कर दिया जाय जिससे औमत नागरिक के लिए नागरिकता की शिक्षा वास्तविक और ठोस बन सके।

राष्ट्रीय विस्तार-सेवाओं का यह अर्थ है कि जनता के जीवन के स्तर को ऊँचा करने के लिए सब दिशाओं में पूरा प्रयत्न किया जाय। १९४८ में नई धारणा को स्वीकार कर हमने के बाद समाज-शिक्षा का भी यही उद्देश्य रखे हैं। इसमें यह निष्पत्ति निकलती है कि समाज-शिक्षा के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धान्तों की शिक्षा के साथ-साथ जिसमें निम्न श्रम और स्वस्थ जीवन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए अधिक उन्नति के उपायों के प्रणिधान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए समाज के पाम बहुत अधिक साधन होने की आवश्यकता है। इसलिए समाज शिक्षा दस्तकारियाँ की शिक्षा के लिए सुविधाएँ का प्रयोग करना चाहती है जिससे स्वास्थ्य-सुधार के लिए आवश्यक

सम्पत्ति का उपाजन समाज कर सब । क्योंकि भारतीय जनता का एक विमान भाग जीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहना है । इसलिए समाज-निष्ठा श्रमि का जन्मति पर विषय रूप में ध्यान दे रही है । समाज-निष्ठा का प्रयत्न यह भी है कि जिन दिना भारतीय किसानों को विषय हाकर खाली रहना पड़ता है उन निम्ना उन्हें कुछ उपायोगी धन करने का भाग निम्नाया जाय । देशान्तों में काय क लिए पर्याप्त ऋण नहीं मिल सकता इसलिए धाम में न भा रह यम और अप्रुण आवश्यकताओं को मिलाकर समाज की सम्पत्ति में वृद्धि करम का प्रयत्न किया जा रहा है । एक शब्द में कहा जाय तो समाज-विज्ञा औरत नागरिक का पूणत और स्वतन्त्रन जीवन बितान का भाग प्रदान करन वाला गणिताली साधन है ।

यहाँ इतना और कह देना उचित होगा कि समाज निष्ठा का वास्तविक उद्देश्य निरक्षर ब्यक्त्त लोगों में मुक्तिमिन् मन का निर्माण करना है । निष्ठा पर इस प्रकार बन मन स यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किस्तिए केवल सागरता का पपात्र नहीं समझा गया । हाल क निम्ना में हमारे सामन ऐसे निम्ना और जातिया के उपाहरण आए ह जो धनर नान की दृष्टि स ता बहुत प्राग बड़ी हुई ह परन्तु जाताय या बर्गीय पपापान के कारण जिनकी निष्ठा अप्रुण रही है । आज भी ससार में ऐसे धनर क्षत्र ह जिनमें धनर नान ता बहन है परन्तु लोगों की ससृति उमम बहुत पटिया है जमी हानी चाहिए और जमी हो सकती है । ससृति के इस प्रकार क धभाव का एक रूप मन मनीवर पत्रनारिता की हानी हुई वृद्धि में सम्त दग के साहित्य की रचना में तथा अपरिपुन और साम्य दग की फिल्मों क प्रदशन में प्रकट हाना है ।

सागरता और ससृति का धभाव—इन दोनों का साय-साय रह सकता मुख्यरूप म इमा युग में पाया जा रहा है । ऐसी स्थिति कबल उमी समय उत्पन्न हा सकती है जबकि समाज क मनोरंजन की आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान न निम्ना गया हा । धौधार्गिक क्रान्ति की सफलता का धय मुख्यरूप मे धम के विनाजन क सिद्धान्त को था जिनके फलस्वरूप बस्तुओं क उत्पादन में धानयजनक बढि हो गई । इसके फलस्वरूप इस सिद्धान्त का जीवन के सामना पर भी मागू करन का प्रोत्साहन मिमा और इसका परिणाम यह हुआ कि मनोरंजन और काय दाना में बहुत स्पष्ट धन्तर हा गया । परन्तु मनोरंजन

इस प्रकार की शिक्षा स्थानीय स्वशासन की कार्यविधि के ज्ञान से प्रारम्भ होनी चाहिए। यही कारण है कि समाज-शिक्षा के सब कार्यक्रमों में इस बात पर बड़ा ध्यान दिया गया है कि नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही न कराया जाय अपितु उन जनक छोटे छोटे समुदायों के सभ्य के रूप में भी कराया जाय जिनमें राज्य संगठित है। १९५२ के बाद सामाजिक विकास-परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कही जाने वाली गतिविधियों का बड़ा विकास हुआ है। सामाजिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि किसी एक समूह देहाती-क्षेत्र का उन जनक सेवाओं की व्यवस्था करके विकसित किया जाय जो अब तक केवल शहरों में ही उपलब्ध थी। राष्ट्रीय विस्तार-कार्यक्रम का लक्ष्य भी इसी प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था अपेक्षाकृत कुछ छोटे पैमाने पर करना है और इसे सामाजिक परियोजना की ओर पहला कदम समझा जा सकता है। जहाँ इन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और परामर्श दिया जाता रहा वहाँ मुख्यरूप से इस बात पर ध्यान दिया गया कि इसे पूरा करने के लिए स्थानीय लोग का प्रोत्साहित किया जाय। इससे फलस्वरूप उन क्षेत्रों के लोगों में उत्साह और पहल करने (प्रारम्भण) की शक्तियाँ जाग्रत हो जाती हैं। यह प्रस्ताव किया गया है कि समाज-शिक्षा के सब कार्यक्रमों को इन राष्ट्रीय विस्तार-सेवाओं के साथ सम्मिलित कर दिया जाय जिससे औसत नागरिक के लिए नागरिकता की शिक्षा वास्तविक और ठान बन सके।

राष्ट्रीय विस्तार-सेवाओं का यह अर्थ है कि जनता के जीवन के स्तर को ऊँचा करने के लिए सब दिशाओं में पूरा प्रयत्न किया जाय। १९४८ में मई धारणा को स्वीकार कर लेने के बाद समाज-शिक्षा का भी यही उद्देश्य रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज शिक्षा के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य के सिद्धान्तों की शिक्षा के साथ-साथ जिसमें कि स्वच्छ और स्वस्थ जीवन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए अधिक उन्नति के उपायों के प्रदर्शन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए समाज के पास बहुत अधिक साधन होने की आवश्यकता है। इसलिए समाज शिक्षा दस्तकारियाँ की शिक्षा के लिए सुविधाओं का प्रबंध करना चाहती है जिससे स्वास्थ्य-मुद्दों के लिए आवश्यक

सम्पत्ति का उपाजन समाज कर सके। क्योंकि भारतीय जनता का एक विशाल भाग जाविका के लिए भूमि पर निर्भर रहता है। इसलिए समाज-शिक्षा कृषि की उन्नति पर विशेष रूप में ध्यान दे रही है। समाज-शिक्षा का प्रयत्न यह भी है कि जिन दिना भारतीय किसानों को विवश होकर खानी रहना पड़ता है उन दिना उन्हें कुछ उपयोगी धंधे करने का माग दिया जाय। देहाना में काय के लिए पर्याप्त ऋण नहीं मिल सकता इसलिए काम में न आरंभ और अधूरा आवश्यकताओं को मिलाकर समाज की सम्पत्ति में वृद्धि करने का प्रयत्न किया जा रहा है। एक शब्द में कहा जाय तो समाज-शिक्षा औसत नागरिक को पूणत और स्वतन्त्र जीवन बिताने का ज्ञान प्रदान करने वाला शिक्षणाली साधन है।

यहाँ इतना और कह देना उचित होगा कि समाज-शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य निरंतर वयस्क लोग में सुनिश्चित मन का निर्माण करना है। शिक्षा पर इस प्रकार बल देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिसलिए केवल साधरना का पयाप्त नहीं समझा गया। हाल के दिना में हमारे सामने ऐसे दगा और जातिया के उन्नाहरण आए हैं जो अक्षर ज्ञान की दृष्टि से तो बहुत आगे बढ़ी हुई हैं परन्तु जातीय या वर्गीय परपात के कारण जिनकी शिक्षा अधूरी रही है। मात्र भी समाज में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें अक्षर ज्ञान तो बहुत है परन्तु लोगों की मस्तिष्क उमस बहुत घटिया है जमी हानी चाहिए और जमी हो सकती है। मस्तिष्क के इस प्रकार के अभाव का एक रूप सन सनाखेड पत्रकारिता की होती हुई वृद्धि में सस्त डग के साहित्य की रचना में तथा अपरिपुष्ट और ग्राम्य डग की शिक्षा के प्रदान में प्रकट होता है।

माधुरता और मस्तिष्क का अभाव—इन दोनों का साथ-साथ रह सकना सम्पूर्ण में इसा यग में पाया जा रहा है। ऐसी स्थिति केवल उसा समय उत्पन्न हो सकती है जबकि समाज के मनोरजन की आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान न दिया गया हो। औद्योगिक क्रान्ति की सफलता का थय मस्तिष्क के थम के विभाजन के सिद्धान्त का था जिसके फलस्वरूप वस्तुओं के उन्नाहन में आवश्यकतक वृद्धि हो गई। एक फलस्वरूप इस सिद्धान्त का ज्ञान के सामाना पर भी लागू करने का प्रोत्साहन मिला और इसका परिणाम यह हुआ कि मनोरजन और कार्ये दाना में बहुत स्पष्ट अन्तर हो गया। परन्तु मनोरजन



और काय, दोनों एक ही जीवन के अलग अलग रूप हैं और उन दोनों को इस प्रकार पुनर्क कर पाना सम्भव नहीं है। जितना ही अधिक समाज काय की चिन्ता में लगता गया उतना ही अधिक व्यक्ति को मनोरंजन और आनन्द प्रमाद की दृष्टि से अपने माधनों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता गया। १९३७ में भारत में वयस्क-शिक्षा के कार्यक्रमों में प्राप्त अनुभव से यह बात सिद्ध हो गई कि यदि मनोरंजन को मुख्य केन्द्र में बनाया जाय तो वयस्क लोग निरक्षरता को समाप्त करने के प्रयत्न से बहुत जल्दी ही थक जाते हैं। मनोरंजन के द्वारा जसा कि इससे नाम से ही स्पष्ट है मनुष्य अपने अवकाश के समय का उपयोग इस रूप में कर सकता है कि फिर जब वह अपने काम पर लौटे तो उस समय वह बिल्कुल तरोताजा हो। इस प्रकार समाज-शिक्षा की समस्या बड़े धनिष्ठ रूप से अवकाश की समस्या में तब खाली छट्टी के समय के साथ जुड़ी हुई है। अतीत में अवकाश या खाली समय केवल थोड़े-से ही लोगों का विशेषाधिकार था। उन थोड़े से लोगों को अपने इन विनाशकारक का उचित ढंग से उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता था और उन्हीं लोगों ने मानवीय कला की अनन्त श्रद्धा कृतियाँ का सृजन किया है। परन्तु आज सबके लिए अवकाश प्राप्त कर पाना सम्भव है। किन्तु अनन्त लोग यह नहीं जानते कि इस अवकाश का उपयोग किस तरह किया जाय। सुशिक्षित मन की परिभाषा इस रूप में की जा सकती है कि सुशिक्षित मन वही है जो अपने अवकाश को सृजनशील ढंग से उपयोग कर सके।

समाज शिक्षा के कार्यक्रमों में कला साहित्य संगीत नृत्य तथा अन्य सृजनशील गतिविधियों का माध्यम से भावनाओं का प्रशिक्षण करने का यत्न किया जाता है। इस प्रकार का साहित्य तैयार करने का भी यत्न किया जा रहा है जिससे सहिष्णुता सदभावना और आवश्यकताओं को कम करने की प्राचीन भारतीय परम्परा को बनाए रखने में सहायता मिले किन्तु साथ ही उस प्रकार की कठोरता में रहे जसी कि भारत में बाद में चलकर उत्पन्न हो गई थी। साहित्य मूल्य नाटक और संगीत तथा दृश्य कलाओं के क्षेत्र में स्वायत्त (ओटोनामस) अकादमियों की स्थापना के द्वारा साथ यह प्रयत्न कर रहा है कि सब प्रकार के कलाकारों को अपनी सृजनशील आत्म-प्रतिबिम्बित के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। नव-साक्षर व्यक्तियों के लिए साहित्य-सृजन

की आवश्यकता की ओर कलाकारों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए विद्यार्थियों की धारणा की गई है। इस प्रकार के पुरस्कारों के लिए पुस्तकों का चुनाव राज्य के अधिकारी नहीं करते अपितु साहित्यकारों और समाजिकता की समितियाँ करती हैं जिनका सिफारिशों निरूपण रूप में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वीकार कर ली जाती है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि धन-धन में स्वतंत्र एक नेशनल बुक ट्रस्ट ( राष्ट्रीय पुस्तक-यात्रा ) की स्थापना की जाय जो भारत तथा अन्य देशों के श्रेष्ठ साहित्य के सशुद्ध सम्बर्ण प्रकाशित करे अथवा प्रकाशित करने में सहायता दे और साथ ही उन सब विषयों पर जिनमें किसी प्रकार का देश के नागरिकों को रुचि हो सकती है मौलिक पुस्तकों प्रकाशित करे या लेखकों का प्रबोध करे।

भारत का सारा इतिहास ही विभिन्न जातियों विभिन्न दृष्टिकोणों और विभिन्न परम्पराओं में परस्पर मिल-मिलाप करने के प्रयत्नों से भरा है। आधुनिक संसार में परस्पर मेल-मिलाप की यह प्रवृत्ति इसलिए और भी अधिक आवश्यक हो गई है क्योंकि विविध राष्ट्रों और देशों के लोग एक-दूसरे के सम्पर्क में आ रहे हैं। इसलिए समाज-शिक्षा के सभी कार्यक्रमों में मानवीय आनुवंशिक और सवर्णनीय सन्तानों के सिद्धान्तों पर विशेष बल दिया जाता है। इस बात पर भी अधिक जोर दिया जाता है कि प्रजातन्त्र शासन में आपसी मतभेदों के प्रति सहिष्णुता की आवश्यकता होती है।

जमा कि पहले कहा जा चुका है बालकों की शिक्षा में तब तक प्रगति नहीं हो सकती जब तक कि वयस्क लोगों का प्रयत्न भी उनके साथ-साथ न हो। दूसरी ओर समाज-शिक्षा की प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उनके समाज की सामान्य शिक्षात्मक गतिविधियों से अनिलुप्त सम्बन्ध न हो। इसलिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि समाज-शिक्षा के सारे कार्यक्रमों में विद्यमान विद्यालयों द्वारा ही क्रियान्वित कराए जाएं जिससे विद्यालय सामाजिक जीवन के केंद्र बन जाए। इस सम्बन्ध में सगमय सभी लोग सहमत हैं कि जनता की समाज-शिक्षा की नई प्रेरणा देने के लिए मुख्य उपकरण के रूप में विद्यालय के अध्यापकों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

४

समाज-शिक्षा के इन मोटे आदर्शों को सभी राज्या ने स्वीकार कर लिया है। किन्तु यह स्वाभाविक ही था कि इस कार्यक्रम का शिथिलान्वित करने हुए कोई राज्य किसी एक पहलू पर बल दे और कोई दूसरे पहलू पर। इस समय भी कुछ राज्या में मुख्यरूप से साक्षरता पर ही जोर दिया जा रहा है किन्तु दूसरी ओर एक या दो राज्य ऐसे भी हैं जहाँ समाज शिक्षा पुरानी परम्परागत मौखिक पद्धतियाँ से ही दी जा रही है। अनन्त आधुनिक दृश्य-श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करने का भी प्रयत्न हो रहा है और यद्यपि ये साधन भले ही भिन्न हों किन्तु दृश्य-श्रव्य उपकरणों के प्रयोग का सिद्धान्त गतान्वियों के अनुभव पर आधारित है। पहले बताया जा चुके कारणों से आधुनिक जगत् में केवल मौखिक परम्परा पर आधारित शिक्षा पर्याप्त नहीं समझी जा सकती। अनुभव से सब राज्य धीरे-धीरे यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें अपने शिक्षा के कार्यक्रमों में साक्षरता की अधिक महत्व देना चाहिए।

इस क्षेत्र में एक मनोरंजन विकास दिस्ती राज्य में गिगा-कारवाँ (एडू केमनल करावान) के रूप में हुआ है। ये कारवाँ तीन या चार जीप माटर गाड़ियों में बन जाते हैं जिनके पीछे एक एक मोटर-उत्सा लगा होता है या नहीं भी लगा होता। इस प्रकार के कारवाँ में एक गाड़ी में चलता फिरता रंगमंच होता है दूसरी में एक छोटा-सा चलता फिरता पुस्तकालय होता है तीसरी में एक प्रदर्शनी होती है और एक चौथी गाड़ी में मिन्या का प्रोजेक्टर (प्रक्षेपक) लगा होता है। यह कारवाँ किसी ऐसे गाँव में जाता है जिनके पास पाल और बहुत-से गाँव बस हुए हों और वहाँ स्वास्थ्य तथा आरोग्य तथा वृद्धि एवं उद्योग से उत्पन्न वस्तुओं की एक समुक्त प्रदर्शनी का आयोजन करता है। शारीरिक व्यायाम के खेल और दंगल और कबड्डी के साम्प्रदायिक जिनमें बालक और बयस्क दोनों ही भाग लेंगे हैं स्थानीय लोग की उत्सुकता का जगान में सहायक होते हैं। स्थानीय लोग की प्रतिभा की सहायता में नाटक भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इन नाटकों में सामान्यतया किसी स्थानीय समस्या पर प्रकाश डाला जाता है और गाँव वालों की शिक्षा का महत्व समझाया जाता है। जब शिक्षा-कारवाँ अपनी प्रदर्शनियाँ आयोजित करके प्रकाश के प्रदर्शनों और प्रति

शिक्षाशास्त्र द्वारा शोभा में समाज-शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न कर चुकना है तब ही या तीस अध्यापक का एक दल जिसमें पुरुष और स्त्रियाँ दोनों हों होंगे उस प्रदेश में चार या छह सप्ताह के लिए जाता है। वे यथासम्भव अधिक अधिक संख्या में पुरुषों और स्त्रियों के लिए समाज-शिक्षा की कक्षाएँ सगठित करने हैं। इस प्रकार निरक्षरता के गढ़ की दीवार तोड़ दी जाती है। जब यह दल वापस लौट जाता है तब स्थानीय अध्यापक काम को समाप्त करने हैं और कार्यक्रम को जारी रखते हैं। सामान्यतया तीन या छह महीने के बाद साक्षरता के प्रमाणपत्र दे दिए जाते हैं।

मिन्नी राज्य का लक्ष्य यह है कि १९५७ के अंत तक चालीस वर्ष या उससे नाबालक की आय वाले बच्चों में से ५ प्रतिशत का साक्षर कर दिया जाय। जब यह कार्यक्रम १९५० में प्रारम्भ हुआ उस समय साक्षरता केवल १ प्रतिशत थी। इसलिए यह लक्ष्य बहुत नीचा नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः हम लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी उनकी अपेक्षा वहीं अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है जितना कि अब तक किया जा रहा है। स्थानीय अध्यापक अपनी ओर से यथाशक्ति अधिकतम कार्य कर रहे हैं परन्तु उनकी संख्या इतनी भी नहीं है कि वे शिक्षा चाहने वाले बच्चों की आवश्यकता को भी पूरा कर सकें। इसलिए समाज शिक्षा का यह लक्ष्य अभी पूरा हो सकता है जब हम क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हो जाय। यह वृद्धि अभी हो सकती है जब विश्वविद्यालय और उच्च विद्यालयों की ऊँचा बग्यानों में पढ़ने वाले छात्र समाज-शिक्षा के कार्य का अपना शिक्षा के कार्यक्रम का ही एक अंग समझकर हम क्षेत्र में सामन आए।

मध्यप्रदेश में समाज-शिक्षा के लिए बनाए गए कार्यक्रम का भी विवरण इस उल्लेख कर देना उचित होगा। १९४८ से ही राज्य-सरकार निरक्षरता को दूर करने और जनता की प्रज्ञान-प्राप्तिके समाज में उसका (जनता के) ऊपर मानवात्मक जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में सचेत करने के लिए औरतों को प्रोत्साहित कर रहा है। इस सम्बन्ध में पाठ्यक्रम उपरिलिखित ढंग का ही है। परन्तु मध्य-प्रदेश के कार्यक्रम की विशेषता यह है कि वहाँ अध्यापकों पर व्यवस्था-शिक्षा के कार्य का दायित्व डाल दिया गया है। मध्यप्रदेश ही पहला राज्य था जिसने भारत में बहुप्रयोजनी समाज-शिक्षा के लिए गिनमा-भाडिया का पहले-पहल

उपयोग करने चलते फिरते विद्यालयों की कल्पना को साकार किया। सामुदायिक रूप से सुनने के लिए रेडियो सटो का भी काफी बड़ा प्रयोग किया गया है और नव-साक्षर बयस्का की शिक्षा और रुचि को बनाए रखने के लिए देहाती पुस्तकालयों की स्थापना की गई है। यह बात उल्लेखनीय है कि जिन लोगों ने इस राज्य के समाज शिक्षा के कार्यक्रमों से लाभ उठाया है उनमें से लगभग २० प्रतिशत स्त्रियाँ हैं।

यहाँ पर बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों द्वारा देहाती क्षेत्रों में समाज शिक्षा को प्रचार के लिए किए गए प्रयत्नों का भी उल्लेख कर देना उचित होगा। अतीत में गायकों के दल गाँवों में जाया करते थे और भक्ति के गीत गाकर लोगों में धार्मिक भावनाएँ जगाया करते थे। बिहार में इस प्रकार के गायक-दलों का उपयोग आधुनिक विचारों के प्रसार के लिए किया जा रहा है। राजस्थान में यह परीक्षण किया गया है कि बड़ी आयु के देहाती लोगों की शिक्षा में रुचि जाग्रत करने के लिए बालक का प्रयोग किया जाय। कई दृष्टियों से राजस्थान का देहाती समाज भारत के अधिकांश ग्राम भागों की अपेक्षा बड़ी अधिक अनुदार और परम्परा प्रेमी है। राज्य के शिक्षा अधिकारियों ने बयस्क लोगों की शिक्षा के प्रति उदासीनता या विरोध को समाप्त करने के लिए विद्यालय के छात्रों द्वारा समस्यापरक नाटकों का अभिनय करवाया। जिन बच्चा ने इन नाटकों का अभिनय किया था उनके माता-पिता तथा अन्य बयस्क लोग इन्हें देखने आए। क्योंकि इस प्रकार के नाटकों में बुराईयों पर जोर दिया जाता है इसलिए इस प्रकार के नाटकों का परिणाम प्रायः यह होता है कि समाज-शिक्षा के प्रति बयस्क लोगों के रुच में काफी उत्साहजनक परिवर्तन हो जाता है।

#### ५

समाज-शिक्षा आन्दोलन का सबसे अधिक आगाजनक पहलू यह है कि इसके कार्यक्रमों में स्त्रियों ने बड़ी रुचि ली है। जहाँ तक स्त्रियों में समाज शिक्षा के प्रसार का सम्बन्ध है बम्बई राज्य कुछ दृष्टियों से सब राज्यों से आगे है। यहाँ तक कि राजस्थान जैसे राज्य में भी जोकि बहुत हाल तक भी सामन्तग्राही शासन के अधीन था स्त्री-आयकर्ताओं के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप

हा उत्साहजनक हुए ह। यदि वे स्त्रियाँ जिनके पास कुछ खाली समय है और सामन हैं समाज-शिक्षा के कार्य को निरन्तर ब्यस्त स्त्रियों में प्रारम्भ करें तो परिणाम अवश्य ही और भी अधिक आश्चर्यजनक होंगे। एक बार यदि स्त्रियाँ में मानसता और शिक्षा का प्रचार हो जाय तो भावी पीढ़ी की शिक्षा की समस्या बहुत सरल हो जायगी। एक लड़के को शिक्षा देने का अर्थ है केवल एक लड़के को शिक्षा देना परन्तु एक लड़की को शिक्षा देने का अर्थ है एक पूरे परिवार को शिक्षा देना।

स्त्रियों में समाज-शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दो बातें आवश्यक प्रतीत होती हैं। पहली बात तो यह है कि इन स्त्रियों की बलाघात के लिए काफी उचित समय चुना जाय। सामान्यतया स्त्रियाँ अपने घर के कामों में सबेरे से लेकर दोपहर तक व्यस्त रहती हैं। शाम के समय उनका घर का काम फिर शुरू हो जाता है। भारतीय स्त्रियाँ आमतौर से पाँच-बजे के घंटों में मिलन-मुलाकात के लिए दोपहर-बाद ही जाती हैं। गप्पाप भी कम से कम उतना ही लोकप्रिय अवश्य है जितनी दुपहरी की नीम। इसलिए सुविधा और परम्परा—दोनों की ही दृष्टि से स्त्रियों के लिए शाम के समय कम्पार्स लगाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ-जहाँ मा स्त्रियाँ के लिए समाज-शिक्षा की कम्पार्स दोपहर-बाद लगाई गईं वहाँ परिणाम काफी सन्तोषजनक रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि समाज-शिक्षा का अविलम्ब व्यावहारिक बना लिया जाय। अधिकांश ब्यस्त स्त्रियाँ अपने परिवार का आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यस्त रहती हैं। उनके लिए आय और व्यय का सन्तुलन बनाए रखना निरन्तर चिन्ता का विषय रहता है। इसलिए यदि समाज-शिक्षा स्त्रियों का अपनी और भावुक करना चाहती है तो यह आवश्यक है कि उन्हें आर्थिक साम की भाँटा बधाई जाय। विभिन्न कुटीर-उद्योगों और दस्तकारियों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने से न केवल स्त्रियाँ समाज-शिक्षा की ओर भावुक होती हैं बल्कि उससे उन्हें अपने परिवार के आय-व्यय को मुधारन में भी सहायता मिलती है। रहन-सहन का व्यय बढ़ जाने के कारण मध्यम वर्ग के अपने परिवारों को विवश होकर अपना जीवन का स्तर घटा देना पड़ा है। कामगर-वर्ग के परिवारों की भी यही हालत होयी यदि उनके परिवार की स्त्रियाँ उपायन करना शुरू न कर दें। जिस भी काम से परिवार की आय में

कुछ भी बढ़ि होती है वह तुरन्त स्वीकार कर लिया जाता है। यह दृष्टि मिलबुन प्रथम रूप में अधिक पक्ष की प्राप्ति के रूप में भी हा सनती है या फिर अप्रथम रूप में परिवार के वस्त्र और भोजन पर हानि डाल ख्यम म हुई बचत के रूप में भी हो सकती है। वार्ड भी स्त्री ऐसी शिक्षा का स्वागत करेगी जो उसे अपने और अपने बच्चा के कपड़ तयार करना सिखा दे या उन भाजनों और अन्य वस्तुओं को तयार करना सिखा दे जो अथवा बाजार से खरीदनी पड़ती। इस प्रकार की शिक्षा यदि विधवाओं को मिल सके तो इससे द्वारा वे अपनी जीविका का उपार्जन स्वयं कर सकेंगी।

स्त्रियों में समाज-शिक्षा का प्रसार होने से जाति भेद तथा अन्य पक्षपाता की कठोरता कम हो जायगी। अतीत में भारत की दुबलता का एक मुख्य कारण यह रहा है कि यहाँ जातिगत साम्प्रदायिक तथा प्रान्तीय स्वकीयता के कारण लोगों में अनग अलग बैल रहन की प्रवृत्ति रही हैं। आज भी भारत की एकता को सबसे बड़ा खतरा जातिवाद से ही है। यह ठीक है कि जात-पात अब काफी कम हो गई है। और अस्पृश्यता को ग़रकानूनी घोषित कर लिया गया है परन्तु देहाती क्षत्रा में जात-पात अब भी बहुत बड़ी शक्ति बनी हुई है। एक बार स्त्रियों में जात-पात की भावना समाप्त हो जाय तो फिर सार देण से जात पात समाप्त होते देर न लगगी।

इसलिए स्त्रियाँ में विशेष रूप से देहाती क्षत्रा में शिक्षा के प्रसार के लिए विद्यार्थ प्रयत्न किया जाना चाहिए।  
 कारणों से  
 सार ५  
 भी

से सचाई यह है कि अनक  
 हुई है। हाल के वर्षों में

५२ क्षत्र अब तक

क्षत्रा में ही है

बड़ा भय यह

करें

वि  
 बीच ५

जनता

थाल की २

भरानुत्ति ५५

पाए, जैसी कि

की दृष्टि से गाँवाँ और शहरों का यह अन्तर और भी अधिक है। इसलिए इस अन्तर के कारणों की जाँच-पड़ताल करना और उन्हें यथा-सिद्ध समाप्त करने के उपाय सुझाना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है।

वयस्क स्त्रियाँ इसलिये निरक्षर रहती हैं क्योंकि जब वे लड़कियाँ था तब उन्हें विद्यालय में शिक्षा नहीं मिल सकी। इसका एक बड़ा कारण यह है कि दहाती क्षत्रा में स्त्री-शिक्षण अघ्यापिकाओं का अभाव है। गाँवों के विद्यालयों में अधिकांश विद्यालयों में एक ही अध्यापक होता है और अधिकांश मामलों में वह अध्यापक पुरुष होता है। दहाती क्षत्रा में इस समय जैसी सामाजिक दशा विद्यमान है उसमें माता पिता अपनी लड़कियाँ को एक विद्यालय में भजने से बचता है जहाँ पर अध्यापक और अधिनायक छात्र पुरुष हों। इसके प्रतिरिक्त दहातों के ये अध्यापक प्रायः अशिक्षित अधिक मुक्त लाग ही होते हैं जबकि विद्यालय में आने वाली देहाती लड़कियाँ विद्यालय में आने वाली शहर की लड़कियाँ से कुछ बड़ी आयु की होती हैं। साथ ही प्रकृति के अनिष्ट सम्बन्ध में रहने के कारण वे कुछ अधिक परिपक्व और प्रगत होती हैं। माता-पिता इन बालों को भय दते हैं और इस कारण वे लड़कियाँ को उन विद्यालयों में नहीं भजना चाहते जहाँ कि सब कायकता पुरुष ही हों।

इसलिए दहाती क्षत्रा में स्त्रियों की शिक्षा की प्रगति को तीव्र करने के लिए पहला कदम यह उठाया जाना चाहिए कि वहाँ ऐसी दगाएँ उत्पन्न की जाएँ जिनमें माता-पिताओं को अपना लड़कियों का विद्यालय में भजन में हिचक न हो। इनका एक उपाय यह हो सकता है और इसे नियमित करने का कई बार प्रयत्न भी किया गया है कि लड़कियों के लिए पृथक विद्यालय खोले जाएँ। शिक्षणालय कारणों के अनिश्चित भी इन प्रकार के दुहरे विद्यालय स्थापना का वित्तीय व्यय इतना अधिक होगा कि यह प्रस्ताव लगभग अव्यावहारिक ही हो जायगा। सब तो यह है कि लड़कियों के लिए पृथक विद्यालय स्थापना का हठ करने का अर्थ प्रायः यह होता है कि लड़कियों को शिक्षा पाने का अवसर ही न मिल सके।

अतः इस समस्या का सबसे अच्छा हल यह है कि देहाती विद्यालयों में अध्यापकों में पुरुषों के साथ-साथ उचित अनुपात में स्त्रियाँ भी हों। वहाँ वही विद्यालय में एक ही अध्यापक का स्थान हो वहाँ पर यदि वह अध्यापक स्त्री



कुछ भी बढ़ि होती है वह तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। यह दृष्टि बिलकुल प्रत्यक्ष रूप में अधिक पस की प्राप्ति के रूप में भी हो सकती है, या फिर अप्रत्यक्ष रूप में परिवार के वस्त्र और भोजन पर होने वाले व्यय में दृढ़ वचन के रूप में भी हो सकती है। कोई भी स्त्री ऐसी शिक्षा का स्वागत करेगी जो उसे अपने और अपने बच्चा के कपड़े तैयार करना सिखा दे या उन भाजना और अन्य वस्तुधा को तैयार करना सिखा दे जो अन्यथा बाजार से खरीदनी पड़ती। इस प्रकार की शिक्षा यदि विद्यवाद्या का मिल सके तो इससे द्वारा वे अपनी जीविका का उपाजन स्वयं कर सकेंगी।

स्त्रियों में समाज-शिक्षा का प्रसार होना स जाति भेद तथा अन्य पक्षपात को कटोरना कम हो जायगी। प्रतीत में भारत की दुर्बलता का एक मुख्य कारण यह रहा है कि यहाँ जातिगत साम्प्रदायिक तथा प्रान्तीय सकीणता के कारण लोगों में अलग-अलग बँटे रहने की प्रवृत्ति रही है। आज भी भारत की एकता को सबसे बड़ा खतरा जातिवाद से ही है। यह ठीक है कि जात-पात अब काफी कम हो गई है। और सम्पुष्टता को गणमान्यता घोषित कर दिया गया है परन्तु देहाती क्षत्र में जात-पात अब भी बहुत बड़ी गति बनी हुई है। एक बार स्त्रियों में जात-पात को भावना समाप्त हो जाय तो फिर सारे देश में जात पात समाप्त होना देर न लगगी।

इसलिए स्त्रियाँ में विद्यप रूप में देहाती क्षत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए विद्यप प्रयत्न किया जाना चाहिए। परन्तु दुभाग्य से मर्यादा यह है कि अनेक कारणों से इसी क्षत्र में अब तक सबसे कम प्रगति हुई है। हाल में वर्षों में सारे देश में स्त्रियों की शिक्षा का बड़ी गति मिली है परन्तु देहाती क्षत्र अब तक भी इस आन्दोलन में अधिकांशतर अछूत-से ही है। क्योंकि देहाती क्षत्र में ही हमें असीत की कमियाँ को सबसे अधिक पूरा करना है। इसलिए बड़ा भय यह है कि वहाँ गहरी क्षत्रों में होने वाली तीव्र प्रगति के कारण गाँवों और गहरी के बीच पहले से ही विद्यमान गार्ई और भी अधिक गहरी और खोड़ी न हो जाय। जनता के एक बड़े वर्ग का निरन्तर निरक्षर बन रहना केवल देश की प्रगति को ध्यान को ही घौमा नहीं कर देता बल्कि समाज की संरचना (स्ट्रक्चर) को भी अगनुत्ति कर देता है। कुल मिलाकर गाँव अभी तक बड़ी उन्नति नहीं कर पाए जैसी कि शहरों में हो चुकी है। स्त्रियों और सङ्घियों की शिक्षा

की दृष्टि में गाँवा और सहरा का यह अन्तर और भी अधिक है। इसलिए इस अन्तर के कारण का जाँच-पड़ताल करना और उन्हें यथा-शीघ्र समाप्त करने का उपाय मुझ्ना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है।

वस्तु-स्त्रियाँ इसलिए निरक्षर हूँ कि जब वे सहकियाँ या सब ठहरे विद्यालय में शिक्षा नहीं मिल सकी। इसका एक बड़ा कारण यह है कि देहली क्षेत्र में स्त्री-शिक्षण अद्यापि अभाव का प्रभाव है। गाँवा के विद्यालयों में अधिकतर विद्यार्थी एक ही अध्यापक होता है और अधिकांश मानता में वह अध्यापक पुरुष होता है। देहली क्षेत्र में इस समय जमीन सामाजिक शांति विद्यमान है उसमें माता-पिता अपनी सहकियाँ को एक विद्यालय में भर्जन में बतलाते हैं जहाँ पर अध्यापक और अधिकतर छात्र पुरुष हैं। इसके प्रतिरूप देहली के अध्यापक प्रायः अपना ही अधिक सबक साग ही होते हैं जबकि विद्यालय में छात्र बानी देहली सहकियाँ विद्यालय में जान बानी गहर की सहकियाँ से कुछ बड़ी भाषा को होती हैं। साथ ही प्रगति के अनिष्ट सम्पत्ति में रहने के कारण वे कुछ अधिक परिष्कृत और प्रगत होती हैं। माता-पिता इन बातों को महत्व देते हैं और इस कारण वे सहकियाँ को उन विद्यालयों में नहीं भर्जना चाहते जहाँ कि सब कार्यकर्ता पुरुष ही हैं।

इसलिए देहली क्षेत्र में स्त्रियों की शिक्षा की प्रगति को तीव्र करने के लिए पहला कदम यह उठाया जाना चाहिए कि वहाँ ऐसी दगाएँ उत्पन्न की जाएँ जिनमें माता-पिता को अपनी सहकियों को विद्यालय में भर्जन में हिक्क न हो। इसका एक उपाय यह हो सकता है और इसे क्रियान्वित करने का कई बार प्रयत्न भी किया गया है कि सहकियों के लिए पृथक् विद्यालय खोले जाएँ। शिक्षणात्मक कारणों के प्रतिरूप भी इस प्रकार के दुहरे विद्यालय स्थापना का किसी व्यय इतना अधिक होगा कि यह प्रस्ताव लगभग अद्यापि बहिष्कृत ही हो जायगा। सब तो यह है कि सहकियों के लिए पृथक् विद्यालय स्थापना का हठ करने का अर्थ यह होता है कि सहकियों को शिक्षा पान का अवसर ही न मिल सके।

वस्तुतः इस समस्या का सबसे अच्छा हल यह है कि देहली विद्यालयों में अध्यापकों में पुरुषों के साथ-साथ उचित अनुपात में स्त्रियाँ भी हों। जहाँ बड़ी विद्यालय में एक ही अध्यापक का स्थान हो वहाँ पर यदि वह अध्यापक स्त्री

हो तो अवश्य ही अधिक लाभ होगा। यह सामान्यतया स्वीकार किया जा चुका है कि छोटी आयु के लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए ही स्त्रियाँ अधिक अच्छी अध्यापक सिद्ध होती हैं। परन्तु एक तो स्त्री अध्यापक की अपर्याप्त संख्या और दूसर अनेक सामाजिक कारणों से कम से कम वर्तमान में यह प्रश्न नहीं उठता कि गाँव में एक अध्यापक वाले विद्यालयों में स्त्री अध्यापक रखी जा सकें।

यदि विद्यालय में भातका की संख्या इतनी है कि दो अध्यापक नियुक्त करना उचित हो तो समस्या का आदश समाधान यह होगा कि उस दो अध्यापकों वाले विद्यालय में एक विवाहित दम्पति को नियुक्त कर लिया जाय। परन्तु इस आदश को भी पूर्ण कर पाना कठिन होगा। प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक जिस सामाजिक स्तर का होता है उसमें अध्यापक की पत्नी को मुक्ति से ही इतनी शिक्षा मिली होती है कि वह अध्यापक का काम कर सके। साथ ही यह भी कठिन होगा कि दो अध्यापकों वाले विद्यालय में एक अध्यापक ऐसी स्त्री हो जिसका पुरुष-अध्यापक के साथ कोई सम्बन्ध न हो। इन सब कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए इस समस्या का समाधान के लिए प्रथम पग के रूप कुछ न कुछ विशेष उपाय बूझने होंगे।

इस समय हम पनि और पत्नी को विद्यालय में दो अध्यापकों के रूप में नहीं रख सकते क्योंकि अध्यापक की पत्नी यथाचित रूप से सुशिक्षित नहीं होता। परन्तु यदि अध्यापक का पत्नी को विद्यालय की माता के रूप में नियुक्त कर दिया जाय तो इसमें कोई हानि नहीं है। बालिका छात्राएँ उसकी देख रेख में रहेंगी और इस प्रकार छात्राओं के माता-पिता और स्वयं छात्राओं में विश्वास उत्पन्न हो सकेगा। लड़कियों और लड़कों को काम में लगाए रखने में भी वह अपने पति की कुछ सहायता कर सकेंगी और दायर लड़कियों को मिर्चा कपड़ों की धुलाई और नागबानी की शिक्षा भी दे सक। विद्यालय में लगना रहना ही इस बात के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन होगा कि लड़कियाँ अधिक संख्या में विद्यालय में आन लेंगी।

विद्यालय में स्त्री की उपस्थिति से न बचने लड़कियाँ अधिक संख्या में विद्यालय में आन लेंगी बल्कि इससे गाँव में समाज शिक्षा का एक नेट्र बनाने में भी सहायता मिलेगी। बालिका-छात्राओं की संख्या में होने वाली वृद्धि से

## समाज-शिक्षा की धारणा

कुछ वष बाग ही दृष्टिगोचर होगी परन्तु इसका तात्कालिक साम यह होगा कि गाव की निरन्तर वयस्क महिलाओं को विद्यालय में भ्रान की प्रेरणा मिलगी । जब एक बार इस प्रकार का केन्द्र स्थापित हो जाएगा तो उसका भविष्य बहुत चञ्चल हो सकता है । यह केन्द्र स्त्रिया की एक गोष्ठी या क्लब जैसा होगा । भाजकल स्त्रिया की गोष्ठी का स्थान प्राय गाँव का कुर्मा या किसी परिवार का भागन होता है । चर्चा का मुख्य विषय स्थानीय गणप ही होता है । यदि एक बार यह केन्द्र उठकर विद्यालय के शिक्षा-सम्बन्ध वातावरण में आ जाय तो हमस शिक्षा की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो एक पीढ़ी में ही देशान क स्वरूप में शान्तिकारी परिवर्तन कर दगी ।

## ६

समाज-शिक्षा की—और कम से कम साक्षरता की—प्रगति क्या तीव्र गति से नहीं हो सकी इसका एक कारण यह है कि इस प्रकार की शिक्षा के सामाजिक भय-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्य ठीक ठीक नहीं आँका गया । जहाँ शिक्षा के मूल्य को सब लोग स्वीकार करते हैं वहाँ सामान्यतया यह भा समझा जाता है कि शिक्षा भाषिक प्रगति का कारण न होकर उसका परिणाम अधिक है । आमतौर से इस बात को अनुभव नहीं किया जाता कि किसी भी देश की सम्पत्ति व्यापक शिक्षा के बिना बढ़ नहीं सकती । फिर भी यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग इस बात को अनुभव न कर पाए । उद्योगों की प्रक्रिया में विज्ञान के प्रयोग से ही औद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ हुआ । इसका पहला परिणाम यह हुआ कि मशीनों से वह काम कराने का प्रयत्न किया गया जिसे पहले मनुष्य अपने हाथ से किया करता था । इसके फलस्वरूप उत्पादन के परिमाण में अत्यधिक वृद्धि हो गई और उसका फिर परिणाम यह हुआ कि बाजारों का विस्तार हो गया । सब से लेकर आधुनिक उद्योग अधिकाधिक मशीनों के प्रयोग पर आश्रित होता गया है । नये आविष्कार और नई-नई मशीनों का उपयोग औद्योगिक उन्नति के लिए एक आवश्यक शर्त बन गया है । इसी प्रकार देश के पान जो साधन विद्यमान हैं उनका अपेक्षाकृत अधिक अच्छा उपयोग करने के लिए भी विज्ञान का प्रयोग कम महत्वपूर्ण नहीं । विज्ञान एक ऐसी स्थिति तक पहुँच गया है जबकि किसी भी वस्तु से सगमय कोई भी काम

निनाला जा सकता है। आधुनिक रसायनशास्त्र कोयले और खडिया से लाख और पेय पदार्थ तैयार कर सकता है। इसी प्रकार नमकी स ऊन और शीशे तथा प्लास्टिक से सब प्रकार की निर्माण-सामग्री तैयार की जा सकती है। इसलिए यह कहना गलत न होगा कि आधुनिक संसार में उद्योगों का विकास ब्यापक ज्ञान का ही एक परिणाम-मात्र है।

परन्तु नई मशीनों के आविष्कार या उत्पादन की नई-नई प्रतिप्रियाओं को पूणता तक पहुँचाने के लिए ब्यापक और प्राविधिक (टेक्निकल) ज्ञान की आवश्यकता होती है। बाजार के विस्तार के साथ-साथ वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की प्रक्रियाएँ अधिक और अधिक पचीदा हो गई हैं। जहाँ पहले उत्पादक को अपने आसपास के ही परिवेश (एनवायरनमण्ट) की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान रखना पड़ता था वहाँ आधुनिक जगत् में उत्पादक को अनक देगा में वस्तुओं की उपलब्धि अनेक स्थितियों में उत्पादन की तुलनात्मक लागत विस्तृत क्षेत्रों में वितरण की सुविधाओं और अनक प्रयोगों के लोगों की रुचि और सामर्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आधुनिक उद्योग के उच्चतर कार्यकारी अधिकारियों का संसार का विस्तृत ज्ञान हान के साथ-साथ अत्यधिक कुशल और बुद्धिमान होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार मशीनों को चलाने वाले लोगों के लिए भी यदि व निपुण और उत्पन्नशील बनना चाहें तो यन्त्र-विद्या का कुछ न कुछ ज्ञान और जिन मशीनों पर वे काम करते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उद्योग और वाणिज्य के आधुनिक रूपों के लिए सारी जनता की अच्छी सामान्य शिक्षा और ऊँच प्रशासनीय तथा ब्यापक कार्यकर्ताओं के लिए उच्च विद्वत् ज्ञान और निपुणता की आवश्यकता होती है।

सभी प्रगतिशील उद्योगपति इस बात को अनभव करते हैं कि आधुनिक उद्योग में प्रत्येक स्थिति के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जिस बात को व सिद्धांत-रूप में स्वीकार करते हैं उसे सच प्रमाणित भी करते हैं। यह बात भारत के सम्बंध में विशेष रूप में सत्य है। यहाँ पर उद्योगपतियों ने शिक्षा के लिए उससे बड़ी कम काम किया है जितना कि अन्य देशों में उद्योगपतियों ने किया है। इसमें शक नहीं कि यहाँ भी कुछ सम्मानार्थ प्रयत्न हैं परन्तु एक बग के रूप में भारतीय उद्योगपतियों

## समाज-शिक्षा की धारणा

ने इस बात को अनमय नहीं किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगाई गई पूंजी से उन्हें बहुत अच्छी प्रतिप्राप्ति (रिटन) होगी। उद्योगपतियाँ को शिक्षा देते हैं और किसी भी प्रकार वह शिक्षा देती ठीक भी है कि भारतीय श्रमिक इनके अनुभव करते प्रतीत नहीं होते कि इस सभी का कारण शिक्षा का अभाव है। इन उद्योगपतियों में से गांधी ही किसी न अपने कारीगरों की शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए कोई काम उठाया हो।

दूसरे प्रगतिशील देशों के बड़े-बड़े व्यवसायिक और उद्योगपतियों ने इस बात को अनुभव कर लिया है कि निरक्षर कारीगरों से यह धाना नहीं की जा सकती कि वे पेचीदा मशीनों से ठीक ढंग में पूरा-पूरा काम से सकेंगे। उनके अनुभव से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि घर-घरवारी प्रयत्न के द्वारा भी देश में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए कितना कुछ किया जा सकता है। कुछ देशों में राष्ट्रीय समाचारपत्रों ने यह बात सिद्ध कर दी है कि बयस्क निरक्षर लोगों के लिए साक्षरता के पाठ कम बड़े सप्ताह रूप में संगठित किए जा सकते हैं। पोर्टो-रिका के दो दैनिक पत्रों में निरक्षर छह महीने तक दो बालकों से लेकर आठ पढ़ तक में बयस्कों के लिए साक्षरता के पाठ प्रकाशित होते रहे। या नाममात्र मूल्य पर पुस्तकें वितरित की। इस प्रकार का विवरण व इसलिए उनकी अपनी छपाई की मशीनों की जिन पर केवल कुछ पाठ-से घंट ही पूरी तरह काम होता था बाकी समय वे खाली रहती थी। उनके पास बड़ा मात्रा में रही कागज भी था जो रौंदरी मशीनों पर ठा काम नहीं आ सकता था, किन्तु किताबें छापने के काम में लाया जा सकता था। इन समाचारपत्रों को वित्तीय दृष्टि से भी काम नकसान नही हुआ। इस प्रकार का व्यवस्तुतः एक विनियोग (इन्वैस्टमेंट) था। सागरों का सफाई से बुद्धिमान के साथ-साथ मुनिविषय रूप से उनका पत्र की विशेषता यह थी और इस कारण वे अपने विनायन की तरफ ध्यान में मग्न हुए। भारतीय समाचारपत्रों का विशेषता बहुत परिमल है क्योंकि उनके पाठकों का अभाव है। यदि कोई साहसी पत्र पोर्टो-रिको के परीक्षण के ढंग पर ही योजना शुरू करे तो यह स्वयं साम

उठाने के साथ-साथ देश की भी बड़ी सेवा कर रहा होगा।

व्यवसाय द्वारा शिक्षा के आन्दोलन का सहायता देन और साथ ही अपने मुनाफे को कानून का एक और उदाहरण अमेरिका की बीमा-कम्पनिया का है। इन कम्पनियों ने सरस पुस्तकें और आहार तथा व्यायाम के नियमों के सम्बन्ध में पुरतर्क प्रकाशित करके स्वास्थ्य की शिक्षा में बड़ी सहायता दी है। इन पुस्तकों की पाठ्य सामग्री में किसी प्रकार का प्रचार नहीं होता। परन्तु पुस्तक की जिल्द पर उसे प्रकाशित करने वाली कम्पनी का नाम छपा रहता है। जो कोई भी इन पुस्तकों को माँगता है, उस पर मुद्रा दी जाती है। इस प्रकार स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी करके ये पुस्तकें उन लोगों की आयु का लम्बा करने में सहायता देती हैं जिन्होंने बीमा करवाया हुआ है। इस प्रकार बीमा कम्पनिया का सीधा लाभ यह होता है कि उन्हें कम दावा का भुगतान करना पड़ता है। इससे अतिरिक्त इस प्रकार की पुस्तिकाएँ प्रचार का प्रत्युत्तम माध्यम हैं। कम्पनी का नाम उन हज़ारों लोगों के सामने आ जाता है जो उसे लाभकारी भी उसका नाम न सुन पाते। कम्पनी को उन लोगों की सद्भावना भी प्राप्त हो जाती है जो उस पुस्तक को पढ़कर लाभ उठाते हैं। यदि इस प्रकार की सेवाओं का मुख्य अमेरिका जहाँ देश में भी छाँटा जाता है तो यह स्पष्ट है कि बीमा-कम्पनिया द्वारा भारत में किए गए ऐसे किसी भी प्रयत्न का महत्त्व बड़ी अधिक होगा क्योंकि भारत में औसत प्रतिशत आय केवल ३० पैसे है और यहाँ राज्य द्वारा स्वास्थ्य-समाधान की व्यवस्था बिल्कुल ही अपर्याप्त है।

व्यवसाय-शिक्षा के उद्देश्य का पूर्ण करने में छोटे-छोटे औद्योगिकों का निर्माण करने वाला व्यापार-संस्थाएँ भी सहायता पहुँचा सकती हैं और अमेरिका में इन संस्थाओं ने ऐसी सहायता पहुँचाई भी है। इन संस्थाओं ने ऐसी पुस्तिकाएँ प्रकाशित की हैं जिनमें कृषि के सम्बन्ध में और सीधे-सादे यंत्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है। इनमें से कुछ पुस्तिकाओं में अपना प्रचार भी किया गया है। पहल कृषि या उद्योग की प्रतिनिधियों का ध्यान करने के बाद ये प्रायः यह सुझाव हैं कि सर्वोत्तम ढंग से कार्य करने के लिए धन का यंत्र या उदाहरण सत्रय संस्था रहेगा। भारतीय व्यवसाय-संस्थाएँ भी तरह-तरह की मशीनें तैयार करती हैं। ये संस्थाएँ विज्ञापन पर भी बड़ी-बड़ी राशियाँ खर्च करती हैं। परन्तु उनमें से शायद ही किसी ने इस बात का अनुमन किया हो कि

विशुद्ध व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस प्रकार की वृत्ति-सम्बन्धी पुस्तिकाओं प्रत्येक सामान्य जन-वित्तीय-सम्बन्धी पुस्तिका में पसंद आना सामान्य विनियोग होगा। इस प्रकार की पुस्तिकाओं से उन व्यवसाय संस्थाओं द्वारा तैयार किया गया मान बढ़ी संस्था में नये ग्राहकों के सम्मुख आ सकेगा और उनका सफल भावनाएं प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार समाज शिक्षा की सफल सिद्धि में न्यायता देने के साथ साथ ये कम्पनियाँ अपने कार्य-क्षेत्र को भी विस्तृत कर रही होगी और अधिक लाभ भी कमा रही होगी। अपने विनायन-व्यय के एक भाग को इस प्रकार के कार्यों में लगाना व्यवसाय की दृष्टि में तो अच्छा होगा ही साथ ही वह देश की भी बड़ी सेवा होगी।

शिक्षा के क्षेत्र में एक और प्रत्यक्ष रूप में सहायता बढ़े-बढ़ उद्योगपति भी कर सकते हैं। इस समय भारत में उद्योगों में काम करने वाले लगभग ५ ०० मजदूर हैं। इन मजदूरों का बहुत बड़ा भाग श्रम शक्ति भी निरक्षर है। यदि औद्योगिक संस्थाएँ अपने कारीगरों का शिक्षा देना प्रारम्भ कर दें तो इससे न केवल उनके कारीगरों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और उन संस्थाओं को लाभ होगा अपितु इससे देश की भी सेवा होगी क्योंकि इससे ज्ञान का प्रसार होगा। कारखानों में काम करने वाला मजदूर सामान्यतया दहाती मजदूर की अपेक्षा अधिक ऊँच स्त्री बुद्धिमान् और चेतनायुक्त होता है। इसलिए वह इस प्रकार की शिक्षा से दहाती मजदूर की अपेक्षा अधिक जल्दी लाभ उठा सकता है। इतना ही नहीं इस प्रकार की शिक्षा का लाभ केवल गहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा। भारत में अभी तक भी एक पथक श्रमिक-वर्ग तैयार नहीं हुआ है। कारखानों के मजदूर यदि शिक्षा विनिष्ठा मौसम में नहीं तो भी बीच-बीच में अपने गाँवों में जाते रहते हैं। इस प्रकार कारखानों के मजदूरों की शिक्षा के फलस्वरूप गाँवों में भी शिक्षा का प्रसार होगा और इससे दहानी क्षेत्रों में विद्यमान जड़ता की नींद को साइन में सहायता मिलेगी। उद्योगपतियों के इस प्रकार के प्रयत्नों में सरकार यह सहायता कर सकती है कि आ अनुमादित व्यय मजदूरों की शिक्षा के उपर्युक्त किया जाए उसे धार-वर्ग की दृष्टि से अवस्थापन-व्यय (एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस) मान लिया जाए।

यह वैभव चाहे न मुमान कि किस प्रकार उद्योग और व्यापार-शिक्षा के क्षेत्र में सहायता कर सकते हैं और इस प्रकार की सहायता करते हुए स्वयं भी



लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कारीगरों के शिक्षित होने के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी और इस प्रकार उद्योग और व्यापार दोनों की समृद्धि बढ़ेगी। शिक्षा से राष्ट्रीय सम्पत्ति इस रूप में भी बढ़ेगी कि धनेक दिशाओं में काफी बचत हो सकेगी। एक उदाहरण लीजिए—अच्छे कारीगर होने का धर्म यह होगा कि विद्यमान यंत्रों की दुरुभाल अच्छी हो सकेगी और उन यंत्रों का जीवन-काल बढ़ जाएगा। केवल परिवहन-उद्योग में ही प्रतिवर्ष लाखों रुपया की बचत की जा सकती है यदि पुराने वाहनों के स्थान पर नये वाहन खरीदने में कमी की जा सके। अच्छे कारीगर केवल अधिक और अच्छी शिक्षा द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा से प्राप्त होने वाले लाभ केवल व्यवसाय तक ही सीमित नहीं रहेंगे। शिक्षा की वृद्धि होने से राष्ट्रीय सम्पत्ति में भी वृद्धि होगी और उसके फलस्वरूप समाज-सेवाओं के आवश्यक विस्तार के लिए नया आधार तैयार हो सकेगा। हमारे देश के लोग का जीवन-स्तर की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण आधार केवल शिक्षा द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। साथ ही लोग अपने खाली समय का सृजनशील रूप से उपयोग कर सकें इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा मन और चरित्र को एक विशाल दृष्टि का प्रशिक्षण दिया जाए। इस प्रकार समाज शिक्षा ही वह आधारभूत है जिससे ऊपर भारत एक ऐसे कल्याण राश्व का निर्माण कर सकता है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा—दोनों का ही यथाचित ध्यान रखा जा सके।

## अध्याय ५

# भारतीय विश्वविद्यालयों के विषय में

हाल में भारत में विश्वविद्यालयों का काफी आलोचना की गई है जिसमें से कुछ उचित भी और कुछ नहीं। बहुत बार यह कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वह आवश्यकता से अधिक सैद्धांतिक होता है और वह व्यक्ति का व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार नहीं करती। बिनापरूप से यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों से पढ़कर निकलने वाले छात्रों में शारीरिक श्रम और दृढ़ता जीवन के प्रति अरुचि हो जाती है। इस प्रकार विश्वविद्यालय एक ऐसा अभिकरण (एजन्सी) बन गए हैं जो गाँवों से ग्राम्य और होनहार युवकों का गहरा में खोच साते हैं परन्तु इस प्रकार गाँवों को जो हानि हो जाती है उससे शहर को लाभ हो जाता हो यह बात नहीं। गाँव के छोटे-से समाज में नया बनने के बजाय—जोकि वे बड़ी आसानी से बन सकते थे—वे शहर की भ्रष्टा जनसंख्या के एक हवाला और कटुभावना से भरे सदस्य मात्र बन पाते हैं।

आलोचना की एक और भी शिगा है जिसमें विश्वविद्यालयों की इससे लगभग ठीक उल्टी कारण से निन्दा की जाती है। इन आलोचकों के कथनानुसार विश्वविद्यालयों का निर्माण केवल लिपिक तथा प्रशासन के लिए आवश्यक निम्नवर्गीय कर्मचारी तैयार करने के लिए किया गया था। इन आलोचकों का कथन है कि जब अंग्रेजों ने भारत में अपना राज्य जमाया तो उन्होंने सारे ऊँचे-ऊँचे पदों को अपने लिए सुरक्षित रख लिए परन्तु कोई भी प्रशासनिक

तब नहीं चलाया जा सकता जब तक कि निचले स्तर पर काम करने वाले कमचारियों की भी काफी संख्या विद्यमान न हो। इसलिए भ्रष्टाचार न यह निश्चय किया कि कुछ भारतीयों का भ्रष्टाचारी का इतना ज्ञान कराया जाए कि जिससे उनका यह प्रयाजन पूरा हो सक। केवल इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रारम्भ की गई थी और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। इसलिए इन आलोचकों के कथनानुसार भारतीय विश्व विद्यालय सिपिब (क्वै) तयार करने वाले कारखाना के सिवाय और कुछ नहीं है।

यह ठीक है कि इन दोनो ही आलोचनाओं में सत्य का कुछ न कुछ भग है फिर भी स्पष्ट रूप से ये दोनों ही आलोचनाएँ अतिरिक्त हैं और 'यायोचित' नहीं हैं। विश्वविद्यालयों की शिक्षा हाँती ही कुछ इस ढंग की है कि उसे अवश्य ही बहुत कुछ अव्यक्त और मिथ्यातात्मक होना पड़ता है। भय सृष्टि पर मनुष्य का प्रभुत्व बहुत कुछ उसकी सामाजिककरण (जनरलाइजेशन) की दृष्टि पर ही निर्भर है और कोई भी व्यक्ति—चाहे अस्थायी रूप से ही सही—अपन आपको विनिष्ट और व्यावहारिक वस्तुओं से पृथक् किए बिना सामाजिककरण नहीं कर सकता। विज्ञान के अनेक अत्यन्त उपयोगी और दूरगामी प्रयोगों का प्रारम्भ करने का श्रेय हम लोगों को है जिनका काम विगुद्ध रूप में मिथ्यात विवेचन करना हो था। परन्तु इस बात में इन्कार नहीं किया जा सकता कि यदि मिथ्यात और व्यवहार दोनों का निरन्तर परस्पर सम्बन्ध न बना रहे तो शिक्षा अध्यात्मिक और अज्ञान हो जाती है। भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा का इन पहलुओं की जिस सीमा तक उपेक्षा की है उस सीमा तक वे विश्वविद्यालयों के एक प्रमुख लक्ष्य को पूरा करने में अव्यर्थ ही भगपत्त रहे हैं।

आलोचना की जा दूसरी दिशा ऊपर बताई गई है उस पर भी इसी प्रकार टीका की जा सकती है। यह सत्य है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में निवृत्त बड़े छात्रों की अधिकांश संख्या केवल सफेत्पोन नौकरी के लिए ही उपयुक्त होती है परन्तु यह कहना सत्य नहीं है कि भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना ही निपिब तयार करने का निष्पत्ती गई थी। वस्तुतः भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए मुख्य रूप से दबाव उस समय की सरकार ने नहीं डाला था बल्कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने तथा कुछ भारतीय दूरदर्शी

नेताओं ने जाना था कि जहाँ उन्हीं समय इस बात का अनुभव कर लिया था कि इस प्रकार का गिना में देश का बौद्धिक पुनरुत्थान हो सकेगा । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम जिसमें गणित और सङ्गणिक पर राजनीति और अधिकांश पर भौतिकशास्त्र और रसायन पर बल दिया जाता है भावी निपिका के प्रतिस्पर्ध के लिए गाय है सर्वोत्तम कहा जा सके । यदि भारतीय विश्वविद्यालयों का मुख्य मकसद ही प्रशासन के लिए निम्नवर्गीय कर्मचारियों तैयार करना होता तो उनमें से इस प्रकार के मिडिलान्तरक विषयों का विस्तृत उदाहरण दिया जाता और मारा ध्यान मध्य-एशियन मामूली शिक्षा-विज्ञान और कार्यालय की कार्यपद्धतियों पर हो दिया जाता ।

यहाँ यह भी सचेत किया जा सकता है कि आलोचना का यही नाम दिया जाए काफी सीमा तक एक दूसरे का काम करता है । यदि यह मान लिया जाए कि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम आवश्यकता से अधिक राष्ट्रीय और मिडिलान्तरक है तो यह स्पष्ट है कि उन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य सिर्फ तैयार करना नहीं हो सकता । और यदि दूसरे ओर यह स्वीकार कर लिया जाए कि विश्वविद्यालय तो निम्नवर्गीय कर्मचारियों तैयार करने के कामकाज हैं तो यह स्पष्ट है कि उनकी इस आधार पर निर्माणा नहीं हो जा सकता कि बड़ा म पढ़कर निकलने वाले छात्र नौकरों के रूप में नहीं हैं । फिर भी यदि कार्य चाहें तो यह आलोचना अवश्य कर सकता है कि वे इतनी अधिक सख्या में निपिका तैयार कर रहे हैं कि जिनका आवश्यकता नहीं है । परन्तु यह आलोचना उसमें बिल्कुल भिन्न और बलुन बिल्कुल विपरीत होगा कि विश्वविद्यालयों में पढ़ कर निकलने वाले छात्र काम कर पान के उपयुक्त नहीं हान ।

भारत में विश्वविद्यालयों का गिना का वास्तविक अर्थों का कारण है—अपवाप्त अध्यापक-बर्ग अपवाप्त धनराशिओं और उच्चतर शिक्षा के सम्बन्ध में लोगों की समझ की कमी । विश्वविद्यालयों का अध्यापक-बर्ग न केवल सख्या की दृष्टि से अपवाप्त है अपितु योग्यता के दृष्टि में भी अपवाप्त है । देश के सबसे योग्य पुरुषों और स्त्रियों में से अनेक अध्यापन के पग का छाड़कर दूसरे पगों में चले जाते हैं । इसका कारण मुख्य रूप से आर्थिक होता है । इस प्रश्न पर विचार करने पर हम तुरन्त धनराशि के प्रश्न पर आ पा सकते हैं । विश्वविद्यालयों के पास अपवाप्त धनराशि हान का परिणाम यह होता है कि वे अध्यापकों

को कम वेतन दे पाते हूँ इसलिए अध्यापक घटिया किस्म के होते हैं। इसके साथ ही धनराशि की कमी के कारण पुस्तकालय प्रयोगशालाएँ कक्षा भवन तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी उनकी नहीं होनी जितनी होनी चाहिए। प्रायः विश्वविद्यालय में वातावरण ऐसा होता है कि यहाँ किसी भी गम्भीर कार्य को देख कर डटकर कर पान की उम्मीद नहीं होती। अध्यापकों और विद्यार्थियों की संख्या में जो अत्यधिक विषम अनुपात पाया जाता है उसका कारण भी अनात धनराशि का अभाव और अत्यंत उच्चतर शिक्षा के प्रति गलत मनोवृत्ति है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो लोग विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने आते हैं उनमें से अधिकांश केवल इसलिए आते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि विश्वविद्यालय की उपाधि नौकरी पान के लिए पामपोर जमी है। जब भारतीय विश्वविद्यालय प्रारम्भ हो गए थे उस समय के अपने स्नातकों को लाभदायक और अनक बार तो सन्तोषजनक नौकरियाँ दिला पाते थे। इस प्रकार जनता के मन में विश्वविद्यालय की शिक्षा का सम्बन्ध नौकरी के साथ अनिष्ट रूप से जुड़ गया। आजकल विश्वविद्यालय की शिक्षा से सब स्नातकों को नौकरी मिल पान की कोई गारंटी नहीं है और इसीलिए विश्वविद्यालयों की निम्न की जाती है। परन्तु इस बात को समझ लेना उचित होगा कि विश्वविद्यालयों की यह निम्न सामाजिक दृष्टि से की जाती है ज्ञान या मिद्वान की दृष्टि से नहीं।

विश्वविद्यालयों की असफलताओं और त्रुटियों के बावजूद एक बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय विश्वविद्यालयों ने नई राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने में बड़ा सुनिश्चित और बहुमूल्य योग दिया है। अपने सब दोषों के बावजूद वे यह दावा कर सकते हैं कि हमारी स्वाधीनता के प्रमुख निर्माता वे ही हैं। परन्तु स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालयों पर बहुत-से नए और अमसाध्य काम पड़े हैं। भारत ने अपने लिए प्रजातंत्र वांछना किया है और प्रजातंत्र में यह आवश्यकता निहित है कि सब लोगों को पाप स्वतंत्रता और समानता प्राप्त रहेगी। इसलिए अब मैं आगे भारतीय विश्वविद्यालयों की परम्प इस बात से भी जाएँगी कि उन्होंने उन उद्देश्यों को प्राप्त कराने में कितनी सहायता की है।

## २

। प्राधुनिक युग पुरान युगा से इस दृष्टि से भिन्न है कि हममें लोगा को बिकार करन और मनमक करन क लिए बिना होना पडता है और हमसे भी अधिक सहृदयपूण बात यह है कि उन्हें सम्मिलित रूप से काय करने के लिए बिना होना पडता है । पुरान जमाने में अलग-अलग समुदाय और समाजा के लिए यह सम्भव था कि वे एक दूसरे स अनभिन्न रहकर जा सकें । उस समय सम्बन्ध-स्थापन (कम्प्युनिकेशन) के साधन बिकसित नहीं हुए थे और एक-दूसरे स दूर रहन बाल लाग बस्तुत परस्पर पयक-पुयक बिभक्त-ने रहत थे । प्राकृतिक रोकें भी एक देग क लागा को दूसर देग के लोगा स पुयक किए रहा थी । एक देग से दूसर देग तक यात्रा करन में जो सम्वा समय लगता था उसक कारण अलग-अलग समाजा में भौतिक और मनोबैज्ञानिक अन्तर और बढ जाता था । आजकल इस प्रकार की सब प्राकृतिक रोकें लुप्त हो चुकी ह या घारे धीरे लुप्त होती जा रही हैं । प्राविधिक उन्नति क कारण यह सम्भव हो गया है कि पृथ्वा क किसी भी एक भाग से किसी भी दूसरे भाग तक केवल २४ घट क अन्दर अन्दर पहुँचा जा सक ।

प्राधुनिक बज्ञानिक प्रगति लगभग तीन या चार शताब्दी पहले प्रारम्भ हुई थी । परन्तु दूरी पर बिजय प्राप्त करन में सफलता पिछल भी वर्षों का ही परिणाम है । टायनबा न अपन एक भाषण में कहा था कि उन्नीसवीं शताब्दी क मध्य में किसी भी अग्रेज राजनीतिज्ञ को राम से लग्न तक जाने में बिमकुल ठीक उतना ही समय लगता था जितना पहली शताब्दी में किसी रोमन सम्राट को इरलड स राम तक पहुँचन में लगता था । परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी का अन्त होते-होते यह यात्रा गाय ४८ घंटे में पूरा की जा सकती थी । य उतने ही घंटे स जितने कि ५ वर्ष पहले इस यात्रा को पूरा करन में दिन लगते थे । आजकल जैत्र और ध्वनि स भी अधिक तोषणायी विमाना क द्वारा हम सबी से उस स्थिति की ओर पहुँच रहे ह जबकि गायद यह सम्भव हो जाएगा कि लन्दन स रोम और रोम से लग्न उतन ही मिनटो में पहुँचा जा सक जितने कि उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में घंटे लगते थे ।

इस प्रकार स्थान और काल के सकुचित होने जान के कारण मनुष्य का

प्रकृति की गतिविधियों के ऊपर अधिकार बढ़ता जा रहा है जिसका मतलब और बुराई दोनों के लिए उपयोग हो सकता है। पुराने समय में जो जहाज कुहरे में भटक जाया था वह जलट्ट हुआ ही समाप्त लिया जाता था परन्तु आजकल ध्रुव प्रदेश के सबसे दूर के कोन में भी यन्त्रियों की प्रकृति यात्री भी भटक गया हो तो वह भी हजारों मील दूर बैठ रखा करने वाले लोग से सम्पर्क स्थापित करने की आशा कर सकता है। अतीत में मनुष्य द्वारा बनाए गए विनाश के मात्र अधिक से अधिक केवल कुछ खाद-मं मनुष्यों को मार सकते थे परन्तु आजकल का एक परमाणु बम या उल्जन बम १० ०० या उससे भी अधिक जनसंख्या वाले शहर का नाम निशान तक मिटाने के लिए पर्याप्त है।

सम्पर्क-स्थापन में हुई इस तीव्र गतिवृद्धि का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धों की समस्याओं पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा है। इसका परिणाम यह भी हुआ है कि अब पहले के किसी भी समय की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अधिक महत्वपूर्ण हो उठी है और राष्ट्रीय कल्याण का एक आवश्यक अंग बन गई है। अतीत काल में जबकि दूरी के कारण मनुष्य वस्तुतः विभक्त हुए रहते थे मसाले के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग अलग अलग अपने मानसिक और नैतिक प्रभाव बनाए रख सकते थे। परन्तु भौतिक निकटता और आध्यात्मिक दृष्टि में दूर दूरी यदि साथ-साथ रहें तो वस्तुतः एक बड़ी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आजकल सब मनुष्य अक्षरशः एक-दूसरे के पड़ोसी हैं। अब वे दिन-राम के बीच चुक रहे जब कोई भी राष्ट्र केवल अपनी सीमाओं के अन्दर रह सकता था और अपने विकास की गतिविधियों का कुछ कम या कुछ अधिक सपना के साथ अपनी इच्छानुसार चला सकता था। आजकल सारा के किसी भी भाग में जा कुछ होता है उसका सांसारिक प्रभाव अथवा सब भागों पर पड़ता है। परन्तु मनुष्य के मनाविज्ञान में अपने आपकी इस विनाश परिरक्षण के अन्तर्गत नहीं आता है। भौतिक दृष्टि से मनुष्य यह जानता है कि सारा ससार एक है परन्तु आजकल भी उसकी सवेगान्तर प्रतिप्रियाओं काफ़ी मनीषा है या अधिक से अधिक कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय है। मनुष्य की वृद्धि और उसकी भावनाओं के परिपुष्ट होने के बीच की यह साई एक मुख्य समस्या है जो इस समय हमारे समकालीन संसार के सम्मुख उपस्थित है।

इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनसे यह प्रगट होता है कि किसी एक मानव मूल्य का किसी एक समूह या वगैरह तक सीमित रहने का परिणाम अतृप्तता यह होता है कि उन मूल्यों का साथ सार समाज के लिए निषेध कर दिया जाता है। अतः जो बात किसी राष्ट्र के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों या समूहों के लिए सत्य थी आज विश्व-समाज में वही बात राष्ट्रों के सम्बन्ध में सत्य है। इसलिए प्रजातन्त्र के लिए एक पहली आवश्यक बात यह है कि इन मानव मूल्यों का प्रयोग सबजनों के रूप से किया जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि भारतीय प्रजातन्त्र का वास्तविक बनाना अभीष्ट है तो भारतीय जनता को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बहिष्मतापूर्वक रुचि लेनी चाहिए। प्राधुनिक संसार में आर्थिक और राजनीतिक विचार राष्ट्रीयता की बाढ़ से ऊपर रहते हैं। अर्थ देश के पान के बिना व्यक्ति का अपने देश के सम्बन्ध में ज्ञान भी अपूर्ण और अविश्वसनीय रहता। इससे अतिरिक्त आर्थिक राजनीति और प्रशासन परस्पर इस प्रकार घनिष्ठ रूप में जुड़ गए हैं कि राज्य को बरबस भीतर नागरिक के जीवन में उसका अपना कहीं अधिक हिस्सा लेना होता है जितना कि वह पहले कभी भी अज्ञात में लेता था। इसलिए प्राधुनिक प्रजातन्त्र के नागरिक को उतना पान होना चाहिए जितना पहले कवन कुछ बाढ़-से सौभाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता था।

संसार ही गिना का कार्यक्षेत्र (इसका क्षेत्र) अनुभव के क्षितिज का विस्तार करत जाना रहा है। वास्तविकता के साथ हमारा प्रत्यक्ष सम्पर्क सदा बहुत परिमित ही रहता है। यदि मनुष्य को केवल अपने तान्त्रिक अनुभव पर ही पूर्णतया निर्भर रहना पड़ता होता तो उसकी प्रगति बहुत ही सीमित रहती। मनुष्य साथ मृत्ति से ऊपर केवल इसलिए उठ सका है क्योंकि वह अपने कामों के अपने व्यक्तियों के अनुभव से भी लाभ उठान में समर्थ हुआ है। यदि मनुष्य में यह क्षमता न होती तो अपनी इच्छाओं की अत्यधिक दुर्बलता के कारण वह अपने प्रतिनिधियों के सम्मुख कभी का परास्त हो गया होता। यदि गिना मानविक क्षितिज का विस्तार करता हो तो यह स्पष्ट है कि गिना जितनी अधिक ऊँची होगी उतना ही अधिक विस्तृत क्षितिज वह हमारे सम्मुख खोल कर रख सकेगी।

परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी देश में उच्चतर शिक्षा जनता के



केवल एक थोड़ा-से भाग को छोड़कर अन्य लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती। अनेक देशों में तो प्रारम्भिक शिक्षा की भी व्यवस्था न तो सबके लिए सामान्य ही है और न पूर्ण ही। हालांकि इस प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा मनुष्य केवल प्रीकित रहन के लिए आवश्यक बातों का ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। दुर्भाग्य से यही वह मजिल है जिस पर पहुँचकर जहाँ तक भी हम भविष्य को देख सकते हैं अधिकतर लोगो को रुक जाना पड़ता है। किसी भी समाज के ८० प्रतिशत या इससे भी अधिक लोग प्रारम्भिक शिक्षा से भाग की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। सामान्य दशामा में उनका जीवन अपने पास-पड़ोस के घरे से बाहर भी कभी नहीं जाता। इनमें से अधिकतर लोग अपना मारा जीवन केवल दस या अधिक से अधिक बीस मील व्यासाय के घरे में रहकर ही बिता देते हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा से भाग जान वाले लोगो की समस्या बहुत भ्रष्ट होती है। इन लोगो को फिर दो वर्गों में बाँटा जा सकता है जिनमें से एक वर्ग अपेक्षाकृत छाटा होता है और दूसरा बड़ा। इनमें से बड़ा वर्ग सामान्यतया माध्यमिक शिक्षा से भागे नहीं जाना। इन लोगो की रुचियाँ का क्षेत्र कुछ अधिक विस्तृत होता है और उसी के अनुसार उनका मानसिक क्षितिज भी अधिक विस्तृत होता है। परन्तु वे भी सामान्यतया देश की नीति के रूप निर्धारण में प्रत्यक्ष अपने पास पड़ाने के क्षेत्र से बाहर होने वाली घटनाओं के निर्धारण में कोई सक्रिय भाग नहीं लेते। उन्हें जानकारी और नियम के लिए ऊर्ध्व और पहल करने के लिए उस अपेक्षाकृत छाट वर्ग पर आश्रित रहना पड़ता है जो उच्चतर शिक्षा का लाभ प्राप्त करता है। इस छाटे-भ वर्ग पर ही अपने देश की नीति को शप बतार के सम्मुख प्रस्तुत करने और क्षेत्र समार की नीति को अपने देशवासियों के सम्मुख प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आ पड़ती है।

परन्तु यदि प्रजातन्त्र का काम ठीक ढंग से चलाना अभीष्ट हो तो कम से कम प्रारम्भिक शिक्षा सभी नागरिकों को दी जानी चाहिए। जनता के लिए इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तम हो बना दायित्व है जितना कि कानून और व्यवस्था का बनाए रखना। यह काम इतना अधिक विस्तृत है कि कोई भी गैर-सरकारी या स्वच्छा से बनाई गई संस्था इस पूरा नहीं कर सकती। प्रारम्भिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों का भी

उसकी अपेक्षा कुछ न कुछ अधिक ही ज्ञान होना चाहिए जितना ज्ञान उनसे भाषा की जाती है कि वे अपने गिन्या को प्रदान करेंगे। इस प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में गिन्या देने वाले अध्यापकों का ज्ञान भी कम से कम विन्व विद्यालय के प्रमाण तक होना ही चाहिए। राष्ट्रीय गिन्या प्रणाली का संगठन करने में प्रमाणा को ऊँचा बनाए रखने सहायक सेवाओं की व्यवस्था करने प्रशासन पर्यवेक्षण और निरीक्षण की समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। इन सबके लिए प्रारम्भिक या माध्यमिक गिन्या-काल में प्राप्त होने वाली गिन्या की अपेक्षा बड़ी अधिक उच्चतर गिन्या प्राप्त होना की आवश्यकता होती है। हमारे गिन्या में कहा जाए तो विद्यालय जनना के लिए बिल्कुल प्रारम्भिक गिन्या की व्यवस्था करने के लिए भी काफी बड़ी मस्या में पड़े पुरुषों और स्त्रियों की आवश्यकता है जिन्हें विन्वविद्यालय में गिन्या प्राप्त हुई है।

इसलिए आधुनिक जगत में सामान्य रूप से गिन्या को और विन्व रूप से उच्चतर गिन्या को बड़ा महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना पड़ता है। लोगों के जीवन स्तर में कोई भी सुधार इस बात पर निर्भर होता है कि उस देश की भौतिक सम्पत्ति में वृद्धि हो। इस प्रकार की वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि देश के मनुष्यों तथा अन्य साधनों का अधिक से अधिक अच्छा उपयोग किया जाए। मनुष्यों और साधनों का अधिक से अधिक अच्छा उपयोग धार्मिक तथा प्राविधिक ज्ञान के विकास द्वारा ही किया जा सकता है। यह ठीक है कि अन्तर्गतता सारी सम्पत्ति का स्रोत प्रकृति है परन्तु आधुनिक जग का मनुष्य अपनी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए प्रकृति की विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करने का यत्न कर रहा है। यह ठीक ही कहा गया है कि आधुनिक जगत में कोई भी देश स्वतः दरिद्र या सम्पन्न नहीं है। कोई भी देश उतना ही सम्पन्न या दरिद्र है जितना उस देश के लोगों का ज्ञान अधिक या कम है। विज्ञान सभी स्थिति तक पहुँच चुका है जिसमें लगभग किसी भी वस्तु से कोई भी काम लिया जा सकता है। रसायन-विज्ञान न कागज और लकड़ी से काग़ और पेपर पैदा कर रहा है। इस प्रकार ज्ञान के रूप में कहना सही है। और धातुओं का स्थान कृत्रिम रूप से बनाए हुए पदार्थों में ले लिया है।

विन्वविद्यालयों की अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान और सद्भावना के प्रसार के केन्द्र के रूप में भी कार्य करना चाहिए। आधुनिक संसार में राष्ट्रीय प्रगति भी

तब तब नहीं की जा सकती जब तब उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मदभावना और भाति की पुष्टभूमि न हो। युद्ध सदा ही बिनाशकारी रहे हूँ परन्तु अतीत में युद्ध प्रायः सत्कार के किसी एक ही प्रदेश तक सीमित रहते थे। यहाँ तक कि जिन भागों में युद्ध हो भी रहा होता था वहाँ की भी असन्निध जनता युद्ध से किसी सीमा तक बची रहती थी। परन्तु आजकल बड़ी तेजी से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है जिसमें सटस्य लोग या युद्ध में किसी एक पक्ष में भाग न लेने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए आधुनिक युद्ध सारे समार को दोन-दरिद्र बना देगा। इसके प्रतिरिक्त उद्योग व्यापार और वाणिज्य इतने समर्पित हो गए हैं कि सत्कार के किसी भी भाग में हाने वाला किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल घटना की प्रतिक्रिया सत्कार के भाग सभी भागों पर होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि यदि प्रत्येक देश के सब नागरिक नहीं तो कम से कम नताभा की अवश्य इतना ज्ञान और उनमें इतनी सूक्ष्म-बुद्धि होनी चाहिए कि वे अपने देश के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय पुष्टभूमि की दृष्टि में रखते हुए ठीक-ठीक ढंग से चला सकें।

किसी भी प्रकार के समाज में नताओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है। बिना नताभा के अनिश्चित-सी विचारों जनता कोई काम कर ही नहीं सकती। प्रजासत्त प्रणाली से भिन्न समाज के रूपों में नता साग जन्म से ही नता होते हैं और चाहे उनमें नता के गुण न भी हों फिर भी उन्हें इसलिए नेता स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने नताभा के कार्य में जन्म लिया है। लोग भ्रातृ या सहजवृत्तिवादी उनके पीछे चलते हैं किन्ती व्यक्तिपुस्त विश्वास के कारण नहीं। इसलिए किसी न किसी प्रकार समाज का काम चलता ही रहता है। परन्तु प्रजासत्त में इस सहजवृत्तिपूर्ण भयवा भाव के कारण नताओं का अनुकरण करने का स्थान स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया हुआ आनापालन ले रता है। इसलिए प्रजासत्त में नताओं का कार्य और भी अधिक महत्वपूर्ण हो उठता है। गैर प्रजासत्तीय पद्धतियों में नेता के प्रति निष्ठा निष्क्रिय होती है जबकि प्रजासत्त प्रणाली में यह निष्ठा जान-बूझकर स्वेच्छापूर्वक अपनाई गई होती है और सचत चुनाव का परिणाम होता है। इसलिए प्रजासत्त में नताओं का चुनाव चरित्र और योग्यता के आधार पर होना चाहिए। लेकिन आजकल के सत्कार में चरित्र और योग्यता का ही आधार काफी नहीं है। आजकल के नताभा

को ज्ञान और तत्त्वज्ञान का आलोक प्राप्त होना भी आवश्यक है। समार के समुचित हो जान और ज्ञानानिव ज्ञान में वृद्धि हो जान के कारण प्राथमिक मनुष्य के हाथ में अत्यधिक विज्ञान सम्भावित नहीं हो पाई है। अज्ञान के ज्ञानों का अन्तर्गत का परिणाम यह हो सकता था कि किसी एक उपजाति या जाति या अधिक से अधिक किसी एक राष्ट्र का राष्ट्र उठाना पड़। वर्तमान परमाणु-युग में ज्ञानों की गतिविधि का परिणाम यह हो सकता है कि इस समार का सर्वज्ञ हो हो जाए।

प्रजातन्त्र में नेताओं का कार्य इतना महत्वपूर्ण होता है इसलिए प्रजातन्त्र में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। प्रजातन्त्र में ज्ञानों का चुनाव समाज के सब वर्गों में से होना चाहिए। यदि किसी एक विभागाधिकार प्राप्त वर्ग या समूह का ही देश के लिए ज्ञान प्रदान करने और उस क्षेत्र के साथ सम्बन्धित नाम प्रदान करने का विभागाधिकार प्राप्त है तो वस्तुतः यह प्रजातन्त्र ही नहीं है। इसलिए प्रजातन्त्र में सब लोगों को ज्ञान के लिए समान अवसर रहना चाहिए और यह केवल अभी हो सकता है जबकि सब लोगों को शिक्षा के लिए एक-ही सुविधाएँ प्राप्त रहें। उस देश में भी व्यक्ति-व्यक्ति में अन्तर रहेगा और वे अनेक दृष्टियों से एक-दूसरे से भिन्न बन रहेंगे। परन्तु इस प्रकार की विविधता प्रजातन्त्र के साथ सम्मत नहीं है। प्रजातन्त्र का यह धर्म भी नहीं है कि देश के सब निवासी राज्य के वास्तविक प्रशासन में समान रूप से हिस्सा लेते रहें हैं। यदि ऐसा करने का प्रयत्न किया जाए तो उसका परिणाम केवल आपा-भापी और अभावस्था ही होगा। प्रजातन्त्र में केवल इस बात की गारंटी रहनी है कि व्यक्तिगत को जो काम सौंपे जाते हैं वे उनकी सामर्थ्य के आधार पर सौंपे जाते हैं। किसी खान परिवार में जन्म होना अथवा धन के आधार पर नहीं सौंपे जाते। यदि सब लोगों को समान अवसर भी दिया जाए तो कुछ लोग अपनी बुद्धि या शक्ति के सहज गुणों के कारण अपने साधनों से धन बढ़ जाएंगे। वे ही समाज के स्वामित्व ज्ञान हों। उनकी नेतृत्व का अवसर प्रदान न करना उचित ही अप्रजातन्त्रात्मक है, जितना कि प्रजातन्त्रात्मक और सम्पूर्ण परिवार में उत्पन्न हुए अभाव्य व्यक्तिगत के नेतृत्व की स्वीकार कर लेना।

## ३

विश्वविद्यालयों का एक और भी काम है जो अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की भाँति भारतीय विश्वविद्यालयों को भी पूरा करना चाहिए। यह काम है—परम्परा और परीक्षण स्थायित्व और परिवर्तन के बीच आवश्यक सन्तुलन बनाए रखना। यह बात स्वतः सिद्ध है कि कोई भी समाज पूर्णतया अचल (स्टैटिक) नहीं रह सकता। बाहरी घटनाओं के दबाव के कारण समाज को अपने आकार प्रकार में कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहना पड़ता है। सूक्ष्म आन्तरिक परिवर्तनों के कारण भी अंगका चरित्र धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार कोई भी जीवन समाज परिवर्तन में बचा नहीं रह सकता। वस्तुतः बाह्य और आन्तरिक प्रेरणाओं का प्रतिग्रह (रिस्पोंस) करने की क्षमता ही इसकी जीविकी शक्ति का माप होती है। परन्तु नई वस्तुओं को अपना लेने और साम्य स्थापन करने की वह शक्ति आन्तरिक स्थायित्व और एकता पर आधारित रहती है। अन्यथा कोई भी समाज बेबल परिवर्तित ही न होगा अपितु ध्वस्त भिन्न हो जाएगा और अन्त में नष्ट हो जाएगा।

हम लग प्रायः उन बड़ी-बड़ी जातियों की वर्चा करते हैं जिन्होंने किसी जाति या देश के चरित्र को बदल डाला। ज्ञानि अतीत के साथ होन बाल एक उग्र परिवर्तन का चिह्न होती है। परन्तु कोई भी जाति अतीत से पूरी तरह सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर देती। फ्रांसीसी और रूसी जातियों की घटनाओं का मूल फ्रांसीसियों और रूसियों के चरित्र और इतिहास में विद्यमान था। फ्रांसीसी जाति में रूसी जाति की विषयताएँ उसने कुछ अधिक दृष्टिगोचर नहीं हो सकती जितनी कि रूसी जाति की विषयताएँ फ्रांसीसी जाति में दीख सकती हैं। जाति में धीमे धीमे और निरन्तर न पड़ने वाले परिवर्तन की प्रक्रियाएँ एकाएक बड़े स्पष्ट रूप में प्रकट हो उठती हैं। फिर भी इसका परिणाम कब यह होता है कि धीमे धीमे बढ़ती हुई प्रवृत्तियाँ अपनी चरम सीमा तक जा पहुँचती हैं। जब कोई आन्विकी समाज किसी गम्भीर समाज के सम्पर्क में आता है तब जो कुछ होता है उसकी सुलना में हमारी जातियों तो बड़ा मामूली-सा परिवार-मान जान पड़ती हैं। हमारे सामने इस सम्बन्ध में आस्ट्रेलिया और अमेरिका के देशी निवासियों के यूरोप की जातियों

के सम्पर्क में आने का उदाहरण मौजूद है। इन जातियों के परस्पर सम्पर्क में आने का परिणाम यह हुआ कि आदिवासियों की संस्कृति पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो गई और वे जातियाँ के लोग विपत्ति और मृत्यु के शिकार हो गए।

न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि समाज के लिए भी स्वस्थ रूप से प्रगति कर पाना तभी तक सम्भव है जब तक कि स्थायित्व को बनाए रखने वाली गतिविधियाँ और परिवर्तन उत्पन्न करने वाली गतिविधियाँ में समन्वय बना रहे। जड़ता का सिद्धांत (सा आफ इन्फॉर्मिटी) समाज पर भी अपना ही लागू होता है जितना कि समाज की भौतिक वस्तुओं पर। मनुष्य सामान्यतः तब तक नई-नई बातों से बचना चाहते हैं जब तक कि परिस्थितियाँ उन्हें उन बातों का स्वीकार करने के लिए विवश न कर दें। इसलिए अत्यधिक विवेचन समाज प्राप्त परिवर्तन को पसन्द नहीं करना और शिक्षा जाति विचार का ही एक उपकरण होती है। प्रायः एक परिवर्तन-विरोधी शक्ति होती है। परन्तु यह उतना परिवर्तन विरोधी नहीं होनी जितनी केवल धार्मिक या प्रथा परिवर्तन विरोधी होती है क्योंकि शिक्षा मन को एक ऊपर बनाने वाली शक्ति भी है यह मन के सम्मुख अतीत और वर्तमान स्थानीय और विदेशी विभिन्न प्रथाओं का समन वहीं अधिक विस्तृत श्रुतता प्रस्तुत कर देती है जितनी कि हम अपने प्रथम अनुभव से जान सकते हैं।

इस प्रकार शिक्षा एक ऐसा मनावृत्ति उत्पन्न करने में सहायक होती है जिसमें मनुष्य बिना उग्र उथल-पुथल के परम्पराओं में परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। आदिवासी समाजों में जो अधिकतर प्रथाओं और रुढ़ियों से शासित रहते हैं इस प्रकार की सचक दिसाई नहीं पड़ती और इसीलिए जब वे अन्य समाजों के सम्पर्क में आते हैं तो वे छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। शिक्षा जितनी जैसा हागी उनका ही अधिक अनुभव का विस्तृत रूप वह हमारे सामने ला सकेगी। इस प्रकार उच्चतर शिक्षा मनुष्य का यह समझने में समर्थ बनाने है कि हमारी वर्तमान मनावृत्तियों और संस्थाओं में क्या कुछ स्थायी है और क्या अस्थायी। यह शिक्षा उन्हें नई वस्तु का मूल्यांकन करना भी सिखाता है, जिससे कोई नया जीवन-मूल्य केवल इसलिए तिरस्कृत न कर दिया जाए क्योंकि वह नया है। शिक्षा नागरिकों से यह धारणा करती है कि वे अतीत और वर्तमान का अनुभव कर सकें, और इस प्रकार यह उन्हें भविष्य की चुनौती को

स्वीकार करने के लिए तैयार करती है। अग्रे देशों के विश्वविद्यालयों की भाँति भारतीय विश्वविद्यालयों को भी स्थिरता को बनाए रखने और समाज में सशक्त उत्पन्न करने का यह दुहरा कृत्य (फकान) पूरा करना होगा।

## ४

अब हम एक ऐसे कृत्य की ओर आते हैं जिसे पूरा करना विनाय रूप से भारतीय विश्वविद्यालयों का काम है। वह कृत्य है—संस्कृतिशास्त्र के समन्वय के लिए एक संयोजक समिति (कॉऑर्डिनेटिंग एजेंट) का रूप में काम करना। इस प्रकार की उक्ति पहलू-पहलू विरोधामात्र की प्रतीत हो सकती है। भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता दूसरों को अपने अन्दर मिला सकने की शक्ति और समन्वय रहती है। विभिन्नता में एकता अब तक भी जितनी प्राप्त की जा चुकी है, वह काफी है। परन्तु वह सचेत विचार के स्तर पर प्राप्त नहीं की गई। इस प्रकार का समन्वय अधिकांश सहजवृत्ति के द्वारा हुआ है और उसका आधार अनुभूतियों और भावनाओं से प्राप्त प्रेरणाएँ रही हैं। यही इस बात का मुख्य कारण है कि हमें भारत में साथ ही साथ विद्यमान समानान्तर समाज और संस्कृतियों दिखाई पड़ती हैं। भारतीय इतिहास की अनन्य दुर्लभ घटनाएँ इस समन्वय (इंटीग्रेशन) और एकीकरण की असफलता का ही परिणाम रही हैं।

इस बात का सबसे स्पष्ट प्रमाण भारत में विद्यमान तीन शिक्षा प्रणालियों के रूप में दिखाई पड़ता है जो समानान्तर धाराओं के रूप में साथ साथ बढ़ रही हैं। पश्चिम के सगमय सभी देशों में अलग अलग संस्थाओं या अनुशासनों में दिखाई पड़ने वाली बड़ी-बड़ी विध्वंसनाओं के होते हुए भी शिक्षा में सामान्य रूप से एकस्यता पाई जाती है। पश्चिम में बौद्धिक जीवन के वातावरण पर प्राकृतिक विज्ञानों का प्रभाव सबसे प्रमुख है। इसका धरत उन संस्थाओं पर भी पड़ा है जिनका उद्देश्य मानव-बुद्धि-विज्ञान का विरोध करना रहा है। पश्चिमी शिक्षा के भी अपने आन्तरिक उपभाग (डिवीजन) हैं परन्तु इस प्रकार के अन्तरों की तुलना भारत में विद्यमान शिक्षा के उपभागों के नहीं की जा सकती। पश्चिम में शिक्षा के क्षेत्र में उपस्थित एकता इसलिए है क्योंकि उस शिक्षा की जड़ें यूनानी और हिब्रू परम्पराओं में जमी हुई हैं और उगक ऊपर

वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव सबसे अधिक छाया हुआ है।

प्राधुनिक भारत में इस समय तीन ममानान्तर शिक्षा प्रणालियाँ विद्यमान हैं जिनका उत्पत्ति प्राचीन भारत में मध्यकालीन भारत में और पश्चिमी संस्कृति के सम्पर्क में आने के बाद हुआ है। अपने प्रारम्भिक दौर में स्वतंत्र रूप से दार्शनिक विचार करने के पश्चात् प्राचीन भारतीय शिक्षा साम्प्रदायिक साहित्यिक और मूल्यन्या दृष्टिपरक हो गई। इसमें एक अधिकारात्मकता (तात्तागोही) की भी ध्वनि आ गई जो सम्भवतः ऐसे समाज में आ जानी अनिवार्य ही है जिसमें विद्या तक केवल साहजिक अल्पसंख्यक लोग ही पहुँच हो। केवल इन साहजिक सीमावर्ती लोगों को ही भारत की विद्यालयी बौद्धिक सम्पत्ति तक पहुँचने का अधिकार था। उनके पास के कुछ छात्र-मात्रे का गायामा और कहानियों के रूप में सन्तों के नैतिक उपदेशों और धार्मिक गुरुओं के प्रवचनों के रूप में जनता तक प्रसार पहुँच जात था। परन्तु जनता तक जा जाना पहुँचना था वह विद्या के ज्ञान का बहुत छाटा-सा भाग होता था। इस प्रकार समाज में दो अलग-अलग ध्रुव तयार हो गए, जिनमें से एक ध्रुव पर तो वे बहुत साहजिक अल्पसंख्यक लोग थे जिनमें ज्ञान और बुद्धि केन्द्रित हो गई थी और दूसरे ध्रुव पर वे विद्यालय बहिष्कृत लोग थे जो अज्ञान और अंधविश्वास में डूब हुए थे। यह कोई आश्चर्य का बात नहीं कि इस प्रकार के समाज के स्वभाव पर बहुत सिद्धान्त और परम्पराओं तथा प्रथाओं के लौह नियम का प्रभुत्व मौज्जा ही छा जाए।

मध्य यग में मुस्लिम शासक अपने साथ शिक्षा की एक अपनी प्रणाली लेकर आए जा अरब और ईरान की परम्पराओं से प्रभावित थी। शुरु-शुरु में इस्लाम धार्मिक प्रज्ञान-आत्मक था। इसका परिणाम यह हुआ कि यह नई शिक्षा प्रणाली सिद्धान्त का दृष्टि से प्रज्ञान-आत्मक थी परन्तु व्यवहार में यह प्रणाली भी जनता के केवल एक छाट भाग तक ही सीमित थी। यह ठीक है कि जम के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने में कोई रोक नहीं थी परन्तु पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति इतना समीचीन थी और पाठ्य-विषय इतने कठिन थे कि मोह-से मुट्ठी-भर सदाके विद्वानों का छात्रवृत्ति कायम हो पाया ही निरुत्साहित हो जाते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा की भाँति यह प्रणाली भी मौज्जा ही अधिकारात्मक (तात्तागोही) अंग थी और बहुत सिद्धान्तात्मक हो गई। इसमें भी अधिक



दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि हम नई प्रणाली का विकास भारत की देशी प्रणाली से बिल्कुल पृथक् स्वतंत्र रूप में हुआ और लगभग उसके विरोध में हुआ। यदि इन दोनों प्रणालियों में कुछ बिन्दुओं पर परस्पर सम्पर्क हा जाता तो उनके स्पष्ट सिद्धान्तवादी के कारण ये दोनों ही अपने-अपने मिद्धातो में कुछ सुधार करती। परन्तु ऐसा नहीं हुआ और ये दोनों प्रणालियाँ साथ-साथ उन समानान्तर रेखाओं के रूप में चलती रही जो कभी भी परस्पर नहीं मिलती।

अधिकांश के भारत में माने जाने वाले इन दोनों प्रणालियों को एक नई प्रणाली से आरदार चुनौती मिली। परन्तु हम चुनौती का परिणाम यह नहीं हुआ कि भारतीय शिक्षा संगठित होकर एक बन जाती। इसके विपरीत हुआ यह कि दो विद्यमान प्रणालियों के साथ-साथ एक और तीसरी शिक्षा प्रणाली भी चल पड़ी। पश्चिमी शिक्षा सिद्धान्त की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से भी त्रमछा अभिवाधिक होने हुए रूप में सबके लिए खुसी थी। इस शिक्षा में न तो जात पात का और न धार्मिक भेदभाव का ही कोई स्थान दिया जाता था। सच तो यह है कि इसे सबसे पहले प्राप्त करने वाले बग कुछ पिछड़े हुए बग ही थे। इस पश्चिमी शिक्षा में विज्ञान और परीक्षणों पर अधिक जोर दिया गया था इसलिए भारतीय जीवन में यह एक नया तत्व आया। विश्वविद्यालयों की स्थापना से जिस रूप में आज हम उन्हें जानते हैं आलोचना करने की भावना को प्रोत्साहन मिला और इसके पनस्वरूप पुराने जीवन मूल्यों के सम्बंध में भ्रमताचीनी की जान लगी। परन्तु प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक ज्ञान के उत्तराधिकार को आपस में मिलाकर एक करने और सम्बन्धों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

परन्तु एक ही देश में रहने वाले लोग एक-दूसरे से बिल्कुल अलग-थलग नहीं रह सकते। भौगोलिक निकटता के कारण लोग को अनिवार्य रूप से एक-दूसरे के सम्पर्क में आना पड़ेगा। परिस्थितियों की आवश्यकताओं ने हिंदुओं और मुसलमानों को परस्पर समझौता करने के लिए विवश कर दिया। मध्य काल के बिल्कुल प्रारम्भ में ही इन दोनों में घनत्व स्तर पर घनत्व बढ़ाते में सम्पर्क प्रारम्भ हो गया था। दरबारों में और बाहरों में सामाजिक उत्पत्ति की दृष्टि से इन लोगों में एक-सा व्यवहार होने लगा था। गाँवों में समाज-सुधारकों धार्मिक मताओं और कवियों के प्रयत्न के फलस्वरूप इन दोनों के समान विद्वानों और

भारतीय विश्वविद्यालय के विषय में

समान प्रमाण विकसित हो चली थी। अतः नानक और रामानन्द जैसी पुरुषा ने हिन्दू की सबसे अलग-थलग रहने का प्रवृत्ति का समाप्त कर दिया और उन्होंने हिन्दू और इस्लाम के बीच की खाई का पाटन का प्रयत्न किया। दूसरी ओर मध्यमाना में भी कबीर चिन्ता और निरामदीन जैसे लोग ने विज्ञान हिन्दू-मनमाना में सम्भावना और एकता उत्पन्न करने की चेष्टा की। प्रत्येक प्रणाली में विज्ञान की विज्ञान का कुछ घन रिम-रिमकर अन्तता तक भी पहुँचता रहता था परन्तु प्रायः उसका रूप इतना बलम जाता था कि उसे पहचान पाना भी सम्भव नहीं होता था। अग्रजों के ध्यान के बाद मध्यम की ही भाँति फिर लोगों में परस्पर सम्पर्क स्थापित हुआ। फिर पहले की ही भाँति पश्चिमी विचारधारा के प्रभाव के फलस्वरूप पुरानी परम्पराएँ और प्रथाएँ अस्त-व्यस्त हुई परन्तु फिर पहले की ही भाँति उनमें समन्वय स्थापित हो गया जो भावनाओं पर अधिक और बड़ि पर कम आधारित था।

विचारों और व्यवहारों की एकताएँ दैनिक जीवन के मामलों की दृष्टि से बड़ा मूल्यवान् था। कोई चाहे ना इस प्रकार की एकता का समन्वय भी कह सकता है परन्तु यह समन्वय व्यवहार सम्भावना और मानव की सहज बड़ि के स्तर पर था। आत्मबलान्तर और सावधान विचार का समन्वय प्राप्त न होने के कारण इसमें ब दुर्बलताएँ थी जो सभी महज प्रवृत्तियों में पाई जाती हैं। यह समन्वय अभी तक टिक सकता था जब तक कि इस विन्नी प्रतिकूल सहज बलित न चुनौती न मिले। केवल अनुभूतियों और भावनाओं से प्राप्त प्रणालियों पर आधारित होने के कारण इस समन्वय में उस सुन्दरता का भी अभाव था जो केवल बौद्धिक स्पष्टता में ही उत्पन्न हो सकती है।

## ५

इस प्रकार भारत में लगभग एक सौ वर्ष तक तीन समानान्तर शिक्षा प्रणालियाँ साथ-साथ विद्यमान रही और फिर भी वे एक-दूसरे में ऐसे ढंग से घम-मिश्र नहीं करी जग कि एक समान दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आवश्यक है। इनमें से पश्चिमी शिक्षा प्रणाली तो प्राचीन भारतीय परम्परा पर आधारित है जिसका मक्य चाहत सस्कृत है दूसरी इस्लामी विचारों पर आधारित है और उसका माध्यम अरबी और फारसी है और तीसरी शिक्षा

प्रणाली आधुनिक यूरोप के दृष्टिकोण पर आधारित है और उसकी भाषा अंग्रेजी है। फजी और दारा जैसे या बाल के बाल में राजा राममोहनराय जैसे विरले लोग को छाड़कर विद्वान लोग न शिक्षा और ज्ञान की इन समानान्तर प्रणालियों में समन्वय कराना का प्रयत्न नहीं किया। हिंदुओं में स कुछ थोड़ा-सा लोग आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों से अरबी और फारसी सीखते थे परन्तु इस लोग संस्कृत नहीं सीख पाते थे। उससे भी कुछ कम संख्या में मुसलमान न संस्कृत का अध्ययन किया। अंग्रेजों के आगमन के बाद पहले हिंदुओं न और उसके बाद मुसलमान न अंग्रेजी का अधिवाधिक अध्ययन करना शुरू किया परन्तु जनता की अधिकांश संख्या चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान एक ही शिक्षा प्रणाली के घर में घूमती रही। संस्कृत के टोल (पाठगालाएँ) और अरबी के भक्तव दो ऐसी अलग-अलग दुनियाएँ थी जिनमें अंग्रेजी पढ़-लिख लोग का प्रवेश नहीं था।

आधुनिक भारतीय जीवन में जितनी अस्त-व्यस्तता थी उतनी ही उनमें से अधिकांश का कारण यही है कि विभिन्न वर्गों का विभिन्न क्षत्र में बाँटकर एक दूसरे से पथक कर दिया गया है। आजकल भी हमें ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जिनकी शिक्षा केवल प्राचीन भारत में निर्धारित आदर्शों और पद्धतियों के अनुसार हुई है। इस लोग के लिए बाल की गति अब से १५-२० वर्ष पहले ही बन्द हो गई दीखती है। इसी प्रकार एक और वर्ग है जिस अरबी और फारसी का तो अच्छा ज्ञान है किन्तु वह संस्कृत साहित्य की परम्पराओं और पश्चिमी देशों के आधुनिक ज्ञान से अनभिज्ञ है। दूसरी ओर विविधविद्यालयों में शिक्षा पान वाले लोग प्रायः संस्कृत अरबी और फारसी से अनभिज्ञ होते हैं। इस प्रकार विविधविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा की श्रेय संस्थाएँ उन समन्वय को प्रतिबिम्बित करने में असफल रही हैं जिस सन्तुष्टि और कविया ने सुधारकों और प्रचारकों न और यहाँ तक कि कम पढ़े हुए या अनपढ़ नर-नारियों न भी घर्म नीति और कला के स्तर पर प्राप्त कर लिया था।

एक-माथे रहने वाले नर-नारियों को एक-दूसरे से पूज्यता प्रयत्न करने नहीं रखा जा सकता। इसलिए बौद्धिक दृष्टि से पूज्य कर लिए गए समूहों ने भावना और पारस्परिक संबंध के क्षेत्र में आपस में सम्पर्क स्थापित कर लिए। बुद्धि और भावना के इस संमेलन के अभाव का परिणाम एक विचित्र प्रति

राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के विषय में

प्रया के रूप में यह हुआ कि व्यक्ति के मन में भ्रम-भ्रम खाने-से बन गए । एक व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से तो पश्चिमी विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करता है परन्तु भावनाओं की दृष्टि में प्राचीन या मध्यकालीन भारत की परम्पराओं में डूबा रहता है । विद्यार्थी की आधुनिकतम प्रणाली बर्ताव और भावनाओं की बिलकुल आदिकालीन पद्धतियों के साथ-साथ विद्यमान रहती है । इस प्रकार के विचलन (एबरशन) के मामला को यदि हम टाल भी दें—और उनकी सख्या इतनी अधिक है कि उनको इतनी आसानी से टाल लेना उचित नहीं कहा जा सकता—फिर भी हम बात में इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश में तीन स्वतंत्र शिक्षा प्रणालियों के सह-अस्तित्व के कारण आधुनिक भारत के शिक्षित नर-नारियों में से अधिकांश का बौद्धिक जीवन दृष्टि हा गया है ।

सारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा का एक समान (साम्प्रदायिक) प्रणाली न हान का ही यह परिणाम हुआ है कि आजकल भी इतन सार भारतीय प्रादेशिक भाषापरक भाषा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से ग्रस्त है । दूसरे दृष्टियों में विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक तत्त्व की विरासत का एक साम कोश में ले भान में बड़ी सहायता की है । भारत में ऐसा नहीं हुआ । इसका परिणाम यह हुआ है कि विभिन्न सम्प्रदायों और विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों में एक सखी अनुभाषिक (सकानल) दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया है और वह अब तक बना हुआ है ।

६

उच्चतर शिक्षा केवल बोर्डे-से बन हुए क्यों तब ही सीमित रही इसका भारतीय समाज पर एक और अवाछनीय प्रभाव हुआ है । हम ऊपर उल्लेख कर चके हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा पर ऐसा प्रतिबन्ध होने के कारण जनता में निम्न प्रकार शिक्षित और अशिक्षित के दो ध्रुव बन गए थे । समाज का विकास असमान रूप से हुआ और समय बीतने के साथ-साथ सुशिक्षित लोग अधिकांश अशिक्षित जनता द्वारा अपनाए जाने वाले पद्धतियों की विरुद्ध दृष्टि में देखने लगे । आजकल उच्चतर शिक्षा के द्वार बंदी अधिक लोग लिए गलत जा रहे हैं । परन्तु शारीरिक श्रम के विभिन्न रूपों के प्रति यथार्थता नहीं तो भी उपमा की पुरानी प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है । प्रवृत्तिबल इस बात के प्रमाण दीव पढ़ने हैं कि देहाती और शहरी जनता

प्रणाली प्राधुनिक यूरोप के दृष्टिकोण पर आधारित है और उसकी भाषा अंग्रेजी है। फंजी और दारा जसे या बालू के बाल में राजा राममोहनराय जैसे बिरले लोगो को छोड़कर विद्वान् लोगो न गिना और ज्ञान की इन समानान्तर प्रणालिया में समय-बय परान का प्रयत्न नहीं किया। हिन्दुओं में से कुछ मोड़-मे लोग आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों से अरबी और फारसी सीखत थे परन्तु ऐसे लोग संस्कृत नहीं सीख पाते थे। उससे भी कुछ कम संख्या में मुसलमानों ने संस्कृत का अध्ययन किया। अंग्रेजों के आगमन के बाद पहले हिन्दुओं ने और उसके बाद मुसलमानों ने अंग्रेजी का अधिकाधिक अध्ययन करना शुरू किया परन्तु जनता की अधिकांश संख्या चाहें वह हिन्दू हो या मुसलमान एक ही शिक्षा प्रणाली के घरे में घूमती रही। संस्कृत के टाल (पाठशालाएँ) और अरबी के मकतब दो ऐसी असंग-असंग दुनियाएँ थी जिनमें अंग्रेजी पढ़-लिख लोगो का प्रवेश नहीं था।

प्राधुनिक भारतीय जीवन में जितनी असंतोषजनक चीजें हैं उनमें से अधिकांश का कारण यही है कि विभिन्न वर्गों को विभिन्न क्षत्रों में बाँटकर एक दूसरे से पृथक् कर दिया गया है। आनन्द भी हमें ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जिनकी शिक्षा केवल प्राचीन भारत में निर्धारित आत्मा और पद्धतियों के अनुसार हुई है। ऐसे लोगो के लिए ज्ञान की गति अब से १५०० वर्ष पहले ही बन्द हो गई दीखती है। इसी प्रकार एक और वर्ग है जिसे अरबी और फारसी का तो अच्छा ज्ञान है किन्तु वह संस्कृत साहित्य की परम्पराओं और पद्धतियों के प्राधुनिक ज्ञान से अनभिज्ञ है। दूसरी ओर विश्वविद्यालयों में शिक्षा पान वाले लोग प्रायः संस्कृत अरबी और फारसी से अनभिज्ञ होते हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा की श्रेष्ठ संस्थाएँ उस समय-बय को प्रतिबिम्बित करने में असफल रही हैं जिस सन्ता और बच्चों ने सुधारकों और प्रचारकों ने और यहाँ तक कि कम पढ़े हुए या अनपढ़ घर-आरिषा न भी कम नीति और कला के स्तरों पर प्राप्त कर लिया था।

एक-भाषा रहन-बाहन पर-आरिषों को एक-दूसरे से पूषतया पूषक करने नहीं रखा जा सकता। इसलिये बौद्धिक दृष्टि से पूषक कर लिए गए समूहों ने भावना और पारस्परिक कर्तव्य के क्षेत्र में आपस में सम्पर्क स्थापित कर लिए। बुद्धि और भावना के इस समेकन के अभाव का परिणाम एक विभिन्न प्रति

क्रिया के रूप में यह हुआ कि व्यक्ति के मन में अनन्त-अनन्त खान-खान बन गए । एक व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से तो पश्चिमी विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करता है परन्तु भावनाशा की दृष्टि से प्राचीन या मध्यकालीन भारत की परम्पराशा में डूबा रहता है । विचारों की आधुनिकतम प्रणाली वर्तमान और भावनाशा की विलकुल आन्तिकालान पद्धतियाँ के साथ-साथ विद्यमान रहती हैं । इस प्रकार के विचलन (एवरेजिंग) के मामलों का यदि हम टाल भी दें—धीरे उनकी समस्या इतनी अधिक है कि उनका इतनी आसानी से टाल देना उचित नहीं कहा जा सकता—फिर भी इस बात में इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश में तीन स्वतंत्र शिक्षा प्रणालियों के सह-अस्तित्व के कारण आधुनिक भारत के शिक्षित नर-नारियों में स अधिकार का बौद्धिक जीवन दृष्टि हो गया है ।

सारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा की एक समान (सामी) प्रणाली न होना का ही यह परिणाम हुआ है कि आजकल भी इतने सारे भारतीय प्राग्नेयिक भाषापरक अथवा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण में अस्तित्व में हैं । दूसरे देशों में विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक तत्व की विरासत को एक साम्प्रदायिक क्षेत्र में ले आने में बड़ी सहायता का है । भारत में ऐसा नहीं हुआ । इसका परिणाम यह हुआ है कि विभिन्न सम्प्रदायों और विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों में एक-सकल अनुभाषिक (सकलानल) दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया है और वह अब तक बना हुआ है ।

## ६

उच्चतर शिक्षा केवल बोर्डों-के बन हुए क्यों तक ही सीमित रही इसका भारतीय समाज पर एक और अवांछनीय प्रभाव हुआ है । हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा पर ऐसा प्रतिबन्ध होने के कारण जनता में जिस प्रकार शिक्षितों और अशिक्षितों के अन्तर्भाव बन गए थे । समाज का विकास असमान रूप में हुआ और समय-बातन के साथ-साथ सुशिक्षित लोग अधिकांश अशिक्षित जनता द्वारा अपनाए जाने वाले पथों का विरोध करने की दृष्टि में अलग सगे । आजकल उच्चतर शिक्षा के द्वार नहीं अधिक लोगों के लिए खोल जा रहे हैं । परन्तु गाररिज थम के विभिन्न रूपों के प्रति यत्नि पूर्ण नहीं तो भी उसकी पुरानी प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है । इसके प्रतिकूल इस बात के प्रमाण स्पष्ट पड़ते हैं कि देहाती और ग्रामीण जनता के

जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि भारतीय ज्ञान को प्रायः धरती विचार धारा का एक विकल्प समझा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में भारतीय इस्लामी और यूरोपियन इन तीनों प्रणालियों का जिन्हान प्राधुनिक भारतीय चेतना को प्रभावित किया है एक प्रणानीबद्ध और मुमगत अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। हमारे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्कों के कारण यह भाव दबक हो गया है कि जिन तत्त्वों का भारतीय विचारधारा पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं भी पड़ा उह भी हमारे पुनर्गठित पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। आज के सुदूरपूर्व के देशों की विचार प्रणालियाँ सगमय अज्ञात ही ह। परन्तु जब तक मानव विचार व विज्ञान में उनके योगदान की उपेक्षा की जाएगी तब तक मानव विचार के विकास का चित्र स्पष्ट नहीं बन सकता। किसी भी विविष्ट क्षेत्र में विविध योग्यता प्राप्त करना तभी उपयोगी और सुजननील हो सकता है जबकि वह इस प्रकार के सामान्य ज्ञान पर आधारित हो।

भाषाभाषा के अध्ययन का क्षत्र इस बात का एक और उदाहरण है कि हमारे पाठ्यक्रम किस प्रकार संकुचन सीमाभाषा में बंधे ह। आक्सफोर्ड के लिटरे ह्यूम नियोजन जते पाठ्यक्रम का मुख्य बल इस बात में निहित है कि उनमें तरण मन्तिज्यों को यूरोप की दो सबसे महत्वपूर्ण सम्प्रदायों के सम्पर्क में लाया जाता है। इस पाठ्यक्रम का स्वीकार करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ग्रीक और लटिन भाषाओं अध्ययन पढ़ना पड़ती हैं और उस यूनान और रोम दोनों के दार्शनिक विचारों और राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनाभाषा (स्ट्रक्चर) का अध्ययन करना पता है। इसके विपरीत भारत में जो लोग संस्कृत का अध्ययन करते हैं वे प्रायः पाली तक ही अग्रगण्य रहते ह। इसी प्रकार जो लोग फारसी का अध्ययन करते ह उनमें से अनेक को अरबी का ज्ञान नहीं के बराबर होता है। अभी तक किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय ने संस्कृत और अरबी का या पाली और फारसी का एकीकृत अर्थात् मिला-जुला पाठ्यक्रम तयार नहीं किया। यदि भारतीय संस्कृति को उसके सब पहलुओं की दृष्टि से हृदयगम करना अभीष्ट है तो देश में कम से कम कुछ विद्वान् एवम् अवश्य होना चाहिये जिन्हें संस्कृत और फारसी पर तथा पाली और अरबी पर समान रूप से अधि कार हो। यूरोप में प्राचीन साहित्य के विद्यालयों में यूनान और रोम की दो

सम्पन्न और विभिन्न सम्पत्ताओं के साथ परिचित होने के कारण निम्न करने का परिपक्व गति विकसित हो जाती है और उन्हें बौद्धिक स्वच्छता प्राप्त हो जाती है। यदि हमारे प्राचीन साहित्य के पाठ्यक्रमों को इतनी ही उदारता से तैयार किया जाए तो हमारे साहित्यिक विद्वानों का प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय सम्पत्ताओं के ज्ञान द्वारा कम से कम उतना ही विस्तृत और मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित कर पान का अवसर प्राप्त होगा।

इस प्रकार के प्रस्ताव के विरुद्ध एक आक्षेप यह किया जा सकता है कि इससे प्राचीन साहित्य का विस्तृत अध्ययन तो हो जाएगा किन्तु गहरा अध्ययन नहीं हो पाएगा। परन्तु यह आक्षेप यक्तिमत्त नहीं है। जिन भाषा में अध्ययन शीलता की आवश्यकता नहीं है उन्हें अध्ययन के बाहेत जिस क्षेत्र में छाड़ दिया जाए वे केवल उथला-उथला अध्ययन ही करगें। आजकल इस प्रकार के विद्यार्थी एक बहुत ही संकुचित क्षेत्र में उथला-उथला ज्ञान प्राप्त कर पाने हैं। दूसरी ओर जिन्हें ज्ञान और अध्ययनशीलता से प्रेम है वे अपनी पसन्द से चुने हुए अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में विविध ज्ञान प्राप्त करते ही रहेंगे। एक विस्तृत पाठ्यक्रम बनाने से उन्हें केवल यह सहमता मिलेगी कि वे जिस विषय में विविधता प्राप्त करेंगे उनमें और भी अधिक गहराई तक पहुँच सकेंगे। यदि हमारे विश्वविद्यालय अपने वास्तविक प्रयोजन का पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें एक ऐसी विस्तृत और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की विभिन्न धाराओं का समान रूप से अध्ययन और मूल्यांकन हो सके।

जब तक हमें उन अनक साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है जहाँ से भारतीय संस्कृति का उद्गम हुआ है तब तक हम उनका महत्त्व उसकी विविधता और उसकी जीवन-शक्ति को हृदयगत नहीं कर सकेंगे। इसलिए भारतीय विश्वविद्यालयों का संस्कृति के वातावरण के रूप में और प्रगति के अग्रदूतों के रूप में इस प्रकार के पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए जिनमें भारतीय जीवन के अनक पहलू प्रतिबिम्बित हों। विश्वविद्यालयों को एक ऐसा संगम बन जाना चाहिए जहाँ प्राचीन और मध्यकालीन भारत से उत्तराधिकार में प्राप्त जीवन-मूल्यों का इस



समय विदेशों से आने वाले ज्ञान और अनुभव के साथ सम्मिश्रण हो सके। केवल इसी प्रकार विश्वविद्यालय हमारे राष्ट्र के अन्दर विद्यमान सत्ता में एकता स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं और जागा में ऐसी कल्पना की दृष्टि और बौद्धिक विगासता उत्पन्न कर सकते हैं जो भारतीय संविधान में घोषित प्रजातन्त्र, याय स्वतन्त्रता समानता और बहुत्व के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आवश्यक है।

## अध्याय ६ अंग्रेजी का अध्ययन

यह बात सुनने में आश्चर्यजनक प्रतीत होती है पर फिर भी यह सत्य है कि स्वाधीनता के बाद अंग्रेजी के अध्ययन की माँग बढ़ती ही गई है। जो लोग पहले अंग्रेजी के सम्बन्ध में उदासीन थे वे अब उसका अध्ययन में बड़ी रुचि लेने लगे हैं। यह बात देहाती लोगों के सम्बन्ध में विशेष रूप से सत्य है। अतीत में गाँवों के अधिकांश विद्यालयों में अंग्रेजी का पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी शायद ही किसी न किसी इस बात की गिनायत की है। परन्तु आजकल गाँवों के लोग अधिकाधिक यह माँग कर रहे हैं कि गाँवों के विद्यालयों में अंग्रेजी की पढ़ाई की जगह ही सुविधाएँ दी जाएँ जैसी शहरों के विद्यालयों में दी जाती हैं।

इस परिवर्तन के अनेक कारण हैं। अतीत में सरकार शहरों के लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का बड़ा अधिक ध्यान रखती थी। इसलिए शिक्षण का सुविधाएँ मुख्य रूप से शहरी इलाकों में ही केन्द्रित थीं। गाँवों के लोगों का यह प्रवृत्ति अमात्यपूर्ण प्रतीत भी होता था तो भी उनमें प्रायः इतना सहन और पहचान करने की भावना नहीं होती थी कि वे अपनी माँग का अधिकारियों के सम्मुख जोर देकर रख सकें। आजकल सारे देश की जनता ही अपने प्रभाव और शक्ति के सम्बन्ध में अधिकारियों से चेत हो रही है। ग्रामीण लोग भी इससे अपवाद नहीं हैं और उनकी यह माँग है कि उनके बालकों को भी वे ही सुविधाएँ दी जानी चाहिए जो शहर के बालकों को

प्राप्त है। देहाती विद्यालयों में अंग्रेजी के अध्ययन की मांग बढ़ते जाने का शायद यह भी एक बड़ा कारण है।

फिर भी यह बात असंगत-भी प्रतीत होती है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद एक विदेशी भाषा के अध्ययन को इतना महत्व क्या दिया जा रहा है। पहले समय में जो भी लोग जीवन में भाग बढ़ाना चाहते थे उन्हें अंग्रेजी पढ़नी ही पड़ती थी। सरकारी नौकरों के लिए तो यह आवश्यक बात थी हाँ अन्य लोगों में भी कोई व्यक्ति जब तक सफल नहीं हो सकता था जब तक कि उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान न हो। जो लोग वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में जाते थे उनके लिए भी अंग्रेजी का ज्ञान न होना एक बड़ी बाधा ही बनी रहती थी। इस प्रकार की विवशताओं के होना हुए भी स्वाधीनता के पहले भारत में अंग्रेजी के विरुद्ध भावना बनी लाज थी। यहाँ तक कि जो लोग सभ्यता और विज्ञान के माध्यम के रूप में इसके मूल्यों को स्वीकार भी करते थे वे भी इस बात पर सहमत थे कि अंग्रेजी के अध्ययन पर जो अनावश्यक जोर दिया जा रहा है वह समान्य हो जाना चाहिए। परन्तु अब अनावृत्ति पूर्णतया बदल चुकी है। आज जबकि देश स्वतंत्र है और अगर हम चाहें तो अंग्रेजी के अध्ययन को बिल्कुल ही बन्द कर सकते हैं जनता के सभी वर्गों में और लगभग सभी प्रदेशों में अंग्रेजी के अध्ययन की मांग निरन्तर बढ़ती ही जा रही है।

यह मांग इतनी विस्तृत रूप से व्यापक है यह बात भारत के देशों में उच्चतर शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने और उसके सुधार के लिए शिफारिशें करने के सम्बन्ध में हाल ही में किए गए एक परिमाण (सर्वेक्षण) के दौरान में बहुत स्पष्ट हो गई थी। इस प्रकार का सर्वेक्षण या परिमाण धनक वारणा से आवश्यक हो गया था। प्रजातंत्र शासन में सब नागरिकों को उन्नति का अवसर समान रूप से मिलना चाहिए। इस प्रकार के अवसरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है—उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर। स्वाधीनता से पूर्व भारत में शिक्षा की मुविषाएँ बड़े ही अममान रूप से बँटी हुई थी। यह ठीक है कि प्रारम्भिक विद्यालयों की अधिकांश समस्या देहाती क्षेत्रों में थी परन्तु यह उस अनुपात में नहीं थी जिसमें कि देश की जनता गाँवों और शहरों में रहती है। इनके अतिरिक्त गाँवों के विद्यालय लगभग निरपवाद रूप से शहरों की अपेक्षा घटिया बिस्म के थे। माध्यमिक शिक्षा के मामले में

तो गांवों की दगा घोर भी गई-गुजरी थी और माध्यमिक शिक्षा में धाग का (माध्यमिकातर शिक्षा की) तो न्यमग्न सभी शिक्षा-मस्याएं गहरों और कम्यों में ही पा ।

इस प्रकार गाँवा के लोगों को वे सुविधाएँ प्राप्त नहीं था जो उनके अधिक मौनान्यासा गहरा में रहने वाले गाँवा नागरिका को प्राप्त था । इस प्रकार के प्रबंध में एक और बड़ी त्रुटि थी । दहाणा क्षत्रा में युवरा का उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गहरा में आना पड़ता था । जब वे अपने जीवन का सबसे अधिक प्रभावग्रहणाल भाग गहर के वातावरण में बिता देते थे तो इसमें कुछ प्राचय नहीं कि उनमें से अधिकांश वापस गाँव में आकर रहना पसन्द नहीं करते थे । इस प्रकार दहानी क्षत्रों से गहरी क्षत्रा की ओर लोग का आते जाना भी विचार और विना के विषय बन गया था । स्थानान्तरण का एक बड़ा कारण दहाती क्षत्रा में शिक्षा का सुविधाभावा का न होना है ।

इसलिए प्रज्ञानत्र की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए और नव लोगो को उन्नति का समान अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि गाँवा में शिक्षा की अधिकाधिक सुविधाएँ देने की व्यवस्था की जाए । यदि हम चाहते हैं कि दगाओं से लोगो का गहर की ओर खिंचने का आना रुक जाए तो उसके लिए मा अभी आवश्यक है । इसका अर्थ केवल प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर ही बड़े विद्यालय पमान पर शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना नहीं है, अपितु उच्चतर शिक्षा के लिए भी नई सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी । दहानी क्षत्रा में उच्चतर शिक्षा की इस समस्या का हल करने के लिए ही भारत सरकार ने यह समिति नियुक्त की थी जिसका उत्पल पहले किया जा चुका है । यह समिति जहाँ जहाँ भी गई वने इसने यह देखा कि सब जगह न केवल सामान्य रूप से उच्चतर शिक्षा की जोरदार माँग है अपितु अग्रजी के अध्ययन की अधिकाधिक सुविधाओं की विप्रेय रूप से माँग है । यह बात एक स्पष्ट या बरछ माल के वाक्य द्वारा स्पष्ट रूप से एक उत्तर से बहुत स्पष्ट हो गई थी । यह वाक्य गुरु एवं अग्र का निरामा था जो अब तक शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ समझा जाता था । उसने पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उस बालक ने बताया कि वह अर्थ जिसी भी वस्तु की अग्रजा भद्रजा का अध्ययन अधिक करना चाहता है । जब उससे पूछा गया कि तुम आखिर अग्रजी को इतना अधिक

पसन्द क्यों करते हो तो उसका उत्तर था यदि मैं अग्रजी नहीं पढ़ूंगा तो मैं भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूँ ?

हम इसे एक मूर्ख बालक का मूखतापूर्ण उत्तर समझकर टाल भी सकते हैं परन्तु बाइबिल में एक जगह कहा गया है कि सत्यप्राय बालका और बच्चों के मुख से प्रकट होता है। इस मामले में भी बालक वस्तुतः एक सत्य की अभिव्यक्ति कर रहा था हालाँकि उसे यह पता न था कि जो कुछ वह कह रहा है उसका अर्थ कितनी दूर तक जाता है। यदि हम इस उत्तर पर गहराई तक विचार करें तो हमें अनुभव होगा कि इसका उत्तर उस युग का प्रतीक था। इस उत्तर में दो भाषाशास्त्री अभिव्यक्ति की गई हैं जो वर्तमान भारत में सबजान बन गई हैं। इनमें से पहला भाषाशास्त्री है प्रजातन्त्र की और प्रजातन्त्रात्मक चेतना की वृद्धि की। क्योंकि इसी भाषाशास्त्री के कारण यह सम्भव हुआ कि एक पिछड़े हुए ग्राम के गाँव का बालक भी यह सोच सका कि वह किसी दिन भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। इस भाषाशास्त्री के साथ ही यह माँग भी जुड़ी हुई है कि प्रजातन्त्र में सबका उन्नति का समान अवसर मिलना चाहिए। यदि अग्रजी की शिक्षा उन लोगों के बच्चा के लिए आवश्यक समझी जाती है जिनके हाथ में धाज देना की राजनीति बन सता है तो यह उन लोगों के बालकों के लिए भी समान रूप से आवश्यक समझी जानी चाहिए जो अब तक देश के नागरिक न रहकर केवल प्रजा के रूप में जी रहे हैं।

उस बालक ने अपने उत्तर में अनजाने ही जिस दूसरी भाषाशास्त्री को व्यक्त किया था वह है समाज के विभाजन के जीवन में भाग लेने की भाषाशास्त्री। प्राधुनिक समाज में कबल अपने देश के सम्बन्ध में ही जान प्राप्त कर लेना काफी नहीं है। जो भी कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में प्रतिष्ठि प्राप्त करना चाहता है उसे सारे समाज में बह रही बड़ी-बड़ी विचारधाराओं के सम्पर्क में रहना होगा। प्राधुनिक समाज में अनवरत रूप से इतिहास और अर्थशास्त्र राजनीति और धर्मों के ज्ञान के बिना नृत्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अग्रजी बाह्य समाज के साथ इस सम्पर्क का प्रतीक है और यही कारण है कि वह सीधा सीमा गाँव का बालक था जिसने भी वस्तु की अपेक्षा अग्रजी पढ़ना अधिक पसन्दी समझता था।

१

प्राधुनिक भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हममें एक ऐसे त्रिजगत् की भावना बसती जा रही है जिसमें समाज के सब सदस्यों को उन्नति का समान अवसर मिलना चाहिए। एक अर्थ में यह हमारा अपन भतीत से ज्ञानिकारा सम्बन्ध-विच्छेद-मा है और यह सम्बन्ध-विच्छेद केवल हमारे अपन ही भतीत में नहीं है अपितु यह नई प्रजातन्त्रात्मक आकांक्षा सारे सत्तार की पुरानी सामाजिक धारणाओं से स्पष्ट रूप से बिलकुल भिन्न है। अथ प्राचीन समाजों की भाँति भतीत में भारतीय समाज भी मुख्य रूप से वगत्तन्त्रात्मक (हियराकिल) रहा है। परन्तु आज सारे समाज में ही इस प्रकार के वगत्तन्त्रात्मक समाज का आधार नष्ट हो गया है। अतः देना में इस समय पुराने सामाजिक रूपा और उन नई आकांक्षाओं का वाच्य संघर्ष चल रहा है जो आकांक्षाएँ पुराने ढाँचा में नहीं समा सकतीं। यदि यह पूछा जाए कि मानवीय व्यवहारों और पुराने पड़े गए वगत्तन्त्रात्मक समाज में यह ज्ञानिकारी परिवर्तन किस कारण हुआ तो उत्तर में कहा जा सकता है कि इसका कारण विज्ञान और प्रविधि अथवा गिन्य में हुई अत्यधिक प्रगति है। यदि फिर यह पूछा जाए कि विज्ञान और प्रविधि में यह उन्नति किस प्रकार सम्भव हुई। इसका उत्तर गायन मनुष्य द्वारा प्रकृति के रहस्यों की अधिक और अधिक जानकारी के ज्ञान में मिले। दूसरे शब्दों में विज्ञान और प्रविधि की यह उन्नति प्राधुनिक जगत् में गिना और ज्ञान के अत्यधिक प्रसार के फलस्वरूप हुई है।

यह अवलोकन का बात नहीं है कि विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ प्रजातन्त्र की भावना में भी वृद्धि हुई है। हमें इस बात को अनुभव करना चाहिए कि प्रजातन्त्र में गिना के कृत्य के सम्बन्ध में कोई भी विचार-विमर्श अब तक पर्याप्त नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसमें इस बात पर पूरा ध्यान न दिया गया हो कि ज्ञान के क्षेत्र में हुई इन प्रगतिओं ने मानवीय इतिहास में ऐसी क्रियाएँ पैदा कर दी हैं जो पहले कभी नहीं हुई थीं। वगत्तन्त्रात्मक समाज भतीत में केवल दो कारणों से विघटित रह सके थे। परिवर्तन और सम्पन्न-स्थापन (महार) के साधन सन्तोषजनक न होने के कारण सत्तार नई रूप-रचना समाज में बटा हुआ था जिनका एक-दूसरे से कोई

सम्पन्न नहीं होता था। इस प्रकार के प्रत्येक समाज में उसका अलग अपने ढंग का धनतन्त्र था और उसकी विशिष्टाधिकारों की अपनी अलग ही प्रणाली होती थी। किसी एक ही समाज के अन्दर रहते हुए व्यक्ति को कभी उस विद्याधिकार की प्रणाली के सम्बन्ध में आशङ्कित करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता था। प्रायः व्यक्ति को उस समाज के अतिरिक्त जिसमें कि वह उत्पन्न हुआ होता था और रहता था किसी अन्य सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं होता था। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसी परिस्थितियों में धनतन्त्रात्मक समाज क्षताभिन्यो तब रह सके।

धनतन्त्रात्मक समाजों के अस्तित्व का दूसरा कारण मरार की उस समय की अथ व्यवस्था पर आधारित था। उस समय की अर्थ-व्यवस्था मुख्य रूप से अभावों की अर्थ-व्यवस्था थी। क्योंकि प्रकृति की शक्तियों पर मनुष्य का नियन्त्रण सीमित था इसलिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा सीमित थी। केवल उन छोटे से लोगो को छोड़कर, जो दूसरा के धर्म पर जीवित रहते थे अन्य लोगो को अवकाश या कुरसत नाम की चीज का पता न था। परन्तु सम्यता और संस्कृति की प्रगति के लिए आवश्यक बातें यह कि लोगो के पास अवकाश हो और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद भी उनके पास कुछ न कुछ सामग्री बच रहती हो। समाज के उस समय विद्यमान आर्थिक संगठन में व्यक्ति अथवा लोगो के दण्ड केवल उसी दण्ड में खाली समय अथवा आवश्यकता से अधिक वस्तुएं प्राप्त कर सकते थे जबकि कुछ लोगो को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से भी वंचित कर दिया जाए। ऐसे समाज में दासता घायल अनिवार्य ही थी। हम दलते हैं कि प्लेटो और अरस्तू जने उत्तार और मनुष्यता प्रती विचारणा न भी क्षमता की प्रथा का समर्थन किया था। उनका विचार था कि इस समय की दण्डाभा में संस्कृति तब तब पतन ही नहीं मरनी जब तक कि बहुमंश्यक साग उन अतिरिक्त सम्पत्ति का उत्पादन न करें जिसका उपभाग अल्पमंश्यक लोग कर रहे हैं।

विज्ञान की प्रगति के परस्पररूप प्रविधि विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि संसार की अर्थ-व्यवस्था का आधार ही बन गया है। आजकल इतना उत्पादन किया जा सकता है कि जिससे सब लोगो की आवश्यकता पूरी हो सके। मर ता यह है कि आजकल के सामान्य आन्धों का भी वे गुविद्या प्राप्त

ह जो पहल जमान में राजाओं और बड़-बड़ मनपतिया को भा प्राप्त नहीं थी। इसलिए इस बात की आवश्यकता नहीं रही है कि एक व्यक्ति को भवकाश या खानी समय केवल उसी दगा में प्राप्त हा सके जबकि उसके बन्ने किसी अन्य व्यक्ति को बड़ा नीरस परिधम करना पड़ रहा हो। इस प्रकार सामाजिक बगल-नवाद का एक प्रमुख कारण समाप्त हा चुका है।

प्रविधि विज्ञान में उन्नत होन के फलस्वरूप सम्पत्-स्थापन (संचार) और परिवहन के साधना में बड़ा भुघार हा गया है। अब ससार के लोग दूरी भयवा भौतिक बाधाओं के कारण एक-दूसरे से बिभक्त नहीं रहे ह। इसका परिणाम यह हुआ है कि ससार निनोदिन घनीभूत होता जा रहा है। ऐसे समाज और जागिया जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि घलग घलग है और जो विकास की भलग भलग स्थितिया म विद्यमान ह एक-दूसरे के धनिष्ठ सम्पत् में आए। विभिन्न प्रकार के समाजो और व्यक्तियों के इस प्रकार परस्पर सम्पत् में भान के फलस्वरूप लोगो न यह अनुभव कर लिया कि किसी भी प्रकार क बगल-नवाद की प्रणाली में भयवा विभाधिकारो में कोई निष्प या पवित्रता की कोई बात नहीं है। इससे भगला कदम यह था कि किसी भी समाज में किन्ही व्यक्तिया या वगो को प्राप्त विभाधिकारा क सम्बन्ध म नुक्ताचीनी की जाए। भलग भलग समाजो की प्रणालिया की तुलना करने का परिणाम यह हुआ कि बहुत-स पुरान स्वीकृत विद्वान समाप्त हो गए। लोग अधिकाधिक इस बात का धनभध बन लग कि किसी भी व्यक्ति का जन्म भयवा सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर कोई विद्यपाधिकार प्राप्त करन का हक नहीं है।

विज्ञान की प्रगति न धर्म-नवाद के विभाधिकारो को समाप्त करन में एक और ढग स भी सहायता का। विज्ञान की प्रगति कबल तभी सम्भव हो सकी जबकि मनुष्य के मन में व्यक्ति के प्रति एक नई मनोवृत्ति जाग्रत हो गई। इस नई मनोवृत्ति के धनसार व्यक्ति को विश्वव्यापी नियम के एक उदाहरण भयवा किसी वग के एक सदस्य के रूप म देखा जान लगा। साथ ही साथ इस मनोवृत्ति के धनसार विश्वव्यापी नियम भयवा साधारण कानून की वधना इस बात पर आधारित की गई कि यह नियम या कानून व्यक्तियों पर किस प्रकार लागू किया जाता है। विज्ञान की विजय-यात्रा सभी प्रारम्भ हुई जबकि विशिष्ट वस्तुधा को उनके सामान्य पहनुभा की दृष्टि से देखा गया



और सामान्य नियम को अलग-अलग उदाहरणों पर लागू किया गया। यह नया दृष्टिकोण केवल विज्ञान के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा। साम्र ही इस सामाजिक क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया। हमने फलस्वरूप एक ऐसे बौद्धिक वातावरण का विकास हुआ जिसमें व्यक्तियों या वर्गों के पृथक् विभाषाधिकारों को न तो स्वीकार किया जाता था और न उचित सम्मान जाता था।

सामाजिक अन्तर्वादों की समाप्ति के पश्चात् मानवीय ऊर्जा बहुत बड़े पैमाने पर उमुक्त हो गई। प्रतिबन्ध लगाने वाले सामाजिक स्तरों की समाप्ति के फलस्वरूप ऐसे करोड़ों व्यक्तियों को पहले-पहल स्वाधीनता और समानता की अनुभूति हुई जा पहले समाज में अपनी दीन-हीन दशा में यह मानकर रहते चले आते थे कि यह उनके भाग्य का फल है। यह कुछ प्राकृतिक या सयोग की बात नहीं है कि पिछले ५०० वर्षों में उससे कहीं अधिक प्रगति हुई है जितनी कि उससे पहले के मानव इतिहास के ५००० वर्षों में हुई थी। सब वस्तुओं का रूप अनूतपूर्व वेग से बदला है और अब भी बदलता जा रहा है। यह बात भी विषयरूप से ध्यान देने योग्य है कि पिछले ५० वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं वे गत ५० वर्षों में हुए परिवर्तनों की अपेक्षा भी कहीं अधिक महान् हैं।

परिवर्तन की प्रक्रिया में इस अत्यन्त विघात लात्र गति के कारण मनुष्य के गन्धर्व नई समस्याएँ आ खड़ी हुई हैं। अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जिसमें यदि मनुष्य को जीवित रहना है तो सब मनुष्यों को एक परिवार के गन्धर्व के रूप में ही जीवित रहना होगा। औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से, और एक अर्थ में तो राजनीतिक दृष्टि से भी सत्तार आज एक हो चुका है। भूमण्डल के किरी भी एक भाग में होने वाली घटनाओं की प्रतिनिधा सत्तार के दूरतम भागों में भी होती है। परन्तु मनुष्य का मन अभी अपने आपका मानव परिवार की इस एका के अनुभूत नहीं ठान सका है। आजकल का सत्तार जिन समस्याओं से ग्रस्त है उनमें से अनेक का कारण यह है कि मानव-परिवार की एका स्थापित तो हो चुकी है किन्तु मनुष्य अभी तक उस अनुभव करने में असमर्थ रहा है।

सार सत्तार की एका की भावना कोई बिलकुल नई वस्तु नहीं है। यदि

काल से ही परम्बर और ऋषि लोग यह घोषणा करते रहे हैं कि सब मनष्य एक हैं। अतीत की प्रत्येक सृष्टि या सम्प्रदाय में विन्व की सृष्टि या विश्व की सम्प्रदाय बनन की सम्भावनाएँ निहित थीं। भारत के प्राचीन स्वयम्भुव में भारतीय सम्प्रदाय की भावना उन सब देवों पर छा गई थी जो उन दिनों भारतवासियों को ज्ञात थे। अतीत सृष्टि या किसी सम्प्रदाय की भावना के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। मध्ययुग में धर्म सम्प्रदाय भी इसी प्रकार सारे ज्ञात ससार पर छा गई थी। पुराने समय की इन विद्वत्प्राणी सम्प्रदायों और आज की दशा में अन्तर एक महत्त्वपूर्ण तथ्य में निहित है। वह तथ्य यह है कि अतीत की इन सम्प्रदायों का उद्देश्य विद्वत्-सम्प्रदाय बनना था और वे विन्व-सम्प्रदाय बन भी सकती थीं। किन्तु वैज्ञानिक और प्राविधिक उपकरणों के अभाव के कारण सारे ससार का एकीकरण केवल एक आदेश मात्र बना रहा। परन्तु आज विज्ञान की सफलताओं के फलस्वरूप वह आदेश सत्य के रूप में साकार हो उठा है।

## २

ससार को इस रूप में देखते हुए कि वह दिनादिन और अक्षिवाधिक एक होता जा रहा है, हमें अपने यौद्धिक उत्तराधिकार में भगवद्गीता के स्थान के सम्बन्ध में विचार करना है। अतीत में जो-जो सम्प्रदाय पनपी उनमें से प्रत्येक का वाहन कोई न कोई भाषा थी जिस उस युग की भाषा कहा जा सकता है। इस प्रकार अपने गौरवपूर्ण दिनों में सृष्टि और उसमें सम्बद्ध भाषाएँ न केवल भारतवासियों के लिए अपितु दक्षिण-पूर्वी एशिया के सारे प्रदेशों के लिए सृष्टि का वाहन बनी हुई थीं। इसी प्रकार किसी समय सदिन भी उस सारे समार में जिसमें रामन कानून और यूनानी सम्प्रदाय स्वीकार की जाती थी एकता स्थापित करने वाला एक सूत्र बनी हुई थी। मध्यकाल में धर्म की भाषा भी उस समय के समस्त ससार में यही काम करती रही। धर्म की भाषा की अवलम्ब के बाद कई सताष्टियाँ तक यह अनिश्चित दशा बनी रही कि उसका स्थान कौन-सी भाषा ले। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि फ्रांसीसी भाषा सारे समार की भाषा बन सकती है और अस्तुतः वह नाम के लिए विश्व भाषा बन भी गई थी परन्तु अन्त में भगवद्गीता की विजय हुई। आज क्या कोई इस

घात से इन्कार कर सकता है कि एक दृष्टि में अग्रजी इस युग की सभ्यता की वाहन है ?

इतिहास का अनुभव हमें यह बताता है कि प्रत्येक सभ्यता की सर्वाङ्गता उस भाषा की उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई थी जो उस सभ्यता का वाहन थी। दूसरी भाषाएँ उस युग की इस सक्रिय भाषा के सम्पर्क से ही बल और जीवन प्राप्त करती थी। आधुनिक यूरोप की सभी भाषाएँ न केवल सेंटिन और ग्रीक से बल्कि अरबी तक से लिए हुए ऋण द्वारा परिपुष्ट हुई हैं। आधुनिक यूरोपियन भाषाभाषा की शक्ति और समृद्धि का अधिकांश भाग इन प्राचीन भाषाभाषा से लिए गए तत्वों से ही बना है। वस्तुतः केवल इस प्रकार के सम्पर्कों द्वारा ही कोई भाषा विश्व भाषा बनने के लिए अथवा आगामी युग की विश्व भाषाओं में से एक बनने के लिए तैयार हो सकता है।

यदि हम इतिहास के किसी विशेष दौर में भाषा के इस कृत्य को मली मानि समझ लें तो यह समझना आसान हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में अग्रजी का इतना अधिक प्रभाव क्या पड़ा। अग्रजी ने भारत को केवल राष्ट्र बल से नहीं जीता। अधिकांश मामलों में तो उन्होंने दो प्रतिस्पर्धी भारतीय भाषाओं के भगदोर का लाभ उठाया और उन्हें आपस में सड़ाते रहकर एक-दूसरे की स्थिति बना कर दी जिसमें कि देश की सत्ता लगभग बिना माँग ही उनके धन हाथ में आ गई। जब अग्रजी पहले भारत में आए तो वे सभ्यता की कलामा की दृष्टि से भारतवासियों की अपेक्षा निरुच्छ थे परन्तु मुँह बला में विज्ञान का उपयोग करते उन्होंने सनिह उत्कृष्टता प्राप्त कर ली थी। मुँह क्षत्र में विजय प्राप्त करने के माध्यम-साधन बूटनीति के प्रयोग से उन्होंने देश में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यह बात बड़ी सदिग्ध है कि जिन सीमा तक वे अग्रजी को भारतवासियों पर बाध पाएँ उस सीमा तक वे उस देश में भी बाध पाने में सफल होन या नहीं जबकि यदि उस समय तक अग्रजी आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता के प्रमुख वाहन के रूप में विकसित न हो गई होता। भारतवासियों ने अग्रजी का सुरक्षित और बिना नवनव के हमला स्वीकार कर लिया क्योंकि हमारे द्वारा भारत उस समय की पश्चिमी सभ्यता का परिधि के अन्दर आ गया।

आधुनिक सभ्यता पर अग्रजी का जो प्रभाव पड़ा वह अनेक रूपों में देखा

जा सकता है और उनमें से दो परिणाम बड़े लाभदायक रहे। एक ओर तो अंग्रेजी न राजनीतिक प्रजातन्त्र का संदेश और राष्ट्रीय एकता की भावना प्रदान की। स्वाधीनता और समानता के लिए जुमन की परम्परा इंग्लैंड के इतिहास में तीन या चार शताब्दियों तक चलती रही। अंग्रेज जनता लोक प्रिय सरकार की स्थापना के लिए अपने राजाशा के विरुद्ध लड़ी और उसने एक राजा का तो बंधन कर दिया। अंग्रेजी साहित्य राजनीतिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष की भावना से प्रेरित है। अंग्रेजी इतिहास और साहित्य का भारतीय मस्तिष्क पर यह प्रभाव हुआ कि उससे दंगमन की एक नई भावना और मानवीय गौरव तथा अधिकारों की एक नई चेतना जाग्रत हुई।

प्रजातन्त्रात्मक चेतना की इस वृद्धि को पुरानी राजभाषा के स्थान पर नई राजभाषा प्रान्त से भी सहायता मिली। भाषा के इस परिवर्तन का फल यह हुआ कि पहले कुछ वर्गों को जो विशेषाधिकार की-सी स्थिति प्राप्त थी वह समाप्त हो गई और जनता के सब वर्ग एक समान स्थिति में आ गए। यह बात मुसलमानों पर विनाश रूप से लागू हुई क्योंकि अंग्रेजों से पहले स्पष्ट रूप से मुसलमानों को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक ऊँची स्थिति प्राप्त थी। मुसलमानों का अंग्रेजी के प्रति पहली प्रतिक्रिया विरोध की थी। इस विरोध का मुख्य आधार उन लोगों के प्रति कटुता की भावना थी जिन्होंने उनके हाथ से सत्ता छीन ली थी। भारतीय समाज के अन्य वर्गों में अंग्रेजी के प्रति इस प्रकार की कोई विरोध भावना नहीं। परन्तु अंग्रेजी के आगमन के कारण उनमें भी उन वर्गों की उन्नति का भवसर प्राप्त हो गया था जो उस समय तक उपक्षित और पिछड़े हुए थे। इस प्रकार अंग्रेजी न उन लोगों के लोगों का समाप्त करके जिन्हें पहले विशेषाधिकार प्राप्त था भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों में समता स्थापन का भवसर प्रदान किया।

वर्तमान युग में पहले भारत में कई भव राष्ट्र (समि नेशनलिटी) जसी जातियाँ थीं। अंग्रेजों शासन के साथ दिए जाने से ये विभिन्न भव राष्ट्र जमी जातियाँ एक राजनीतिक प्रणाली में बंध गई। देश के विभिन्न भागों के लोग एक ही और उसी किन्हीं शक्ति द्वारा शासित होने के कारण आपस में एकता अनुभव करने लगे। इस प्रकार अंग्रेजी के भारत से सम्बन्ध के कारण विघातात्मक (पोजिटिव) और निपघातक दोनों ही उग से राजनीतिक एकता की भावना

के परिपुष्ट होने में सहायता मिली। विधानात्मक रूप से तो यह सहायता राष्ट्रीयता के संघर्ष द्वारा मिली जिसमें कि अंग्रेजी का साहित्य और कविता बरी हुई है। नियंतात्मक रूप में यह सहायता इस तरह मिली कि बिना किसी जाति धर्म या समाज के भ्रम भाव के सब भारतीयों के कष्टों की तुलना विदेशी अंग्रेजों को प्राप्त विभाषाधिकारों के साथ की गई और इससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी।

अंग्रेजी पढ़ने से जो लाभ हुए उनमें से एक मुख्य लाभ यह था कि भारत में राजनीतिक जागृति हुई। परन्तु इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारतीय मस्तिष्क में एक नई बौद्धिक जागृति उत्पन्न हुई। प्राचीन काल में भारत के लगभग सारे ही गाँव संसार के साथ सम्पर्क विद्यमान थे। मध्ययुग में अरबी और फारसी इस्लामी जगत् के साथ सम्पर्क स्थापन का माध्यम बनी रहीं। परन्तु इससे भ्रम अंग्रेजों के साथ भारत के सम्बन्ध यदि स्थापित नहीं भी हो गए तो भी शङ्कित अवश्य हो गए। परन्तु सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते न होते विज्ञान और प्रविधि विज्ञान के क्षेत्रों में पहले पश्चिमी देशों के हाथ में जा चुकी थी। अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होने से पहले ज्ञान और आलोचक के इस नये सात तन पहुँचने का कार्य उपाय नहीं था। इस नये ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि भारतीय जीवन और शिक्षा में जो एक प्राथमिकारात्मक (प्रौद्योगिकीय) अर्थानुष्ठानादी की मनोवृत्ति थी वह समाप्त होने लगी। प्राचीन भारतीय समाज में प्राथमिकारात्मक मनोवृत्ति का एक उदाहरण भाष्यकारों का प्राचीन पुस्तकों पर भाष्य करने की मनोवृत्ति में दिखाई पड़ता है। जब किसी भाष्यकार का मूल लेखक की व्याख्या के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था तो भ्रम होता था तब भी वह इस बात का आग्रह करता था कि उसने जो नया अर्थ निकाला है वह वस्तुतः नया नहीं है बल्कि वह मूल लेखक की रचना में ही निहित था।

अंग्रेजी शिक्षा के मध्यम में ज्ञान के फलस्वरूप व्यक्तिगत विचार के महत्व पर जोर दिया गया। पश्चिम में अनेक विचारों का न बिना शर्तों के पुराने महान् लेखकों का शस्त्रमस्तकालीन किया है। वास्तव में तो यही तक बढ़ गया, कि उसने ईश्वर तथा का मानने से इंकार कर दिया। इन प्रकार अंग्रेजी का अध्ययन प्रारम्भ होने से व्यक्तिगत विचार-पद्धति को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस

प्रकार के अध्ययन से जिसे मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति कहा जाता है उसने परि-  
पोषण को भी प्राप्त करने मिला। भगवद्गीता के अध्ययन से एक भिन्न नई  
संस्कृति और विश्व-दृष्टिकोण के सम्पन्न में मान के कारण हमारा मानसिक  
दृष्टिकोण और अधिक विस्तृत हो गया।

गुरु सौ वर्षों या उससे भी कुछ अधिक काल में भारत न केवल विज्ञान और  
प्रयोगात्मक विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं अपितु साहित्य दर्शन और राजनीति  
के क्षेत्र में भी बड़े मेधावी पुरुषों को जन्म दिया है। एगिप्स में और भी ऐसे  
विस्तृत प्रश्न हैं जहाँ के लोगों की सहज स्वभाविक योग्यता या बौद्धिक शक्ति  
भारतवासियों जैसी ही है। परन्तु उन देशों में भारत जितनी प्रगति नहीं हो सकी।  
इस अन्तर की एक मात्र व्याख्या यही प्रतीत होती है कि इन प्रदेशों के लोगों  
न वैज्ञानिक अनुसंधान की भावना का जो कि आधुनिक युग की विपत्ति है  
उतनी ही वह प्राप्त नहीं किया है जितनी हृदय तक भारतवासियों ने। ऐसा  
प्रतीत होता है कि भगवद्गीता के अध्ययन से भारतवासियों के मन में भी उसी  
प्रकार की द्रुत गति की भावना आ गई है जैसी सन्तुलन शक्त की प्रारम्भ  
में भगवद्गीता के मन में उत्पन्न हुई थी।

जहाँ तक मानवीय व्यवहार का सम्बन्ध है हम 'गान्ध' का कोई ऐसी शक्ति  
या उपकरण दृष्टिकोण हो सके जिसमें विशिष्ट अर्थार्थ ही अर्थार्थ हो या  
विज्ञान बुराई ही बुराई। भगवद्गीता के अध्ययन से भारतीय मन को जो लाभ हुआ  
है उनके बावजूद इस सार चित्र का एक और भाग पहलू है जिसकी हमें उपेक्षा  
नहीं करना चाहिए। सन्तुलन-युग के इस नाम खान बालू पृष्ठ पर पहली मद  
यह है कि भगवद्गीता के अध्ययन के कारण मातृभाषा और प्राचीन भारतीय  
साहित्य के अध्ययन की उपेक्षा हो गई। भगवद्गीता की और अधिकाधिक ध्यान  
दिए जाने का परिणाम यह हुआ कि इस नये शिक्षित युग और शायद जनता के  
बीच एक गहरी खाई उत्पन्न हो गई। जिन लोगों का यह नई आधुनिक शिक्षा  
प्राप्त हो जाती थी उनका अपनी प्राचीन परम्पराओं से प्रायः सम्बन्ध-विच्छेद  
हो जाता था और अनेक बार तो वे लोग प्राचीन परम्पराओं के प्रति खुल्लम  
खुल्ला निरस्कार और घणा भी व्यक्त करने लगते थे। इसके फलस्वरूप हमारे  
सामाजिक संगठन की शक्ति कम हो गई और भारतीय समाज में अनेक भ्रष्ट  
छनीय मनोभावों का प्रसार हुआ। शहरों और गाँवों के बीच जो एक खाई उत्पन्न

हो गई है वह समाज की खड़ीकरण (फर्मेन्टेशन) की धोर बढ़न की प्रवृत्ति का ही एक प्रकट रूप है।

अंग्रेजी के अध्ययन पर बहुत बल देने का एक और अवाछनीय परिणाम यह हुआ कि उन्नति का अवसर केवल उन लोगों के लिए सीमित हो गया जिनमें केवल भाषा सीखन की अत्यधिक योग्यता थी। इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं कि अनेक न्यायिकों तक भारत में विज्ञान और प्रविधि विज्ञान की उपेक्षा होती रही। इसके फलस्वरूप भारतीय उद्योग और कला-कौशल का विकास काफी पिछड़ा रहा। परन्तु अंग्रेजी पर इस प्रकार अनचित्त जोर देने से जो एक बड़ी बुराई उत्पन्न हुई, वह ऐसी नहीं थी कि जो विमकुल आवश्यक ही हो। यह बुराई अंग्रेजी के अध्ययन के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं हुई थी अपितु इसलिए उत्पन्न हुई थी कि अंग्रेजी को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपना लिया गया था। विदेशी भाषा के बोझ के कारण मन के स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती थी। इसके फलस्वरूप अध्ययन बड़ी सीमा तक एक रटन्त की चीज बन गया। केवल पाठ-पुस्तकें भर मेधावी छात्रों का छाटकर बाकी छात्रों के लिए इस प्रकार की शिक्षा में विचार कल्पना और अनुभूति की शक्तियाँ के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं था। मगर तो यह है कि अधिकांश विद्यार्थियों के लिए अध्यापन का माध्यम ही अपने आप में शिक्षा का सम्यक् बनकर रह जाता था।

अंग्रेजी के अध्ययन पर इतना अधिक बल देने का एक और भी अवाछनीय दुष्परिणाम हुआ। यह पहले बतलाया जा चुका है कि मध्ययुग में पाप सत्कार के साथ भारत के सम्बन्ध इसलिए सीमित रहे क्योंकि अरबी और फारसी की पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया गया था। आधुनिक युग में अंग्रेजी का भी ऐसा ही दुष्प्रभाव हुआ। भारतवासी सारी दुनिया का अंग्रेजी के ही चक्के में दखन लगे। जहाँ भारत का अंग्रेजी के विज्ञान और समृद्ध साहित्य से सम्पर्क कल्याणकारी हुआ वहीं पूर्वोद्यों के साहित्य तथा पाप यूरोपियन साहित्य की ओर रुझान जान का परिणाम अनवरत यह हुआ कि भारतवासियों के सम्मुख सगर का केवल एकपक्षीय स्वरूप ही आ गया। स्वाधीनता का प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा के सामने एक नये महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि इस मनोवृत्ति को सुधारन का प्रयत्न किया जाए।

परि भी कुल मिलाकर अंग्रेजी का अध्ययन भारतीय जनता की प्रगति

और उल्लानि में सहायक तत्व रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस समय का अप्रज्ञा सरकार पहले इस देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रारम्भ करने के पक्ष में नहीं थी। काफी समय तक भी ईस्ट इंडिया कम्पनी का सारा ध्यान केवल मनाफा कमान पर ही लगा रहा। जब कम्पनी ने प्रशासन का कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर लीं तो गुरु-गुरु में वह केवल पूर्वी विषयों के अध्ययन का ही प्रास्ताविक देने के पक्ष में था। इसमें संदेह नहीं कि यूरोपियन घर्मे प्रचारक विलकुल प्रारम्भ से ही पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। परन्तु इस सम्बन्ध में सबसे अधिक निर्णायक तत्व गायद उन चौड़े-मालों का प्राप्त भारतवासियों का प्रभाव रहा जिनके नेता राजा राममोहन राय थे और जिनका यह विश्वास था कि यूरोपियन विज्ञान और ज्ञान के सम्पर्क में आने से भारत के पुनरुत्थान में सहायता मिलेगी।

अतीत में जब अप्रज्ञा इस देश पर छापी गई थी तब चाहे क्या जा भी क्यों न रही हो परन्तु इस समय स्वतंत्र भारत में अप्रज्ञा को जारी रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कारण विद्यमान हैं। पहली बात तो यह है कि अप्रज्ञा आधुनिक समाज की संस्कृति का एक प्रमुख वाहन है। इसलिए इस अध्ययन को रोक देने का अर्थ यह होगा कि इतिहास के क्षेत्र में बाध कर रही प्रगतिशील शक्तियों के साथ भारत का सम्बन्ध टूट जाय। दूसरा कारण यह है कि आज जब प्रत्येक राष्ट्र में आन्तरिक जीवन की ऐसी-सी दिनाग्नि बन्ती जा रही है। इस कारण इस बात की आवश्यकता है कि उस समाज को बनाने वाली विभिन्न इच्छाओं में उनकी अपेक्षा कही अधिक लवक और स्थितिस्थापकता (प्लविस बिलिटी) या लोच हो जितनी कि अतीत में आवश्यक थी। अप्रज्ञा के सम्पर्क में एक परिवर्तन उत्पन्न करने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करके भारतीय राष्ट्र के अन्तर अन्तर्कालनीय सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। इस बात को विना करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर एक पहलू में ही दिखाई पड़ जाती है। अप्रज्ञा का जारी रखने के पक्ष में तीसरा कारण है विभिन्न राष्ट्रों और प्रजा के बीच बढ़ते हुए पारस्परिक सम्बन्ध। प्रत्येक राष्ट्र का अपनी मकीण परिधि के बाहर जाना सीखना चाहिए और दूसरे राष्ट्र के साथ सम्पर्क स्थापन (संसार) के माग बनाने चाहिए। इस समय वर्तमान संसार में अर्थ देशों के साथ सम्पर्क स्थापन के लिए



अंग्रेजी की अपेक्षा अच्छा साधन शायद और ढोई नहीं हो सकता ।

• ३

परन्तु अंग्रेजी के पक्षपोषण में युक्तियाँ देने का यह अर्थ नहीं है कि इसका अध्ययन उसी रूप में रखे जाने की आवश्यकता है या रखा जा सकता है जैसा वह पिछले सौ या ढ़ सौ वर्षों में रहा है । ठीक सौ वर्ष पहले अंग्रेजी के प्रथम सम्पर्क में आन के कारण भारतीय जनता के एक वर्ग के मन कुछ घमाचोंघ-से उठ थे । अंग्रेजी के प्रवाह में पड़कर उनके पाव इस हद तक उलझ गए कि उनमें से अनक न तो अपनी भाषा और संस्कृति तक को त्याग देने का यत्न किया । उस समय ऐसे अनक प्रतिभाशाली नर-नारी थे जो इस बात में गर्व अनुभव करते थे कि वे अंग्रेजी अपनी मातृभाषा की अपेक्षा भी अधिक अच्छी बोल सकते हैं । इस अतिरेक की प्रतिक्रिया होनी अनिवार्य थी । हम देखते हैं कि दस में आज भी एक बग विद्यमान है जो बिल्कुल दूसरी सीमा तक पहुँचते हैं और यह चाहते हैं कि भारत से अंग्रेजी का नाम निगान उठा लिया जाए । परन्तु वे शोग यह भूल जाते हैं कि इतिहास की प्रक्रियाओं को उलटा नहीं सौटाया जा सकता । अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा प्रणाली उस समय भले ही विदोषी रही हो जब वे भारत में पहले-महल शुरू की गई थी परन्तु एक शताब्दी से भी अधिक समय तक भारत से सम्बद्ध रहने के कारण वे आज भारतीय संस्कृति का अङ्ग बन गई हैं । यदि हम आज अंग्रेजी का अपने जीवन से बिल्कुल बाहर निकाल भी दें तो भी उसके प्रभाव के अवशेष बचे रहने और सबूतों में सामने आते रहने ।

फिर भी हम आधुनिक भारत के प्रसंग में अंग्रेजी के विभिन्न उपयोगों में अलग-अलग अन्तर कर सकते हैं । देश की अधिकांश जनता को जिसने अब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ी अविष्य में भी अंग्रेजी पढ़ने की ढोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु उन्होंने भी अग्रस्थ रूप से भारतीय भाषाभाषा में लिखी गई उन पुस्तकों को पढ़कर अंग्रेजी के प्रभाव को अनुभव किया है जो अंग्रेजी से प्रेरणा प्राप्त करके लिखी गई हैं । यह प्रक्रिया जारी रहनी और विभिन्न भारतीय भाषाभाषा की बुद्धि और विश्वास के साथ-साथ साथ ही बढ़ती जाएगी ।

भारतीयों का एक दूसरा बग भी है जो यह चाहता है कि दूसरे लोग के साथ मामूला बातचान या विचारों के आदान प्रदान के लिए भद्रजा का प्रयोग किया जाए। यद्यपि ही इन प्रकार के प्रयोग में भाग्य-मन्य स्तर हाथ। कुछ लोग भद्रजा भाषा का ब्रह्म प्रारम्भिक कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त करने सन्तुष्ट हो जाएंगे और दूसरे लोग के साथ धरती मूल भाव-मन्यताओं को पूरा करने के लिए नया स्थापन में इस भाषा का प्रयोग करेंगे। कुछ अन्य लोग भद्रजा का प्रयोग कुछ छोटे अधिक पचास विषयों के सम्बन्ध में दूसरे लोगों के साथ या अन्यराष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य उद्योग-धोग यहाँ तक कि राजनयिक सम्बन्धों के स्तर पर सम्भव स्थापन के लिए करेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य भाषा के सम्भव स्थापन के माध्यम के रूप में उपयोग करने पर होगा सन्तुष्टि के माध्यम के रूप में उपयोग करने पर नही।

परन्तु एक तीसरा बग भी होगा जो यद्यपि ही सच्चा में बहुत अन्य होगा जो यह चाहता होगा कि भद्रजा भाषा का उपयोग ब्रह्म सम्भव स्थापन के साधन के रूप में ही न किया जाए ज्ञान के उपरिर्वाग्य दूसरा बग चाहता है यद्यपि इस भाषा का प्रयोग एक एक माध्यम के रूप में किया जाए किन्तु द्वारा वे पवित्री सन्तुष्टि में पोषण प्राप्त कर सकें। यही भा इन लोग के अन्त-प्रयोग स्तर हाथ। कुछ लोग इस भाषा से ब्रह्म इच्छा परिचय प्राप्त करने सन्तुष्ट हो जाएंगे कि वे उसका साहित्य का रस में सकें। कुछ अन्य लोग विज्ञान ज्ञान तथा अन्य बौद्धिक क्षमता में कुछ और गहरा तथा विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस भाषा का उपयोग करना चाहता। परन्तु कुछ थोड़े-से अन्यसंस्था के लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस भाषा में और भी अधिक तथा भाषा का मजबूत रूप से उपयोग करें।

यदि भद्रजा के सम्बन्ध में इस रस का अपना दिया जाए, तो इसका परिणाम यह होगा कि भारतवासियों के अधिकतर भाग के लिए भद्रजा पढ़ना आवश्यक नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि उनके लिए स्थिति में कोई परिबन्धन नहीं होगा क्योंकि वे भाषा के भी अधिक नहीं पढ़ेंगे। इसा उद्योग को एक दूसरे रूप में प्रकट किया जा सकता है। किसी भी देश में सम्भवतः ८० प्रतिशत लोग अपना सारा जीवन अपने गाँव के आनन्द-मन्य दम या पन्हु मोल के धरे के अन्दर ही बिता देते हैं। इस प्रकार के लोगों को बाहरी दुनिया के

मामलों की कोई चिन्ता नहीं होती और वे अपना जीवन परम्परागत ढंग से बिताने में ही सन्तुष्ट रहते हैं। वे न तो विदेशी भाषाभाषा का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न ही करते हैं और न उन्हें उसकी आवश्यकता ही होती है। भारत में इस सभ्यता का अपना रूप नहीं है। इसलिए ८० प्रतिशत भारतवासियों का शिक्षण अंग्रेजी का मुश्किल से ही कोई साम होना चाहिए। सब तो यह है कि उन्हें जितना एकमात्र भाषा की सीखन की आवश्यकता होगी वह उनकी मातृभाषा है परन्तु यदि वे चाहें तो उन्हें अंग्रेजी या सब कहा जाए तो किसी भी अर्थव्यय का सीखन का उतना ही भवसर होना चाहिए जितना देश के अर्थव्यय किसी भी नागरिक को है। क्योंकि प्राथमिक संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्णतया पृथक् रहकर जीवन नहीं बिता सकता इसलिए उनमें भी वह सबक उत्पन्न होनी चाहिए, जो बाहर से प्राप्त होन वाली प्रशिक्षण का ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। इसलिए स्वतन्त्र और गणतन्त्रात्मक भारत में लोग नागरिक के रूप में सन्तुष्टजनक रूप में काम कर सकें इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी मातृभाषाएँ खूब समृद्ध बनें।

सोना का अपेक्षाकृत बहुत छोटा एक और वग होगा चाहे उसकी मूल्य भाँसा में हो जिनकी शक्ति और गतिविधि का क्षेत्र इस सर्वोच्च वृत्ति के बाह्य होगा और वह क्षेत्र या तो अपने सारे राज्य में या कुछ मामलों में सारे भारत तक में फैला होगा। भारतीय एकता की चेतना का मुख्य कारण प्राथमिक शिक्षा का विकास है। इसलिए हम वग के लिए यह वाछनीय होगा कि उसे अंग्रेजी का सामन्तमात्र मान लें। इस प्रकार का मान इस दृष्टिकोण से भी आवश्यक होगा कि वे लोग बाहरी शक्तियों के भारतीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का ठीक ठीक मूल्यांकन कर सकें। अतः में एक और छोटा वग होगा जो अतिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहा होगा और अन्य देशों के साथ भारत के व्यवहार में नतस्थ प्रदान करेगा। इन सोना के लिए अंग्रेजी का मान न बढ़ने वाछनीय होगा अपितु आवश्यक भी होगा। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भारत की वर्तमान प्रतिष्ठा का एक कारण यह भी है कि भारत ने अपनी नीति का पोषण बड़ी स्पष्टता के साथ की है। इसमें सन्देह नहीं कि नीति की यह स्पष्टता केवल इसलिए हो गयी है कि भारतीयों का अंग्रेजी भाषा पर



में शिक्षा पान वाले भारतीय विद्यार्थी स यह आशा की जाती है कि वह मातृ-भाषा पढ़गा और उसके अतिरिक्त हिन्दी पढ़गा जो भारतीय सभ की राज्य-भाषा है। इसने अतिरिक्त एक तीसरी भाषा अंग्रेजी के साथ-साथ कुछ लाग उससे यह आशा करत है कि वह कोई एक प्राचीन भाषा भी सीखे। इस प्रकार बालक को काफी छोटी आयु में ही एक साथ चार भाषाएँ सीखनी पड़गी। इससे भी बुरी स्थिति उन बच्चे बालक की है जिसकी मातृभाषा प्रादेशिक या राज्य भाषा से भी भिन्न कोई अन्य भाषा है। उस उन चार के अतिरिक्त एक और भाषा भी सीखनी पड़गी। यदि किसी बालक को अपने विद्यालय-काल में ही पाँच भाषाएँ सीखनी पड़ें तो यह प्रश्न उठता है कि भाषाओं के विषय विषयों का पढ़न का समय उसे कब मिलेगा।

यदि बालक का इन सब भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करना होता तो यह स्थिति सचमुच ही अगह्य होती परन्तु यदि मातृभाषा को छोड़कर माध्यमिक शिक्षाकाल में इन भाषाओं को केवल मामूली बोलचाल या सम्पर्क स्थापना के साधन के रूप में सीखना ही उद्देश्य हो तो इस आशय में कुछ विचार बन नहीं रहता। सच तो यह है कि यदि छात्र बालक को ये भाषाएँ साथ-साथ सिखाई जाएं तो उसकी दूसरे भाषा के साथ वार्तालाप विचार विनिमय और सम्पर्क स्थापन की शक्तियाँ और अधिक विकसित हो जाएगी। एक बात यह भी विचारणीय है कि क्या अंग्रेजी एक बड़ी सीमा तक उस स्थान को नहीं ले सकती जो पहले विद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्राचीन भाषाओं के अध्ययन को प्राप्त था? पुरानी जमी हुई भाषाओं के सम्पर्क में आकर नई भाषाओं का विकास होता है। प्राचीन भाषाओं के अध्ययन पर जोर देने का एक महत्वपूर्ण कारण यही था। हाल के वर्षों में कई भारतीय भाषाओं ने अंग्रेजी के प्रभाव से प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा पाकर बहुत अधिक प्रगति की है। यदि हम इस विषय में सावधान रहें कि अंग्रेजी बालक के ऊपर बोझ बन जाए तो अंग्रेजी के सम्पर्क में ध्यान के फलस्वरूप उसमें भाषा की भावना पनप सकती है। समय ध्यान पर यह प्रवृत्ति उस अपनी भाषा में साहित्य सृजन करने में और प्राधुनिक युग के उपयुक्त विज्ञान और साहित्य का निर्माण करने में सहायता दे सकती है।

फिर भी एक बात निश्चित है। यदि हमारे विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली



भाषा का ज्ञानबलाऊ ज्ञान प्राप्त करने में कम समय लगता है। भूतकाल में हमारे माध्यमिक विद्यालयों के छात्र अपनी भाषा का समुचित ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही अंग्रेजी का अध्ययन प्रारम्भ कर देते थे। भविष्य में माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को अंग्रेजी का अध्ययन प्रारम्भ करने से पहले अपनी भाषा पर पहले की अपेक्षा अधिक अधिकार हो चुकना। इन दो तत्त्वों का कारण— उन्नत शिक्षण पद्धति और अपनी भाषा पर पहले की अपेक्षा अधिक अधिकार— हमें उस कठिनाई को बहुत कुछ हल कर सकना चाहिए जो अंग्रेजी के अध्ययन के लिए प्राप्त होने वाली अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न होगी।

माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन मूलतः एक भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन रहेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजी की पाठ्य वस्तु सब प्रकार की मानवीय रचनाओं से विलग रहेंगी। सब तो यह है कि किसी भाषा को सीखने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि उसके वाक्यों को ध्यान से समझा जाय। इसलिए साहित्यिक रचनाओं को विद्यालयों में पाठ्यक्रम में भी कुछ न कुछ स्थान मिलना चाहिए। परन्तु हमें इस सम्बन्ध में बहुत सावधान रहना चाहिए कि इस प्रकार की रचनाएँ उन लोगों के अनुभवों की पहुँच में आ सकें जो उन रचनाओं को पढ़ाया जाता है। इस सम्बन्ध में हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालयों के अंग्रेजी के प्राध्यापकों का सम्मेलन में भी कई एक सिफारिशों को स्वीकार कर लेना आवश्यक हमारे लिए उचित हो। इन प्राध्यापकों का विचार था कि विद्यालयों में स्तर पर केवल प्राथमिक सरल अंग्रेजी गद्य की पाठ्य पुस्तकों का ही विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। यह अंग्रेजी गद्य केवल लगभग २५० मूल अंग्रेजी वाक्यों की शब्दावली के अन्तर्गत ही लिखा जा सकता है। परन्तु इसका पूरा रूप में साहित्यिक रचना की गद्य और पद्य की चुनी हुई पुस्तकों से युक्त पाठ (रिडिंग) का लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए।

यदि हमें अपनी संस्कृति को समझ करने के लिए और अपनी भाषाओं की सम्पत्ति का बढाने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना है तो हमें कुछ पाठ्य सामग्री भी होनी चाहिए जो अंग्रेजी का भाषा और साहित्य दोनों ही रूपों में अध्ययन करने का तैयार हो। इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी का अध्ययन अपने-आप में एक पुरस्कार होगा। अंग्रेजी में उच्च कल्पनामय साहित्य

विद्यमान है जिसका ससार में अत्यन्त जोड़ मिलना कठिन है। नाटक गति काव्य कविता और सलित साहित्य के क्षेत्रों में अग्रजी की साहित्य-सम्पत्ति बहुत विचाल है। कथा समुच्चय और गम्भीर निबन्ध के क्षेत्र में अग्रजी का साहित्य समार का अधिकांश भाग्यमा के साहित्य का मुकाबला कर सनता है। अग्रजी भाषा और साहित्य के गम्भीर विद्याधिया के लिए इस प्रकार के अध्ययन से एक नए ससार का द्वार खल जाएगा और इससे उह एक नई प्ररणा प्राप्त होगी जिससे वे अपनी भाषा में अत्यन्त सुन्दर साहित्य की रचना कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में यह जान लेना अनारजक होगा कि आधुनिक भारत के सभी महान् लेखका न अग्रजी के प्रभाव को अनभव किया है। यहाँ प जवाहर लाल नेहरू श्री अरविन्द या प्राप्तेसर राधाकृष्णन् जैसे लेखका का जिहान अपन रचन के मुख्य माध्यम के रूप में अग्रजी का उपयोग किया है विचार लेखन करन की आवश्यकता नहीं है। जिन लोग न मुख्यतया किता भारतीय भाषा में साहित्य लिखा है उन पर भी प्रायः अग्रजी का प्रभाव रहा है। राजा राममोहनराम ने लेकर हमारे बंगाल में माइकेल मधुसूदनन्त से रवीन्द्रनाथ ठाकुर तक एस लेखका की उज्ज्वल शृलला विद्यमान है जिन्होंने मध्य रूप से प्ररणा अग्रजी साहित्य के अध्ययन से ही प्राप्त की। अग्रजी के अध्ययन से उनका मन में ऐसी योग्यता आ गई जिससे वे अपना भाषा में उत्कृष्टतम काटि का साहित्य सृजन करन में सफल हुए। आधुनिक गुजराती साहित्य के जन्मदाता महामा गांधी भी इसी प्रकार अग्रजी-लेखन में अत्यन्त कुशल थे। मौलाना आज़ाद जम लम्बक भी जिन्होंने अग्रजी गिज्ञा श्रीग्वारिक रूप से विद्यालय में प्राप्त नहीं की और जिन्होंने अग्रजी का अध्ययन स्वयं किया है अग्रजी से बहुत अधिक प्रभावित हुए ह। यह प्रक्रिया अभी तक जारी है। वस्तुतः अग्रजी तथा अन्य यूरोपियन भाषाओं के साथ अधिकाधिक सम्बन्ध होने के फलस्वरूप भारतीय साहित्य में अनेक नये और रोचक विराम हा रहे ह।

सजन्गील साहित्य के प्रभाव के अतिरिक्त अग्रजी से हमें मानवीय गति विधि के समस्त क्षत्रा में आधुनिक ज्ञान का विगुड सार प्राप्त हो जाता है। प्राकृतिक विज्ञान दान अर्थशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों मानव शरीर रचना शास्त्र (ऐंथ्रोपोलाजी) तथा इतिहास के क्षेत्र में अग्रजी का न केवल



## अध्याय ७

# सांस्कृतिक गतिविधियाँ और राज्य

पिछले सौ सवा सौ वर्षों से भारत में जो निरन्तर क्रान्ति हो रही थी वह अत में राजनीतिक स्वाधीनता का प्राप्ति के रूप में धाकर समाप्त हुई। इस सार काल की एक विचित्रता यह रहा कि सब धार प्रशान्त और असतान छाया रहा। कभी-कभी यह नई जागृति सब स्वीकृत प्रमाणा के विरुद्ध केवल विचार के रूप में प्रकट हुई और कभी यह कलाकृतियों के रूप में प्रकट धार्मिक या सामाजिक सुधारों के धादोलना के रूप में प्रकट हुई। इन सब प्रकार का अमिष्यकितया में विरोह की न भी सही ता भी जिज्ञासा की भावना समान रूप से पाई जाती थी। इस प्रकार का असतोष अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि किसी नई वस्तु का जन्म हो रहा था। पहले तारों को छिन्न-भिन्न हाकर मूल्य हो जाना पड़ता है तभी नवीन मूल्य का उद्भव होता है।

भारत में सभी जगह सामाजिक उषल-मुषल और प्रगति है। ऐसी दशा में हमें क्या आश्चर्य है कि कला के क्षेत्र में भी अमिष्यकित और सफलता के स्थान पर परीक्षा और प्रयत्न ही अधिक निश्चि है। विभिन्न कारणों से हाल के भारतीय जीवन में व्यक्तिवाद पर इतना अधिक धन दिया गया है कि इस युग की वही एक बड़ी विचित्रता बन गया है। व्यक्तिवाद की इस प्रकार की प्रधानता के कारण सामाजिक बंधन गिरिस हो जाने ह। प्रधान और परम्परागत ममान के एक जगह सगठित बनाए रखन के लिए सीमेंट का स

काम करता है। सामाजिक समेकन के लिए एक शत यह है कि समाज के प्रयाजना के लिए व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दे। जब व्यक्ति अपने-आपको समाज से बड़ा समझने लगता है तब पुरानी समाज-व्यवस्थाएँ ढगमगाकर गिरने लगती हैं। विछली घाटी के उत्तरार्ध में भारत में यही प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी और स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद और भी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है।

समाज के इस प्रकार अस्त-व्यस्त होने की इस प्रक्रिया का कभी-कभी एक विचित्र परिणाम यह होता है कि कुछ कलाओं में जैसे चित्रकला और साहित्य में एकाएक नई चमक आ जाती है। इसके विपरीत इस प्रकार की समाज की अस्तव्यस्तता का फलस्वरूप नाट्यकला और वास्तुकला में और साथ ही दार्शनिक अन्तर्दृष्टि में स्पष्ट भ्रष्टता प्राप्त नहीं हो पाती।

कविता और चित्रकला मूलतः व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्तियाँ हैं। उनका सामाजिक या साधारण बहना उनकी निन्दा करना है। और दूसरी ओर वास्तुकला और कुछ सीमा तक नाट्यकला अपने सौन्दर्य के लिए लगभग पूर्णतया सामाजिकता की भावना पर निर्भर है। कवि अपने आदर्श की ओर एकाकी बढ़ सकता है। चित्रकार भी एकान्त में रहकर पूर्णता प्राप्त कर सकता है। संगीत व्यक्ति ऊँचा उठ सकता है किन्तु उसका मूल व्यक्तिगत तत्त्वीयता में ही है। वास्तुकला को अपनी प्रत्येक दृष्टि में सामाजिक उपकरणों पर निर्भर रहना होता है। वास्तुकला की महान् कृतियाँ केवल सहकारी प्रयत्न द्वारा ही तैयार की जा सकती हैं। न केवल सबसे बड़े प्रमुख निर्माता को ही अच्छा कारागार होना चाहिए अपितु उसके सब सहायकों में भी कारीगरी के प्रति अनुराग होना चाहिए। थोड़े से परिष्कृत रूप में यही बात समान रूप से रंगमंच के लिए भी कही जा सकती है। इसलिए कुछ आश्चर्य नहीं कि आधुनिक भारत में कविता, चित्रकला और संगीत के विषय में तो भ्रष्टाचार-परीक्षण हुए हैं परन्तु वास्तुकला या नाट्यकला के सम्बन्ध में लगभग कुछ भी नहीं हुआ है।

स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद यह अज्ञान और असंतोष की पनिया कुछ बड़ा ही है। भटी नहीं। भावना की जिस उत्पत्ति के परिणामस्वरूप स्वाधीनता प्राप्त हुई है वह अभी तक शांत नहीं हुई। क्या राजनीतिक समाधि

और नया सामाजिक सभी क्षेत्रों में नये समतुलन (ईक्विलिब्रियम) स्थापित होने अभी बाय है। परिणामतः चित्रकला कविता और संगीत के क्षेत्र में स्वाधीन भारत की कला बहुत कुछ वही चीज है जो स्वाधीनता के पूरे के भारत में चल रही थी। नई चेतना के जागरण के कुछ चिह्न अवश्य दिखाई पड़ रहे हैं परन्तु अभी ये नई प्राप्तियाँ इतनी काफी धनीभूत नहीं हो पाई हैं कि वे संकलना के एक नये ढंग का प्रारम्भ बिन्दु बन सकें।

हमारी राष्ट्रीय विजय एक लम्बे और कठिन संघर्ष का परिणाम थी। इसमें आशय की कोई बात नहीं है क्योंकि प्रकृति में गायन ही कोई चीज कभी बिलकुल नये सिरे से प्रारम्भ होती है। जहाँ पर ऊपर से दखन पर यह प्रतीत होता है कि घटनाओं का अतीत के साथ बड़े उग्र रूप से सम्बंध विच्छन्न हो गया है वहाँ भी यदि हम सावधानी से देखें तो हमें ऐसी अनक प्रवृत्तियाँ और शक्तियाँ काम करती दीख पड़ेंगी जो ऊपर से दीख पड़ने वाले लम्बे-थ विच्छन्न में पहले भी काम करती रही थी और सम्बंध विच्छन्न के बाद भी अपना काम जारी रख रही हैं। ज्ञानियाँ वस्तुतः विश्वास की एक लम्बी प्रक्रिया के कुछ तीव्रगतियुक्त और एक-दूसरे से टकराने हुए दौर होती हैं। सब बड़ी बड़ी राजनीतिक ज्ञानियाँ हमारे इस वक्तव्य का सत्यता का प्रमाद्विन करती हैं। प्रत्येक ज्ञानि का स्वरूप और उसके साथ होने वाली घटनाओं का तम उन ज्ञानियाँ से सम्बद्ध जनता के स्वभाव परम्पराओं और इतिहास पर निर्भर रहता है।

निरंतरता का यह नियम मनष्य की सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में और भी पूर्ण रूप में गत्य उत्तरता है। संस्कृति जनता के इतिहास का विच्छन्न सार है। लम्बे समय के अनुभव का निष्पत्ति उन रीतियाँ और परम्पराओं का रूप में आ जाता है जिससे मिनकर संस्कृति बनती है। इसलिए संस्कृति का बना बट में अतीत में पूर्णतया सम्बंध विच्छन्न बहुत ही असाधारण वस्तु है और जब कभी भी ऐसा सम्बंध विच्छन्न होता है तो यह सामान्यतया उन लोगों के लिए विनाशकारी होता है जिनका इस संस्कृति-परिवहन में सम्बंध होता है। जहाँ किसी पुरानी संस्कृति का किसी बिलकुल नई संस्कृति का सामना करना पड़ता है और उससे प्रभाव के कारण पुरानी संस्कृति पराजित हो जाती है तो वे जानियाँ भी छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाती हैं। साम्यलिया घमरिना

इत्यादि का आदिम जातिवादी आधुनिक यूरोप की सम्यक्ता के सम्पर्क में आकर नष्ट हो गई। उसका कारण भी यही है। सांस्कृतिक परम्परा की निरंतरता का बन रहना किसी भी राष्ट्र के जीवित रहने के लिए एक आवश्यक तत्व है।

इसलिए यह आभास करना कि भारतीय गणतन्त्र की स्थापना होते ही भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ बिलकुल नई वस्तुएँ प्रारम्भ हो जाएँगी अशुभितयक्त है। हमारे गणतन्त्र की स्थापना ही इसलिए हो सकेगी क्योंकि कई दशाब्दियों से हमारी जनता में सांस्कृतिक नव जागरण हो रहा था। इस सम्बन्ध में सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं है कि राजनीतिक पराधीनता या राष्ट्रीय चरित्र की उस दुर्दशा का ही एक रूप है जिसका दूसरे दुष्परिणाम बना विनाश और दर्शन के ह्रास के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। जब राष्ट्र का पुनर्जागरण प्रारम्भ होता है तब एक नई चेतना प्रकट होती है और वह नवनव राजनीतिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष के रूप में ही नहीं अपितु संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अपने-आपको और अधिक पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने की भाँसा या के रूप में भी प्रकट होती है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में राजनीतिक क्षेत्र के सभी महान् नायकता माय ही माय सांस्कृतिक पुनर्स्थापन के क्षेत्र में भी मागदाग रह रहे हैं। रामा राममोहनराय भारत के सबसे प्रथम राजनीतिक नेताओं में से ही एक नहीं थे अपितु वह बंगाला गद्य के जन्मदाता तथा शिक्षा के पुनर्गठन और महिला सुधार आन्दोलन के अग्रदूत भी थे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर केवल एक महान् कवि और कलाकार ही नहीं थे अपितु वह उन सबसे प्रथम लोगों में से थे जिन्होंने यह अनुभव किया कि राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण और हमारे प्रामाणिक जीवन के पुनर्गठन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। महात्मा गांधी भारतीय स्वाधीनता के सर्वोत्कृष्ट गिल्थी थे किन्तु साथ ही वह आधुनिक गुजराना गद्य के भी जन्मदाता थे। अनन्तर भारतीय भाषाभाषा को नये सिरे से गौरव प्रदान करने का कार्य भी मुख्यतया उनकी ही है। नवजागत भारत के नेताओं में से पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमलाना अंबेडकर के नाम आजाद न केवल स्वाधीनता-संघर्ष के निर्भीक याददा रहे हैं अपितु हमारे सृजनशील लक्ष्य में भी उनका स्थान अग्रगण्य है।

## २

इसलिए स्वाधीनता प्राप्ति के बाद की सांस्कृतिक गतिविधि का बणन केवल उस काल को ही ध्यात करनी पड़ेगी जसा है जो कई दशकों पहले प्रारम्भ हुई थी। स्वाधीनता से पूर्व के दिनों में इस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ की ओर मुख्यतया इनमें रुचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा समुदायों का ही ध्यान रहता था। एक उल्लेखनीय परिवर्तन यह हुआ है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इस प्रकार की गतिविधियों को राज्य की ओर से बड़ी अधिक मात्रा में प्रोत्साहन दिया जाना लगा है और सहायता दी जाने लगी है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है भारत में स्वाधीन होने के पहले ही बड़-बड़ एम्पक कलाकार संगीतज्ञ और वैज्ञानिक विद्यमान थे। परन्तु राज्य की ओर से इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई पर्याप्त संगठित प्रयत्न नहीं किया गया था। यह ठीक है कि समय-समय पर राज्य के उच्च अधिकारी भारतवासियों की कला, दान या विज्ञान की सफलताओं में रुचि दिखाया करते थे परन्तु इस प्रकार की रुचि सामान्यतया व्यक्तिगत स्तर पर होती थी। राज्य अपने आपमें कला के सम्पर्क से अछूता बना हुआ था।

हाल के वर्षों में इस बात को अधिक-अधिक अनुभव किया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी राज्य का एक कर्तव्य है। अनेक प्राधुनिक राज्यों में शिक्षा-मन्त्रियों को विद्वत् अध्यापन और शिक्षण के कर्तव्यों के अतिरिक्त समाज के सांस्कृतिक जीवन के विकास और उन्नति का भी काम सौंपा गया है और ऐसा होना भी चाहिए। साथ-साथ वर्षों में शिक्षा के अन्तर्गत कला तथा अन्य सांस्कृतिक रूपों में मानवीय अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों का समावेश होना चाहिए। यदि शिक्षा का अर्थ यह है कि मनुष्य में जो कुछ प्रसूत अवस्था में विद्यमान है उसे जाग्रत करके बाहर लाया जाए तो यह अनिवार्य है कि इस प्रकार की प्रशिक्षण अध्यापन-कार्य में दी जाने वाली जानकारी की सर्वांगीण सीमाओं के बाहर भी फैली जानी चाहिए। साथ-साथ यह है कि अनुभव से यह बात स्पष्ट हो गई है कि विद्वत् जानकारी भी सभी संपन्न और प्रभावशाली होनी है जब कि उसका सम्बन्ध व्यक्तिगत के इन विचलित पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ हो। यही कारण है कि आजकल यह

चाह सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि कला कोई प्रसाधन या सजावट की वस्तु नहीं है। यद्यपि यह मानना के दृष्टान्तिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है। यदि कला को स्वच्छन्द आत्म अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए तो उनका विकास कहीं अधिक तेजी से होता है। और यदि यह कला का प्रारम्भिक रूप नहीं तो और क्या है ?

इसलिए यह उचित ही था कि जब गिन्ना-विभाग—यह गिन्ना-मंत्रालय—को भारत सरकार में एक अलग इकाई के रूप में संगठित किया गया तो उसका नाम शिक्षा और कला विभाग रखा गया। अनेक कारणों से अनेक विस्तृत उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। स्वाधीनता से पूर्व के भारत में औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ कला और सांस्कृतिक गतिविधियाँ व विकास के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिला था। जो लोग कला की ओर आकृष्ट हो जाते थे वे प्रायः देश की सामान्य शिक्षा प्रणाली से दूर ही दूर रहते थे जबकि जो अधिकांश छात्र सामान्य शिक्षा प्राप्त करते थे वे कला की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी नई पीढ़ी की मानसिक गति का अधिकांश कारण यही है कि परम्परागत शिक्षा प्रणाली में उनके सवगात्मक और ललितकलात्मक पहलु की इस प्रकार उपेक्षा की गई थी।

परन्तु गत विषयबुद्ध की समाप्ति के वर्षों में मुद्रांतर शिक्षा के लिए बनाई गई विकास की योजनाओं में कला की आवश्यकता का काफी कुछ स्थान दिया गया था। बंगाल की राज्य एग्रीकल्चरल सासाइटी ने यह प्रस्ताव किया था कि भारत सरकार भारत के सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को उन्नत और विकसित करने के लिए एक सांस्कृतिक 'बोर्ड' (कल्चरल ट्रस्ट) का स्थापना करे। यह प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया और तीन अकादमियों—(१) साहित्य की (२) द्रव्यकलाओं की और (३) नाट्य नृत्य और संगीत की अकादमियों—की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की गई थी। क्योंकि सांस्कृतिक गतिविधियाँ के लिए बहुत अधिक धन और मूल्य सहानुभूति पूर्ण प्रतिश्रमाओं की आवश्यकता होती है इसलिए इस योजना का बनाने वाले लोगो ने प्रस्ताव किया कि यह 'बोर्ड' एक स्वायत्त निगम हो जिसके पास व्यय करने के लिए अपनी स्वतन्त्र विधियाँ हों।

यह स्वीकार हो करना होगा कि स्वाधीनता से पूर्व के भारत में इन सामान्य

योजनाओं के प्रतिरिक्त कला अथवा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की वृद्धि के लिए विचार कुछ नहीं किया गया। यह सत्य है कि कलकत्ता मद्रास बम्बई या लखनऊ जम महत्वपूर्ण केन्द्रों में कला में कुछ विद्यालय स्थापित किए गए थे परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा के क्षेत्र में कला के साथ मौननी पुत्री जमा व्यवहार किया जाता था। संगीत नृत्य और नाट्य कला की दशा और भी अधिक असंतोषजनक थी। इन कलाओं का प्रचार करने वाला लोग पर समाज की कोपदृष्टि थी और यदि बहुत हुआ तो समाज इसके प्रति विनम्र उत्पत्ति रहता था। इस काल में सलित कलाएँ बिलकुल समाप्त नहीं हो गई हमारा कारण यह था कि कुछ गिन चुन कलाकार भक्ति-पूर्वक इन कलाओं की स्थापना में लग गए थे और उन्हें कुछ आश्रयदाता भी मिले हुए थे।

संस्कृति सभी सर्वोत्तम रूप में बनपती है जब कि एक ऐसा वातावरण दिया मान हो जिसमें उसका अन्य संस्कृतियों के साथ खुला आदान प्रदान हो सके। दुर्भाग्य से भारत में अग्रजों के मान के बाद भारत के अपने पडासियों के साथ प्राचीन सम्बंध समाप्त हो गए थे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शायद ससार के साथ भारत के सम्बंधों का बहाना का बल किया और भारत के स्वाधीन होने से बहुत पहले ही वह भारत में अनपिठित (गैर-सरकारी) राजदूत का काम करते रहे। यूरोप के देशों अमेरिका दक्षिण अमेरिका दक्षिण-पूर्वी एशिया जापान, चीन ईरान और सोवियत रूस की उनकी यात्राएँ बहुत कुछ विजय-यात्राओं जमी थी। उनका इन यात्राओं से इन देशों के साथ भारत के सम्बंध फिर स्थापित हुए। परन्तु क्याकि ये सम्बंध मूलतः उनके व्यक्तित्व के कारण बने थे इसलिए यह भय था कि वही उनकी मृत्यु के बाद ये सम्बंध समाप्त न हो जाए। इस शताब्दी की तीसरी दशक की शुरुआत और चौथी दशक की प्रारम्भ में पं. जवाहरलाल नेहरू ने यूरोप के देशों का विस्तृत पर्यटन किया और इसने भी प्रभाव यह हुआ कि इन देशों का भारत के सम्बंधों में काफी कुछ पता चला। जगन्निचन्द्र बोस चन्द्रशेखर वकट रमन मेघनाद साहा तथा अन्य वैज्ञानिकों के साथ ही शिक्षा में भारत के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। प्रोफसर राधाकृष्णन ने भारतीय विज्ञान की जिस प्रकार नए ढंग से व्याख्या की, उसमें सारे सगर में विज्ञान का ध्यान आकृष्ट हुआ। साथ ही श्री अरविन्द के प्रभाव

भी पश्चिम के सभी देशों में विद्यमान थे। यह सत्यान म भले ही कम थे किन्तु ये सब प्रभावशाली लोग थे। अतः मैं किन्तु बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव आधुनिक सभार पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का रहा जिन्होंने मनुष्य की अन्तरात्मा को गहराई तक आलोचित कर दिया और सभार के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध म भारतम सस्कृति के महत्व को लोगों के सामन अधिकारिण रूप में स्पष्ट कर दिया।

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि स्वाधीनता की प्राप्ति से पहले तक भारत क सम्बन्ध में दूसरे देशों की रुचि छटपुट और अस्पष्ट-सी थी। परन्तु स्वतन्त्र भारत के उत्थान के बाद सभार ने सहसा हम बात को अनुभव किया कि यह एक ऐसा नया देश उठ खड़ा हुआ है जिसन न केवल अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की है अपितु उस स्वतन्त्रता को ऐसे सुसस्कृत और सुसभ्य ढंग से प्राप्त किया है जिसकी सारे मानवीय इतिहास में गायब रहा भी उपमा नहीं मिलता। स्वतन्त्र भारत का सरकार न भी हम बात को अनुभव किया कि सभार का भारत का जन मध्य रूप स सस्कृति और नतिक्ता क क्षत्रों में ही होगा। अनेक शताब्दियों में पहली बार भारत न एक राज्य के रूप में न केवल अपने देश के अन्दर अपितु दक्ष के बाहर भी कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का उन्नति में मज्जित रुचि लनी प्रारम्भ की।

### ३

हम अध्ययन में उन अनेक बातों में स कुछ का केवल एक बहुत सक्षिप्त विवरण ही प्रस्तुत किया जा सकता है जिन्हें भारत सरकार और राज्य-सरकारों देश के स्वाधीन होने के बाद करन का प्रयत्न करती रहा।। शायद यहाँ सबसे पहले यूनस्को के साथ सहयोग करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का उल्लेख कर देना उचित होगा। यूनस्को की स्थापना युद्धकाल के वर्षों म उन मूर्ख-युक्त तथा सदभावना वाले लोगों ने की थी जिन्होंने इस बात को अनुभव किया था कि जब तक राष्ट्रा का विभक्त रखने वाले सन्देश द्वेष और ईर्ष्या के भाव मगमगा नहीं हो जात तब तक स्थायी शान्ति की कोई आशा नहीं है। यूनस्को के सविधान में प्रस्तावना में यह ठीक ही कहा गया है कि क्योंकि सारे युद्धों का प्रारम्भ मनुष्यों के मन में होता है इसलिए शान्ति के



गठों का निर्माण भी मनुष्यों के मन में ही किया जाना चाहिए। यूनेस्को ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि विभिन्न राष्ट्रों में पारस्परिक प्रेम और सद्भावना स्थापित करने का कार्य पूरी तरह सरकारों पर नहीं छाड़ा जा सकता। सरकारें समाज के सगठित उपकरणों जैसी होती हैं और सरकारों का सम्बन्ध राजनीतिक प्रश्नों से होता है जिनमें मतभेद प्रायः अनिवार्य ही होता है। इसलिए यूनेस्को ने यह आदेश दिया कि इसमें भाग लेने वाला प्रत्येक देश अपने यहाँ एक गैर-सरकारी आयोग की स्थापना करे जिसका काम दूसरे राष्ट्रा के व्यक्तियों के साथ पारस्परिक सद्भावना और प्रेम को बढ़ाना हो। राजनीतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली भयानकताओं से स्वतन्त्र होने के कारण ये आयोग दूसरे देशों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने में सरकारी अभिकरणों (एजेंसियों) की अपेक्षा अधिक सफल हो सकेंगे।

भारत यूनेस्को का एक संस्थापक सदस्य है और बिलकुल प्रारम्भ में ही भारत ने सम्पूर्ण हृदय से यूनेस्को के उद्देश्यों को स्वीकार कर लिया है। इन उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से १९४९ में भारत सरकार ने एक अन्तःकालीन आयोग की स्थापना की थी जिसे बाद में १९५३ में स्थायी बना लिया गया। इस स्थायी राष्ट्रीय आयोग की ओर से पहला सम्मेलन जनवरी १९५४ में किया गया जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया। इस सम्मेलन में एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों से अनेक बड़े प्रतिनिधि आए हुए थे। मंच कहा जाए तो यह सम्मेलन यूनेस्को का लगभग एक प्रायोगिक सम्मेलन ही बन गया था और शायद यह पहला अवसर था जबकि किसी राष्ट्रीय आयोग ने इस प्रकार के सम्मेलन को बुलाने में पहल की हो। यह आयोग प्रत्यक्ष रूप से और अपने अन्य साथी संगठनों की मारफत जो विविध रूपों में शिक्षा विज्ञान और संस्कृति की उन्नति में जुटे हुए हैं दोनों ही उग में कार्य करता है। विज्ञान तथा शिक्षा की उन्नति के लिए जो यत्नजात (अपीनरी) खड़ा किया गया है उसका यहाँ विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह तो भारतीय शिक्षा का सामान्य क्या-का ही एक अंग बन गया है। फिर भी यहाँ उग यत्न जात का कुछ वर्णन कर देना उचित होगा जो सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए खड़ा किया गया है।

बंगाल की रायस एशियाटिक सोसायटी द्वारा प्रस्तावित उग योजना का

उल्लेख ऊपर किया जा चुका है जिसमें एक ऐसे सांस्कृतिक याम की स्थापना करने का मुझाव दिया गया था जो भाषा और साहित्य संगीत नाट्य और नृत्य चित्रकला वास्तुकला तथा अन्य दृश्य कलाओं के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तीन अकादमियों की माफत काम करने वाले एक सांस्कृतिक न्यास की स्थापना का मुझाव दिया गया था। इस सम्बन्ध में सोसायटी के प्रस्तावों पर विभिन्न कलाओं के सुप्रसिद्ध प्रतिनिधियों के कई सम्मेलनों में और भी विचार किया गया। इन सम्मेलनों में पुराने परम्पराओं को बनाए रखने और उन्हें समृद्ध करने के साथ-साथ नये युग की भावना के अनुसार परीक्षण और नवीनीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ उपाय सुझाए। इस समय तीन राष्ट्रीय अकादमियाँ स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित की जा चुकी हैं और उनका काम यह है कि वे कला के क्षेत्रों में प्रमाणा को न केवल पहले जैसा बनाए रखें अपितु उन्हें और भी उन्नत करें और नये विकास को प्रोत्साहन दें।

दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए १९४७ के बाद बहुत आशाजनक काम किया जा चुका है। अनेक कारणों से स्वाधीनता प्राप्त करने से पहले भारत के सम्बन्ध एशिया तथा अफ्रीका के देशों के साथ नहीं क बराबर थे। भारत के यूरोपीय देशों के साथ सम्बन्ध भी मुख्यतया इंग्लैंड के साथ ही थे। इसलिए यह अनुभव किया गया कि पहला काम यह होना चाहिए कि अपने विनकुल निकट के पड़ोसियों के साथ विरप्राधीन सम्बन्धों को फिर से स्थापित किया जाए। द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्तिम वर्षों में ईरान में एक सद्भावना निष्ठमंडल भारत आया था और उसके फलस्वरूप दिल्ली में एक छोटी-सी भारत ईरानी संस्कृति समिति की स्थापना हुई थी। स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद यह अनुभव हुआ कि इस समिति के कार्यक्षेत्र और कार्यक्षेत्र को इतना विस्तृत कर दिया जाना चाहिए कि इसका लक्ष्य केवल ईरान के साथ ही सांस्कृतिक सम्बन्धों का सुन्दर करना न रहे बल्कि भारत के सभी पड़ोसियों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को सुन्दर करना बन जाए। तदनुसार भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध-परिषद् (इण्डियन कौंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स) की स्थापना एक स्वाधीन और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई। इस परिषद् का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने इसकी स्थापना का स्वागत करते हुए कहा कि यह मध्या भारत तथा संसार के अन्य देशों के मध्य संस्कृति के क्षेत्र में अनिच्छ

सम्बन्धों की स्थापना के लिए एक शुभ गुरुन सित्द होगी । इस समय इस परिषद् में कई अनुभाग (सेक्शन) हैं । इनमें से एक अनुभाग पश्चिमी एशिया के देशों तथा टर्की के साथ व्यवहार करता है दूसरा दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ और तीसरा अफ्रीका के देशों के साथ । यह प्रस्ताव है कि समय बीतने के साथ-साथ यूरोप तथा अमेरिका के देशों के साथ सम्बन्ध घनिष्ठ करने के लिए और भी अनुभाग आले जाए ।

इस परिषद् में अनेक प्रकार की गतिविधियाँ अपने हाथ में ली हैं जिनमें से यहाँ केवल कुछ प्रमुख गतिविधियाँ का ही उल्लेख करना उचित होगा । इस परिषद् में एक पुस्तकालय और वाचनालय तैयार किया है और यह अनेक पत्रिकाओं तथा अन्य सांस्कृतिक सामग्री के प्रकाशन में भी सहायता दे रही है । इस परिषद् में दूसरे देशों से प्रापमरा तथा अन्य विज्ञानों का भारत के साथ आदान प्रदान किया है और कलाकारों के देशों को सांस्कृतिक यात्राएँ करने में सहायता दी है ।

इस परिषद् के कार्यों के अनिवारित स्वतन्त्र भारत ने दूसरे देशों के साथ अपने सांस्कृतिक सम्बन्ध अन्य उपायों द्वारा भी बढ़ाने का प्रयत्न किया है । अमेरिका इंग्लैंड ईरान अफगानिस्तान आस्ट्रेलिया टर्की जापान रूस और अफ्रीका के कुछ देशों में भारत से विद्वान् और छात्र भेजे गए हैं और उन देशों के विद्वान् और छात्र भारत में भेजाए गए हैं । भारत ने तत्मानिया जर्जीबार् अफगानिस्तान मलाया इथियोपिया और मूडान जस देशों में अध्ययन भजन का भी प्रवर्धन किया है । भारतीय संस्कृति और इतिहास के सम्बन्ध में पुस्तक अनेक देशों के चुन हुए पुस्तकालयों का भेंट की गई है । भारत में कुछ पुस्तकालय संपुर्ण राष्ट्र और उसके विभिन्न अभिकरणों (एजेंसियों) के प्रकाशनों का संग्रह अपने यहाँ रख रहे हैं । भारत ने अमेरिका और इंग्लैंड की सरकारों से यह भी समझौता किया है कि इन देशों के सब सरकारी प्रकाशनों का भारत के सरकारी प्रकाशनों से विनिमय कर लिया जाए ।

विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि उन देशों में विद्यापिया और विद्वानों का आवागमन स्वच्छ रूप से होना रहे । भारत ने काफी बड़ी सख्या में इस प्रकार की छात्रवृत्तियाँ तथा फेलोशिपों के विनिमय का प्रवर्धन

किया है। एक योजना के अनुसार जो पुनर्बाइल कामकाज नाम से प्रसिद्ध है पिछले पाँच वर्षों में भारतीय और अमेरिकन अध्यापकों और छात्रों का काफी बड़ा सन्ध्या में विनिमय हुआ है। इन्सट्रुक्शन के सम्बन्ध में इस प्रकार के कामकाज का सगठित करने के लिए ब्रिटिश कौंसिल ने काफी सहायता दी है। विनिमय के आधार पर काम मित्र इटली ईरान जर्मनी यूगोस्लाविया और चीन में भी इस प्रकार की फैलावटों की व्यवस्था की गई है। पिछले कुछ वर्षों से सांस्कृतिक छात्रवृत्तियों के लिए एक सर्वांगमय योजना भी चल रही है जिसके अन्तर्गत एशिया और अफ्रीका के विज्ञान प्रयोगशाला जान ह और कुछ गम प्रयोगशाला जान ह जहाँ भारतीय जाकर काम करते हैं।

पिछले हाल के वर्षों में भारत ने ईरान अफगानिस्तान और इजानिया में पुरातत्त्वविद्या के मदद में भेजा है। अनेक सरकारी सम्प्रदायों की सहायता से भारत ने समार के वर्ल्ड्स में भारतीय कला की प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया। भारत में अमेरिका से चीन फ्रांस इजानिया तथा अन्य देशों से भी सरकारी या सरकारी प्रदर्शनियाँ आ चुकी हैं। भारत के अनेक नगरों में प्राचिनक यूरोपियन उत्कृष्ट कलाकृतियों की मूर्तियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियाँ भी हो चुकी हैं। यहाँ पर अमेरिका आस्ट्रिया और जर्मनी जैसे अनेक देशों में हुई अन्तर्राष्ट्रीय कला-कला प्रदर्शनियों में भारत की ओर से मजबूत गई कृतियाँ तथा नई दिल्ली में 'गोल्डन बीकली' का द्वार से प्रति वर्ष आयोजित की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय कला-कला प्रदर्शनियों का विविध रूप से उत्कृष्ट कराना उचित होगा।

भारत के स्वाधीन होने से कुछ ही पहले लन्दन की रायल एकेडेमी ने भारतीय कला की एक प्रदर्शनी की थी। शायद इससे बड़ा भारतीय कला की प्रदर्शनी और काम नहीं हुई। इस प्रदर्शनी में पिछले पाँच हजार वर्षों में हुए भारतीय कला के विकास का बड़ा विचार प्रदर्शन किया गया था। अविभक्त भारत के सब प्रभुत्वानुसार और निजी रूप से कलाकृतियों का संग्रह करने वाले लोगों तथा राजाओं के उत्तरदायी महयोग के कारण यह प्रदर्शनी अत्यन्त सफल थी। यह अनन्त किया गया कि इस प्रदर्शनी को विस्तारित करने से पहले इसका प्रदर्शन दिल्ली में हो दिया जाए। इस प्रदर्शनी का महत्त्व से इस विचार का आलोचना मिली कि इस प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुष्ठान के नाभिक

(यूविलयस) के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाए। जब तक अदभुततासय के भवन भवन का निर्माण न हो जाए तब तक के लिए कुछ कलाकृतियाँ राष्ट्रपति भवन में रख दी गईं। यह राष्ट्रीय अद्भुततासय देग की कला का सच्चा प्रतिनिधि हो इसके लिए सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि दूसरे देगों में विद्यमान बहुमूल्य भारतीय कलाकृतियाँ की खोज की जाए। यह सोचा गया है कि जहाँ तक सम्भव हो मूल कलाकृतियों को प्राप्त करने का यत्न किया जाए और यदि मूल कलाकृतियाँ उपलब्ध न हों तब तो कुशल विगणना द्वारा उनकी प्रतिकृतियाँ (मकलें) तयार करा ली जाए। बहुमूल्य कलाकृतियों के देग से अविवेकपूर्ण निर्यात को रोकने के लिए कानून बनाया जा चुका है। अद्भुततासय के स्थायी भवन की आधार गिला भी हाल ही में रखी जा चुकी है। आधुनिक भारतीय कला का एक संग्रह उद्य जगह रखा गया है जो पहले जयपुर हाउस कहलाता था और कलाकृतियों के इस संग्रह को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। कुछ राज्य-सरकारों के सहयोग से महत्वपूर्ण कलाकृतियों की खरीद के लिए एक स्थायी निधि बना ली गई है।

यहाँ भारत सरकार के सत्त्वावधान में प्रकाशित किए गए विश्व-दर्शन के सर्वांग-सम्पूर्ण इतिहास का भी विगण रूप से उल्लेख कर देना उचित है। अब तक इस प्रकार के जितने इतिहास लिख गए थे उनमें केवल एक देग या प्रवेश के देगानशास्त्र का ही बणन रहता था। पश्चिमी देगान के इतिहासों में भारतीय अथवा अरबी शानशास्त्र का कभी-कभी उल्लेख मात्र ही होता था। इसी प्रकार भारतीय दर्शन के इतिहासों में भी अन्य देगों के देगानशास्त्र का जहाँ तहाँ उल्लेख रहता था परन्तु अब तक विभिन्न देगों और विभिन्न युगों के मानवीय विचार के विकास का कोई सर्वांग-सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं था। वस्तुतः इस प्रकार का अध्ययन किसी भी समय महत्वपूर्ण समझा जाता परन्तु आधुनिक युग में जबकि विभिन्न जातियों और विभिन्न गणकृतियों एक-दूसरे के बहुत निकट आ गई हैं—राष्ट्रा में एक-दूसरे के प्रति सहभावना उत्पन्न करने के लिए—इस प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता बहुत तीव्र हो उठी है। इसलिए गिगा-मन्त्रालय का एक पहला काम यह था कि समार के विभिन्न देगों के सम्बन्ध ६० विज्ञानों के महयोग में शौरस्थ और पाश्चात्य देगान के इतिहास

(हिन्दी भाषा फिलोसफी इन्स्टीट्यूट एण्ड सेंटर) तयार कराया जाए और प्रकाशित किया जाए।

#### ४

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार अपने आपमें उत्कृष्ट कलाकृतियाँ का सृजन नहीं कर सकता। कुछ सामाजिक लोग तो यही सब विचार है कि सरकार कला का उत्थान में भाग सहायक नहीं हो सकता क्योंकि सरकार का संरक्षण मितन पर सम्भव है कि लोगों की कलात्मक गतिविधियाँ गन्त गंगा में धली जाए। इस प्रकार के मतों में सचन के लिए ही भारत में तीन राष्ट्रीय अकादमियों की स्थापना की गई है। इन अकादमियों के मुख्य मुख्य रूप से विभिन्न गंगा में कार्य कर रहे कलाकार हैं। फिर भी इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राप्ताह और समर्थन का उचित वातावरण तयार करके राज्य कलाका के विकास में सहायता दे सकता है और उस देनी भी चाहिए। प्रजातन्त्र में यह बात और भी अधिक आवश्यक हो गई है। अतीत काल में सम्पूर्ण लोग—चाहे उन्हें पता ही न था प्राप्त होता था अथवा उद्योग से—कला के संरक्षण बन सकते थे। परन्तु जो दण समानतावादी की ओर बढ़ रहा है उसमें या तो नम प्रकार के विग्राहिकार्यक दण लुप्त हो चक हैं या लुप्त हो जा रहे हैं और उनका स्थान राज्य का लेना ही चाहिए।

भारत सरकार ने एक बिल्कुल नया काम सब उठाया जब उसने यह निश्चय किया कि तदण कलाकारों को इस प्रकार की छात्रवृत्तियाँ दी जाएगी कि जिनमें वे एक या एक से अधिक वर्षों के लिए पैसे की बिना स मक्त हो जाए और स्वतन्त्र रहकर अपना कला का विकास कर सकें। एक और योजना के अन्तर्गत स्यातिप्रिय कलाकारों को इस प्रकार के अनुदान दिए गए कि जिनमें वे विभिन्न प्रकार की कलाका का परिमाण (सर्वेक्षण या सर्वे) कर सकें और उन कलाकृतियों का प्रदर्शन कर सकें जो संरक्षण के अभाव में नष्ट हुई जा रहा है। राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना के बाद अमरवमा चित्र-ग्रंथों (पोस्टरालिया) तथा चित्रमय पोस्टरालों के प्रकाशन की व्यवस्था की गई जिससे कला जनता में लोकप्रिय हो जाए। तदण कलाकारों का प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए सामयिक प्रशस्तियाँ अधिकधिक परिमाण में दी जा रही हैं। यहाँ पर

उन युद्ध कलाकारों के लिए जिन्होंने अतीत में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी और इस समय आर्थिक कठिनाइयाँ महसूस करने की प्रणाली का भी विरोध रूप से उत्पन्न किया जा सकता है।

साहित्य प्रकाशकों साहित्यकारों की इसी प्रकार की सेवा करने का प्रयत्न कर रही है। इसमें राष्ट्रीय पुस्तक बणन-सूची तैयार करने का काम हाथ में लिया है। यह प्रकाशकों को लिखने की ओर आकर्षित करने का सबसे बड़ा कदम है। रचनाओं का एक प्रमाण सस्करण तैयार करने में सहायता दे रही है। साहित्य प्रकाशकों ने यह भी निश्चय किया है कि प्रत्येक आधुनिक भारतीय भाषा की सर्वोत्तम रचनाओं के संग्रह प्रकाशित किए जाएँ और उनके अनुवाद दूसरी भाषाओं में कराए जाएँ जिससे सारे देश की एकमात्र साहित्यिक निधि तैयार हो जाए।

अब समय आ गया है कि संगीत के क्षेत्र में भी हम अपनी अतीत की सफलताओं का नये सिर से मूल्यांकन करें। इस समय हमारे संगीतज्ञों में नये-नये परीक्षणों की प्रेरणा बहुत स्पष्ट नहीं है। फिर भी धारकस्ट्रा का प्रयोग तथा नये ध्वनिसंयोगों को तैयार करने की ओर प्रयत्न का कुछ प्रारम्भ हुआ बीछता है। एक लम्बे युग से भारतीय संगीत अपने पुराने ढंग पर ही रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बीच-बीच में कुछ संगीत के सुधारकों की कोशिशें रह चुकी हैं जिन्होंने कुछ नये तत्वों का मिश्रण करने की कोशिश की। हम सम्भव है कि हमारे सुधारकों का नाम लिया जा सकता है। फिर भी भारतीय संगीत की प्रमुख रूपरेखा लगभग २०० वर्षों में अपरिवर्तित बनी आ रही है।

इस समय व्यक्तियों और देशों के द्वारा किए जा रहे पृथक् पृथक् प्रयत्नों का अतिरिक्त भारत सरकार भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करके—जिनमें विभिन्न स्वीकृत संगीत-पद्धतियों का संगीतज्ञ मिलकर काम कर सकें और नई पद्धतियों का विकास कर सकें—भारतीय संगीत को समुन्नत करने का प्रयत्न कर रही है। यह बात गवर्नरित है कि उत्तर और दक्षिण भारत में भारतीय संगीत नगमन समानान्तर गताओं में विकसित हुआ है। यह प्रमाण देता गया है कि राष्ट्रीय प्रकाशकों का संचालन में विभिन्न प्रणालियों में विकसित हुई संगीत पद्धतियों का अध्ययन करने का लिए प्रायोगिक प्रकाशकों का स्थापना की जाए।

खलनऊ की हिन्दुस्तानी संगीत प्रकाशेमी तथा दक्षिण में बर्नाटक संगीत विद्यालय प्राचीन संगीत-परम्पराओं के कोशागारों के रूप में प्रयुक्त किए जा सकेंगे। यह भी विचार है कि इन संस्थाओं को संगीतशास्त्र में नये परीक्षणों की प्रयोगशाला-सा बना डाला जाए। हिन्दुस्तानी प्रकाशेमी की स्थापना के तुरन्त बाद में ही एक मनोरञ्जक प्रयत्न यह किया जा रहा है कि संगीत का उपयोग भावनाओं को सुसंस्कृत करने के लिए किया जाए। इस परीक्षण का उद्देश्य यह पता चलाना है कि संगीत की विभिन्न तरंगों, धुनों और गतों का वाक्मय के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार जब इस सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकाल लिए जाएंगे तब उस ज्ञान का उपयोग विद्यालयों के सामान्य पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए किया जा सकेगा।

भारत में लोकनृत्य की परम्परा कई सताब्दी पुरानी है। अग्रजों के आगमन के पश्चात् इस बात का भय था कि यहाँ यह परम्परा समाप्त न हो जाए। अनेक दशकों तक नृत्यकला केवल उन छोटे-से पेशेवर नर्तक और नर्तकियों तक ही सीमित रही जिनका कि स्थान समाज में बहुत नीचा था। इस शताब्दी की चौथी दशक में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रेरणा से नृत्यकला का पुनरुत्थान हुआ। उन्होंने न केवल नृत्य के अनेक पुराने रूपों को पुनरुज्जीवित किया अपितु नृत्य को प्रतिष्ठा की वस्तु भी बना लिया। इस सम्बन्ध में उल्लेख करने का नाम का उल्लेख करना भी उचित होगा जिसने विदेशों में भारतीय नृत्यकला की शक्ति के लिए बहुत काम किया है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद नृत्य के विभिन्न रूपों के सम्बन्ध में लोगों की रुचि तीव्र रूप से जागृत हो गई है। भारत सरकार ने विद्यालयों में प्रारम्भ करने के लिए प्रतिनिधि लोकनृत्यों और संगीतों का संग्रह करने का काम प्रारम्भ कर दिया है। क्योंकि यह अनुभव किया गया है कि कला के इन सजीव रूपों को जीवित बनाए रखने का यही एक सर्वोत्तम उपाय है कि उसका विद्यालयों में अभ्यास कराया जाए।

साहित्य के क्षेत्र में सभी भारतीय भाषाओं में लेखन की बाढ़-सी आई हुई है। इस सम्पूर्ण लेखन की एक विशेषता प्रस्तावनात्मकता और बकनीकपन भी हो सकती है। साहित्य के प्राचीन रूपों की परम्परा वर्तमान की आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए भी जा रही है और प्रायः इन प्राचीन रूपों पर यह आभास किया जाता है कि वे अप्रयोज्य हैं। स्वयं भाषा तक के ज्ञान-धाने में





## १

यह स्पष्ट है कि कोई प्रभावी उपाय शुरू करने से पहले हमें परिस्थिति का ठीक-ठीक पान होना चाहिए और वर्तमान अज्ञानि को उत्पन्न करने वाले कारणों का सुस्पष्ट रूप में पता होना चाहिए। यदि इन सब कारणों का विश्लेषण करने बैठें तो एक पूरी पोथी तयार हो जाए। परन्तु कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारणों का जिनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना उचित है। यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जाता है।

### (क) अध्यापकों की नतत्व-शक्ति का ह्रास

छात्रों में वर्तमान अज्ञानि की दशा का प्रथम और सबप्रथम कारण अध्यापकों की स्थिति है। जहाँ अध्यापक लोग छात्रों का समुचित नतत्व करते हैं वहाँ छात्रों में अन्यायमहीनता की कोई समस्या उठ हा नहीं सकती। दुर्भाग्य से आजकल अध्यापकों को अपने छात्रों का उतना ध्यान और प्रेम प्राप्त नहीं है जितना उह अतीत में प्राप्त था। इसका मुख्य दोष उनके ही सिर नहीं है। अध्यापकों की नतत्व-शक्ति का ह्रास जिन कारणों से हुआ है उनमें से कुछ मुख्य कारणों का वर्णन संक्षेप में नीचे दिया जाता है।

(अ) १९२० के बाद राजनीतिक चेतना की बढ़ि हान के साथ-साथ विद्यार्थी लोग भी राजनीतिक संघर्ष में बूढ़ पड़। इन संघर्षों में उन्होंने निरन्तर या किसी मुमकत रूप से भाग नहीं लिया परन्तु राजनीतिक दमता के विरुद्ध विद्रोह की सामान्य भावना और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए सड़न की इच्छा सबत्र फल गई थी। महात्मा गांधी की चितरंजनगत १० जवाहरनाल नहुन मौसानी अहुल बनाम भाडा और थी मुभापचद बोस तथा अन्य नेताओं के व्यक्तित्व का भी यवक विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अध्यापकों लोग अनक कारणों से राजनीतिक संघर्ष में सक्रिय भाग नहीं ले सक और किसी सीमा तक अपने छात्रों की दृष्टि में प्रतिष्ठा और धार गंवा बैठ।

(आ) गत ३ वर्षों में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की अविराम और अनक बार तो बड़ी विस्तृत आलोचना होती रही है। आलोचना और निन्दा में बवल एक काम का ही अन्तर रहता है। इस शिक्षा प्रणाली की निन्दा में शिक्षकों की भी निन्दा की जाती है। इसके कारण अध्यापकों का आत्मविश्वास और

नतिक वस दीण हो गया और जनता के मन में इस पेग के प्रति घनादर का भाव जाग उठा। इस आलोचना के फलस्वरूप विद्यार्थियां भी गिना प्रणाली और गिनाकी के प्रति तिरस्कार की भावना उत्पन्न हो गई और वे इनसे उतना साम भी नहीं उठा सके जितना कि उठाया जा सकता था।

(इ) कम काल में उपयुक्त कारणा से तो अध्यापक की प्रतिष्ठा निरन्तर गिरती ही जा रही थी वरन्तु उसकी प्रतिष्ठा के गिरने का सबसे बड़ा कारण यह था कि अध्यापक की आय बहुत थोड़ी थी। तीस या चालीस वष पहले केवल पाइसे ही भारतीयों को ऊँची सरकारी नौकरी या सैन्य की भागा रहती थी। उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्रों में भी घसघात का अवसर बहुत कम था। ज़्यादा अन्य दिशाओं में लोगों को काम करने का अवसर मिलने लग गया-एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती गई जिसमें अध्यापन के क्षेत्र में वे ही लोग आने लग जो अन्य किसी क्षेत्र में जा पान में असफल रहते थे।

(ई) यज्ञकाल में और यज्ञोत्तर मुद्रा प्रसार (इनफ्लेशन) के काल में उत्पन्न कठिनाइयों के कारण लोगों में यह सामान्य इच्छा जाग उठी कि अधिनाधिक वेतन वाले पद प्राप्त करने की कोशिश की जाए। अध्यापकों के वेतन पहले ही बहुत असंतोषजनक थे अब तो वे जीवन निर्वाह के लिए भी अपर्याप्त हो गए। अध्यापकों को विविध रूप से बड़े सहरो में आय के अन्य महायुक्त साधन ढूँढने के लिए विवश होना पड़ा। अतः पुराने अध्यापक इस पेग की छानने के लिए विवश हो गए और युवक लोग अध्यापक बनने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। इसका परिणाम यह हुआ कि आजकल के अध्यापक न केवल दरिद्र हैं अपितु प्रायः हताश और कटुता से भरे हुए हैं। इससे समाज में उनका स्थान ही नीचा नहीं होता अपितु वे समाज के लिए वास्तविक सबूत के स्रोत बन गए हैं।

(उ) गिना की सुविधाओं में विस्तार के लिए जो माँग की गई वह यद्यपि पूर्णतया उचित थी फिर भी उसमें अध्यापक की प्रतिष्ठा दो रूपों में कम हो गई है। एक ओर तो कम आय और बड़ी संख्या में अध्यापकों की माँग हान के कारण हम पेग के द्वार उन लोगों के लिए भी खोल दिए गए, जिनमें अध्यापन के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी। दूसरी ओर विद्यार्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने का परिणाम यह हुआ कि अध्यापकों और गिनों में व्यक्तिगत सम्पर्क बिल्कुल समाप्त हो गए। अतीत

काल में इस प्रकार के व्यक्तिगत सम्पत्तियों के फलस्वरूप अध्यापक अपनी विद्वत्ता या चरित्र या दोनों के कारण अपने शिष्या की निष्ठा और भ्रमण वार उनका प्रेम तक प्राप्त करने में सफल होते थे। इस नई परिस्थिति में प्रयोग्य अध्यापकों के लिए जिनका अपने छात्रों से निजी सम्पर्क बनाने का भवसर नहीं के बराबर था किसी भी प्रकार विद्यार्थियों का आदर प्राप्त कर पाता बहुत कठिन हो गया।

(क) विद्वत् शिक्षा के मामले पर भी अध्यापक का नियंत्रण बहुत कम था। विश्वविद्यालय कॉलेज और स्कूलों पर प्रायः राजनीतिज्ञों का ही नियंत्रण रहता है। यहाँ तक कि पाठ्याक्रम और परीक्षाओं का क्षेत्र भी अध्यापक के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर ही बाहर रहता है। परीक्षाओं पर आवश्यकता से अधिक जार देन का परिणाम यह हुआ कि अध्यापक लोग छात्रों को केवल परीक्षा के लिए तैयार कराने मात्र अभिवर्तित (एजेंट) मात्र रह गए हैं।

(ख) अध्यापक के महत्त्व का ह्रास निरन्तर बढ़ता होता गया। इसका एक और बड़ा कारण यह है कि उन्होंने पैसे लेकर निजी ट्यूशन करीब-करीब व्यापारिक स्तर पर करना प्रारम्भ कर दिया। ऐसे भी भ्रमण अध्यापक हैं जो अपने विद्यालय के काम की अपेक्षा निजी ट्यूशन पर कहीं अधिक समय लगाते हैं और उन पर कहीं अधिक ध्यान देते हैं। ऐसे मामले भी कम नहीं हैं जिनमें कि अध्यापक अपना निजी काम करने के कारण जितन अधिक पैसे पाते हैं कि वे विद्यालय में अपने कर्तव्यों की उचित रूप से पूरा नहीं कर पाते। इससे अतिरिक्त किसी विद्यार्थी या विद्यार्थी के सरसकट से सीने छोर पर पैसा लेने का परिणाम यह हो जाता है कि अध्यापक और शिष्य में एक ऐसा आर्थिक सम्बन्ध बन जाता है जिसके कारण अध्यापक अपने छात्र पर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता और उम्र पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता।

(ग) उपरिलिखित कारणों से विद्वत्ता तथा भ्रमण दृष्टियों से भी अध्यापक की उत्कृष्टता का ह्रास होना आवश्यक था। जब एक बार अध्यापक की उत्कृष्टता घट गई तो छात्रों के समक्ष उनकी महत्त्वशक्ति और भी तेजी से कम होती चली गई। इस प्रकार एक ऐसा दुश्चक्र-भाग बन गया जिनमें एक ओर तो अध्यापक की महत्त्वशक्ति कम होनी जान के कारण योग्य व्यक्ति इस पेशे से दूर हो रहे होंगे और दूसरी ओर क्योंकि योग्य व्यक्ति इस पेशे

स दूर रहन सग इसलिये अध्यापक की नतत्व-शक्ति निम्नलिखित कम और कम होती चली गई।

### (ख) आर्थिक कठिनाइयाँ की वृद्धि

अध्यापक की नतत्व-शक्ति का हानि अपने आप में हर हालत में एक सम्भार समस्या होती परन्तु आर्थिक कठिनाइयाँ की वृद्धि के कारण यह और भी चिन्ताजनक हो उठी। देश के औद्योगिक और वाणिज्य-सम्बन्धी विकास तथा काम पाव के लिए एक अनवरत नय-जम साधन बनाएँ या उच्च प्रसन्निक संकाय-क्षेत्र से ज्ञान के बाजार में जा पहुँचाने के लिए लगभग बिनाकुल बन्धन आर्थिक कठिनाई निरन्तर बढ़ती ही गई है। अतः यह सारे समार में विद्यमान स्थिति का ही एक अंग है। युद्धकाल में सम्पत्ति और उनके खाना का महान् निम्न हानि के कारण समाज में स्वतन्त्रता का भाव उत्पन्न हो गई है। औद्योगिक तथा आर्थिक स्थिति में कहीं अधिक विकसित देश भी इस निम्नलिखित में फँसे हुए हैं तो बाह्य आर्थिक की बात नहीं कि भारत का भी इस कठिनाई का सामना करना पड़। जनसंख्या में वृद्धि हानि के प्रतिरिक्त परिस्थिति इस कारण और भी अधिक विषम हो गई है क्योंकि लोग अब उन गान-हीन देशों में रहने के लिए तैयार नहीं हैं जिनमें वे पहले बिना होकर गये थे। इस स्थिति का छात्र वर्ग पर भी अनवरत रूप से प्रभाव पड़ा है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण रूप निम्नलिखित हैं

(घ) छात्रों का संख्या में उड़ी से वृद्धि हुई है और बहुत-से छात्र उन सामाजिक स्तर से आए हैं जो उनका न्यूनतम आवश्यकताओं का पूरा करने का प्रबंध नहीं कर सकते। अतः में छात्रों की संख्या बहुत बढ़ी होगी और वे सामान्यतया अपना कुल सम्पन्न वर्गों में से आते हैं। इसलिए उस समय उन्हें कम से कम अपने छात्र-जीवन में किन्हीं बड़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था। अब क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ गई है और वे समाज के सभी वर्गों में से आने लग गए इसलिए वे अपने छात्र-जीवन में भी आर्थिक संघर्ष के बोझ को अनुभव करने लग गए। अपने मामलों में तो छात्रों को अपने विद्यालय और कॉलेज के अध्ययन-काल में भी अपना निवाह पणवत्ता अपना आर्थिक रूप से अपने परिश्रम द्वारा ही करना पड़ता ॥

प्राप्त करना चाहता है परन्तु इसमें उन बातों की धीर किंगारा के लिए जिनकी रुचियाँ धीरे धीरे अभिव्यक्तताएँ ललित कलाओं में प्राविधिक (गिल्ड सम्बन्धी) या अन्य व्यावहारिक प्रशिक्षण की ओर झुकी हुई हैं पर्याप्त प्रवृत्ति नहीं है। अतः यह कहना असाध्यपूर्ण होगा कि आजकल की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल लिपिक तैयार करना है वही हम यह भी स्वीकार करना चाहेंगे कि इस शिक्षा के फलस्वरूप लोग का भ्रूण स्वच्छन्दस्वीय व्यक्तियों की ओर हा जाता है और इस शिक्षा का प्राप्त करने वाले लोग में स अनन्त केवल इस प्रकार के कामों के प्रतिरिक्त और किसी काम के उपयुक्त नहीं होते। इस शिक्षा-प्रणाली में ज्ञान-विद्या की दारोरेक क्षमताओं के विकास का उपेक्षा की जाती है। यह शिक्षा प्रणाली शिक्षित लोग का नारीरिक धर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न कर देता है क्योंकि ये शिक्षित लोग हाथ की मामूली कारीगरियाँ से भी अनभिज्ञ होते हैं। इस शिक्षा प्रणाली में छात्रों के चरित्र के विकास और उनमें नैतिक मूल्यों की भावना उत्पन्न करने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और यह प्रणाली इस सम्बन्ध में अधिकारों की उदासीन रहती है।

(भा) विद्वान् ज्ञान के दृष्टिकोण में भी यह शिक्षा प्रणाली पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं। पालक प्रायः बहुत अल्प होते हैं और यदि उनको ठीक-ठीक उग से पढ़ाया जाए तो उनके द्वारा छात्रों में स्वतन्त्र विचार और सन्तुलित निष्पत्ति करने की शक्ति विकसित हो सकती है परन्तु वस्तु में जिस वस्तु का विकास होना है वह है बिना समझे ब्रूम अपने मस्तिष्क में जानकारी का ठोस स्तम्भ की प्रकृति। इस प्रकृति का एक मुख्य कारण यह है कि अन्तिम परीक्षा का तरीका ठीक नहीं है और अन्तिम परीक्षा पर अनुचित रूप से अधिक जोर दिया जाता है। विद्यार्थियों की परत अन्तिम परीक्षा द्वारा का जाती है जो वस्तुतः किसी विषय की समझ की अवस्था निष्पत्ति करने की परत में हाथर स्मृति-शक्ति की जाँच भर होती है। इसका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी अपने अपने शिक्षा-व्यय में तो अपने काम की उपेक्षा करते रहते हैं और अन्तिम कुछ सप्ताहों में रट रटाकर अपने विषय में इसकी जानकारी ठोस करना चाहते हैं कि जिनके वे जैसे-तैसे अन्तिम परीक्षा में पास हो जाए। इनके अनेक अवांछनीय परिणाम होते हैं। क्योंकि वे अधिकार भाग में छात्रों की ऊर्जाएँ पूरी तरह कायम नहीं रहती—इसलिए वे अनेक गतिविधियाँ

के रूप में बाहर निकलने के मार्ग दृढ़ होती रहती है जिनमें से अनन्य निश्चित रूप से समाज-विरोधी होती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से बीच-बीच में रुक-रुक कर काम करना की अपेक्षा पड़ जाती है जिसके फलस्वरूप बहुत-से विद्यार्थी सम्बन्धित समय तक निरन्तर कठिन परिश्रम करने में असमर्थ हो जाते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि अन्तिम परीक्षा पर अनुचित जोर देने का यह परिणाम हो सकता है और बहुत बार होता है कि विद्यार्थी आसानी से सफलता प्राप्त करने के लिए अनचित् उपायों का अवलम्बन करने लगते हैं।

(इ) अन्तिम परीक्षा पर अनुचित जोर देने के कारण जो बुराई उत्पन्न हुई है वह इस कारण और भी उग्र हो उठी है कि चाहे सरकार में हा भ्रष्टाचार निजी कार्यालयों या व्यवसाय संस्थाओं में केवल बहुत निचले स्तर के छात्रों को नौकरी पान के लिए विश्वविद्यालय की उपाधि होने की बात आवश्यक समझी जाती है। जिन छात्रों ने सारे ज्ञान कुछ भी काम नहीं किया होता व अपना सारा विश्वास अन्तिम परीक्षा पर केंद्रित किए रहते हैं और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अनन्य अवाधनीय उपायों का अवलम्बन करते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की उपाधि के लिए इतना भाग्य होने के कारण यदि हज़ारों नहीं तो सैकड़ों एम. ए. छात्र विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट होते हैं जिनमें न तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता ही होती है न रुचि ही। अनन्य बार तो इस प्रकार के छात्र विश्वविद्यालय की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले विषयों का समझ पान में बिल्कुल ही असमर्थ होते हैं। कक्षाओं में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थियों की उपस्थिति जो विषय का समझ पान में असमर्थ हों या उस विषय में रुचि ही न रखते हों या असमर्थ और रुचिहीन जाना ही है न केवल शिक्षा के प्रभाव को नीचे गिरा देती है और वास्तविक विद्यार्थियों की प्रगति में बाधा डालती है अपितु विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए नई समस्याएँ भी खड़ी कर देती है। जब तक विद्यार्थियों को किसी विषय में रुचि रहती है तब तक कक्षा में अनुशासन की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। जिन विद्यार्थियों को कक्षा में दिए जा रहे भाषणों में न तो रुचि होती है और न उन्हें समझ पाने की योग्यता ही होती है वे भाषणों में गप-गप करने लगते हैं या अन्य किसी तरह कक्षा में गड़बड़ी मचाते हैं। फिर यह अव्यवस्था केवल अध्यापन-कक्ष तक ही सीमित नहीं रहती। जब एक बार उनको अध्यापन-कक्ष में नियम भंग करने की अपेक्षा पड़

जाती है तो वे कक्षा के बाहर भी नियमा का उल्लंघन शुरू कर देते हैं।

(ई) वर्तमान शिक्षा प्रणाली का प्राधिकारात्मक ढंग भी विद्यार्थियों में अज्ञाति और अनुशासनहीनता का वृद्धि का एक बड़ा कारण है। यह हमारे समाज की इस प्राधिकारात्मक प्रवृत्ति का ही एक प्रतिबिम्ब है कि हमारे यहां अपने स बड़े किसी व्यक्ति से मतभेद हान का भय प्रायः यह समझा जाता है कि उस बड़े व्यक्ति का अनादर किया जा रहा है। वर्तमान पाठ्यक्रम में अथवा सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में भी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता या पहल करने का अवकाश बहुत कम रहता है और सामान्यतया वे ऊपर से मिलने वाले आदेशों को निष्पक्ष भाव से स्वीकार कर लेते हैं। विद्यालय एक प्रजातन्त्रात्मक समाज न होकर प्रायः बड़े कठोर रूप में विभिन्न स्तरों में बँटा हुआ समाज होता है जिसमें प्रत्येक स्तर पर अधिकारी लोग यह चाहते हैं कि उनके नीचे के लोग बिना प्रश्नोत्तर किए चुपचाप आज्ञा पालन करते बैठे जाएं। जब तक हम शिक्षा प्रणाली में अविवेक में नौकरी मिलने की गारंटी न भी सही कम से कम आज्ञा बधी रहती तब तक तो छात्रों और छात्रा के माता पिताओं की दृष्टि में इस प्राधिकारात्मक संरचना (संरचना) का कुछ न कुछ औचित्य समझा जाता रहा और सामान्यतया इस पर कोई एतराज नहीं किया गया। परन्तु आजकल शिक्षित लोगों में क्वारी बदन के साथ-साथ यह अनिवार्य है कि अतीत की इस प्रतिरोधहीन आज्ञाकारिता के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो। विद्यार्थियों तथा अन्य सबकों के मामलों में यह विद्रोह की भावना और भी अधिक उग्र इसलिए हो गई क्योंकि स्वाधीनता-संग्राम का कारण एक आज्ञा-भंग का वातावरण बन गया था। सविनय आज्ञा भंग आन्दोलन में लोगों ने यह आग्रह किया गया था कि वे अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करने से इनकार करें और उनका उल्लंघन करें। परन्तु अन्यायपूर्ण कानून और अन्यायपूर्ण कानून का बीच अन्तर की रेखा खींच पाना कठिन हो जाता है। इनके मामलों में ऐसा हुआ कि जब विद्यार्थियों को एक बार कुछ कानूनों को तोड़ने का आदेश पड़ गया तो उनका मन में सभी कानूनों के प्रति अवहेलना की भावना उत्पन्न हो गई। आजकल छात्रों में जो अनुशासनहीनता दीखती है वह बहुत कुछ उनके द्वारा राष्ट्रीय संग्राम में लिए गए भाग का ही अन्तर्-फल है।

## (घ) आदर्शवाद का सामान्य ह्रास

दर्दिरता का निरन्तर दबाव पड़ते रहने से मनुष्य की अनक उत्तम भावनाएँ मरुट हो जाती ह । इस समय पतमान आर्थिक गठिनाई के दोषजनक परिणाम इसलिये और भी उग्र हो गए ह । क्वाकि अनक कारणों से आदर्शवाद का सामान्यतया ह्रास हो गया है । पिछली दो या तीन दशावधियों में ससार के घटना-वक्र न मिठीपन साम और विद्रोहात्मकता की भावनाभा को बढ़ाया है । इसके कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित ह

(अ) गत दो विषययुद्धों ने सारे ससार में एक सामान्य नतिक पतन की प्रक्रिया गरु कर दी है । इन युद्धों में सबसे पहली हत्या सत्य की हुई । जनता क अधिकारों की का धम द्रप और शत्रुता हो बन गई । युद्धकाल में वह वग खूब धनी हो गया जिसन कि सब प्रकार की अनुचित पद्धतिया का सहारा लिया । ईमानदार व्यक्ति कण सह रहे थ और इनकी तुलना में मृनाफाक्षोर खूब समझ हो रहे थ । अतिये समाज के सामान्य नतिक स्तर में गिरावट आ गई । इस नतिकता क ह्रास का सब भार फैली हुई चोर-बाजारी रिश्वत और घनाचार का प्रभाव यकक लोगों पर भी पड़ना अनिवाय था ।

(आ) समाज के प्रमापी न सामान्य गिरावट क अतिरिक्त युद्ध क कारण विद्यार्थी वग के एक बड़ भाग के सम्मल बो गम्भीर लक्ष्य नहीं रहा । युद्ध काल में कुछ विाप प्रकार क व्यवसायों और उद्योगों में अत्यधिक बढ़ि हुई । सरकारी गतिविधियों का विस्तार भी बहुत बड़ पैमान पर हुआ । कम योग्यता वाल या विलकुल अयोग्य यवका को भी इन दालामा में काफी बड़ी सख्या में भासानी स काम मिल गया । अनक बार तो शोभ्य व्यक्तियों की अपेक्षा उचित अनुचित का विवेक न करन वाले साग ही अधिक फलते-फूलने थे । ऐसी दशा में धामवीर थ लोग की यह धारणा बन गई कि जीवन में सफलता पाने के लिये न ता चरित्र की ही आवश्यकता है न योग्यता की और न कठार परिश्रम करने की । एसा दशा में हममें क्या आश्चर्य है कि विद्यार्थियों का नतिक स्तर युद्धकाल और उसके बाद के वर्षों में बहुत गिर गया और विनता तथा अध्वपन के प्रमापा में आ काफी गिरावट आ गई ।



(६) भौतिकवादी विचारधारा के प्रसार के कारण भी जीवन के मूल्यों को समझन में काफी कमी आ गई है। क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार यदि लक्ष्य प्राप्त हो तो उसके लिए उचित अनूचित सब साधनों का प्रयोग क्षम्य समझा जाता है। सामाजिक न्याय के लिए साम्यवादी मार्ग का सभी लोग पर और विनाश रूप से युक्त लाया पर तुरन्त प्रभाव पड़ा क्योंकि इसमें उन्हें एक न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था की सम्भावना दी गई पड़ी। साम्यवाद में विद्यमान आदर्शवाद का यह तत्त्व अब तक स्वीकृत जीवन-मूल्यों के प्रति उदासीनता के कारण और भी अधिक भयावह हो उठा है। धार्मिक कठिनाइयों बकारी और मिथ्या आस्था के भग्न हो जान के कारण तरुण विद्यार्थी नैतिक आदर्शों के ह्रास प्रथम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छिन जान के भय से भी भयभीत नहीं होतें क्योंकि वे समझते हैं कि जीवन में 'युनतम सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कम से कम इतनी कीमत तो चुकानी ही होगी।

(७) हमने ऊपर हम बात का उल्लेख किया है कि वर्तमान पीढ़ी के विद्यार्थी एक धार्मिक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहते हैं। उनके सामाजिक बंधनों प्रथम सम्बन्ध की समाप्ति का प्रभाव और भी अधिक गहरा और दूरगामी हुआ है। पुरानी समस्याएँ और विवाद नष्ट हो गए हैं जिसका फल यह हुआ है कि आजकल के युवकों के पास उस दृष्ट आधार का अभाव है कि जिसके ऊपर वे अपने जीवन के भवन का निर्माण कर सकें। किसी समय समुक्त परिवार एक गंगा अधिकार-क्षेत्र था जिसके अन्दर व्यक्ति बड़ी सरलता से काम कर सकता था। उस समय न केवल समुक्त परिवार प्रथा छिन्न-भिन्न हो गई है अपितु सभी पारिवारिक बंधन बहुत अधिक निर्मित हो गए हैं। इस प्रकार बालक का सामाजिक जीवन बाली एक सवर्ग प्रथम व्यक्ति के समझ में पड़ गई है और उसका स्थान किसी अन्य व्यक्ति में नहीं दिया है। इस दृष्ट में बालक को अधिकाधिक अपने ही सहारे रहना पड़ता है और यह एक अनभव करना है कि न तो कोई उसकी देख रखा करता है और न रखा करता है। विद्याभ्यास में नियमानुसार आगम और अननुमानितता बहुत कुछ उनकी इस अनुभूति के कारण है कि वे निमा के भय में नहीं हैं।

(८) परिस्थिति के इस प्रकार और अधिक बिगड़ने का एक कारण हमारे राष्ट्रीय गणतन्त्र की सफलता के पक्षमूल्य उत्पन्न हुआ है। २५ या ३० वर्ष

पहले इस सधाम के नायकों की प्रार्थना होगी इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कष्ट उठाए थे। उस समय विद्यार्थी एक धार्मिकवाद के वातावरण में पसते थे जिसमें कायस और राष्ट्रीय नेता उन्हें कष्ट सहन करने और बलिदान करने के लिए प्रेरित करते थे। स्वाधीनता प्राप्ति के साथ सधाम का यह दौर समाप्त हो गया है और उस समय जो लोग सधाम के नेता थे वे अब सरकार के नेता हैं। ऐसा होना अनिवार्य है। परन्तु दुर्भाग्य से इसके कारण युवकों में एक भ्रमोपन की भावना उत्पन्न हो गई है और वह भी विनाश रूप से उन युवकों में जिन्हें हमारे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा उठाए गए कष्टों का व्यक्तिगत रूप से स्मरण नहीं है और वे केवल उन्हें अधिकार और प्रतिष्ठा के पद पर बैठे हुए देखते हैं।

(क) अध्यापकों की समाज में बहुत कम प्रतिष्ठा होना का परिणाम भी यह हुआ है कि विद्यार्थियों में आदर्शवाद का ह्रास हो गया है। वस्तुतः इसके कारण जीवन मूल्यों के प्रति उनकी भावना बिल्कुल बर्धन से ही कुम्हला जाती है। बालक अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि अध्यापकों का सम्मान किया जाना चाहिए और वास्तविक जीवन में अध्यापकों की सम्मानहीन स्थिति से उसकी तुलना करते हैं। इसके कारण उनके मन में एक ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण वे सिद्धांत और व्यवहार में स्पष्ट दीखते हुए विभेद को भी बिल्कुल स्वाभाविक समझने लगते हैं। इस प्रकार वे यह विश्वास कर बैठते हैं कि जो कुछ पुस्तकों में पढ़ाया जाता है उसका जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं होता। प्लेटो ने आत्मा में विद्यमान असत्य को व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बताया है। हमारे सम्मुख आज एक ऐसा समाज विद्यमान है जो अध्यापकों के प्रति सम्मान प्रकट नहीं करके अपनी सारी की सारी नई पीढ़ी की आत्मा में असत्य की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है।

(ग) उपर्युक्त कारणों से युवकों की मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि वे जीवन में एकमात्र सफलता को ही महत्ववान समझते हैं। सफलता की व्याख्या भी वे यह सूक्ष्म रूप में और मुख्य रूप से सांसारिक सुविधाओं को प्राप्त करने के अर्थ में करते हैं। जिस सफलता में किसी महान सत्य के लिए—जैसे सत्य का भजन अथवा विज्ञान का अनुसंधान—दीर्घ काल तक प्रयत्न और परिश्रम करने की आवश्यकता हो आजकल उसका आदर उम भीतिक

सफलता की अपेक्षा बहुत कम है जो धन की प्राप्ति के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है।

## २

अब क्याकि हमन भारत में विद्यार्थियों में विद्यमान अशांति और अनुशासनहीनता के कुछ प्रमुख कारणों को देख लिया है इसलिए हम उन कारणों को दूर करने के उपायों पर विचार प्रारम्भ कर सकते हैं। इन सब कारणों को एकत्र समान नहीं किया जा सकता। यह रोग बहुत सम्बन्ध में धीरे धीरे बढ़कर हम दवा तक पहुँचा है इसलिए हमकी चिकित्सा भी धीरे धीरे काफी गम्भीर अवधि में हो सकती है। हम सम्बन्ध में भी मतभेद हो सकता है कि चिकित्सा के उपायों में किन बातों को अधिक ध्यान दी जाए। परन्तु ये विचार हम अध्यापकों के नतुत्व के हास की समस्या को मुलभूत से हल करने का प्रारम्भ करना चाहिए। यह समस्या पूर्णरूप से शिक्षा की ही समस्या है जबकि दूसरे प्रमुख कारणों को हटाने के लिए अन्य स्तरों पर कार्यवाई करनी आवश्यक होगी। यदि किसी प्रकार अध्यापकों के नतुत्व को फिर स्थापित किया जा सके तो दूसरी बहुत-सी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। एक सम्मानित और सक्षम अध्यापक विद्यार्थियों में विद्यमान अनिश्चितता और सिद्धान्त की राक्षसों में काफी सहामता कर सकता है। यदि विद्यार्थियों में फिर भी नतिव बल आ जाए तो उसका प्रभाव अवश्य ही समाज के सभी स्तरों पर पड़ेगा।

(क) अध्यापकों के समाप्त हो चुके नतुत्व को फिर से स्थापित करने के उपाय

इसलिए हमारा पहला उपाय ऐसा होना चाहिए जिसका लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों के नतुत्व को फिर से स्थापित करना हो। यह ठीक है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में निरन्तर सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया जाए किन्तु इसकी व्यापक रूप में निंदा बंद होनी चाहिए। जैसा पहले कहा जा चुका है इन प्रकार की सामान्य निन्दा में हमने अतिरिक्त और कोई परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ कि अध्यापकों का नतिव बल समाप्त हो जाए और

विद्यार्थियों में एक निराशा की भावना छा जाए। शिक्षात्मक सुधारों के लिए उपाय प्रवर्धन करने चाहिए और इसमें कमी ठीक नहीं दी जानी चाहिए परन्तु इसके लिए वनमान शिक्षा प्रणाली की वृद्धि का प्रतिरजन नहीं किया जाना चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि नये और पुराने अध्यापकों में कोई बड़ा स्पष्ट भेदभाव उत्पन्न न हो जाए। नये अध्यापकों को अपने काम में विश्वास और उत्साह प्रवर्धन होना चाहिए किन्तु वह विश्वास और उत्साह इस रूप में प्रकट नहीं होना चाहिए कि वे अपने आपको पुराने अध्यापकों से इस ढंग में बड़ा समझें लगे कि उससे पुराने अध्यापकों की भावनाओं को ठस पहुँचे। और न उन्हें ऐसा सम्मन चाहिए कि पुराने अध्यापकों से शिक्षा-क्षेत्र के काम प्रत्यापन लोग हैं जिनका सुधार हो नहीं किया जा सकता।

इन माध्यमों में पहला उपाय तो यह होना चाहिए कि अध्यापन के क्षेत्र में जो लोग नये भरती किए जाएं उनकी योग्यता पहलू की अपेक्षा अधिक रखी जाए। अध्यापकों और छात्रों की संख्या में भी कोई अनुपात निश्चित किया जाना चाहिए। जब तक इन क्षेत्रों में और अधिक योग्य व्यक्ति न आए, तब तक कोई वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि सर्वोत्तम लोग भी सब तक पूरी सरसता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि अध्यापकों और छात्रों की संख्या में वर्तमान विषमता बनी रहती। अध्यापकों की संख्या में न केवल इसलिए वृद्धि होनी चाहिए कि इससे अध्यापकों की योग्यता में सुधार होगा अपितु इसलिए भी होनी चाहिए कि इसका सारे देश पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में केवल प्राथमिक स्तर पर ही लगभग २७ लाख अध्यापकों की आवश्यकता होगी। इस समय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का संख्या ६ लाख से कुछ ही अधिक है। इस प्रकार यदि शिक्षा का आवश्यक विस्तार किया जा सके तो कम से कम २० लाख अध्यापकों शिक्षा प्रणाली में लगाए जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा संस्थाओं में भी इना अनुपात में वृद्धि होगी। उस समय युवकों में पाई जाने वाली निराशा का एक मुख्य कारण शिक्षित लोगों की बकाली है। यदि सब स्तरों पर कुल मिलाकर केवल ४ लाख अध्यापक भी और नियुक्त किए जा सकें तो शिक्षित लोगों की बकाली पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसमें यवकों में आशा और

प्रगति की भावना भर उठनी और देश की मनो-शांति में भी शान्तिकारी परिवर्तन हो जाएगा।

आर्थिक उपायों का अवलम्बन तो करना आवश्यक ही है परन्तु केवल आर्थिक उपाय अध्यापकों की उत्कृष्टता का विकास और समाज में उनकी प्रतिष्ठा की दृढ़ि करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ साधन हमें हैं जो मारा और अध्यापकों के वेतन क्रम का सुधारन पर होते हैं किन्तु कुछ अन्य विचारका का विचार है कि यह समस्या अध्यापकों की घटने के की क्षमता में सुधार करने से ही हल होगी। कुछ अन्य सीमारे प्रकार के विचारका का कथन है कि अध्यापका के सम्मुख छात्रों की दृष्टि देना ही पर्याप्त होगा। परन्तु वस्तुतः इन तीन बातों का सम्मिश्रण से ही समीष्ट परिणाम उत्पन्न हो सकेगा है। विश्व विद्यालय के स्तर के लिए निम्नलिखित उपायों का मुझसे प्रस्तुत किया जाता है

(अ) अध्यापन के पेशे की ओर योग्य व्यक्तियों के आकर्षण हान के कारणों में से दो का विनाश उत्पन्न करना आवश्यक है। एक कारण तो विश्वविद्यालयों में भावना बड़ी दूषित हो गई है और उनमें समुचित अध्ययनात्मक वातावरण का अभाव है। दूसरी ओर पर्याप्त योग्यता वाले व्यक्तियों का सभी शिक्षण मस्त्राओं में जो बतन मिलता है वह बहुत बड़ा होता है और लगभग अन्य सभी पेशों में प्राप्त ज्ञान का वेतन की तुलना में बहुत कम होता है।

विश्वविद्यालयों में फिर से अध्ययन-अध्यापन का वातावरण उत्पन्न करने के लिए राजनीतिक पार्टियों और दलबन्धियों का समाप्त करके कुछ काम उठाए जान चाहिए। विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति किसी दल विनाश का ध्यान रखकर नहीं की जाना चाहिए अपितु केवल शिक्षा-अन्वेषी योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। उपकुलपति के चुनाव तथा विश्वविद्यालयों के गिर्दीनेतों और मोनटा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में राष्ट्राध्यक्षन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर एवं न के दाप काफी सीमा तक दूर हो सकेगा है। इन सिफारिशों का श्रियावित करने के लिए अपने विश्वविद्यालय अधिनियमों में संशोधन करने की तो आवश्यकता होगी किन्तु वित्तीय अडचन घायन ही कोई पड़े।

हमारे साथ ही वेतन-क्रम भी बढ़ाए जान चाहिए और विनाश रूप में

प्रारम्भिक दशाब्दा में। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हमारे साहित्य तथा विज्ञान और प्रविधि के क्षेत्रों में सर्वोत्तम नर-नारियों का एक काफी बड़ा भाग विन्वविद्यालयों में ही रखा जा सके। यदि विन्वविद्यालय उतना प्रारम्भिक बतन दे सकें जितना कि युवको को सरकारी नौकरी वाणिज्य और उद्योगों में मिलन का आग होती है ता अनक सर्वोत्तम नवयुवक अवश्य ही अध्यापन के पेश का ओर आकृष्ट हो सकेंगे। अब वे एक बार अध्यापन के पेश में आ जायें और उन्हें अपने विविध क्षेत्रों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी ता सरकारी नौकरी वाणिज्य और उद्योगों के क्षेत्र में सफल व्यक्तियों के होन बाल अपनाकृत अधिक लाभ का आकर्षण भी उनको बहुत नहीं रहेगा। उस दशा में कबन चाह-न ही आग अध्यापन के पेश का बाव में से छाहकर आग और य लाग के हाग जिनमें अध्यापन के पेश के प्रति अनुराग नही होगा। विन्वविद्यालयों में काय और नौकरी की छतें अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इतनी अधिक मुख ह कि यदि जीवन की बड़ी-बड़ी आवश्यकताएँ पूरी होती रहें तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में अधिक बतन का आकर्षण भी बहुत लोगों को लभा नहीं सकता। इन्हें कि विन्वविद्यालयों में प्राप्त अनुभव के आधार पर इस प्रकार की आशा उचित ही प्रतीत होती है। (इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में भी अनक याम्य-तम विद्यार्थियों का अध्यापन के पेश की ओर आकर्षित किया जा सकता है और उ- वहीं रखा जा सकता है यदि उनका प्रारम्भिक बतन प्रशासन सवाभा का अपना अधिक या कम से कम उनक बराबर हो )

(आ) बनने के मुबार के लिए इन सामान्य उपायों के अतिरिक्त विद्यार्थी अनुशासन योग्यता बाल नर-नारियों के लिए कुछ विद्यार्थी उपाय भी बनने जान चाहिए। एक मुख यह है कि (अ) में राष्ट्रीय प्राध्यापक-वृत्तियों (नगनल प्राध्यापक) का प्रणाला प्रारम्भ की जाए। इस प्रणाला के अंतर्गत प्राध्यापक का न केवल बतन अधिक होगा अपितु इस प्रकार के पेश का प्राप्त करना अपने आप में एक उच्च सफलता का चिह्न समझा जाएगा। किसी भी विन्वविद्यालय को इस प्रकार का नियुक्तियों का कोई नियत कोटा प्राप्त नहीं होगा क्योंकि तब तक कोई भी युवक या स्त्री राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त नहीं हो सकेगी जब तक कि उन किसी भी क्षेत्र में एक अधिकारी व्यक्ति स्वीकार न कर लिया जाए। राष्ट्रीय चुनाव-समिति को सिफारिश पर किसी भी विषय में राष्ट्रीय

प्रोफसर की नियुक्ति की जा सकती है। एक बार नियुक्ति हो जान के बाद राष्ट्रीय प्रोफेसर की नियुक्ति उसके सारे जीवन-काल के लिए होगी और वह भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य कर सकता है। यह सम्भव है कि शायद बहुत थोड़े ही विश्वविद्यालय ऐसे हों जिनमें एक-सं अधिक व्यक्ति राष्ट्रीय प्रोफसर नियुक्त होने के योग्य समझ जाए। कुछ विश्वविद्यालयों में ऐसा शायद एक भी व्यक्ति न हो फिर भी इस प्रकार के एक विद्यमान रहने के कारण विश्वविद्यालय के अध्यापकों को और अधिक प्रयत्न करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और उन्हें यह आश्वासन रहेगा कि यदि उन्होंने समाधारण सफलता प्राप्त कर ली तो समाज उनका आदर करेगा। इस प्रकार के प्रोफसर-वर्ग की स्थापना का तात्कालिक परिणाम यह होगा कि योग्य व्यक्ति विश्वविद्यालयों को छोड़कर दूसरी नौकरियों में जाना बन्द कर देंगे।

(६) एक और आवश्यक उपाय यह किया जाना चाहिए कि (जिन अध्यापकों में कॉलेज के क्षेत्र में संगठित जीवन का निर्माण करने की विद्या क्षमता विद्यमान है उन्हें कुछ विशेष मान दिया जाए)। आजकल की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रत्येक विश्वविद्यालय में ऐसे कुछ न कुछ अध्यापक विद्यमान हैं जो अपने छात्रों के लिए मित्र-शान्तिक और पथदर्शक बन गए हैं। इनके बाद तो इस प्रकार के अध्यापकों का न केवल उन छात्रों पर प्रभाव होता है जो उनके अपने विभागों में पढ़ रहे होते हैं अपितु विश्वविद्यालय के सारे ही छात्र-वर्ग पर उनका प्रभाव होता है। इस प्रकार के अध्यापकों को यदि समुचित मान्यता दी जाए तो वे अध्यापकों के मतत्व को फिर से स्थापित करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल के अधिकांश विद्यार्थियों में जो एक निरुद्देश्यता और निराशा की-सी भावना पाई जाती है उसे हटाने में भी वे सहायता कर सकते हैं।

(७) इसी प्रकार का एक और कदम उन लोगों को भी विशेष मान्यता देने के लिए उठाया जाना चाहिए जिनमें अध्यापन के लिए विद्या उत्साह है। हममें से प्रत्येक कुछ न कुछ ऐसे अध्यापकों का स्मरण कर सकता है जिनमें अपने विषय का समाधारण विद्वान या अनुसंधानकर्ता न होते हुए भी एक ऐसा विशेष गुण विद्यमान था जिसके द्वारा वे अपने छात्रों में अध्यापन के लिए नया उत्साह उत्पन्न कर देते थे। अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की

गति अध्यापन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व होती है। और वह मनुष्य किसी अध्यापक में उसकी विद्वत्ता के अनुपात में नहीं पाई जाती। यदि विश्व विद्यालय के दानों ही उद्देश्य हैं अर्थात् एक तो यह कि समाज के पान जो ज्ञान पहले से विद्यमान है उसे नई पाण का प्रमाण दिया जाए और दूसरा यह है कि इस प्रकार के ज्ञान का सीमाओं को और अधिक विस्तार किया जाए, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में विद्वत् जनसंघानवन्ता और विद्वत् अध्यापक गाना ही प्रकार के व्यक्ति शिक्षक बग में रहने चाहिए। मात्रकल कई बार यह प्रवृत्ति निम्नांकित पड़ती है कि जनसंघान के कार्य पर बहुत जोर दिया जाए चाहे उसके लिए अध्यापन के कार्य को बलिदान हो कर देना पड़े। यह ठीक है कि जनसंघान का निश्चित रूप से बड़ा महत्व है परन्तु अध्यापक का उसकी अध्यापन की योग्यता के लिए भी मान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की क्षमता की जाँच के लिए कोई यज्ञ सद्गुण उपाय मुझ पाना तो कठिन होगा परन्तु इस सम्बन्ध में विद्याधियों का नियम प्रायः काफी कुछ ठीक नियम होता है। वस्तुतः जनक बार विद्यार्थी अध्यापक की क्षमताओं के समन कही अधिक अच्छे नियामक होने हैं जितना कि अध्यापक विद्यार्थियों की क्षमताओं का नियामक होता है।

(४) काल्जा और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए बिना मविष्य अध्यापन की सुविधाओं का प्रबंध करके उनके उत्तमतर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ बिगिष्ट छात्रवृत्तियों की स्थापना में न केवल काफी सस्या में योग्य मनुष्य अध्यापन के पान का भार धारण होगा अपितु तरंग अध्यापकों का चुन हुए पश्चिमी विश्वविद्यालयों के कहीं अधिक विस्तारपूर्ण परिवर्ण (गनवामरनमेंट) में रहने का अवसर प्राप्त होने के परिणामस्वरूप हमारे विश्वविद्यालयों के अध्यापन और अध्यापन के वातावरण को सुधारन में भी सहायता मिलेगी। यह हमें स्वीकार करना होगा कि कुछ पाठ्य-सम्माननीय अध्यापकों का छात्रकल हमारे काल्जों और विश्वविद्यालयों के अधिकांश अध्यापकों से समान और मवा की भावना मदात्त हो चकी है। पश्चिम के जनक विश्वविद्यालयों में यह भावना अब भी प्रभूत मात्रा में पाई जाती है। इनमें से कुछ विश्वविद्यालयों में तो अध्यापन अध्यापन का वातावरण अनेकानेक बहुराष्ट्रों का अध्यापक है और उनके कार्यक्षेत्रों में ऐसे अनेक



व्यक्ति विद्यमान है जिनमें सखी सेवा की मायना भरी है। जीवन के प्रारम्भ में इस प्रकार के व्यक्तियों के सम्पर्क में आने से हमारे अध्यापकों की भगसी पीढ़ी पर अवश्य ही गहरा प्रभाव पड़ेगा।

यदि हम अपने प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए कम से कम एक-एक विदेशी प्रसिद्ध विदेशी विद्वान् की सेवाएँ तीन सप्तेकर पाँच वर्ष तक के लिए प्राप्त कर सकें तो इसका भी परिणाम हमारे विश्वविद्यालयों के वातावरण पर अच्छा पड़ेगा। अनेक बार किसी एक ही व्यक्ति की उपस्थिति काल्प के सम्पूर्ण वातावरण को बदलने में समर्थ होती है। यदि हम विदेशी प्रोफ़ेसर्स का चुनाव बुद्धिमत्तापूर्वक करें तो वे अध्यापन का प्रमाण ऊँचा करने तथा विश्वविद्यालयों में समुचित अध्ययन अध्यापन का वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होंगे। वस्तुतः सर्वोत्तम परिणाम उस देश में प्राप्त हो सकते हैं जहाँ विदेशी से प्राफ़ेसर्स का यहाँ पर बुलाना तथा यहाँ के तरुण अध्यापकों को अध्ययन के लिए बाहर भेजना दोनों ही एक समेकित कार्यक्रम के अंग हैं जिससे जब हमारे युवक अध्यापक विशेष से लौटकर आएँ तो वे उस काम का भाग जारी रख सकें जिसे यहाँ पर आने वाले विदेशी प्राफ़ेसर्स प्रारम्भ कर चुका होगा।

(क) सभी स्तरों पर अध्ययन अध्यापन के वातावरण में सुधार और अध्यापकों के वेतन में वृद्धि बहुत आवश्यक है परन्तु उनका ही आवश्यक यह भी है कि अध्यापकों की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाए। विदेशी तथा अन्य दूसरे कारणों से अध्यापकों के वेतन कम को उचित सीमा तक बढ़ाने में तो काफी समय लगगा परन्तु उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय बरतने में कोई बाधा नहीं है। सामान्यतया सरकारी नौकरी में तथा अन्य स्थानों में भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सम्बन्ध उसे प्राप्त होने वाले वेतन या उसकी आय के साथ जड़ा रहता है। परन्तु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। भारतीय प्रशासन सेवा के कनिष्ठ (जूनियर) सभ्य की प्रतिष्ठा भी प्रांतीय प्रशासन सेवा के सभ्य की अपेक्षा अधिक होती है मले ही प्रान्तीय प्रशासन सेवा वाले व्यक्ति का वेतन अधिक भी क्यों न हो। आजकल मंत्रियों की स्वामी सेवा के सदस्यों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है परन्तु इससे उनके सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई बाधा नहीं आती।

मंत्रियों की स्थिति इस कारण सुरक्षित रहती है क्योंकि उनके हाथ में

राजनीतिक गति रहता है। अध्यापक के सम्बन्ध में समाज में उनकी प्रतिष्ठा का बर्तान के लिए कुछ विनाश उपाय बरतने पड़ेंगे। हमें फिर उस प्राचीन परम्परा को ध्यान का प्रयत्न करना चाहिए जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा का सम्बन्ध व्यक्ति का आर्थिक स्थिति के साथ अनिवार्य रूप से नहीं जुड़ा होता था। प्राचीन भारत में विद्वान् लोगों का आदर व कितने भी गरीब क्या न हा बड़ा सम्मान किया जाता था और यह स्थिति तो बहुत हान में ही हुई है कि सामाजिक प्रतिष्ठा का सम्बन्ध वन-मुम्पन्नता के साथ इतने घनिष्ठ रूप से जुड़ गया है।

(ए) अध्यापकों की सामाजिक प्रतिष्ठा का बर्तान के लिए अनेक उपायों में न हम अपने देश में भी उस एक उपाय का प्रयोग कर सकत ह जो टर्कों में बहुत सुकन रहा है। टर्कों की सरकार जब भी कोई महत्वपूर्ण कानून बनाना चाहती है तो वह विधिविधालय के अध्यापकों की एक समिति इसलिए नियुक्त कर देती है कि वह समिति उस कानून का शास्त्रीय दृष्टि से और विगपज्ञा की दृष्टि से जाच-पड़ताल स। सरकार इस समिति की सलाह का मानन के लिए बाधित नहीं है परन्तु केवल इस उध्य के कारण कि कानून बनाने से पहले विधिविधानय के अध्यापकों की सलाह ली जाती है जनता की दृष्टि में अध्यापकों की प्रतिष्ठा बहुत बढ जाती है। यह पद्धति शिक्षण की दृष्टि से लाभदायक और राजनीतिक दृष्टि से स्वस्थ पद्धति है। अध्यापकों के सामने मुस्पष्ट समझाए एक दा जाता ह जिससे वे उनका अध्ययन कर सकें और वास्तविकता की गहराई तक समझ सकें। किसी भी समस्या का विद्वानों की एक एसी सस्था द्वारा जो राजनीतिक पक्षपात से काफी कुछ परे है विनिर्णय करवा देने से सरकार को भी लाभ रहता है और वह उन गलतियाँ को करन से बच जाती है, जिन्हें कि वह राजनीतिक दबाव और दलबन्धी के जोर में कर बैठती।

काल्पना और विधिविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनों सामाजिक प्रतिष्ठा तथा अपने देश की समता को बढ़ाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, वह सब का सब माध्यमिक और प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापकों पर और भी अधिक सबल रूप से लागू होता है। इन अध्यापकों के वेतन कई बार तो इतने कम होते ह कि उनके द्वारा वे अपना अनिवार्य आवश्यकताएँ तक

मुक्ति से ही पूरा कर पाते हैं। जो लोग अध्ययन-अध्यापन व जीवन की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं उनका लिए इन अध्यापकों की सामाजिक प्रतिष्ठा एक निरन्तर चिन्ता का विषय बनी हुई है। अनेक बार इन अध्यापकों की अपन पेशे की क्षमता इतनी कम होती है कि वह इस पेशे के लिए निर्धारित बिल्कुल न्यूनतम प्रमाणा तक का पूरा नहीं कर पाती। इस दशा को सुधारने के लिए कुछ अनिवार्य उपाय हैं।

(घ) प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन त्रम में सुधार की आवश्यकता सबसे अधिक है और इसी में सबसे बड़ी कठिनाई भी है क्योंकि इन अध्यापकों की संख्या बहुत अधिक है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सभी ग्रेडों के अध्यापकों की संख्या कुल मिलाकर तीस हज़ार से कुछ कम ही है और इनकी तुलना में प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या लगभग आठ लाख है। यदि इन अध्यापकों की आर्थिक स्थिति में बिल्कुल मामूली-सा भी सुधार करना हो तो उसके लिए भी बहुत विनाश धनराशि की आवश्यकता होगी। परन्तु यदि हम देश के भविष्य को सुधारने के लिए कुछ भी चिन्तित ह तो इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है कि यह आवश्यक धन राशि किसी न किसी प्रकार जुटाई जाए।

(घा) कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की अपेक्षा भी बड़ी अधिक आवश्यकता प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रतिष्ठा जनता की दृष्टि में बढ़ाने की है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह सम्भव नहीं दीखता कि निश्चित भविष्य में उनके वेतन त्रम में कोई ऐसा सुधार किया जा सके जिससे वे समाज के सम्पन्न लोगों में गिन जा सकें। इस समय तो उनकी माँग केवल यह है कि उनकी आय कम से कम इतनी हो जानी चाहिए कि जिससे उनकी आधारभूत मानवीय आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँ और उनके सिरपर धरका सर्चा पूरा करने की चिन्ता हर समय सवार न रहे। ऐसी दशा में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपायों का अवलम्बन करना अनिवार्य हो जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने एक क़ानून उठाया है जिसके द्वारा राज्य की ओर से मिलकुल मगण्य-संख्या पर अध्यापकों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जा सकती है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की ओर से प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का अभिनन्दन किया गया। इस

पर वही मामूला घनराशि व्यय हुई परन्तु कबन इस तथ्य के कारण कि राष्ट्रपति की आर स उन पुरुषों और स्त्रियों के नाम नियन्त्रण-पत्र गए जिन्हें कि अब तक गाँवा के लोग बिलकुल मामूली आत्मी समझते रहे थे । नेताओं में काशी कुछ हलचल-भी मची । माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए इसी प्रकार के अभिनन्दना तथा भय विद्यप समारोहों का आयोजन प्रत्येक राज्य कर सकता है जिनमें कि उन राज्यों का अध्यापक-संघाल और मुख्य मंत्री भी उपस्थित रहें । यदि सब राज्यों के मुख्य मंत्री यह नियम बना लें कि वे जिन भी किसी केंद्र में जायें वहाँ के कुछ माध्यमिक और प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापकों से अवगत मिलेंगे तो इससे सामान्य जनता की दृष्टि में और विद्यप रूप से दृष्टां सत्रा में अध्यापकों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी ।

(६) इस सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि प्रधानाध्यापक के पद और प्रतिष्ठा में बढि कर दी जाए । एक अच्छा प्रधानाध्यापक विद्यालय में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है । इंग्लैंड की पब्लिक स्कूल प्रणाली की महान् सफलता का एक रहस्य यह भी है कि इन स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की हैसियत बहुत ऊँचा होता है और उनकी योग्यता भी बहुत होती है । तीस या चालीस वर्ष पहले भारत में एक कई प्रसिद्ध प्रधानाध्यापक थे जिनका ख्याति सारे प्रांत में और कुछ मामलों में तो सारे भारत में फैली होती था । आज कल ऐसे प्रधानाध्यापक भी मिलने कठिन हैं जिनकी ख्याति एक पूरे राज्य के अन्दर भी फैली हुई हो । इसलिए हमारा एक अविलम्ब काम यह होना चाहिए कि प्रधानाध्यापक का पद और प्रतिष्ठा और बढ़ा दी जाए । उस न केवल इतना क्षेत्र दिया जाए कि निम्नलिखित ढंग के लोग इस काम के लिए मिल सकें बल्कि उस अध्यापक को नियुक्त करने और उनकी पगालति करने के सम्बन्ध में भी विस्तृत अधिकार दिए जाएँ । सत्र में प्रधानाध्यापक सारी सस्था का मेहनत दाना चाहिए और सस्था की प्रगति और उन्नति का सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी जाना चाहिए । अब विद्यालय के कल्याण और प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी पूरी तरह उसके कंधा पर डाल दी जाएगी तो यह प्रायः का जा सकती है कि वह उस पुरा करने का प्रयत्न करेगा ।

मन जापान में दखा कि वहाँ माध्यमिक और प्रारम्भिक विद्यालयों के प्रभा

नाध्यापकों को सममग उत्तना ही वेतन दिया जाता है जिसना कि कायकारी (एग्जीक्यूटिव) अधिकारियों को। टर्की में मैने देखा कि प्रारम्भिक विद्यालय के अध्यापक का वेतन लगभग २५० रुपये प्रति मास से प्रारम्भ होकर ५०० रुपये प्रति मास तक जाता है और इसकी तुलना में सरकार के सचिव का वेतन लगभग ११०० रुपये प्रति मास से लेकर १५०० रुपये प्रति मास तक जाता है। दूसरे शब्दों में वहाँ प्रारम्भिक विद्यालय के अध्यापक के अधिकतम वेतन और राज्य के उच्चतम प्रशासक के वेतन में अनुपात केवल लगभग १ और ३ का है। भारत में यह अनुपात किन्हीं किन्हीं मामला में तो १ और ८० तक का भी है।

(ई) माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर अध्यापन की उत्कृष्टता की सबसे बड़ी शत्रु है काय की एकरसता और नीरसता। साल के बाल सान उही पाठा को दुहराते-दुहराते उस विषय में अध्यापकों की रुचि नहीं रहती। इसलिए इस एकरसता को समाप्त करने के लिए कुछ न कुछ उपाय किए जाने चाहिए। अध्यापकों की उत्कृष्टता को बढ़ाने की दृष्टि से सेवा-काल में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के महत्त्व के सम्बन्ध में जितना कहा जाए वह कम ही है। हाल के वर्षों में इंग्लैंड में हुए परीक्षाओं से यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस प्रकार के सेवा-काल में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के कारण अयोग्य अध्यापकों में भी इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि अब वे पुराने रूप में पहचान जाने भी नहीं बैठते हैं। इसलिए हमें अध्यापकों के लिए नवचेतनाप्रद (रिफ्रेशर) पाठ्यक्रमों और सेवा-काल में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की व्यवस्था को और बढ़ाना चाहिए। इस व्यवस्था को करने का एक उपाय यह है कि सब स्तरों के अध्यापकों के लिए संमिनारों और अध्ययन-निधियों का संगठन किया जाए। १९५२ में भारत सरकार के तत्वावधान में अखिल भारतीय प्रधानाध्यापकों का जो संमिनार हुआ था उसमें पचीस राज्यो के पचास प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया था। इसके ऊपर २० हजार रुपये भी व्यय नहीं हुए थे किन्तु इससे सारे देश में प्रधानाध्यापकों के नैतिक बल को बढ़ाने में काफी सफलता मिली। इसके परिणाम-स्वरूप भारत में प्रधानाध्यापकों का पहला व्यावसायिक संगठन भी स्थापित हुआ। यह प्रस्ताव रखा गया है कि प्रधानाध्यापकों के लिए इस प्रकार के कैम्प सह-संमिनारों की प्रणाली को जारी रखा जाए। १९५४-५५ में भारत के

विभिन्न भागा में इस प्रकार के १० समिनार किए गए और इस प्रयाजन के लिए धनराशि पाठ पाठ-द्वारा से प्राप्त हुई ।

यदि इसी प्रकार के प्रधानाध्यापकों का सम्म-मह-समिनार राय की धार से किया जाए, तो उस पर और भी कम व्यय होगा । इसलिए किसी भी राय के लिए प्रति वष एम हा समिनारा का आयोजन करना कठिन नहीं होना चाहिए । इसका अर्थ यह होगा कि इस योजना में राय में प्रति वष लगभग १०० अध्यापक लाभ उठा सकेंगे । इसमें कुछ हा वषों का अवधि में छार दश में माध्यमिक शिक्षा का सम्पूर्णनया सबल बनान में सहायता मिलेगी । इस प्रकार के समिनारा और अध्ययन-सिविरा का आयोजन प्रारम्भिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों के लिए भी किया जाना चाहिए ।

(उ) नवचतनाप्र (रिन्गार) पाल्यक्रम और सुवा-काल से लिया जान वाला प्रशिक्षण अध्यापक का जीवन का एकरसता का शान का दृष्टि से बहुत स्वागत-योग्य वस्तु है । इस प्रकार के प्रशिक्षण के अतिरिक्त हमें इन अध्यापकों को अवकाश गिविरा और स्वास्थ्य-मुधार-महा के द्वारा आत्मिक और धारारिक शक्ति-संग्रह करने का अवसर भी देना चाहिए । माध्यमिक और प्रारम्भिक विद्यालयों के वन्त पाठ प्रधानाध्यापक और उमम भी कम अध्यापक अधिक कठिनाइयों के कारण इस योग्य हात ह कि अवकाश के निम्न में वही जाकर आनन्द मना सकें । फिर भी उन्हें इस प्रकार की सुविधाया का आवश्यकता अन्य अधिकांश पर बाल लागे का अपना अधिक है । साल के बा माल अध्यापन काम में काम करते रहने के कारण अध्यापकों का ऊर्जा और जीवन-शक्ति मूख जाती है । यदि उन्हें कम प्रकार की छुट्टियां न दी जाएं जिनमें कि वे नई शक्ति-मन्त्र कर सकें तो उनका काम उन्माहहीन जीवनहीन और मन सदा हाता जाता है । इसका परिणाम यह हा सकता है कि नई पाढ़ी को एसी धनि पहुच जाए जो स्वाया बन जाए । और इस सति से हर हातन में बचना ही चाहिए । यदि बहुत पाठ पमान पर भी अवकाश गिविरा और स्वास्थ्य-मुधार-महा की व्यवस्था की जाए तो उमका भी अध्यापकों के नविक बन पर वन्त अधिक प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार के उपाया से उन्हें न केवल यह अनुभव होगा कि समाज का उनके सम्बाध का ध्यान है यन्तु मुरन्त ही उनके काय का दलृष्टता भी बहुत बढ़ जाएगी ।

(ऊ) विद्यालयों की प्रबन्ध-समितियों की रचना इस तरह होनी चाहिए कि यदि उनमें से दलबन्धियाँ और गुटबन्धियाँ बिलकुल समाप्त न भी की जा सकें तो भी वे न्यूनतम भव्य हों जाएँ। जहाँ चुनावों और पद्धतियों के कारण विश्वविद्यालयों में अनुशासन को धक्का पहुँचा है वहाँ पर इस प्रकार के संघर्षों का प्रभाव विद्यालयों पर और भी अधिक हानिकारक हुआ है। इस प्रकार के अनक उत्साहरण विद्यमान हैं जहाँ कि प्रबन्ध-समिति का सचिव (सेक्रेटरी) प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के लिए एक छोटा-मोटा अत्याचारी शासक-सा बन जाता है। यदि प्रबन्ध-समितियों के संविधान में से चुनाव का बिलकुल ही समाप्त न किया जा सके तो भी कोई ऐसी पद्धति अपनाई जाए जसी न्यूयार्क राज्य में बोर्ड आफ़ रीजेंट्स के चुनाव में अपनाई गई है। यह बोर्ड न्यूयार्क राज्य में शिक्षण-क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति है और इसका चुनाव राज्य की विधान सभा करती है। फिर भी यह दलगत राजनीति का पूरी तरह स्वतन्त्र है। इसका कारण यह है कि इस बोर्ड के १३ सदस्यों में से प्रति वर्ष केवल एक सदस्य का चुनाव होता है और वह सदस्य १३ वर्ष के लिए चुना जाता है। क्योंकि राज्य के गवर्नर का कार्यक्रम केवल ४ वर्ष का होता है और विधान-सभा के सदस्यों का कार्य-काल केवल २ वर्षों का इसलिए किसी भी सदस्य के ऊपर किसी भी दल का प्रभाव एक या दो वर्षों बीतने के बाद बहुत थोड़ा ही रह जाता है। भारतीय विद्यालयों की प्रबन्ध-समितियों के लिए यदि इसी प्रकार की चुनाव-पद्धति अपनाई जाए तो उसके फलस्वरूप वे दलगत संघर्ष और पद्धत बहुत कम हो जाएंगे जिनके कारण आजकल के विद्यालय-समाज का जीवन बहुत दूषित हो गया है।

(ए) इस समय निजी अध्ययन करने की जो दूषित प्रथा विद्यमान है उसे भव्य रोक जाना चाहिए। परन्तु यह केवल सभी सफ़सलापूर्वक किया जा सकता है जबकि अध्यापक को जीवन निर्वाह-योग्य वेतन मिल रहा हो। इस समय भी इस प्रकार के नियम बने हुए हैं कि कोई भी अध्यापक बिना मुख्य अध्यापक को बताए और उसकी सहमति के बिना निजी अध्ययन नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में भी नियम बन गए हैं कि कोई अध्यापक एक समय में कितनी निजी अध्ययनों कर सकता है। किन्तु प्रायः इन नियमों का पालन कम होता है और उत्पन्न अधिक। अपने पक्ष के समर्थन में अध्यापक लोग प्रायः यह कहते

ह कि उनके लिए पढ़ान की भी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण वस्तु जीवित रहना है, और उनके वेतन इतने पर्याप्त नहीं है कि उनसे उनकी और उनके परिवार की 'युनतम आवश्यकताएँ' भी पूरी हो सकें। ज्यों-ज्यों वेतन क्रम में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा, त्यों-त्यों इस प्रकार के नियमा का पालन और अधिक सकती स किया जा सकेगा और अध्यापको द्वारा की जाने वाली निजी व्यूहाना को कठोरतापूर्वक नियमित किया जा सकेगा। किन्तु जब तक अध्यापका के वेतन क्रम में काफी सुधार न हो जाए, तब तक कम से कम इतना प्रबंध व्यवस्था किया जाना चाहिए कि व्यूहानो की व्यवस्था विद्यालय की भांति की जाए और व्यूहान पढ़ान का काम भी विद्यालय में ही हो। प्रधानाध्यापक को वह अधिकार दिया जाना चाहिए कि जो बालक पढ़ाई में धीरे से कुछ कमजोर या पिछड़ हुए ह, उनकी विशेष पढ़ाई का प्रबंध वह करे और यह काम उन प्रधानाध्यापक की देख रेख में चुन हुए अध्यापकों द्वारा विद्यालय में ही होता चाहिए। इस प्रकार के अध्ययन से जो फीस प्राप्त हो, वह सब अध्यापकों में बाँट दी जाए और स्वभावतः ही इस वितरण में उन अध्यापको को कुछ अधिक भाग मिलेगा जिन्होंने कि वस्तुतः इस पढ़ाई के काम में हिस्सा लिया होगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस काम के लिए अध्यापको को चुनने में प्रधानाध्यापक किसी प्रकार के पक्षपात से काम न ले। इस प्रकार निजी व्यूहानो की वर्तमान अनियमित प्रथा की रोक-थाम का का सकती है और इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न न जा सकती है जिनमें कि अध्यापक अपनी मारी ऊर्जा और ध्यान विद्यालय के काम पर ही केन्द्रित कर सकें। यदि कोई चाहे तो यहाँ तक कह सकता है कि वर्तमान स्थिति में बिना कोई अन्य परिवर्तन किए केवल इस उपाय से ही—यदि इसे प्रभावी रूप से विद्यार्थित किया जाए तो—भारतीय शिक्षा में क्रान्तिकारी सुधार हो सकता है।

(ख) विद्यार्थियों की आर्थिक कठिनाइयों को हल करने के उपाय

विद्यार्थी लोग जिन आर्थिक कठिनाइयों से ग्रस्त ह, उन्हें दतोरात नहीं हटाया जा सकता और न उनका हल सारे समाज ने पृथक् किसी एक ढंग से किया जा सकता है। जब तक समाज की आर्थिक दशा में सामान्य रूप से सुधार नहीं हो जाता तब तक शिक्षा-संस्थाओं में छात्रों की दशा भी असंतोष



जनक रहेगी। फिर भी गुपार करने और थुटिया को हटाने के लिए यथामुभव प्रत्येक प्रयत्न किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ प्रस्तावित उपायों को नियां न्वित करने के लिए सार्वजनिक निधियों में धनराशि की सहायता की आवश्यकता होगी। किन्तु ये धनराशियाँ आवश्यक नहीं कि बहुत बड़ी ही हों। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कुछ विशिष्ट उपाय सुझाव के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

(घ) उन योग्य छात्रों को जो आर्थिक दृष्टि में तंगी की दशा में हैं अधिकारपूर्वक सुविधाएँ देने के लिए बंदम उठाए जा सकते हैं और प्रत्येक उठाए जाने की चाहिए। यह समस्या विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के स्तर पर जाकर तो सबसे अधिक उभर हो ही उठती है परन्तु बहुत बार माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को भी अपने निर्वाह के लिए स्वयं उपाजन करना पड़ता है। इस समय विद्यालयों और कॉलेजों में पन्द्रह से तेरह बीस प्रतिशत तक छात्रों का छात्र वृत्तियाँ छात्र वेतन या अन्य रियायतें देने की व्यवस्था है। इंग्लैंड जहाँ सम्पन्न देशों में सार्वजनिक ऋण से इस प्रकार सहायता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या नहीं अधिक होती है। आक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय में १० प्रतिशत से अधिक छात्रों को किसी न किसी रूप में सार्वजनिक सहायता मिल रही होती है। यह ठीक है कि हमारे पास इतना साधन नहीं है कि छात्रों को इतने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सहायता दी जा सके परन्तु वर्तमान व्यवस्था में कुछ न कुछ वृद्धि कर पाना बहुत आवश्यक है और सम्भव भी है। अपने सीमित साधनों को देखते हुए हमें उन पद्धतियों पर भी विचार करना चाहिए जिनके द्वारा विद्यार्थियों को अपना निर्वाह करने में कुछ सहायता मिल सकती है। इनमें से एक उपाय यह है कि विद्यालय और महाविद्यालय में आवश्यक सेवा कार्य करने के लिए विद्यार्थियों के परिश्रम का धन तक जितना उपयोग किया जाता है उसकी अपेक्षा नहीं अधिक उपयोग किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण इस सम्बन्ध में बड़ा सानदार है। वहाँ धनक विद्यार्थी विद्यालयों और कॉलेजों में घटी बजाने, खपरासगीरी करने, जीवनीकरी करने, खसवार बचन पुस्तकालयों में सहायक का काम करके अथवा अन्य कार्य करके अपना अध्ययन पूरा करते हैं। गरीब विद्यार्थियों को सहायता देने का एक और उपाय यह है कि कॉलेजों और विद्यालयों में छात्रों के एक अनुष्ठान में वर्णित

मुविद्याया का बृद्धि करने के लिए इन गरीब छात्रों का उपयोग किया जाए।

(घा) जहाँ शिक्षण-अस्थाएँ विद्यार्थियों के वित्तीय बाध को कम करने में सहायता कर सकती हैं और उनको करना भी चाहिए वहाँ उन्हें इस बात के निष्पत्ति के लिए भी कोई काम उठाना चाहिए कि विद्यार्थी लोग इस प्रकार प्रस्तुत का गर्व मुविद्याओं से प्राप्त उठा सकें। छात्रों के इनके विद्यार्थियों में जो निरक्षरता पाई जाती है उसे शिक्षा का उत्कृष्टतर आयोजन करके हटाया जाना चाहिए। प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म ज्ञात अधिकार सम्मान आ सकता है। वरन्तु हमारा जैसी वर्तमान परिस्थिति है उसमें प्रारम्भिक शिक्षा में भाग की शिक्षा अपने उपायों में ही प्राप्त करनी होगी। प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति पर इस बात की काफी आवश्यकता है और माध्यमिक शिक्षा-काल का समाप्ति पर और भी अधिक कठोरतापूर्वक पड़ताल होनी चाहिए कि जो लोग भाग की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे उसके योग्य हैं या नहीं। सामान्यतया बालों और विविध विद्यालयों में केवल उन्हीं विद्यार्थियों का प्रवेश मिलना चाहिए जिनमें उत्कृष्टतर शिक्षा प्राप्त करने की विषय अभियोक्तता और रुचि है। इस प्रकार का चुनाव मुख्य रूप से अध्यापकों द्वारा ही होना चाहिए और मुख्य रूप से छात्रों और उनके सरक्षकों को सलाह के रूप में बताया जाना चाहिए।

छात्रों जब कभी भी हम छात्रों के लिए सलाह देते हैं या उनके व्यावसायिक पथप्रदर्शन की चर्चा करते हैं तबही मनोवैज्ञानिक और मनोविशेषज्ञों का सलाह लेने का बात करने का रिवाज-सा हो गया है। इसमें बड़ा सन्देह है कि इस प्रकार की विलास की बातें उन दशा के लिए भी वांछनीय हैं या नहीं जो इतने सम्पन्न नहीं हैं कि इस प्रकार का सलाह से पान में समर्थ हैं। यह भाग्य करना क्या-सी है कि कोई भी विशेषण किसी बालक से एक या दो बार आये छात्र घटे के लिए मिलकर उनकी अभियोक्तताओं और रुचियों का ठीक-ठीक जाँच सकता है। दूसरी बात यह प्रत्यक्ष कि सब बालकों के लिए इस प्रकार का पथप्रदर्शन प्रत्येक बालक की सम्यक् अवधि तक उचित रूप में रखने के लिए किया जाए वह सब बड़े धनी लोगों के बस का भी न होगा। और कम से कम भारत के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम सोचने या शुरू करने का सा प्रश्न ही नहीं उठता।

परन्तु हमका भय यह नहीं है कि हमारे बालका को सलाह या पथप्रदान किया ही नहीं जा सकता । जिन अध्यापको को सारे साल और मनक भार तो लगातार कई साल तक बालक को देखते रहने का भवसर मिलता है वे उसकी अभियोग्यताया और रुचिया के सम्बन्ध में काफी कुछ सही भावना न कर सकते ह । भावभावता इस बात की है कि अध्यापक विद्यार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करें । यह बिलकुल स्पष्ट है कि इस प्रकार की याजना केवल तभी सफल हो सकती है जबकि अध्यापका और बालका के माता-पिताभा में घनिष्ठ सहयोग हो । यदि अध्यापक अपने छात्रा में कुछ और अधिक दिलचस्पी लें और बालको के माता पिताभा से व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करें तो अध्यापक और माता-पिता मिलकर ही बालक का उसके भविष्य के लिए सर्वोत्तम सलाह दे सकते है । इसक लिए प्राक्टोरियस प्रणाली जसी प्रणाली को शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है । यह प्रणाली साबास शिक्षण संस्थाभा (रजिस्ट्रार इस्टीमेशन) में पायी जाती है । इसके अनुसार प्रत्येक अध्यापक को कुछ-कुछ छात्र सौंप दिए जात ह और उनकी जिम्मेदारी उसी पर रहती है । वर्तमान परिस्थितियों में इस बात का जालिम है कि इस प्रकार की प्रणाली अद्बुदय अध्यापका के हाथ में जाकर दूषित होकर छोटे मोटे अत्याचार या छुपिया पुलिस की भी निगरानी के रूप में परिवर्तित हो जाए । परन्तु इस प्रणाली के दुष्योग का खतरा उस समय नगण्य-ता हो जाएगा जब अध्यापक लोग माता पिताभा और सरसकों के घनिष्ठ सहयोग में काय कर रहे होंग ।

यदि अध्यापक लोग अपने निर्धारित कतव्य का मूक बुक और बुद्धिमत्ता के साथ पूरा करें तो इससे दुहरा लाभ होगा । एक ओर तो अध्यापको को उनका खोया हुआ नसुख फिर प्राप्त हा जाएगा और दूसरी ओर कालेजा और विश्वविद्यालयों में किशोरो में इस समय जो निरुद्ध्यता की भावना पाई जाती है वह यदि बिलकुल समाप्त न भी हो तो भी कम भवश्य हो जाएगी । उच्चतर शिक्षा में प्रवेश करने वाले छात्रा की योग्यता और संख्या पर नियन्त्रण रहने के कारण उन शिक्षित युवको की आगाधा और सामर्थ्य में उतनी बढ़ी खाई भी नहीं रहेगी जितनी कि भन है और जो आजकन के युवका में पाई जान वाली निराशा का बहुत बड़ा कारण है ।

(६) परन्तु विद्यार्थियों की आर्थिक कठिनाइयाँ एक दिन में हल नहीं हो

सकती। इसी प्रकार अध्यापकों और माता-पिताओं द्वारा सलाह और पथप्रदर्शन के फलस्वरूप भी सब विद्यार्थी तुरन्त शिक्षा या प्रशिक्षण के उन मार्गों पर नहीं झल जा सकेंगे जिनके लिए वे विशेष रूप से उपयुक्त हैं। इसलिए विद्यालयों और कालेजों में विद्यमान अनेक सुविधाओं को अधिक बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

यहाँ पर हम सबसे पहले अपना काम घाप करो कायक्रमों पर विचार कर सकते हैं। खेल के मैदानों प्रेसागृहों (स्टडियम) रंगमंचों (थियेटर) और उद्यानों का निर्माण या सुधार और बड़ी आयु के छात्रों के सम्बन्ध में विद्यालयों और छात्रावासों के भवनो का निर्माण जहाँ तक सम्भव हो अध्यापकों के नेतृत्व में छात्रों द्वारा ही कराया जाना चाहिए। यह चीज अशुभव नहीं है यह बात देश के विभिन्न भागों में प्रवेष्टा से बनाए गए संगठनों के अनुभव से सिद्ध हो चुकी है। इस सम्बन्ध में किसी एक समस्या का उल्लेख करना व्यापक न होगा क्योंकि अनेक सोसाइटियाँ और ट्रस्टों ने कालेजों प्रशिक्षण-संस्थाओं अनेक उच्च तथा प्राथमिक विद्यालयों और छात्रावासों के भवनो का निर्माण पूर्णतया उही छात्रों के परिश्रम द्वारा किया है जो उनका उपयोग करते हैं।

शिक्षण-संस्थाओं में आधारभूत भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिए अध्यापकों के नजर में छात्रों के श्रम का उपयोग करने से अनेक लाभ होंगे। इससे जो छात्र अपना निर्वाह स्वयं अपने उपार्जन द्वारा करना चाहते हैं उन्हें सहायता मिलेगी और अपने व्यय का कम से कम कुछ भाग स्वयं उपार्जन करने का अवसर मिल जाएगा। इस व्यवस्था से जिस भौतिक परिवेश (एनवायरनमेंट) में वे रहते हैं उसके सुधार में भी सहायता मिलेगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है यह स्वास्थ्यकर परिवेश भी उनमें कटुता की भावना जगाने वाला एक बड़ा कारण है। यह भी समझ लिया जाना चाहिए कि यदि विद्यालय को सामाजिक जीवन का केन्द्र बनाना है और उससे बालक और किशोरो के सर्वांगीण विकास में सहायता लेनी है तो उनमें श्रद्धा-सत्ता और उद्योगों समाभवनों और विधायकताओं तथा पुस्तकालयों और वाचनालयों का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कार्यक्रमों से अध्यापकों को अपने छात्रों के घनिष्ठ सम्पर्क में आने का अवसर मिलेगा और छात्रों को अपनी ऊर्जा के प्रयोग के लिए अनेक सज्जनात्मक मार्ग मिल जाएंगे।

इस प्रकार के अपनी सहायता प्राप्त करो वायव्यमात्र अतिरिक्त विद्यालय और कॉलेज एसी योजनाएँ प्रारम्भ कर सकें हूँ अथवा एसी योजनाएँ में सहायता दमकने हूँ जिनमें छात्रों को श्रम करने के बन्धन समा दिया जाता हो और उम्र धर्म से समाज का सम्पत्ति में वृद्धि होती हो। इस सम्बन्ध में जिन उम्र हरणों का मुरन्त ध्यान आता है वे हूँ स्थानीय संस्थाएँ अथवा गैरसरकारी संगठनों द्वारा रात्रि-विद्यार्थियों और स्वास्थ्य-केन्द्र जैसी सामाजिक सेवाएँ की व्यवस्था अथवा मातृजनिक उद्यानों, श्रीका-शाला और उपवनों जैसी सुविधाएँ का प्रवर्धन।

राज्य को इस सम्बन्ध में भी काम उठाना चाहिए कि विद्यालयों के बालकों को या तो बिलकुल मुफ्त या केवल नाममात्र मूल्य पर मध्याह्नाह्न (दोपहर का हल्का भोजन) दिया जाए। विद्यालयों में मिलन वाले मध्याह्नाह्न का परिणाम इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्यालयों में पतना अच्छा हुआ है कि इस एक अनेक उपाय से छात्रों का नतिक बल इतना उन्नत हो गया है कि उतना धन्य किसी भी एक उपाय से नहीं हुआ। मध्याह्नाह्न के लिए छात्रों से मामूली धनराशि ली जा सकती है परन्तु प्रसिप्त या प्रधानाध्यापक को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने विवेक के आधार पर कम से कम ऐसे विद्यार्थियों को मध्याह्नाह्न मुफ्त देने की अनुमति दे जो उसका लिए मूल्य दे नहीं सकते। जहाँ वही सम्भव हो इस प्रकार के मुफ्त मध्याह्नाह्न के बदले छात्रों से काम करा लिया जाए। बुनियादी शिक्षा प्रणाली में इस बात की प्राप्ति दीव्यती है कि बालक विद्यालय की विधियाँ के लिए कुछ धनराशि हूँ सकेंगे। इन प्रकार प्राप्त होने वाली धनराशियाँ का इससे अच्छा और कोई उपयोग नहीं हो सकता कि उन्हें बालकों के मध्याह्नाह्न पर ही व्यय कर दिया जाए। यदि उसका धन भी कुछ धनराशि बच रहे तो उसका उपयोग विद्यार्थियों को विद्यालय की सामग्रीपूर्ण धर्ती देने के लिए किया जा सकता है।

### (ग) यत्नमान शिक्षा प्रणाली के दोषों का सुधार

यत्नमान शिक्षा प्रणाली के यह पैमाने पर पुनर्गठन करने में अन्याय ही काफी समय लगगा। इसके अतिरिक्त इस प्रकार का पुनर्गठन एक अविच्छिन्न प्रक्रिया होगी क्योंकि शिक्षा जैसी सजीव वस्तु में कोई भी दशा अन्तिम नहीं

समझी जा सकती। फिर भी हमारे पहले दिए गए विश्लेषण की दृष्टि में रखते हुए कुछ स्पष्ट दीख पड़ने वाले दावों को तुरन्त हटाया जा सकता है और हटाया जाना भी चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का विचार रूप से उल्लेख किया जा सकता है

(घ) विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग और माध्यमिक शिक्षा-आयोग दोनों न ही किशोरो की विविध रुचियों और अभियोग्यताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन का सुझाव प्रस्तुत किया था। प्रारम्भिक शिक्षा सब बालकों के लिए एकरूप हो सकती है क्योंकि प्रारम्भिक शिक्षा-काल में शिक्षा का सत्य बालक का कुछ आवश्यक जानकारी दे देना और उसमें विचार और कार्य करने की कुछ निश्चित भावों डाल देना भर होता है। परन्तु किशोरावस्था के आगमन के साथ बालकों की रुचियाँ और अभि-योग्यताओं में अन्तर बहुत स्पष्ट दीख पड़ने लगता है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक विविधतापूर्ण होनी चाहिए। इन समय नई संस्थाओं के रूप में अथवा विद्यमान संस्थाओं को रूपांतरित करके बहुमुखी विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख है। यह भाषा की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा-काल में पाठ्यक्रम में अधिक विविधता होने के कारण किशोरो की अधिकाधिक संख्या विगुप्त शास्त्रीय अध्ययन को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चली जाएगी। इससे विश्वविद्यालयों पर दबाव कुछ कम हो जाएगा। इससे अनजान युवकों और युवतियों का विगारावस्था की समाप्ति पर लाभदायक व्यवसाय में काम मिल जाएगा और इससे उनमें पाए जाने वाले असंतोष और निराशा की भावना का एक बड़ा कारण दूर हो जाएगा।

पाठ्यक्रम की संरचना में इन परिवर्तनों के साथ-साथ बालकों की शारीरिक और नैतिक शिक्षा देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। कालेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए नम्रता बढट कर जसी संस्थाओं का सदस्य होना सनिक शिक्षा के दृष्टिकोण से उतना मूल्यवान् नहीं है जितना कि वह युवकों और युवतियों के शारीरिक विकास और उनमें नियमितता और अनुशासन की भावों उत्पन्न करने की दृष्टि से मूल्यवान् है। हमारा अन्तिम सत्य यह होना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी चाहें उन सबको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा सके। किन्तु इस सत्य को पूरा करना शायद वित्तीय

कठिनाइयों के कारण आसान न हो। फिर भी इस प्रकार का सुविधाएँ इतनी बढ़ाई जानी चाहिए कि इस प्रकार का प्रशिक्षण चाहने वाले सब विद्यार्थियों को कम से कम एक साल तक नेशनल कडेट बोर्ड का सदस्य रहने का अवसर मिल सके।

नेशनल कडेट बोर्ड पर होने वाले व्यय को दृष्टि में रखते हुए सब समय शरीर वाले विद्यार्थियों के लिए सना और शारीरिक शिक्षा का कोई और सरलतर रूप प्रारम्भ किया जा सकता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए नेशनल कडेट बोर्ड में प्रशिक्षण पाए हुए छात्र नता और शिक्षक का काम कर सकते हैं। इस प्रकार इस योजना पर होने वाला व्यय भी बहुत कम हो जाएगा और प्रशिक्षित कडेटों को नेतृत्व करने का अवसर मिल जाएगा। जो भी छात्र नेशनल कडेट बोर्ड में भरती होना चाहते हैं उन सबके लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस भी छात्र में कोई शारीरिक क्षेप न हो उस शारीरिक खेल की अनेक प्रकार की परीक्षाओं में नियत न्यूनतम क्षमता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। शारीरिक व्यायाम को छात्रों की शिक्षणारम्भ दिवसों का ही एक भाग बना देने से न केवल उनके अनुशासन को सुधारने में सहायता मिलेगी अपितु उनमें एक नया उत्साह भी भर जाएगा।

विद्यालय के बालकों के लिए बासकेट बालन्दोलन और माग-दर्शन प्रायः चरित्र के विकास और पहल करने की शक्ति (प्रारम्भण) के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करते हैं। ये गतिविधियाँ बालकों की ऊर्जाओं के उपयोग के लिए न केवल स्वस्थ और उपयोगी माग प्रदान करती हैं अपितु उन्हें कहीं अधिक आत्मविश्वासी और प्रत्युत्पन्नमति भी बना देती हैं। ये गतिविधियाँ उनमें समाज की सेवा की भावना विकसित करने में भी सहायक होती हैं। यह ठीक है कि इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य न किया जाए परन्तु इनके बारे में सुविधाएँ इतनी बढ़ाई जाएँ और उनकी सदस्यता इतनी आकर्षक बना दी जाए कि जिससे मुश्किल से ही कोई ऐसा बालक बन, जो उनमें भाग न ले रहा हो।

(भा) पाठ्यक्रमों के विविधीकरण और सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में वृद्धि करने के साथ-साथ वर्तमान परीक्षा प्रणाली का भी पुनर्गठन करना आवश्यक

है। इस समय अन्तिम परीक्षा पर अनुचित रूप से बहुत अधिक बल दिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वय व अधिकांश भाग में विद्यार्थी की ऊर्जाओं का कोई उपयोग नहीं हो रहा होता। यदि इन विद्यार्थियों का सार सान निरन्तर नाम करने के लिए बिना दिया जाए तो विद्यार्थियों में भावनात्मक या अशान्ति और अनुशासनहीनता विद्यमान है वह बहुत कुछ समाप्त हो जाएगा। निरन्तर काय में जुट रहने के कारण विद्यार्थियों की फालतू ऊर्जा का सदुपयोग हो जाएगा और उन्हें गंवारत करने के लिए अवसर ही न मिलेगा। इससे उनमें निरन्तर काय करने की आत्त का विकास हो सकेगा और इस प्रकार का आत्त का विकास भाविता का एक बड़ा मध्य है। इस प्रकार परीक्षा की प्रणाली का इस प्रकार का पुनर्गठन जिसमें विद्यार्थी का योग्यता का जोष उसके वय भर में किए हुए काय के अनिल्ल (रिवाज) और माध ही साथ अन्तिम परीक्षा में किए गए उसके काय द्वारा का जाएगी अधिकांश विद्यार्थियों के जीवन में एक नया अनुशासन उपस्थित कर सकेगा।

(इ) इस समय विद्यार्थियों और कान्वासों दोनों में ही अध्यापन-कक्षा में अध्यापन का जो पद्धतिपूर्ण विद्यमान है उनमें भा परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। आजकल सामान्यतया होता यह है कि अध्यापक भाषण दे रहा होता है या पाठ पढ़ा रहा होता है और विद्यार्थी बिल्कुल निष्क्रिय आता मात्र होते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों से मनेत्र रहने की अपेक्षा नहीं की जाती इसलिए उनका ध्यान इधर-उधर भटकन लगता है और ऐसा विषय रूप से सब होता है जबकि पढ़ाने वाला अध्यापक या पढ़ाया जा रहा विषय गुप्त और नीरस हो। निरवधानता और उन्मादीनता में एक कर्म का ही अन्तर है। जब एक बार पाठ के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो जाता है तो कक्षा के अनुशासन का आधार ढगमगा जाता है और कुछ ही समय बाद अनुशासनहीनता अनेक बाह्य रूपों में प्रकट होने लगती है। अब यह बात अलग-अलग समाजों के स्वाकार की जाती है कि प्रारम्भिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को एसी गतिविधियाँ में लगाया जाना चाहिए जिनमें वे निरन्तर व्यस्त बन रहे सकें और उन्हें अध्यापन-कक्षा के काय में रवि उत्पन्न हो। बड़ी भाग्य के विद्यार्थियों के लिए एन्टोरियन कक्षाओं समितारा और बाद-विद्यार्थी का आयोजन करके इसा प्रकार के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जहाँ विद्यार्थियों का कक्षा के काय में सक्रिय रूप से भाग



लेना पड़ता है वहाँ पर नाय के अनुशासन के कारण उनसे चरित्र का विकास होता है और उनके फलस्वरूप वे विद्यालय-समाज का अपेक्षाकृत अच्छे सदस्य बन पाते हैं ।

इस समय जो अध्यापन-पद्धति सामान्यतया प्रचलित है उसमें छात्रों को कम काम करना पड़ता है और अध्यापकों को अधिक । यदि भाषणों और उपदेशों का बोझ कुछ कम हो जाए तो अध्यापक छात्रों के काम का पर्यवेक्षण भी भली भाँति कर सकता है । ट्यूटोरियल और सैमिनार की पूरी तरह विकसित प्रणाली के लिए अध्यापकों की संख्या में काफी वृद्धि करने की आवश्यकता होगी और शायद इसीलिए इस प्रणाली को वित्तीय दृष्टि से निकट भविष्य में खालू कर पाना सम्भव न हो । परन्तु इस कठिनाई को यदि पूरी तरह हल करने में न भी सही तो भी कम करने में दो उपायों से सहायता मिल सकती है । एक उपाय तो यह है कि भाषण या प्रवचन के लिए जितने घंटे भ्रष्ट किए जाते हैं उन की संख्या कम कर दी जाए और उस समय का उपयोग विद्याभ्यास के समूहों के काम का पर्यवेक्षण करने में किया जाए । दूसरा उपाय यह है कि वरिष्ठ (सीनियर) या योग्यतर छात्रों का उपयोग अपेक्षाकृत छोटे छात्रों के काम के पर्यवेक्षण के लिए किया जाए । यदि इन दो उपायों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाए तो इससे कक्षा का आकार छोटा हो जाएगा और इस प्रकार अध्यापकों को अपने गिण्टो के साथ और अधिक घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने में सहायता मिलेगी । इस प्रणाली में क्योंकि छात्रों को अधिक प्रयत्न करना होगा और काम में पहले करनी होगी इसलिए उन्हें प्राप्त होने वाली शिक्षा भी भव्य की अपेक्षा, कहीं अधिक उत्कृष्ट कोटि की होगी साथ ही इससे अध्यापकों को छात्रों पर व्यक्तिगत प्रत्यक्ष छोटे-छोटे समूहों के रूप में अधिक ध्यान देने का अवसर मिलेगा । इस प्रकार अध्यापक द्वारा भाषण या प्रवचन पर से जोर हटाकर छात्रों के सत्रिय सहयोग पर जोर देने से वर्तमान शिक्षा-प्रणाली की एक बड़ी दुर्बलता को समाप्त करने में सहायता मिलेगी ।

(ई) आवश्यक यह जो आग्रह किया जाता है कि सबसे निचले स्तर को छोड़कर सारे नीकरिया के लिए विश्वविद्यालय की उपाधि अवश्य ही होनी चाहिए यह भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए । इंग्लैंड के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो गई है कि बिना विश्वविद्यालय की उपाधि का आग्रह किए भी

सांस्कृतिक सभाओं में पर्याप्त सख्या में योग्य व्यक्तियों की भरती भी जा सकती है। वस्तुतः नौकरी के साथ विविधविद्यालयों की उपाधि का सम्बन्ध समाप्त कर देने पर इंग्लैंड में विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक सभाओं दोनों पर ही बड़ा सामंजस्य प्रभाव हुआ है और हम आशा कर सकते हैं कि भारत में भी विविध विद्यालयों की उपाधि का नौकरी के साथ सम्बन्ध समाप्त कर देने में ऐसा ही परिणाम होगा।

विविधविद्यालयों की उपाधि की छान उड़ा देने से एक और बड़ा मंत्री सामान्य वातावरण का सुधार में सहायता मिलेगी और उसका अनुशासन भी समस्या पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देगा। इंग्लैंड में विभिन्न स्तर की सेवाओं के लिए भरती का आधार आयु होती है। इसका परिणाम यह होता है कि १९ वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते अधिकांश नवयुवक विभिन्न पेशों और व्यवसायों में लग चुकें होते हैं। जब वे मुनिचित रूप से अपने कार्यों पर लग जाते हैं उससे या तो उन्हें अपनी-अपनी विशिष्ट कार्य-शिष्टियों में और साथ-प्रशिक्षण प्राप्त होता है। वे बाद-से युवक भी आगे प्रशिक्षण जारी रखते हैं। इस दृष्टि में पड़ रहे होते हैं कि या तो वे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करें या उन व्यवसायों के लिए योग्यता प्राप्त करें जिनके लिए वैज्ञानिक या प्राविधिक ज्ञान की काफी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। भारत में भी इस प्रकार की प्रणाली प्रारम्भ हो जाने पर विविधविद्यालयों और कालेजों से वे बहुत-से छात्र बाहर चले जाएंगे जो वहाँ बिना किसी उद्देश्य के पढ़ रहे होते हैं और प्रायः उच्चतर शिक्षा पान के लिए प्रयोज्य होते हैं।

(उ) विद्यालयों के वातावरण का कुछ और अधिक प्रजातन्त्रीकरण होना चाहिए जिसमें छात्रों में स्वतंत्रता और सहूलियत करने की भावना कुछ और अधिक उत्पन्न हो। हाल के वर्षों में युवकों के काफी बड़ बग में आदेशों का उल्लंघन करने की भावना उत्पन्न हो गई है वह भ्रम उनका सत्ता के सामने चुनौती सिद्ध मुकाबले की पहले की मनोवृत्ति की प्रतिक्रिया है। यदि विद्यार्थियों को अपने सीमित क्षेत्र के अन्दर स्वाधीनता न दी जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है कि जब उनके निरीक्षण में जरा ढील हो तो उसी समय वे छात्र उच्छेदकता पर उतर आते हैं। जहाँ पर छात्रों को स्वतंत्रता या सांस्कृतिक या शिक्षण-सम्बन्धी गतिविधियों में आत्म-निर्भरता का अवसर मिलता रहता

है वहाँ पर सत्ता के विरुद्ध विरोह कभी भी इतना स्पष्ट और गम्भीर नहीं होता। जहाँ पर विद्यार्थियों की स्वतन्त्रता की अनवरत आवाजाही का बाह्य निवर्तन के लिए साधारण और स्वस्थ द्वार नहीं मिल पाते वहाँ पर विद्यार्थी ऐसी गतिविधियाँ की ओर झुकने लगते हैं जो समाजवादी या समाज-विरोधी होती हैं। अनुशासन का विकास उत्तरदायित्व की भावना से होता है और उत्तरदायित्व की भावना केवल उत्तरदायित्व की व्यवहार में मान से ही उत्पन्न हो सकती है।

विद्यार्थियों को कुछ और अधिक आत्मशान्ति का अवसर देने का उपाय है वहाँ उस एक प्रणाली का उल्लेख जिसमें स्वयं से कर देना उचित है जिसमें विद्यालय का कुछ सदना (हाउस) में बाँट दिया जाता है। फिर इनमें से प्रत्येक सदन का कुछ कक्षाओं में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक कक्षा में दो या पञ्चवीस विद्यार्थी होते हैं और उनका साथ-साथ एक अध्यापक को सौंप दिया जाता है। इस अध्यापक की सहायता के लिए एक या एक से अधिक मानीटर नियुक्त किए जाते हैं। मानीटरों के चुनाव में शिक्षा की योग्यता की अपेक्षा चरित्र की अधिक महत्व दिया जाता है। कक्षाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए इन मानीटरों को काफी अधिकार दिया जाता है। हमें इस प्रणाली को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यथोचित संशोधन करके अपना लेना चाहिए।

इतना ही नहीं विभिन्न कक्षाओं के मानीटरों को मिलाकर एक मानीटर परिषद् बनाई जानी चाहिए। इस परिषद् का काम सारे विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना हो। प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह इन मानीटरों को उनकी कक्षाओं के नेता के रूप में और मानीटर-परिषद् का सारे विद्यालय के सामूहिक नृत्य के रूप में मान्यता दे। बोर्ड-संसाधनों पर निर्भर के बाद यह प्रणाली कानेटा और विश्वविद्यालयों में और भी अधिक सफल हो सकती चाहिए।

मानीटर-परिषद् एक 'जुवेनाइल बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स' के रूप में भी काम कर सकती है। यह सामान्य अनुभव की बात है कि यदि बालकों को उनके गौरव या इज्जत का ध्यान दिया जाए तो वे अनुशासनहीनता तथा अन्य अव्यवस्थायी कामों से दूर ही दूर रहते हैं। गौरव की भावना को जगाने की

प्रशासक बिलकुल प्रारम्भिक कक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालय की कक्षाओं तक विद्यार्थियों का आना चाहिए।

विद्यार्थियों का ध्यान धर्मव्यक्ति के लिए विभिन्न रूपों में व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें निम्न एक और भी महत्वपूर्ण कारण विद्यमान है। जीवन में हमें धर्म के महत्वपूर्ण पाठ 'यत्न करो और मननी मुझसे' के नियम से सीखना पड़ता है। यह वही अधिक अच्छा है कि यत्न और मननी के य पराजय एक इस क्षण में हो जाए जहाँ मनता के पक्षस्वरूप समाज के लिए कोई बड़ा खतरा उत्पन्न न हो। यदि विद्यार्थियों को अपने मायता की सच्ची मर्यादाओं की अधिकाधिक व्यवहार किया जाए तो अनुशासन और उत्तरदायित्व की भावना को जो राजनीतिक संपर्क के वर्षों में बहुत दुर्लभ पद हो चुका है फिर से प्राप्त करने में विहारा प्रभाव पड़ेगा। वे लागू होंगे और कार्यरत रहेंगे और अपनी ऊर्जाओं का प्रयोग उपयोगी गतिविधियों के लिए करेंगे उन्हें नागरिकता और आत्मशासन की कला में प्रशिक्षण मिल जाएगा जिससे वे अपने देश के जीवन में उन गतिधर्मों से बच सकेंगे जिनमें धर्मशास्त्र की संरचना को ही क्षति पहुँचानी और सत्य महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इन स्वच्छता से स्वीकृत कार्यों का पूरा करके आत्मानुभूति का आनन्द प्राप्त कर सकेंगे।

(घ) छात्रों में जीवन-मूल्यों की भावना को फिर से प्राप्त करने के उपाय

हम पहले ही इस सत्य का उल्लेख कर चुके हैं कि विद्यार्थियों में विद्यमान भ्रान्ति और अनुशासनहीनता आधुनिक जगत् के समाज की एक सामान्य रोगाणु का ही भग है। यदि हमें यह सिखाया जाय कि युवकों के एक बड़े वर्ग में आदर्शवाद का समाज है तो यह स्वयं इस बात पर आश्रय है कि समाज की जीवन-मूल्यों की भावना समाप्त हो चुका है। विद्यार्थी समाज के एक धर्मव्यक्ति और सम्भवन सबसे अधिक अनुभूतिहीन वर्ग हैं। यह स्पष्ट है कि जब एक समाज का सामान्य स्वभाव गन्त और नीची है तब तब हम छात्रों में भी जीवन-मूल्यों की प्रथम भावना को आगे नहीं बढ़ा सकते। इससे पहले यह उचित और भी अधिक सुस्पष्ट हो उठता है कि निम्न एक सामाजिक दृष्टि है और इसी उन्नति या भवति भी समाज की सामान्य उन्नति या भवति पर निर्भर

है। यदि हमें विद्यार्थियों में आदर्शवाद की भावना फिर से जगानी है तो हमें एक ऐसा सामाजिक वातावरण तयार करना होगा जिसमें जीवन-मूल्यों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हो और विद्यार्थियों में उनको प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह समस्या मुख्यतः स्वयं समाज में ही जीवन-मूल्यों के प्रति आदर उत्पन्न करने की समस्या है।

इस बात को जितनी बार दुहराया जाए उतना ही कम है कि इस समय समाज में अध्यापकों की जो स्थिति है उसके परस्पर जीवन मूल्यों के प्रति हमारी भावनाएँ बचपन से ही कुम्हला जाती हैं। वस्तुतः नई पीढ़ी में जीवन मूल्यों के ह्रास का यह भी एक बड़ा कारण है। अध्यापक की वास्तविक दुर्दशा उस भवका जीता-आगता निषेध है जो सिद्धान्ततः अध्यापक का उचित प्राप्य माना जाता है। सिद्धान्त और व्यवहार की ऐसी एकलत विषमता छात्र के विचित्रता के आधार को ही खोलता कर देती है। इस प्रकार के सीमों और चिढ़े हुए अध्यापकों का आचरण छात्रों के विचित्रता के लिए और भी हानिकारक होता है। यह सिद्धान्त कि आचरण उपदेश की अपेक्षा उत्कृष्ट होता है बालकों के विषय में जितना सत्य है उतना शायद और कहीं नहीं। भगवान् स्नहहीन और दूरिद्र अध्यापकों का आचरण छात्रों के आचरण के प्रमाण को और इसीलिए समाज के आचरण के प्रमाण को नीचे गिरा देता है। अध्यापक की सामाजिक प्रतिष्ठा को उत्पन्न करने और उसके नतुत्व को फिर से स्थापित करने के लिए हमन जो उपाय सुझाए हैं यदि उन्हें क्रियान्वित किया जाए तो छात्रों में आदर्शवाद के ह्रास का एक प्रमुख कारण समाप्त हो जाएगा।

यदि एक बार अध्यापकों की सामाजिक प्रतिष्ठा फिर से स्थापित हो जाए तो यह धारणा की जा सकती है कि इस देश में जीवन-मूल्यों के प्रति आदर की भावना फिर उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे उपाय सोच जा सकते हैं जिनसे छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य की भावना जाग्रत हो। सभी देशों में विद्यार्थियों का निर्वाह दूसरे साधन के प्रयत्न से होता है और उन्हें पोषण समाज की सम्पत्ति से प्राप्त होता है। भारत जैसे देश में जहाँ प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ३०० रुपये भी नहीं एक विद्यालय के छात्र का व्यय समाज के ऊपर ५०० से ६०० रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं पड़ता और कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र का व्यय १००० रुपये वार्षिक के लगभग पड़ता है। क्योंकि छात्र अपने

अध्ययन-काल में आमात्रिक सम्पत्ति के उत्थान में मुक्तिक से ही कोई योग देते हैं। इसलिए इनका भय यह है कि विद्यालय में पढ़ने वाला एक बालक का भरण पोषण करने के लिए तीन व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति होने वाला भाग का भाग व्यक्तता पड़ती है। इसी प्रकार काठेड़ के विद्यार्थी के निवाह का व्यय चार या पाँच व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति होने वाला भाग के बराबर होता है। इस लक्ष्य के कारण सभी विद्यार्थियों के ऊपर एक विषय उत्तरदायित्व भा पड़ता है। अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद उन्हें समाज की उसमें कुछ धनिक हा सौजन्य का प्रयत्न करना चाहिए जितना कि उन्होंने समाज में प्राप्त किया है। यदि वे इनका न भा कर मुझे तो भा उन्हें कम से कम समाज का उतना तो लौना ही नता चाहिए, जितना समाज ने उनके ऊपर व्यय किया है।

छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य का भावना का उत्पन्न करने का उपाय यह है कि उन्हें समाज-सुधार का विभिन्न परियोजनाओं के साथ सम्बन्ध बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विद्यार्थियों के सामने के साथ उन्हें यह बात अनुभव करनी चाहिए कि गिना एक बड़ा विद्यार्थी है जो समाज ने उन्हें दिया है और भावा नागरिकता की तयारी के प्राथमिक कर्तव्य के रूप में आभाषित रूप से उन्हें अपने समाज से लिए हुए ऋण का कुछ भगता लौटा देने का यत्न करना ही चाहिए। छात्रों के सक्रिय सहयोग से इनके प्रकार का समाज-सुधारों का विकास किया जा सकता है। कुछ देशों में काल्पना और विद्यार्थियों ने पहल के बिना एक गाँव का भरण हाथ में ले लिया है और उसका उल्लिखित के लिए इनके रूपों में काम किया है। कुछ अन्य देशों में छात्रों तथा भय यवका ने राष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से भाग लिया है। भारत में राष्ट्रीय जीवन के पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों में काम करने के लिए, चाह के कार्यक्रम सामुदायिक परियोजनाओं के रूप में हा दा राष्ट्रीय विस्तार-सुधारों के रूप में या पिछड़े हुए क्षेत्रों में गिना और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुधारों का व्यवस्था करने के रूप में हा युवकों के लिए बड़ा उत्तम अवसर विद्यमान है।

हमने विचार-पद्धति के दुर्गतरिणों और सारे ससार में भौतिकतावादी विचार पारा का ऊपर उल्लेख किया है। जहाँ यह ठीक है कि उनके दुर्भावनाजनक भाव से इनकार नहीं किया जा सकता वही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए

कि युद्ध के अनुभव ने करोड़ा व्यक्तियों में किस प्रकार कृतव्य और वलिदान की भावना जगा दी है। प्रथम विश्वयुद्ध के पदचात युवक लोग न्याय समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शान्ति के सपने सेन लग थे। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद ससार के विनाशसंस्कार लोगो को स्वाधीनता प्राप्त हो गई है और सामाजिक न्याय का आन्ध्र सम्य समाज के तान-बान का ही एक भग बन गया है। चाहे जो हो हम यह अवश्य याद रखना चाहिए कि आन्ध्रवा विगोरा वस्था की सबसे बड़ी विपत्ति है। जीवन को इस अवस्था में भावनाओं का एक सहसा अभ्युत्थान होता है और युवक लोग किसी आन्ध्र क लिए वह से बड़ा जोखिम उठान को तयार हो जाते हैं। कठिनाइयाँ और संकटों को भलने का युवकों को विशेष धाव हाता है और यदि उनके सम्मुख सही आन्ध्र उपस्थित किए जाएँ तो बलिदान की कोई ऐसी भीमा नहीं है जहाँ तक वे न पहुँच सकें।

यहाँ युवकों में आदर्शवाद की भावना उत्पन्न करने में धर्म का क्या हाथ हो सकता है इस सम्बन्ध में भी दो बातें कह देना उचित होगा। धर्म उन अनेक मानसिक द्वन्द्वों को समाप्त कर देता है जिनके कारण व्यक्ति के विचार और क्रियाशक्ति पंगु बनी रहती है। धर्म ऐसी ऊर्जाओं को उन्मुक्त कर देता है जो कठिनाई या पराजय को स्वीकार करना जानती ही नहीं। धर्म के द्वारा व्यक्ति को अपने आपसे बड़ी शक्तियों के साथ एकाकार होने का न केवल अवसर मिलता है अपितु इसके लिए प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है। इस प्रकार धर्म व्यक्ति को लोभ और स्वाय के बन्धनों से ऊपर उठने में समर्थ बनाता है। जब धर्म कट्टर सिद्धान्तों और विधि-विधानों के फेर में पड़ जाता है तभी वह एक संकुचित करने वाला तत्त्व बन जाता है और लोगों में धारस्परिक संघर्ष का कारण बनता है। व्यक्ति को आत्मा के बंधन से मुक्ति दिलाने वाले विस्तृततर पहलू की दृष्टि से धर्म मनुष्य को उन्नत बनाने वाली महान्तम शक्तियों में से एक है।

क्योंकि विश्वराजस्था में मन किसी भी महान् उद्देश्य को अंगीकार करने के लिए सबसे अधिक तयार होना है और उस उद्देश्य के लिए सब कुछ बलिदान करने को उद्यत होता है इसलिए यह आवश्यक है कि इन विस्तृत धर्मों में छात्रों को धर्म के इस उदार बनाने वाले प्रभाव से अधिक न रखा जाए। कट्टर

सिद्धान्तों और विधि विधानों से रहित यह धम उन महान् माननीय प्राध्यापकों को प्रकट करेगा जिनके द्वारा सारे विश्व का नातिशास्त्र बना है। यदि विद्यापिया को मानव के इन महान् आश्यों के सम्पर्क में न लाया जाएगा तो उनके जीवन दरिद्र और अशुभ बन रहेंगे।

छात्रों को इन आश्यों के सम्पर्क में लाने का एक तरीका यह है कि विद्यालय और कालेज में प्रतिदिन एक प्रायश्चात-सभा हो जिसमें सब विद्यापियों का एकत्र होकर मानव जाति के सौम्य उत्तराधिकार की सम्पत्ति में से हिस्सा बँटाने का अवसर प्राप्त हो। कुछ मिनटों के लिए एक जगह एकत्र होना चाहे फिर यह विलुप्त मौन धीरे-धीरे निराला हो क्यों न हो विद्यापिया को इस बात का स्मरण करा देना है कि वे एक ही शिक्षा-जगत के समान रूप से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार प्रायश्चात-सभा का ध्यान भाग में एक बड़ा महत्त्व है क्योंकि इससे सब विद्यापियों का अनुशासन में रहकर एक साथ अनुभव में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से पूजा करने अर्थात् महान् प्रभुता की पदों से उन्हें इस बात का भी अवसर मिलता है कि वे कुछ उच्चतर जीवन मूल्यों के सम्पर्क में आ सकें और इस बात को अनुभव कर सकें कि सभी मानव प्राणियों और महत्वाकांक्षाएँ मूलतः एक ही हैं। यह सामान्य अनुभव की बात है कि जिन विद्यालयों और कालेजों में प्रायश्चात-सभा होती है, उनके छात्रों में मुनिचित रूप से अनुशासन और बचस्य की भावना कहीं अधिक होती है।

मानवीय आश्यों की मूलमूल एकता को अनुभव कर लेने के पत्रस्वरूप अपने इतिहास और राष्ट्रीय परम्पराओं के अध्ययन के नवीनकरण के कार्यक्रम का अभ्यास करना भी सरल हो जाएगा। प्राधुनिक समाज में अधिकांश समय और कष्ट केवल इस कारण है कि इतिहास गलत ढंग से पढ़ाया जाता है। बहुत हाल तक भी इतिहास को केवल युद्धों और विषयों का एक अभिलेख मात्र समझा जाता था उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए अनुशासन और राष्ट्रों का मूल्यांकन इस दृष्टि से नहीं किया गया कि उन्होंने मानव-कल्याण में क्या योग दिया अपितु इस दृष्टि से किया गया कि उन्होंने राष्ट्रों में कितनी सफलता प्राप्त की। यहाँ तक कि राष्ट्रीय परम्पराओं को भी अपने राष्ट्र के अत्यधिक गौरव और अभिमान को उभारने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया।



व्यक्ति और राष्ट्र सन्निव विजयों में अत्यधिक अभिमान अनुभव करत रहें हैं और वे यह भूल गए हैं कि युद्ध का परिणाम अनिवार्य रूप से यह होता है कि पहले तो भौतिक और बाद में नैतिक प्रमाण नीचे गिर जाते हैं।

यदि अतीत में युद्ध के कारण मानव प्रगति में बाधा पड़ी है और उनके कारण समाज की दशा घबनत्र हुई है तो प्राधुनिक युग में तो यह सतरा उत्पन्न हो गया है कि कहीं युद्ध के कारण मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त न हो जाए। इसलिए यह बड़ी आवश्यक बात है कि आजकल विद्यार्थी सत्तार को पहले की अपेक्षा अधिक सही रूप में देखें और इस बात को अनुभव करें कि मनुष्य का इतिहास अधिकाधिक प्रमाण स्वाधीनता और मर्यादा की ओर एक धिरेयुग से चली आ रही लम्बी यात्रा है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों देशों और युगों के नर नारियाँ न कभी सा जानते-बुझते और अनेक बार बिना यह अनुभव किए कि उनका लक्ष्य और प्रयत्न एक ही है परस्पर सहयोग किया है। अब तक मनुष्य ऊपर सतह पर दास पड़ने वाले सघर्ष और प्रतियोगिता के प्रति अधिक संवेदनशील रहे हैं और उस सहयोग के प्रति कम संवेदनशील जो सम्पूर्ण मानव प्रगति का आधार है। परन्तु अब उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह बात कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सघर्ष ही जीवन का नियम है केवल अर्ध सत्य है।

जहाँ कभी-कभी प्रतियोगिता ने प्रगति की ओर बढ़ने में सहायता दी है वहाँ सहयोग प्राणियों के जीवित रहने का आधार रहा है। मनुष्य के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से सत्य है। अपनी दुर्बल इन्द्रियाँ और स्वयं शारीरिक शक्ति के द्वारा भी वह क्षय सृष्टि पर केवल इसीलिए विजय प्राप्त कर सका, क्योंकि वह इतने बड़े पैमाने पर सहयोग कर सकता था जितना कि अन्य कोई पशु नहीं कर सकता था। यह सहयोग भाषा के कारण सम्भव हो सका। भाषा के कारण उसमें अत्यन्त सूक्ष्म सुनिश्चितता के साथ और अनुभव के इतने बड़े क्षेत्र में अपने विचारों का आदान प्रदान करने की शक्ति आ गई जो अनुपम है। क्योंकि भाषा एक ऐसा सामाजिक उत्तराधिकार है जो शिक्षा के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी भाषे चलता चला जाता है इसीलिए शिक्षा का समाज के प्रति महत्त्व है कि वे सहयोग के उस तत्त्व पर विशेष बल दें जो भाषा के माध्यम

से किए जान वाले सब सम्पन्न स्थापनों (कम्प्युनिक्शन) संचारणों में निहित है।

हमन ऊपर इस बात का उत्पन्न किया है कि युवका में आधुनिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अभिरक्षा का भावना व कारण किस प्रकार सिद्धिपन्न-सा प्राप्त गया है और छात्रों का ह्रास हो गया है। हमन ऊपर कुछ उपायों का भी संकेत किया है जो युवका के मन में इस अभिरक्षा की भावना को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अभ्यापका छात्रों और माता-पिताओं के बीच प्रतिष्ठित पारस्परिक सम्पर्क स्थापित हान स युवका में समुदाय की भावना विकसित होगी और इसका फलस्वरूप वे आत्मीयता का अनुभव कर सकेंगे। जब एक बार युवकों में यह अनुभूति उत्पन्न हो जाएगी तब वे निरहङ्गता की उस भावना से भी बहुत पीड़ित नहीं रहेंगे जिसके कारण वे आजकल विकृत व्यक्तित्व से रहते हैं। मर ही इस समय समुक्त परिवार प्रणाली समाप्त हो चुकी है फिर भी अभ्यापकों और माता-पिताओं के सहयोग से बालक को व जीवन-मूल्य काफी कुछ मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं जो पहले इस प्रणाली द्वारा प्राप्त होते थे। समाज में सहयोग व महत्त्व की बात बसल विभिन्न समूह व मध्य अभ्यक्त सम्बन्धों के वर्णन पर ही समाप्त नहीं हो जानी चाहिए अपितु उनके अन्तर्गत विभिन्न आयु और विभिन्न सम्बन्धों वाले व्यक्तियों के साथ हान वाले दैनिक सम्पर्कों का भी वर्णन हो जाना चाहिए। यदि आजकल के युवक यह अनुभव कर सकें कि उनके पूर्वजों की परम्परा अभी तक भी जीवित है और बढ़ रही है तो उनका किसी का आत्मीय न होने की भावना समाप्त हो जाएगी।

परम्पराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक आवश्यक बात यह है कि परिवर्तन की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया जाए। युवकों के सामाजिक जिज्ञासे भटक जान का एक बड़ा कारण यह है कि अलग अलग पीढ़ियाँ मानसिक दृष्टि से एक-दूसरे से दूर होती हैं। प्रत्येक पीढ़ी अपने विचारों के साथ चिपकी रहती है और उनमें किमा प्रकार की सृष्टि या परिवर्तन को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। क्योंकि तरुण पीढ़ी की पद्धति और परिवर्तन प्रसंग होता है इसीलिए हम पुराने छात्रों को समझ जान पड़ते हैं। हमलिये यदि पुरानी पाठ्य इस बात का अनुभव कर लें कि उनके छात्रों की प्रणाली से पहले नई पीढ़ी उनमें बाधा-बहुत हेर-फेर अवश्य करेगी तो पिताओं और पुत्रों के

साथ होन वाले विवाहों का एक बड़ा कारण समाप्त हो जाएगा। इससे साथ ही साथ आजकल की नई पीढ़ी में पाई जाने वाली अज्ञानता और जीवन-मृत्यु का हाथ भी बहुत कुछ समाप्त हो जाएगा।

ऊपर बताया गए उपायों से विद्यार्थियों में मनशासनहीनता और अज्ञानता की समस्या का हल करने में काफी सहायता मिलेगी। परन्तु यदि इस अध्ययन में लिए गए सब सुझावों को भी अपना लिया जाए तो भी बिना ही तात्कालिक और जादू के-से परिणामों की आशा करना मूर्खता होगी। यह भी सम्भव नहीं है कि इन सब उपायों का प्रयोग एक-साथ किया जा सके। इन उपायों के रूप में हम न केवल शिक्षा-सुधार के अपितु समाज-सुधार के भी उपाय प्रारम्भ कर रहे होंगे। जहाँ शिक्षा भावी नागरिक को प्रशिक्षण देती है वहाँ यह भावी समाज के स्वरूप का भी निर्धारण करती है। इस प्रकार की शिक्षा का मूल्य शिक्षा को प्रदान करने वाले अध्यापकों के चरित्र और कायस्थमता पर निर्भर होता है। यही कारण है कि समाज का भविष्य उसने अध्यापकों की उत्कृष्टता पर निर्भर रहता है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अकायस्थम और असन्तुष्ट अध्यापक समाज की नींव को ही खोखला कर देने हैं। उनकी अकायस्थमता और असन्तोष की छूत बालका को लग जाती है और इस प्रकार जाति विघटन और विनाश के बीज बो दिए जाते हैं। इसके विपरीत आदर्शों में आस्था रखने वाला और परम्पराओं में निरंतर पुनरुज्जीवन के लिए कृतसंकल्प अध्यापकों का दल मानव जाति के लिए असीम उन्नति और समृद्धि की दशाएँ प्रस्तुत कर सकता है।

## अध्याय ६

# शिक्षा का नियत कर्तव्य

प्रायः लोग में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे शिक्षा का मूल्यांकन उसकी मानवीय गुणा को विकसित करने की क्षमता द्वारा नहीं अपितु उसकी नौकरी दिलाने की क्षमता द्वारा करते हैं। जहाँ इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा का यह काम है कि वह व्यक्तियों को समाज का सज्जनशील सदस्य बनाए, वहाँ यह प्रश्न भी अवश्य उठाया जा सकता है कि क्या नौकरी दिलाना शिक्षा का मुख्य ध्येय है ? यह स्पष्ट है कि यह प्रारम्भिक या माध्यमिक शिक्षा तक का भी सत्य नहीं हो सकता। प्रारम्भिक शिक्षा अधिक से अधिक बालक की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास कर सकती है उसे आवश्यक ज्ञान की एक यूनवम मात्रा प्रदान कर सकती है और उसमें सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक भावते डाल सकती है। यदि समाज ने स्थितिशील (जड़) भी न बने रहना हो तो माध्यमिक शिक्षा का भी सदैव ऐसे यवक तयार करना होना चाहिए जिनमें किसी एक ही सकुचित क्षेत्र में योग्यता-प्राप्त करीगर बन रहने के बजाय नये ज्ञान और नई प्रविधियों (टेक्नीक) का विकास करने की क्षमता विद्यमान हो।

माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद हम शिक्षा को व्यावसायिक या पेशे सम्बन्धी प्रशिक्षण और उच्चतर शिक्षा इन दो भागों में बांट सकते हैं। व्यावसायिक या पेशे-सम्बन्धी प्रशिक्षण समाज के बने रहने के लिए बहुत आवश्यक है। परन्तु केवल एकमात्र इस प्रकार के प्रशिक्षण पर सारा ध्यान

मैत्रित्व कर लेना खतरे से खासी नहीं है। जनक समाजों में अपने सबसे अधिक हानिकार युक्त धार्मिकों का इस प्रकार का अव्यधिक विनाशकारी प्रशिक्षण निश्चयापन और कई बार उन्हें स्वयं दाँति उठाकर यह समझना पड़ा कि उत्पादन की पद्धतियाँ में परिवर्तन हो जाना अथवा प्रकृति के नियमों और प्रतियोगिता के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान के बढ़ जान के कारण इस प्रकार के उच्च प्रशिक्षित लोग बिलकुल बेकार हो गए और कई बार तो ऐसी दशा हो गई कि उनको कोई काम दे पाना ही असम्भव हो गया।

इस पक्ष-सम्बन्धी प्रशिक्षण से बिलकुल भिन्न उच्चतर शिक्षा एक अव्यक्त प्रकार की शिक्षा है और प्रायः उसका जीवन की व्यावहारिक समस्याओं से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। परन्तु इसकी अव्यक्तता इसका रक्षक गुण है क्योंकि इसका कारण इस प्रकार की शिक्षा विवर्जनीय ढंग की शिक्षा बन जाती है। किसी एक विषय क्षेत्र तक सीमित न रहने के कारण यह मन को उन सामान्य सत्यों तक ऊँचा उठ पाने में समर्थ बना देती है जो हमें आध्यात्मिक जगत् की पहली भलबाँ दिला पाते हैं। इन विवर्जनीय सत्यों का अनुसंधान ही समस्त मानव प्रगति का आधार भी है।

## १

वस्तुतः इस प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं दिया जा सकता कि शिक्षा कबल उन विषयों तक सीमित रहनी चाहिए जिनका सम्बन्ध मनुष्य मात्र से समान रूप से है या अलग अलग व्यक्तियों की विविष्ट योग्यताओं के प्रशिक्षण की दृष्टि से ही जानी चाहिए। इस विरोध को प्रकट करने का लोचप्रिय ढंग यह है कि इसे जीवन के लिए शिक्षा बनाम पेशे के लिए शिक्षा के रूप में वर्णित किया जाय। परन्तु ज्याही यह प्रश्न इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है त्योंही जनक सदेह उठ खड़े होते हैं। जीवन के लिए शिक्षा इस वाक्यांश से हमारा ठीक-ठीक क्या अभिप्राय है? सामान्य रूप से जीवन जसी कोई वस्तु नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति किसी विशिष्ट समाज का सदस्य होता है और उस समाज में उसका जो भी विशिष्ट स्थान होता है उसके साथ जुड़ हुए कुछ निश्चित विशिष्ट कृत्यों को वह करता है। यदि जीवन में किसी विशिष्ट स्थान के साथ जुड़ हुए बिन्ही सुनिश्चित कर्तव्या पर जोर दिया जाए, तो जीवन के लिए शिक्षा और

पैसे के लिए शिक्षा इन दोनों का अन्तर समाप्तप्राप्त हो जाता है ।

इसी प्रकार यदि हम यह जीवन का यत्न करें कि 'पैसा' के लिए 'शिक्षा' का क्या ध्येय है तो भी बड़ी परिणाम निकलता है । कोई भी पैसा अपने आप में जीवन का एक टुकड़ा मात्र होता है और इस कारण पैसा के लिए दो जान वाली शिक्षा जीवन के किसी बिन्दु पर डग के लिए दी जान वाली शिक्षा है । हमें इस सम्बन्ध में भी सावधान हो रहना चाहिए कि जीवन में व्यक्ति की पदस्थिति (स्टेशन) की धारणा को बहुत दूर तक न सींचा जाए । पदस्थिति पर बहुत जोर देने का परिणाम यह हो सकता है कि समाज बड़ बड़ोर रूप में विभिन्न स्तरों में बंट जाय और उसके फलस्वरूप कोई जाति या वर्ग की-सी संरचना (स्ट्रक्चर) उत्पन्न हो जाए, जिसमें व्यक्ति का नाम किसी पहलू में निर्धारित विनिष्ट कृत्य को करना भर हो । यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय तो जीवन के लिए शिक्षा और किसी पैसा के लिए शिक्षा के बीच का अन्तर फिर लुप्त हो जाता है । यहाँ पर इस बात की धार भी संकेत कर देना उचित होगा कि व्यक्ति की पदस्थिति के ऊपर बहुत जोर देने का परिणाम अधिक सम्भव यही है कि एक स्थितिशील (स्टैटिक) समाज तयार हो जाय । मानव प्रगति की एक मुख्य शिक्षा यह रही है कि वर्ग भेदवादी जाति की कठोर संरचना से दूर हटा जाय और व्यक्ति को अपने भविष्य के व्यवसाय का चुनाव करने के लिए अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाय ।

इस प्रकार सामान्य रूप से स्वीकार किया जाने वाला विरोध बनाए नहीं रखा जा सकता और इससे यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि समय-समय पर शिक्षा के उद्देश्यों की नयी छिन्ने से परिमाणा करने की आवश्यकता होती है । जब इन उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में हृत्पद्म कर लिया जाय उसके बाद ही हम जिसे सामान्य शिक्षा कहा जा सकता है उसका सम्बन्ध विनियमनप्राप्त शिक्षा के साथ जाड़न का प्रयत्न कर सकते हैं । इन उद्देश्यों का सवाग सम्पूर्ण विनियमन एक छोट-छोटे निबन्ध में नहीं किया जा सकता । शिक्षा की प्रवृत्ति को ठीक-ठीक रूप में समझने के लिए हमें मन की प्रवृत्ति और उसकी क्रियाओं के विनियमन और मानव मन के समाज और संसार के भाव सम्बन्ध की आधार बनाना होगा । इस प्रकार के विश्लेषण के फलस्वरूप उत्पन्न होना वाला विस्तृत विचार-क्षेत्र में न जाकर हम उन धार परस्पर सम्बद्ध किन्तु एक-दूसरे

से पृथक् प्रयोजना का समझने का प्रयत्न करेंगे जो शिक्षा का लक्ष्य समझ जा सकते हैं। शिक्षा का पहला प्रयोजन व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा का एक प्रयोजन व्यक्ति का उस संसार के सम्बन्ध में ज्ञान देना भी है जिसमें कि वह रहता है। तीसरा प्रयोजन यह है कि व्यक्ति में उन निपुणताओं को विकसित किया जाय जो सामाजिक जीवन को बनाए रखने और उन्नत करने के लिए आवश्यक हैं जिससे व्यक्ति समाज का एक सृजनात्मक सम्पदा बन सके। इन तीनों के साथ सम्बद्ध परन्तु मात्र ही इन तीनों से बिलकुल पृथक् एक चौथा प्रयोजन भी है और वह है—व्यक्ति की जीवन मूल्यों की स्थापना की आवश्यकता को पूरा करना।

इन चारों में से प्रत्येक उद्देश्य का उसकी अपेक्षा बड़ी अधिक विस्तृत और मुनिश्चित विवेचन करने की आवश्यकता है मितना कि यहाँ किया जा सकता है। जब हम व्यक्तित्व के विकास की बात कहते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यक्ति की शारीरिक मानसिक भवेगात्मक और आध्यात्मिक योग्यताओं की वृद्धि और परिपक्वता से होता है। अविकसित शरीर केवल शारीरिक वृद्धि के अभाव का नाम नहीं होता बल्कि उसमें कुछ स्पष्ट विध्यात्मक (पोज़ीटिव) अवाछनीय निम्नगताएँ भी पाई जाती हैं। इसी प्रकार अविकसित मन में न केवल बौद्धिक स्वतंत्रता का विकास नहीं होता बल्कि वह मन अविश्वास सुधारों के विरोध भय और द्वय का भी एक स्रोत बना रहता है। यह सामान्य अनुभव की बात है कि किसी जानक को स्नेह न देने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि बालक सवेगा की दृष्टि से क्षुब्ध रह जाय अपितु वह दूसरों के लिए एक तकरार का और भ्रष्टता फैलाने का साधन बन जाता है। व्यक्तित्व के आध्यात्मिक विकास की परिभाषा कर पाना और भी अधिक कठिन हो सकता है किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अर्थ मामलों का अतीति इस क्षेत्र में भी वृद्धि न हो पाना केवल एक अभाव मात्र नहीं है अपितु एक ऐसा निषकारमय वस्तु है जिसका कि स्वयं उस व्यक्ति पर तथा दूसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः इस सम्बन्ध में सोचते हुए आश्चर्य जगत् में भटकने वाला बालिका एलिन की दगा का ध्यान आ जाता है। वह देखती है कि उस अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है और फिर भी वह वहाँ रहती है जहाँ वह पहले खड़ी थी। वृद्धि होने में असफलता के पश्चात् व्यक्ति वहीं नहीं रहता,

जहाँ कि वह पहुँच या अपितु एका अमकलता उस अमन प्रारम्भ बिन्दु से भी कुछ नीचे की ओर वापस घुमेल देती है ।

गिरीषा का दूसरा दृश्य भौतिक जगत का और उसके साथ-साथ समाज के विचारों और भावों का ज्ञान प्राप्त करना है । इस प्रकार के ज्ञान के बिना व्यक्ति बना भी नहीं रह सकता फिर अपने व्यक्तित्व का विकास करना तो दूर का बात है । वस्तुतः व्यक्तिगत विकास और समाज की सेवा दोनों के लिए ही इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होना एक आवश्यक ज्ञान है । कई बार गिरीषा को जवन जानकारों प्राप्त करने के लिये मजबूर जाता है परन्तु हमें इस सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए कि भौतिक समाज या विचारान्तर (माइ डिपेंडेंस) परिवर्तन का अलग अलग ज्ञान में स किमी भा एक पर आवश्यकता में अधिक अनधिकृत बल न दिया जाय क्योंकि इस संसार की समझ के लिए हमारे लिए य दोनो ही प्रकार के ज्ञान समान रूप में महत्वपूर्ण है । फिर भी जिस संसार में हम रहते हैं उसमें सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना गिरीषा के समाज के काम के लिए आवश्यक है ।

गिरीषा के लिये सत्य तब पहुँचने के लिए व्यक्तित्व का विकास और परिवर्तन के सम्बन्ध में ज्ञान की प्राप्ति दोनो ही आवश्यक है । व्यक्ति केवल समाज में रहने हुए भी अपना कृत्य (फैशन) करता रह सकता है । यदि व्यक्ति की वृद्धि और विकास के साथ-साथ इस परिवर्तन में परिवर्तन और विकास न हो तो उनका ही उत्पन्न हो जाना अनिवार्य है । सचता यह है कि अनुकूल परिवर्तन न व्यक्ति की वृद्धि और विकास में सहायता मिलती है और अनिवार्य परिवर्तन स वाधा पड़ता है । दूसरी ओर अलग-अलग व्यक्तियों की प्रगति अथवा दुर्घटना का परिणाम समाज की उन्नति या अवनति होता है । यदि कोई व्यक्ति समाज का सज्जनगीत सम्बन्ध बनाता चाहता है तो उसे न केवल अपनी वृद्धि को बनाए रखना होगा अपितु समाज की वृद्धि में भी कुछ न कुछ योग देना होगा । समाज के सामाजिक दशाओं में व्यक्ति को अपनी मारी सीमित ऊर्जा समाज को सन्तुष्ट बनाए रखने में लगानी पड़ती है । दूसरी ओर प्रगति के लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि समाज कितनी कुछ सफलता प्राप्त कर चुका है उससे भागे बड़ा जाय । क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में हमारी ऊर्जा का अधिकांश भाग केवल सामाजिक स्थिति का बनाए रखने में ही लग जाता है इस



लिए उससे धाने बढ़ने के लिए धमाधारण प्रयत्न की आवश्यकता होती है। फिर भी यह एक ऐसी डिम्पेदारी है जिम प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी सीमा तक पूरा करना ही चाहिए। जब तक हम कुछ दे नहीं तब तक हम कुछ ले नहीं सकते और जब तक हम कुछ ले नहीं तब तक कुछ दे भी नहीं सकते।

यह परिस्थिति इस तथ्य के कारण और भी उत्पन्न जाती है कि समाज के सन्तुष्ट के रूप में नियत कर्तव्य को पूरा करने के प्रतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति का एक अक्षुण्ण व्यक्तित्व भी है जो बिल्कुल निरासा है। मनुष्य को अपनी आंतरिक प्रकृति की माँग को पूरा करने ही सतोष प्राप्त हो सकता है। इसे हम जीवन मूल्य की खोज अथवा आत्म ज्ञान की यात्रा कह सकते हैं। परन्तु हम चाहे हमका वयन किसी भी रूप में क्या न करें प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर एक ऐसा तत्त्व होता है जहाँ पहुँचकर वह अपनी सामाजिक आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाता है। वह आत्मज्ञान का केवल अपने समाज की माँग को पूरा करके अथवा अपने पंग के हितों को पूरा करने प्राप्त नहीं कर सकता।

ऊपर हम विरोधाभास का उल्लेख किया जा चुका है कि जीवन के लिए शिक्षा का अर्थ वस्तुतः जीवन में किसी बिन्दु पर हित के लिए शिक्षा भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में यदि 'जीवन के लिए शिक्षा' की संकुचित अर्थों में व्याख्या की जाय तो उस पंग के लिए शिक्षा से पुनर्बन्ध कर पाना कठिन ही है। फिर भी पहले बताए जा चुके कारणों से इन दोनों के बीच अन्तर करना ही होगा। एक ओर तो समाज की प्रगति पर स्थिति (स्टेटस) से युगबन्ध (क्वेट्रेन्ट) की ओर तथा कठोरता से सरलता (प्रवहणीयता) की ओर है दूसरी ओर समाज के वर्तमान संगठन में इसके अधिकांश सदस्यों की लगभग सारी शक्ति सम्पत्ता के केवल उस अभाव को बनाए रखने में लगा देने पड़ती है जोकि अब तक प्राप्त किया जा चुका है। यह सम्भव है कि समाज विकास की ओर अधिक प्रगति होन पर हमें यह पता चले कि मनुष्य में सृजनशील ज्योति उसकी अपेक्षा अधिक विस्तृत रूप से व्यापक हो गई है जितना कि हम इस समय कल्पना करते हैं परन्तु अब की अपेक्षा अधिक सुखी समाज में भी लोगों की इस मजबूत 'ज्योति' की भाभा में अन्तर रहेगा ही। यह सम्भव है कि भविष्य में समाज के सब सदस्य सामान्य सामाजिक कल्याण में अब की अपेक्षा अधिक

योग्य है। परन्तु वस्तुतः महत्वपूर्ण प्रगतिशील उस समय भाग्य की ही भाँति प्रतिभागानों व्यक्तिगतों के प्रयत्न के फलस्वरूप ही होगा। परन्तु इससे पहले कि ऐसा कोई प्रयत्न किया जा सके हमें इन बातों का देखना होगा कि ऐसा प्रयत्न करने वाला व्यक्ति या व्यक्ति-समूह समाज के अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए प्राप्त कर सका है। अविषय के लिए नये परीक्षण केवल इस समय तक प्राप्त सुफलताओं के आधार पर ही किए जा सकें ह।

शिक्षा के पहले का उद्देश्य है—व्यक्ति के विभिन्न गुणों का विकास करना और उस संसार का कुछ ज्ञान प्राप्त करना। जहाँ तक इनमें से पहले उद्देश्य का सम्बन्ध है हमें उन विषय-वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो व्यक्ति को बाद के जीवन में करने पड़ सकें ह। विषय-पद्धति प्राप्ति शिक्षा के दूसरे उद्देश्य में दीखती गुरु होती है और इनके द्वारा ही वास्तविकता के उन पहलुओं का निवारण होता है जिनका उस व्यक्ति का कुछ अधिक या कुछ कम गहरा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जब हम शिक्षा के तीसरे और चौथे उद्देश्यों पर विचार करते हैं तब यह विषय-पद्धति प्राप्ति और भी अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ने लगता है। बाद भी व्यक्ति सामाजिक समस्या को बनाए रखने या उन्हें उन्मूलन करने में और इस प्रकार समाज का एक सज्जनशील सम्पूर्ण बनने में बल अपने व्यक्तिगत ढंग से ही योग दे सकता है। इस प्रकार उसका पुरातन जीवन-मूल्यों का अध्ययन करना और नये जीवन मूल्यों का अनुसंधान भी उसकी व्यक्तिगत समता पर ही आधारित होगा। आत्मज्ञान प्रकृत्या ऐसी वस्तु है जो मुख्यतः एक व्यक्तिगत कृत्य है। धर्म के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यह वह वस्तु है जिसकी साधना मनुष्य एकांत में करता है। विज्ञान दर्शन और कला से मूल्य निस्तृप्त हो सामाजिक जीवन का समर्थ बनाते हैं परन्तु धर्म की भाँति वे भी मुख्यतया मनुष्य की एकान्त साधना के ही परिणाम हैं।

इस प्रकार पहली दृष्टि में यह दिखाई पड़ता है कि शिक्षा का पहला लक्ष्य हमें सामान्य शिक्षा के सिद्धान्त की ओर लाना है और साधारण लक्ष्य विभिन्न गुणों और योग्यताओं के प्रतिष्ठान का सुझाव प्रस्तुत करता है। दूसरे लक्ष्य में संसार का सामान्य ज्ञान और जिनकी खास व्यवस्थाओं के उपयुक्त विषय-ज्ञान

दोना ही धा जाते हैं। बीया उद्भूय इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं जाता और यह सबसे भ्रष्ट हो रहता है।

परन्तु विश्लेषण करने पर यह बात स्पष्ट हो जायगी कि इन सभ्यों में किया गया इस प्रकार का भ्रष्टाचार ठीक नहीं सकता। इनमें से प्रत्येक उद्भूय दूसरे उद्भूय का समकक्ष है और उनसे समन्वित भी है। इस बात का एक जबरन उदाहरण यह है कि जीवन के भौतिक प्रमाणों में उन्नति उन भ्रष्टाचार अनुसंधानों के परिणामस्वरूप हुई है जिनका पहली दृष्टि में व्यावहारिक समस्याओं से कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ता।

## २

अब हम यह देखने का यत्न करते हैं कि क्या शिक्षा के इन प्रयोजनों का सम्बन्ध शिक्षा को भ्रष्टाचार-भरित दशाओं से जोड़ा जा सकता है? परन्तु इस सम्बन्ध में एक चेतावनी दे देना आवश्यक है। किसी विविध प्रयोजन का सम्बन्ध किसी विशेष दशा से जोड़ने का यह भय वर्दाप नहीं है कि वह प्रयोजन शिक्षा की अन्य दशाओं में काम नहीं कर रहा होगा। हमारा अभिप्राय बस इतना ही है कि कोई विविध प्रयोजन किसी विविध दशा में और दशाओं की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

अब यह बात स्पष्ट है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और उत्थार के सामाजिक मान की प्राप्ति का प्रारम्भ प्राथमिक या प्रारम्भिक स्तर से होना चाहिए। यह दशा बचपन के प्रारम्भ से लेकर किशोरावस्था के आगमन तक की होती है। इस दशा में किसी निश्चित निपुणताओं या योग्यताओं के विकास का कोई प्रयत्न नहीं उठता। इस स्तर पर शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य यह है कि बालक को वह ज्ञान प्रदान कर दिया जाए जो उसके समाज में अन्य सदस्यों को प्राप्त है और वास्तव में उन दारिद्र्य-बोधक सामाजिक और नैतिक मानकों का विकास कर दिया जाए जो उसके जीवन रहन और प्रगति करने के लिए आवश्यक हैं। इसके अनिश्चित जीवन की इस प्रारम्भिक दशा में उसकी अभियोग्यताएँ भी बहुत कुछ अशुद्ध ही होती हैं। इसीलिए हम बालक को सी जानने वाली शिक्षा को सामाजिक धर्म की शिक्षा कह सकते हैं और प्रायः कहते भी हैं।

जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा उद्देश्य की दृष्टि से सबसे अधिक सामान्य है वहाँ साथ ही सब दगावा की अपेक्षा मुख्यतः (कौशिल्य) भी है। हम बालक को उस समाज का जिसमें कि वह रहता है ज्ञान केवल भासपास की वस्तुओं से प्रारम्भ करके ही दे सकते हैं। जो भी निपुणताएँ हम उसमें विकसित करना चाहते हैं वे भी उनके परिवेश की तात्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित हानी चाहिए। यदि प्राथमिक शिक्षा का अपना वास्तविक सन्ध पूरा करना है तो वह समाज के स्थानीय अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार का अनुभव एक विशिष्ट ढंग का होता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा उद्देश्य की दृष्टि से और शायद प्रणाली की दृष्टि से भी सामान्य होते हुए भी विषय की दृष्टि से अथ किसी भी दगा की शिक्षा की अपेक्षा बड़ी अधिक सुनिश्चित (स्पेसिफिक) होती है।

बुनियादी शिक्षा की धारणा में जा हाल ही में भारत में विकसित हुई है इसी सत्य का स्वीकार किया गया है। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बालक को किसी ऐसी दस्तकारी के द्वारा जिससे कि वह परिचित है ज्ञान देकर उसके व्यक्तित्व का विकास करना है। किसी प्रचलित दस्तकारी के ऊपर आग्रह करके बुनियादी शिक्षा न एक महत्वपूर्ण सत्य को पकड़ लिया है। यह शिक्षा इस बात को स्वीकार करती है कि बालक के लिए अव्यक्त शिक्षण न केवल एक बोझ बन जाता है बल्कि अवास्तविक भी रहता है। दस्तकारी पर जोर देने के कारण गतिविधि का तत्व भी शिक्षा की प्रणाली में तुरन्त घा पहुँचता है। इतना ही नहीं दस्तकारी का अर्थ एक सामाजिक दृष्टि से उपमाणी गतिविधि भी है और हमके फलस्वरूप बालक को बिनाकुल प्रारम्भ से ही समाज के एक सदस्य के रूप में अपने कतव्य को समझने की शिक्षा दी जाती है। किसी स्थानीय दस्तकारी पर आग्रह करने का कारण शिक्षा के हम सिद्धान्त को स्वीकार करना है कि शिक्षा परिचित से शुरू होकर अपरिचित की ओर या गति से अज्ञात की ओर बानी चाहिए। अन्त में बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बालकों में नागरिकता की भावें डालना है और ये भावें अव्यक्त मिट्टा-ता के द्वारा नहीं डाला जा सकता क्योंकि उनका बालकों के लिए कोई अर्थ नहीं होता। अतः ये भावें उन्हें दैनिक जीवन में अभ्यास के द्वारा डाली जाती हैं।

बुनियादी शिक्षा के इन गुणों से ही यह बात ध्वनित हो जाती है कि प्रार-

भिन्न शिक्षा के विषय अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग ही होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रणाली सब जगह एक ही होगी परन्तु विस्तार की बातें अलग-अलग स्थानों में इतनी अलग-अलग होंगी कि मावधान पयवेदाश के सिवाय अन्य व्यक्ति उनके अन्दर द्वितीय हृदय एकता को सायद पहचान ही न सके। शिक्षा के उद्देश्य सबके लिए समान होंगे परन्तु शिक्षा की इस दशा में जिन विधियों से इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है वे इस बात पर निर्भर होंगी कि शिक्षा को किस प्रकार अधिकतम सुव्यक्त और सुनिर्दिष्ट बनाया जा सकता है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस बात का भी औचित्य बताया जा सकता है कि किसी सुनिर्दिष्ट परिवेश में रहते हुए भी प्रारम्भिक शिक्षा सामान्य क्या होती है। यह शिक्षा सामान्य इसलिए होती है, क्योंकि यह बालक की विस्तृत रूप से प्राप्त जिज्ञासा को पूर्ण करती है। बालक के सम्मुख जो भी वस्तु आती है उसके सम्मुख में वह क्यों का उत्तर भव्य जानना चाहता है। इस शिक्षा का उद्देश्य एक सामान्य संसार में उन विभिन्न अनुभवों को मिलाकर एक करना है जो अपने विलकुल नये-नये रूपों में यहाँ प्राप्त होते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा को परिवेश की दृष्टि से सुनिर्दिष्ट किन्तु उद्देश्य की दृष्टि से सामान्य होना होगा। यह सुनिर्दिष्ट इसलिए है क्योंकि इसका प्रारम्भ ज्ञात परिवेश होता है। यह सामान्य इसलिए है क्योंकि इसका उद्देश्य बालक के जीवन का समाज के जीवन के साथ समेकन (इंटीग्रेशन) करना है।

जब हम प्रारम्भिक शिक्षा से भाग बढ़कर माध्यमिक शिक्षा पर आते हैं तो एक नया सिद्धान्त लागू हो उठता है। मनुष्य का शरीर प्राणियों से अन्तर उसकी अध्यवसीकरण (एड्युकेशन) की दृष्टि से कारण है। शारीरिक शक्ति और मानसिकता की दुबलता की अक्षमता के होते हुए भी मनुष्य ने शरीर सब प्राणियों पर इसलिए विजय प्राप्त कर ली है क्योंकि उसमें विविष्ट घटनाओं के सामान्य नियम निकाल पाने की क्षमता है। इस प्रकार के सामायीकरण का सार यह है कि असम्बद्ध या अनावश्यक वस्तु से महत्वपूर्ण वस्तु को पृथक् कर लिया जाय। किसी भी क्षण हमारा अनुभव असंख्य पृथक्-पृथक् वस्तुओं (आइटेम) से पूर्ण होता है। हम अपना ध्यान भले ही किसी एक विविष्ट वस्तु पर केन्द्रित किए हुए हों परन्तु हम अपनी चेतना के छोरों पर अनुभव होने वाले शेष शक्ति और दृष्टि

के प्रभावों को विनष्ट करने पर नहीं कर सकते। परन्तु यदि हम इन्द्रियों के इन असह्य अनुभवों से अपना ध्यान विचलित होन दें तो हमें शायद कभी भा किसी एक अनुभव की अनुमति ही न हो सके। केवल सम्बद्ध वस्तुओं को चुनन और उनको किसी महत्त्वपूर्ण वस्तु के रूप में संयुक्त कर लेने के द्वारा ही हमारा अनुभव सुसंगत और साधनमय बन पाता है।

यह भी कहा जा सकता है कि एक दृष्टि से क्या भी अपने अनुभवों में सम्बद्ध और महत्त्वपूर्ण का अन्तर कर लेते हैं। अपने चिन्तन का पीछा करता हुआ बाह्य चिन्तन के प्रतिरिक्त अर्थ किसी भी वस्तु का धार ध्यान नहीं देता। फिर भी इन प्रकार के चुनाव में और मानवीय विचार में होने वाली चुनाव की प्रक्रिया में अन्तर है। पशुओं के लिए इस प्रकार का चुनाव सदैव एक सहज वृत्ति (इंस्टिक्ट) द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए यह पुनरावृत्ति के दृष्टि की और साम ही एक ही दिशा में होने वाली क्रिया होती है। यदि एक ही प्रकार की परिस्थिति हो तो इस क्रिया में वृत्ति प्रायः कभी होती ही नहीं। परन्तु यदि परिस्थिति बदल जाय तो सहज वृत्ति द्वारा संचालित प्रतिग्रह (रिस्पांस) का परिणाम बहुत साधारण हो सकता है और प्रायः होता भी है। मनुष्य के मामले में यह चुनाव सहज वृत्ति का काम न होकर बुद्धि का काम होता है। इसीलिए यह कभी अधिक पेचीदा होता है और शायद ही कभी पुनरावृत्त्यात्मक होता है। क्योंकि इस प्रकार का चुनाव अव्यक्तीकरण पर आधारित होता है इसलिए यह मनुष्य की अपने अनुभवों को अपने अपने दृष्टिकोण में विभक्त कर सकने की शक्ति और उन दृष्टिकोणों में परस्पर सम्बन्ध निर्धारित करने का शक्ति से प्राप्त होता है। यह शक्ति मनुष्य को विषयों को अत्यधिक पचीन्गी की एकता के ढांच में ढालने में समर्थ बनाती है और अन्य सब पशुओं की अपेक्षा मनुष्य की अदृष्टता का आधार यही शक्ति है। यह बात मनुष्य की अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाने की क्षमता के रूप में स्पष्ट देखी जा सकती है। पशु और पक्षी भाषाओं करते हैं किन्तु उनका अर्थ बहुत सीमित होता है। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने सुस्पष्ट ध्वनियाँ के द्वारा भाषा का सृजन किया है।

जहाँ विचारों की शक्ति मनुष्य को अन्तर्गतता अर्थ सब प्राणियों की अपेक्षा अदृष्ट बना देती है, यहाँ जब तक इन शक्तियों का समुचित विकास न

हो तब तक यह धर्म पानुषों की सुसुता में अपेक्षाकृत असह्य रहता है। अधिकांश प्राणियों के मामले में जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक निपुणता उन्हें विगोरावस्था की समाप्ति से पूर्व ही प्राप्त हो जाती है। मानव विगोर विषय रूप से प्राधुनिक समाज का मानव विगोर अपनी दक्ष रेष स्वयं उचित रूप से बन पाने में प्रमथ है। इसके प्रतिरिक्त मनस्य के मामले में विगोरावस्था की अवधि भी अपेक्षाकृत समी है। इसलिए उसकी जीवन के लिए तमारी सारे बाल्यकाल में और विगोरावस्था में और उसका बाद भी जारी रहती है।

सांख्यिक शिक्षा-काल को मोटे तौर पर विगोरावस्था की अवधि में बराबर समझा जा सकता है। कुछ मिनाकर बाल्यकाल की विगोरावस्था बड़ी स्पष्ट और एकस्य होती है। इसलिए बाल्यकाल के साथ व्यवहार करते हुए व्यक्ति अपने भावों का भी कुछ सुदृढ़ आधार पर प्रमथ करता है। उन्हें एक निश्चित मात्रा में जानकारी दी जानी होती है और विचार और शिक्षा का कुछ निश्चित आदता का प्रशिक्षण दिया जाना होता है। दूसरी ओर, बड़ी आयु के लोगों के साथ व्यवहार में भी एक सुनिश्चित रूप अपनाया जा सकता है क्योंकि उनकी आदतों और अभिप्रेक्षाओं अपेक्षाकृत पक्का हो चुकी होती है। परन्तु विगोर न तो बाल्य ही होते हैं और न वयस्क ही और इससे भी अधिक परेगानी की बात यह है कि वे एक दौर से बड़ी तेजी से दूसरे दौर में पहुँचते जाते हैं। उस समय वे एक अनक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में से गुजर रहे होते हैं जिसका व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हा बड़ा महत्व होता है। इसके प्रतिरिक्त विगोरावस्था के प्रगमन के साथ-साथ अभिप्रेक्षाओं और रुचियों में अन्तर और अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है और इसलिए चुनाव के लिए विद्यालय सर ग्य की आवश्यकता होती है। धन इस सामा पर आकर प्रारम्भिक शिक्षा का एक रूप प्रणाली के स्थान पर रुचि अभिप्रेक्षाओं और योग्यता की विविधताओं को सन्तुष्ट करने के लिए काफी विविध पाठ्यक्रम रखे जान चाहिए।

पाठ्यक्रमों के विविधीकरण (डाइवर्सिफिकेशन) और विषयज्ञताप्राप्ति (स्पेशलाइजेशन) में बराबर काम का ही अन्तर है। किन्हीं चुनी हुई विद्याभ्या में विज्ञान का परिणाम अनिवार्य रूप से यह होता है कि विषयज्ञताप्राप्ति के पाठ्यक्रमों का व्यवस्था की माँग की जान सग। यह माँग प्रायः यह रूप धारण

करती है कि जीवन की तैयारी के लिए विन्हीं मुनिर्दिष्ट निपुणताओं की प्राप्ति की माँग की जाए। इस सम्बन्ध में यह व्यक्ति दा जाता है कि जब व्यक्ति 'मातृ' के रूप में आधारभूत आवश्यक निपुणताओं की प्राप्ति कर चुका तो माध्यमिक शिक्षा-काल में उस एसी मुनिर्दिष्ट निपुणताएँ प्राप्त करनी चाहिए जिनमें कि वह किसी ऐसे क योग्य बन सक। यह मा व्यक्ति दा गई है कि यदि ऐसा न किया जाए तो माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा की ही धीरे धीरे आधार घसाटना भर रह जायगी। इस दृष्टिकोण क समर्थता के विचार क माध्यमिक शिक्षा किसी विनिर्दिष्ट व्यवसाय के लिए शिक्षा अथवा प्रशिक्षण होनी चाहिए।

परन्तु मुक्त ऐसा सगता है कि माध्यमिक शिक्षा-काल में किसी पम क लिए प्रशिक्षण की यह माँग उचित नहीं है। इसमें सन्देह नही कि प्रारम्भिक शिक्षा आधारभूत निपुणताएँ प्राप्त करा सकती है परन्तु यह निपुणता प्राप्ति केवल बहुत ही सामान्य अर्थों में होने है। माय ही प्रारम्भिक शिक्षा का अर्थ है इतनी छोटी होता है कि उसमें यह भरना नहीं किया जा सकता कि क निपुणताएँ विद्यार्थी क मन में स्थायी रूप क अम गई ह। इस प्रकार यह सतरा बराबर बना रहता है कि यदि प्रारम्भिक शिक्षा-काल के बाद मा कुछ पम तक उनका अभ्यास न किया जाए तो वे फिर विम्युत हा जा सकती ह।

फिर प्रारम्भिक शिक्षा-काल में प्राप्त किया ज्ञान इतना अल्प और इतना अनिश्चित होता है कि उसके भराम यह आता नहीं की जा सकती कि व्यक्ति अपने जीवन में सरलतापूर्वक प्रगति करता सता जायगा। सामाजिक प्राणी होने क कारण मनुष्य केवल अपने ही अनुभव पर निर्भर नहीं रहता अपितु उस समाज क अनुभव पर भी निर्भर रहता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। क्योंकि उसक काय मुख्यरूप क सहजवृत्ति (इंस्टिक्ट) पर आधारित नहीं रहते अपितु विम्युषण और अभ्यक्तीकरण पर आधारित रहते ह। इसलिए उस अपने काम करने क लिए काफी विद्याल और विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हा जाता है। इस प्रकार सामान्य शिक्षा की कुछ और सम्ब बाल तक साधने की माँग मनष्य का प्रकृति पर आधारित है। या तो इस बात की आवश्यकता सता स ही रहती है परन्तु आधुनिक जीवन की बड़ी हुई और निरन्तर बढ़ता वैधीन्य के कारण यह आवश्यकता कहीं अधिक महत्वपूर्ण हा उठी है। इसलिए समाज का अपने अध्यात्मिक बह साध की शिक्षा की जारी रखने की व्यवस्था



या तो माध्यमिक शिक्षा के रूप में अथवा वाद में होत वाले वयस्क शिक्षा के रूप में ध्यान करनी चाहिए।

कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिनके कारण माध्यमिक शिक्षा को मुख्य रूप से बहू होता चाहिए जिसे सामान्य या उदार शिक्षा कहा जाता है। हम ऊपर किशोरों की अस्थिरता का उल्लेख कर चुके हैं। यह वह धक्का होती है जिसमें बालक बढ़कर वयस्क बन रहे होते हैं और उनकी यह वृद्धि अनेक दौरो में सं गुजरनी है। सम्भव है कि प्रत्येक दौर में व्यक्तित्व का कोई अलग ही पहलू अधिक प्रमुख हो। साथ ही किसी विशिष्ट गुण (ट्रैट) के प्रकट होत के आधार पर भावी जीवन के सम्बन्ध में निश्चय करने की दृष्टि से यह समय बहुत अल्प होता है। इस दशा में भावी पढ़ाई के सम्बन्ध में किए गए किसी भी अन्तिम निर्णय के कारण बड़ी भारी शक्तियां हो सकती हैं। किशोरवस्था में जबान लड़का या लड़कियों को जहाँ तक भी सम्भव हो अधिक से अधिक छूट दी जानी चाहिए। क्योंकि किसी विशिष्ट पढ़ाई के सम्बन्ध में प्रशिक्षण किशोर की अनोखी भावना होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के साथ-साथ बदलता नहीं जा सकता इसलिए यह आवश्यक है कि इन स्तर पर शिक्षा को यथासम्भव विशालतम आधार पर आधारित और यथासम्भव सामान्य बनाया जाय। यदि किशोर युवक या युवती का अपना पढ़ाई का एक बार चुनाव कर लेना के बाद उस निर्णय के साथ ऐसा बाध दिया जाय कि वह उस पढ़ाई में न सक तो विविध पाठ्यक्रमा की व्यवस्था करने का अधिवाश महत्व तो समाप्त ही हो जायगा।

व्यक्ति की आवश्यकताओं के अतिरिक्त समाज की आवश्यकताएं भी उस दशा में कहा अधिक अच्छी तरह पूरी हो सकती हैं जबकि माध्यमिक शिक्षा में विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों के साथ-साथ अपेक्षाकृत अधिक सामान्य ढंग की शिक्षा दी जाती है। किशोरवस्था ऐसा काल है जिसमें कि व्यक्ति नई निपुणताएं भी प्राप्त कर रहा होता है। यही वह दशा है जिसमें कि निपुणताएं किसी व्यक्ति में स्थायी रूप से पक्की होकर जम सकती हैं। यदि ये निपुणताएं अल्पधिक विशिष्ट ढंग की हों तो इस बात का अर्थ है कि व्यक्ति किसी एक सुनिश्चित ढांचे में ही बस जायगा। उस दशा में समाज की प्रणाली में यदि कोई परिवर्तन हो तो इन निपुणताओं की न केवल उपयोगिता कम हो जाएगी अपितु उस व्यक्ति के लिए बढती हुई परिस्थितियों के साथ अपना समझन

(साम्यस्थापन या बठ-विठाव) करना बहुत कठिन हो जायगा। परन्तु यदि इस स्तर पर बहुत मात्रा डग की निपुणताएँ प्राप्त की जाएं तो उनका प्रयोग विविध प्रकार की परिस्थितियों में कर पान की सम्भावना बहुत बढ़ जायगी।

इस सम्बन्ध में मनावज्ञानिक साधारणतया एकमत है कि गिना का उच्च सामान्योपकरण करने की शक्ति प्राप्त करना है। यदि मात्रा डग की निपुणताएँ प्राप्त कर ली जाएं तो उनका प्रयोग विविध प्रकार का परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि सामान्योपकरण की शक्ति के विषय में बहुत ही अत्यधिक विषयज्ञानाश्रित निपुणताएँ एक ही नौकरी पर कर ली जाएं, तो सम्भव है कि बर्तन हुए परिवर्तन (एनवायरनमेंट) में व्यक्ति अपने आपको बिल्कुल असहाय अनुभव करे। किसी स्थितिगत (स्टैटिक) समाज में इस प्रकार का निपुणताओं का विकास करने का प्रयत्न किता सीमा तक उचित कहा जा सकता है परन्तु जिस समाज में परिवर्तन बड़ी तीव्र गति में हो सकने का उसमें ऐसा प्रयत्न करना बहुत खतरनाक होगा। आजकल का समाज विषय रूप में गतिशील है। आज के व्यवहारों में स्थान पर कल बिल्कुल नए व्यवहार आ सके होते हैं। इस तेजी से चलते हुए समाज में व्यक्ति को उत्कृष्टतर जीवन के लिए तैयार करने के बजाय छोटी उमर में ही उस विषयज्ञता प्राप्त निपुणताओं में पक्का कर देना उस परिवर्तित होत हुए काल का अनौचित्य का सामना करने में कम समय बना देता है।

जो कुछ माध्यमिक गिना के सम्बन्ध में कहा गया है वही धारणा-प्रकार के साथ उच्चतर गिना पर भी लागू होता है। दोनों में मुख्य अन्तर यह है कि माध्यमिकाल (पोस्ट सेकेंडरी) गिना में सामान्य निपुणताओं का विकास करने की आवश्यकता इतनी तीव्र नहीं होती। समाज का यह भाग करने का अधिकार है कि माध्यमिक गिना-काल में इस प्रकार का निपुणताएँ न केवल प्राप्त हो चुकी होंगी अपितु पक्की भी हो चुका होगी। समाज को यह भी धारणा करने का अधिकार है कि माध्यमिक गिना में व्यक्ति का अन्दर ध्वस्त विचार और सामान्योपकरण की शक्ति भी विकसित हो गई होगी। यह भी धारणा की जाती है कि इस माध्यमिक गिना-काल का समाप्ति तक व्यक्ति में विचार की स्पष्टता और जीवन मूल्यों का अनुसंधान करने की आपारभूत मानवीय विषयताएँ भी विकसित हो गई होंगी। इसलिए इस दशा के परवान् विविध निपुणताओं की

प्राप्ति पर ध्यान केन्द्रित करने में क्या जोखिम नहीं है जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-काल में होता है। यदि हम यह मान लें कि समाज के सदस्यों में माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के समय तक मानव प्राणियाँ और भाग्यशर्कों के रूप में साधारण बुद्धिमत्ता प्राप्त कर ली है तो इसमें आग बसकर के मुख्य रूप में अपनी ध्यान उन विविध नियत कृतव्यों की तयारी की ओर लगा सकते हैं जो उन्हें भाग्य बसकर समाज में पूरे करने पड़ेंगे। उनमें से नियत कृतव्य किन्हीं विविध पक्षों को करने वाले कामकाजी लोग के कृतव्य भी हो सकते हैं या फिर वे उन विविध मनुष्यों के नियत कृतव्य हो सकते हैं जो अपने जीवन का ध्येय सत्य की स्थापना ही बना लेंगे।

हम यह कह चुके हैं कि इस देश में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विविध निपुणताओं की प्राप्ति करना है परन्तु इस प्रकार का विशेषता प्राप्ति का विकास सामाजिक सदभावना और अन्तर्दृष्टि के अधिकाधिक गहरा होन के साथ-साथ होना चाहिए। जीवन के अग्र और उद्देश्य के सम्बन्ध में हमारी समझ हमारे अनुभव की गहराई और विविधता पर निर्भर होती है। स्पष्ट है कि किशोरावस्था में प्राप्त हुआ परिमित अनुभव इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है। यह अनुभव हमें वयस्क जीवन के दौरान में प्राप्त करना होगा। हमें यह भी याद रखना होगा कि जिस हम किसी विविध पक्षों के लिए शिक्षा का नाम देते हैं उसमें यदि उसे पूर्णतया सन्तोषजनक बनाना है तो उदार शिक्षा के आधारभूत जीवन-मूल्य अवश्य विद्यमान रहने चाहिए। हम चाहें किसी पक्ष को क्या न अपनाए वह प्रश्न ही किसी न किसी सामाजिक आवश्यकता पर आधारित होता है। इस प्रकार की आवश्यकताओं में अग्रता (प्रायोरिटी) का निर्माण करना ही जीवन-मूल्यों का मूल्यांकन है और इसी के कारण किसी पक्ष को उसका सामाजिक महत्त्व प्राप्त रहता है। इस महत्त्व को ठीक-ठीक समझने से न केवल व्यक्ति का जीवन समृद्ध बनता है अपितु वे तत्त्व भी बहुत सुस्पष्ट हो जाते हैं जिनमें वह पक्ष बना है और इस प्रकार जैसा कि व्हाइटहेड ने कहा है पक्षों के लिए दी जाने वाली शिक्षा में निहित उच्च जीवन-मूल्य सामान्य प्राप्त हैं।

यहाँ चलावनी के रूप में एक बात यह देना आवश्यक है। जिस रूप में आजकल माध्यमिक शिक्षा संगठित है उससे व्यक्ति को सदैव समार का भाव

स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता और न उसमें वह विचारगमक बुद्धिमत्ता और अनुशासित कल्पना हो विरमिन हो पाती है जिसकी वि माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर प्राप्ति की जा सकती है। प्रायः होता यह है कि व्यक्ति के विस्तृत आधार वाली शिक्षा को प्राप्त करने में पड़ता हो जिससे कि वह समाज का सुजनशील सदस्य बन सकता था। किसी एक संकीर्ण क्षेत्र पर विशेषज्ञताप्राप्ति प्रारम्भ हो जाती है। यही कारण है कि हमें कभी-कभी ऐसे अनक विपन्न मिलते हैं जो अपने क्षेत्र से बाहर बौद्धिक और सवेगामक दृष्टि से अपरिपक्व होते हैं। बुद्धिमत्ता या समझदारी के अभाव में उनका ज्ञान अपने आप में समाज के लिए एक सबट बन सकता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने माध्यमिकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों का इस ढंग से नवीनीकरण करें कि जीवन-मृत्यु की भावना नष्ट न होने पाए। किंतु यवक जीवन और समाज में तथ्यों के सम्बन्ध में ज्ञान अवश्य प्राप्त कर सकता है किन्तु उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उनके महत्त्व को गहराई तक भी समझ सकेगा।

शिक्षा का चौथा उद्देश्य इस दृष्टि में पर्यवेक्षक सबसे स्पष्ट रूप में दौलत लगाता है। इस उद्देश्य का हमने यह परिभाषा करने की कोशिश की थी कि यह व्यक्ति की जीवन-मृत्यु के प्रति छात्र अथवा आत्म-अनुसंधान की यात्रा है। अलग-अलग व्यक्ति इसे अलग-अलग ढंग से पूरा कर सकेंगे। कुछ लोग इसमें सन्तोष अनुभव करके कि उन्होंने जो पेश अपनाए हैं उनका साथ लगे हुए वस्तुओं का वे मनी भाति पालन करते रहेंगे। इन पक्षों के लिए शारीरिक बौद्धिक और ललित (एस्थेटिक) निपुणताओं की आवश्यकता हो सकती है। कुछ भय भोग ऐसे भी होंगे जिन्हें आत्मज्ञान मृत्यु की छात्र में अथवा समाज में नय जीवन मूल्य का मुजन करने के प्रयत्न में प्राप्त होता हो। व्यक्ति अपने सामन चाहे कुछ भी लक्ष्य क्या न रखे किन्तु वह इस काम को अपने हाथ में सभी ले सकता है जब वह अपने विनिष्ट वेग के लिए आवश्यक अपने समाज में प्राप्त हो सकने वाले ज्ञान और अनुभवों पर पूरा अधिकार प्राप्त कर ले। वह कुशल यात्र विशेषज्ञ उसी दृष्टि में बन सकता है जबकि उस उतनी यात्रविद्या अवश्य प्राप्ति हो जितनी कि उस समय तक विषमिष्ट हो चुकी है। वह अपने विनिष्ट क्षेत्र में ज्ञान की सीमाओं का विस्तार केवल उसी दृष्टि में

कर सकता है जबकि वह उस सम्बन्ध में पहले से विद्यमान गान-जगत् का पूरा नया अपना मन में उतार ले।

अब हम उस विरोधाभास के ठीक दूसरे पक्ष पर आ पहुँचे हैं जिसका हमन प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में उल्लेख किया था। प्रारम्भिक शिक्षा उद्देश्य की दृष्टि से सामान्य किन्तु विषय की दृष्टि से मुख्यक होती है। उच्चतर शिक्षा में उद्देश्य और विषय दोनों ही अध्ययन होते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा में क्षेत्र धनभक्त के साथ साथ विस्तृत होता जाता है परन्तु उच्चतर शिक्षा में हम निरन्तर संकुचित होत जाते हैं क्षेत्र में ही अधिक और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में चाहे अध्ययन का क्षेत्र कितना ही विविष्ट क्षेत्र का क्यों न हो हम उसे अपने विद्यार्थी की पहलू के रूप में समझना चाहते हैं और उस ऐसे नियमों के अधीन ले आना चाहते हैं जिन नियमों का प्रयोग अधिकाधिक विस्तृत रूप से किया जा सकता हो।

इसलिए हम निम्नलिखित अन्तिम निष्कर्षों तक पहुँच सकते हैं। जीवन के लिए शिक्षा और पैसे के लिए शिक्षा इन दोनों के बीच कोई बड़ा स्पष्ट भेद नहीं किया जा सकता। शिक्षा की अलग अलग दशाओं में सम्भव है कि इनमें से किसी एक पर और किसी दूसरे पर कुछ अधिक जोर दे दिया जाय। परन्तु किसी भी दशा में इनमें से किसी एक तत्व की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर भी यदि हम शिक्षा (एज्यूकेशन) और प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) में अन्तर कर लें तो गड़बड़झाला काफी कुछ कम हो जायगा। शिक्षा व्यक्ति के अन्दर विद्यमान गुणा को विकसित करके बाहर लाने का नाम है। प्रशिक्षण व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था में जीवित नहीं रह सकता इसलिए शिक्षा में व्यक्ति के सामाजिक तत्व भी रहता है। परन्तु यह बात समाज की है कि व्यक्ति का सामाजिक रूप से सामाजिक मानसिक और नैतिक विकास किया जाय। प्रशिक्षण व्यक्ति का शारीरिक मानसिक और नैतिक विकास किया जाय। प्रशिक्षण व्यक्ति को करने की शारीरिक का नाम है। ऊपर बताया गया है कि प्रशिक्षण उसी समय सर्वोत्तम किया जा सकता है जबकि जीवन

क लिए दो गई गिम्मा उस दगा तक पहुँच जाय जिसमें कि गान और निपुणताएँ यथाचित रूप से पक्की हो चुकी हों और मानव-सम्बन्धों का एक ऐसा सामान्य ढांचा तयार हो चुका हो जिसके अन्दर विविध गान और निपुणताएँ अपना पूरा महत्व प्राप्त कर सकें। अपने आपमें प्रारम्भिक और माध्यमिक गिम्मा मुख्य रूप से गिम्मा का प्रशिक्षण है जबकि माध्यमिक गिम्मा के द्वा- दो दगाएँ— कुछ विरले मामलों को छोड़कर—मुख्य रूप से प्रशिक्षण के दौर हैं। परन्तु क्योंकि सामान्य रूप में जावन नाम का कोई वस्तु नहीं हो सकती बल्कि किसी विशिष्ट समाज में विविध कृत्यों का करतल है जो जीवन रह सकता है इसलिए प्रारम्भिक गिम्मा में न तो प्रशिक्षण के तत्त्व का एकात्म निबालकर बाहर नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर क्योंकि प्रत्येक पद्या जीवन की एक अभिव्यक्ति है इसलिए जिन हम जिम्मा विविध पद्या के लिए प्रशिक्षण समझते हैं उनके अन्दर या विस्तृततम अर्थों में गिम्मा का कुछ न कुछ तत्त्व अवश्य विद्यमान रहना चाहिए।

### ३

अन्तिम विचारण में पहुँचकर जिम्मा भी गिम्मा प्रणाली की कार्यक्षमता अध्यापकों की उत्कृष्टता पर धारित रहता है। अच्छे अध्यापकों के अभाव में सर्वोत्तम गिम्मा प्रणाली भी अमर नहीं रहेगी। यदि अध्यापक अच्छे हों तो गिम्मा प्रणाली का प्रयुक्त का भा बड़ी सीमा तक ठीक किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि गिम्मा के पद्य में ठीक रूप के पुरुषों और स्त्रियों को छात्रों किया जाय और उन्हें अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाय और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाएँ जिनमें अपने वेने में काम करत हुए सारे जावन भर उनमें उत्साह बना रहे।

जहाँ अध्यापक से जिम्मा का उत्कृष्टता का निर्धारण होता है वहाँ समाज की भावा समृद्धि का भी मुख्य आधार बनी होता है। समाज की उत्कृष्टता का निर्धारण व्यक्तियों की उत्कृष्टता से होता है और व्यक्ति मुख्य रूप से उसे मिली गिम्मा का परिणाम होता है। इसलिए सामाजिक प्रणाली में अध्यापक का स्थान बड़ा निर्णायक स्थान है। फिर या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान भारत में और गायन यहाँ तक कहा जा सकता कि

वर्तमान समय में अध्यापक को न तो वह शान्ति और न वह सामाजिक प्रतिष्ठा ही प्राप्त है, जो उसे भिन्ननी चाहिए। इसमें भी बुरी बात यह है कि स्वयं अध्यापकों में भी अपने पेशे के प्रति शान्ति का भाव नहीं रहता और समाज उनके साथ जैसा भी व्यवहार करता है उसका वह सिर झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं।

अध्यापक के प्रति अवहेलना का यह भाव वर्तमान समय में मानव-भूत्यों के प्रति अवहेलना का एक लक्षण है। आपत्ति समाज में प्रत्येक वस्तु को भौतिक दृष्टि से नापा जान लगा है। किसी भी व्यक्ति या पेशे का महत्व उस या अधिकारी की दृष्टि से ही परखा जान लगा है। अतीत के साथ बड़ा स्पष्ट विरोध में—जबकि अध्यापक चाहे कितनी ही निष्ठा या अधिकारहीन क्या न हों फिर भी उनका बड़ा सम्मान किया जाता था। धारक न के भारत में पैसे के प्रमाणों पर बहुत ही अनुचित बल दिया जाता है। भारत में अध्यापक की कीमत सबसे कम आती जाती है और फिर भी यह विचित्र प्रतीत होता है कि ऐसा हो। यदि बवल बिगुल भीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो भी यह विचित्र प्रतीत होता है कि जो लोग अपने कीमती पेशे का अप्रशिक्षित या गैर-हिम्मतदार कारीगरों के हाथ में देते बतराते हैं वे इतनी आसानी से समाज की सर्वोत्तम सम्पत्ति—अर्थात् भारी पीढ़ी—को ऐसे लोगों के हाथ में सौंप देते हैं जो प्रायः अल्प प्रशिक्षित होते हैं और लगभग मरदा ही अनुचित रूप से कम वेतन पाते हैं और असन्तुष्ट रहते हैं। एक बार एक अनुभवी अध्यापक ने बहुत खिन्न होकर कहा था—क्योंकि समाज अध्यापकों के शरीर को भूसा मारता है इसलिए अध्यापक लोग बदले के रूप में मानका की आत्मा का भूसा मारते हैं। यह कोई बड़ी सन्तापप्रद भावना नहीं है फिर भी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि यदि वर्तमान देश का भविष्य बचाना किया जाय तो वह प्रायः मही होगा।

कई भी यवक कितने ही भले भादवों का लेकर अपने अध्यापन के व्यवसाय को प्रारम्भ करते किन्तु भाग्य की पाटें उनका भादवों का बहुत शीघ्र ही धूर-धूर कर देती हैं उनकी आशाएं टूट जाती हैं और यह प्रायः बतता है भर जाता है। किसी भी युवक व्यक्ति के उन्माह को भंग करने वाली वस्तु सिद्धिपन की भावना से बढ़कर और कोई नहीं है। यह एक दुःखद तथ्य है कि अध्यापक लोग

इस प्रकार की सिखीपन की भावना और निराशा के बहुधा गिकार बन जाते हैं। इसका प्रभाव तरुण पीढ़ियों पर क्या होगा इसकी कल्पना सरलता से की जा सकती है। इसलिए जो समाज अपने अध्यापकों से दुर्व्यवहार करता है वह अपने वर्तमान कल्याण और भविष्य की प्रगति की नीचा का खोखला कर रहा होता है।

अध्यापक के आत्मसम्मान का ह्रास प्रशत उन गक्तियों के कारण होता है जिनके अन्तर उसका अपना कोई बस नहीं होता। सामाजिक मूल्यांकन में परिवर्तन हो जान के कारण स्वयं अध्यापन के पेश के प्रति उसका रव परिवर्तित हो गया है। अन्य अधिकांश लोगों की भांति वह भी पहले की अपेक्षा अधिक पैसे का पीर बन गया है। अब से बीस या तीस वष पहले तब भी भारत में ऐसे अध्यापक थे जो गरीब होते हुए भी केवल अपने चरित्र के बल के कारण सवजनीन रूप से आदर के पात्र थे। आजकल ऐसे अध्यापक बहुत ही बिरल हैं और उनकी सख्या कम और कम होती जा रही है। इसके विपरीत आजकल ऐसे अनक अध्यापक हैं जो सम्पति या अधिकार वाले लोगों के पीछे दौड़ते हैं।

किन्तु इसका सारा दोष केवल समाज के ही सिर नहीं है। वर्तमान दूषित दशा की शिम्मेदारी में अध्यापक बच नहीं सकता। उसने भी अपने व्यवसाय को भुना दिया है। जो व्यक्ति अपने आदर्शों से च्युत हो गया हो उससे बढ़कर करणाजनक दृश्य और कोई नहीं हो सकता। आजकल अध्यापक की जो दुर्दशा है उसका कुछ कारण दरिद्रता और उपेक्षा भी हो सकती है परन्तु वह किमी भी प्रकार उस दुर्दशा का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। अध्यापन के पेश में ऐसे अनेक लोग आ घुसते हैं जिनमें इस व्यवसाय के प्रति आस्था नहीं होती। वे इसलिए अध्यापक बन जाते हैं क्योंकि वे और कुछ कर नहीं सकते। इस प्रकार केवल सब स्थानों से अस्वीकृत अनुपयुक्त और निराश लोग इस पेश में भर जाते हैं और वे इस पेश में अपनी दृष्टि के प्रतिकूल इसलिए डट रहते हैं क्योंकि वे और कही जा नहीं सकते। जब तब ऐसी दशा रहूँगी तब तब अध्यापक की सामाजिक प्रतिष्ठा में अथवा जो शिक्षा से प्रदान करते हैं उसकी किम्में में कोई सुधार कैसे हो सकता है ?

शिक्षा के सम्बन्ध में जो भी पुनर्गठन किया जाएगा वह अन्तर्गतत्वा अध्या-



पका द्वारा किए जाने वाले काम पर ही निर्भर होगा। व अक्षरस्य राष्ट्र के भाग्य निर्माता है। मूल ही यह बात मुनने में स्वयंसिद्धि-सी प्रतीत हो फिर भी इस बात को और देकर कहना आवश्यक है कि शिक्षा के पुनर्गठन के किसी भी कार्य-क्रम का आधार सम्पादन ही है। जब तक वायसराय और अठावार्न् सम्पादक किसी योजना को प्रियान्वित करने के लिए विद्यमान न हों तब तक शिक्षण सुधारों की पूर्ण स पूरा योजना निर्वाह अक्षर मान बनकर रह जायगी। इसी प्रकार सामाजिक उन्नति के अत्यन्त सावधानी से तैयार किए हुए कार्यक्रम भी उस दशा में अमरम हो रह जायेंगे जब तक कि उनको प्रियान्वित करने के लिए समुचित योग्यता वाले व्यक्ति विद्यमान न हों। इस सम्बन्ध में निर्णायक तत्व व्यक्तियों का उत्कृष्टता या योग्यता है और यह योग्यता या उत्कृष्टता मुख्य रूप से समाज में प्रचलित शिक्षा और प्रशिक्षण के ढंग पर निर्भर होती है।

इसलिए शिक्षा व पुनर्गठन या समाज के पुनर्निर्माण के किसी भी कार्यक्रम में जिन लोगों का महत्त्व है व सम्पादन ही है जो सभी पीढ़ियों को प्रशिक्षण द्या। तबल व्यक्तियों की एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण जिनमें मन की स्फूर्ति अनुभूतियों की सम्बन्धशीलता और 'गैरिख' तथा मानसिक क्रियाओं की निपुणता विद्यमान हो एक ऐसा आदर्श है जिसे प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रयत्न किया जाना चाहिए। इन बच्चों को सही भाँति पूरा करने के लिए सम्पादकों को वह माध्यम बनना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे समाज का सर्वोत्तम अंश नयी पीढ़ी तक पहुँच सक। शिक्षा की प्रक्रिया जानकारी देने की इस ढंग की प्रक्रिया नहीं है कि जैसे एक बाल्टी से पानी दूसरी बाल्टी में डबल लिया जाए। यह बहुत कुछ उस ढंग की प्रक्रिया है जिस प्रकार एक दीपक अन्य दीपकों को जलाने में सहायता देता है। यदि वह दीपशिक्षा जिससे अन्य दीपक जलाए जायें व अपने आप में सजीव न हो तो समाज का प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्त्व सम्पादक और शिक्षक के मध्य स्थापित हुए उन निजी सम्पर्कों का है, जो उनकी सत्य की सामी खोज के दौरान में विकसित हुए हैं। यदि इस बात को भुला दिया जाय तो मके ही सम्पादकों के अतन क्रम बितन ही अर्थ क्यों न हों और सम्पादन व प्रशिक्षण के लिए बितनी ही विद्यद प्रणालियाँ क्यों न हो और व सम्पादक बितन ही

भामुनिकृत उपकरणों का प्रयोग क्या न करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया निर्जीव और निश्चेष्ट ही बनी रहती है।

यही यह भी संकेत कर देना उचित होगा कि अध्यापक के वर्तमान का चाहे वह कितना ही बोझिल क्यों हो एवं अपना भी प्रतिकूल होता है। आत्म अभिव्यक्ति एक ऐसी वस्तु है जिस व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्मज्ञान और कलाकार कवि और चित्रकार सब इस बात के साक्षी हैं कि अपने अस्तित्व की अनुभूति के बराबर और कोई आनन्द नहीं। अध्यापक को यह आत्म-अभि व्यक्ति का भवसर चाहें जितनी मात्रा में प्राप्त हो सकता है। उसे प्रतिदिन जो काम करना पड़ता है उसमें सम्मिलित है कि काफी बड़ा भाग जिसकुल नीरस दिन चर्या का है और ऐसा वस्तु होता भी है परन्तु ऐसे भी अनेक भवसर आते हैं जबकि वस्तुएं एक दमक के रूप में स्पष्ट हो उठती हैं और उसका नीरस कार्य उठकर एक बहुत ऊँचे स्तर तक पहुँच जाता है। जो भी अध्यापक अध्यापक कहलाते हैं उन सब इस प्रकार का अनुभव किया है और वे जानते हैं कि यह दैनिक नीरस दिनचर्या का पर्याप्त प्रतिकार (मुआवजा) है।

अध्यापक और शिष्य के बीच सम्पर्क मनुष्यों के बीच होने वाली सृजनशील प्रक्रिया का कुछ उदाहरणों में से एक है। इस सम्पर्क को नियमों या कड़ियों द्वारा नियमित नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि हम अनेक भौतिक कारण हैं जिससे अध्यापक सदा सृजनशील स्तर पर नहीं रह सकते या केवल विरल क्षणों में ही इस सृजनशील स्तर तक उठ पाते हैं। जिन दशाओं में रहकर उन्हें काम करना पड़ता है वे बहुधा दयनीय होती हैं। यह स्पष्ट है कि यदि कक्षा में आवश्यकता से अधिक विद्यार्थी हैं यदि काम के घंटे इतने अधिक हैं कि उनमें सुविधापूर्वक काम कर पाना सामान्य दृष्टि से कठिन हो और वतन इतना कम हो कि उनसे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ भी पूरी न होती हों तो अध्यापक सर्वोत्तम ढंग से काम नहीं कर सकता। इन सब समस्याओं के होते हुए भी यह सम्भव है कि अध्यापक अपने शिष्या का कुछ ऐसा वस्तु दे सके जिसके लिए वे आजीवन उसके आभारी रहें।

४

इस बात को ध्यान में बहुत ही छोड़ा समय हुआ है कि जब से सब मागारिकों

के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व मान लिया गया है एवं भय में यह समाज की प्रजातन्त्रात्मक धारणा की एक आवश्यक अनुमति (नोरोसरी) ही कही जा सकती है। प्रजातन्त्र का सार यह है कि कानून की दृष्टि में सब नागरिक समान हैं। यह भी स्पष्ट है कि यदि सब लोगों को अपनी प्रसुप्त क्षमताओं का विकास करने का समान अवसर प्राप्त न हो तो इस प्रकार की समानता का कोई भय नहीं रहता। इस प्रकार शिक्षा प्रजातन्त्र को पूरा और सुजनशील बनाने का एक मुख्य उपकरण बन जाती है। यह ठीक है कि भ्रम-भ्रमण पुरुषों और स्त्रियों की स्वाभाविक योग्यताओं में अन्तर होता है परन्तु इस प्रकार का अन्तर किसी उस सामाजिक या भाषिक स्तर के कारण नहीं होता जिसका कि वह व्यक्ति भग है। यदि प्रजातन्त्र को सचमुच प्रभावी बनाना हो और सब व्यक्तियों के लिए पूरी सीमा तक विकास करने के अधिकार की गारंटी करनी हो तो शिक्षा सबजनीन और निःशुल्क होना चाहिए।

इसलिए निःशुल्क सबजनीन शिक्षा का व्यवस्था करना राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य माना जाता है। परन्तु वित्तीय तथा अन्य कारणों से अब तक कोई भी राज्य केवल प्रारम्भिक स्तर को छोड़कर सबजनीन अनिवार्य शिक्षा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना में समय नहीं हुआ है। जिन देशों में बयस्क लोग बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं वहाँ उनकी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रकार की व्यवस्था के अलावा अन्य सुविधाएँ मुख्य रूप से एन्ट्रान्स डेग की हैं और यह व्यक्तियों या परिवारों की इच्छा पर निर्भर है कि वे उन सुविधाओं का उपयोग करें या नहीं। समुक्त राज्य अमेरिका जैसे समृद्ध और शिक्षा की दृष्टि से सचत देश में भी अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था केवल १६ वर्ष की आयु तक के लिए ही है।

प्रजातन्त्र के प्रसार के साथ-साथ जनता के अवसरों की समानता की माँग भी और पकड़नी जा रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि राज्य को दो रूपों में शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ानी पड़ती हैं। एक और सा राज्य का प्रयत्न यह रहता है कि उन क्षेत्रों में और लोगों के उन वर्गों में शिक्षा के प्रसार को व्यवस्था की जाय जिन्हें पहले शिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं थी। दूसरी ओर राज्य धीरे धीरे सभी लोगों को दी जान वाली शिक्षा की अवधि को बढ़ाता जा रहा है। इन्हें का यह निश्चय, कि लोग को दी जान वाली अनिवार्य शिक्षा

का काल और बढ़ा दिया जाय और सभी स्तर पर अधिकाधिक मात्रा में छात्र वृत्तियों की व्यवस्था की जाए इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि यह मनोवृत्ति राज्य की क्रिया में किस प्रकार प्रकट होती है।

क्योंकि भारत न प्रथम लिए प्रजातन्त्र प्रणाली को बना है इसलिए भारत में तो ऐसी भाग का औचित्य पहले से ही स्वीकार-सा कर दिया गया है। जिन प्रदेशों और जनता के जिन वर्गों को पहले कमी शिक्षा के सामे प्राप्त नहीं हुए थे वे आजकल यह भाग कर रहे हैं कि उनकी कमी को पूरा करने के लिए विद्यार्थी कर्म उठाए जाएं जिससे वे भी गण दण के साथ समानता के स्तर पर रह सकें। अनिवार्य शिक्षा का सिद्धान्त धीरे-धीरे प्रारम्भ किया जा रहा है और विस्तृत भी किया जा रहा है। पिछले सात वर्षों में अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत लाया गया प्रदेश पहले की अपेक्षा कई गुना हो गया है। साथ ही साथ अनिवार्य शिक्षा का कान भी उम्मा किया जा रहा है। अब तक अनिवार्य शिक्षा केवल १ या ११ वर्ष की आयु तक के लिए ही लागू की गई थी परन्तु अब सब लाग इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनिवार्य शिक्षा की यह अवधि बढ़ा कर १४ वर्ष की आयु तक के लिए कर दी जानी चाहिए और इस बात को संविधान में भी स्वीकार कर लिया गया है। स्वतन्त्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद तो कुछ और आगे तक बढ़े हैं और उन्होंने घोषणा की है कि उनके विचार में प्रत्येक नागरिक का यह विषय अधिकार है कि वह माध्यमिक स्तर तक नि शुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा का विस्तार स्थान और काल दोनों की ही दृष्टि से किया जा रहा है।

आधुनिक मनुष्य के सम्मुख कई ऐसी समस्याएँ हैं जो अभी उसके पूर्वजों के सम्मुख नहीं आई थीं। पहले के समाजों में थोड़े-से अल्पसंख्यक लोग ही जनता का नस्त्व करते नीतियाँ निश्चिन करते और उन नीतियों को क्रिया न्वित करते थे। जनता की विनाश बहुसंख्या केवल उन नतामा का अनुगमन करने ही मनुष्ट रहती थी। परन्तु प्रजातन्त्र के प्रसार के साथ-साथ परिस्थिति बदल गई है और राज्य के मामलों के संचालन में सभी नागरिकों का हाथ रहता है। इससे अतिरिक्त आजकल राज्या का एक-दूसरे से सम्बन्ध इतना अधिक बढ़ गया है कि जितना पहले अभी नहीं था। इसलिए आजकल सामान्य

मनुष्य संसार के भविष्य के लिए जितना जिम्मेदार है उतना भतीत में अभी नहीं रहा। इस बड़े हुए उत्तरदायित्व के कारण यह आवश्यक हो गया है कि आधुनिक राज्य के प्रत्येक नागरिक को यह ज्ञान प्राप्त करने का अवसर अवश्य प्राप्त हो जिसकी संसार के विकास की इस सन्नति की दशा में यद्विमतापूर्वक कार्य करने के लिए बड़ी आवश्यकता है। परन्तु किसी भी समाज के सब सदस्य उन्नति की सर्वोच्च सीढ़ियों तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए इस बात का बड़ा भय है कि नताओं प्रचारकों पथप्रदर्शकों और नवसन्देशवाहकों के तथा उनकी अनुयायी विद्यालय जनता के बीच सम्पर्क बिल्कुल समाप्त ही न हो जाए। इस खाई को पाटने का काम माध्यमिक शिक्षा को करना होगा और माध्यमिक नेताओं के एक ऐसे वर्ग को प्रशिक्षित करना होगा जो नताओं का सन्देश सामान्य जनता तक पहुँचा सके। इस प्रसंग में ही हम मौलाना आज़ाद के इस आग्रह को ठीक भयों में समझ सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक को न केवल प्रारम्भिक अपितु माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आजकल के संसार में जिसमें कि विभिन्न समाज और व्यक्ति एक-दूसरे के घनिष्ठ सम्पर्क में आ गए हैं स्थान और काल दोनों की ही दृष्टि से शिक्षा का इस प्रकार का विस्तार और भी अधिक आवश्यक हो गया है। सभी प्राणी एक प्रविष्ट परिकर्तन की प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं। यह बात समाजों और व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होती है। व्यक्तियों में परिवर्तन बुद्धि और नय अनुभवों की प्राप्ति के द्वारा होता है। समाजों में परिवर्तन बुद्धि और नय के द्वारा और एक पीढ़ी के स्थान पर नई पीढ़ी आने के द्वारा होता है। हम यह यत्न कर सकते हैं कि हमारे बालक हमारे ही प्रमाणों और आदर्शों को मानकर चलें किन्तु हम उन्हें इस बात से नहीं रोक् सकते कि वे हमारी शिक्षाओं की अपने मनमाने ढंग से व्याख्या कर लें। परन्तु सभी व्याख्याएँ परिवर्तन हैं। जब समाज और व्यक्ति अपेक्षाकृत एक-दूसरे से घनिष्ठ-अलग रहते हैं तब भी इस प्रकार का परिवर्तन होता रहता है। जब विभिन्न संस्कृतियों और सम्प्रदायों परस्पर मिलती हैं तब इस प्रकार के परिवर्तन और भी अधिक तीव्र और दूरगामी हो उठते हैं।

वर्तमान युग का एक विरोधाभास यह भी है कि ससार के लोग भौतिक दृष्टि से एक-दूसरे के निकट पड़ोस में रहते हुए भी आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टि से एक-दूसरे से दूर और अलग-अलग रह रहे हैं। यदि विभिन्न पृष्ठभूमियों और दृष्टिकोणों वाले विभिन्न लोग एक-दूसरे के साथ मिलकर निर्वाह करना न सीखें तो उनमें संघर्ष होना अनिवार्य है। आधुनिक युग में यदि कोई संघर्ष हुआ तो वह अवश्य ही सवनाशकारी होगा। यदि सभी समाज अपने दृष्टिकोण और स्वभाव में कुछ आवश्यक समंजन (बैठ-बिठाव) करने को तैयार न हों तो संघर्ष से किसी प्रकार बचा नहीं जा सकता। संघर्ष ही यह है कि इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिरोध करने से परिवर्तन के लिए कार्य कर रही शक्तियाँ को और बल मिलेगा और उसका परिणाम हिंसात्मक उथल-धुल भी हो सकता है। क्योंकि परिवर्तन अनिवार्य है इसलिए शिक्षा का कृत्य (फक्कान) ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना होना चाहिए जिनमें समंजन (बैठ-बिठाव) और परिष्कार किसी हिंसात्मक उत्पात या उपद्रव के बिना किए जा सकें।

प्रजातन्त्र के प्रसार के साथ-साथ परिवर्तनों को बिना उत्पात के क्रियान्वित कर पान की आवश्यकता और सम्भावना—दोनों ही बढ़ गई हैं। जहाँ पर विभाषाधिकार किसी एक अल्पसंख्यक वर्ग तक सीमित रहते हैं वहाँ यह अल्प संख्यक वर्ग उन अधिकारों को बनाए रखने के लिए लड़ता है। परन्तु जिन बहुसंख्यक लोगों को उन्नति करने के लिए सबसे समान अवसर प्राप्त नहीं होते उनमें समाज की वर्तमान रुढ़ियाँ का विरोध करने की प्रवृत्ति आग उठती है। इस प्रकार अप्रजातन्त्रीय समाज में तनाव उत्पन्न होना अनिवार्य हो जाता है। मार्क्स न वर्ग-संघर्ष के रूप में सामाजिक परिवर्तन का जो आधारभूत सिद्धान्त प्रस्तुत किया है उसमें सत्य का अंग यही है। परन्तु स्वयं मार्क्स और एंजिल्स ने भी यह स्वीकार किया है कि प्रजातन्त्रीय समाज में बिना हिंसात्मक संघर्ष के भी आवश्यक परिवर्तन साधे जा सकते हैं।

अपनी पुस्तक 'विज्ञान प्रजातन्त्र और इस्लाम' (साइंस डिमोनेस्ट्रो एण्ड इस्लाम) में मन उन कुछ जोखिमों का उल्लेख किया है जो हिंसा द्वारा सामाजिक परिवर्तन करने के प्रयत्नों के साथ सजे रहते हैं। सामाजिक समतुलन (इक्विलिब्रियम) स्थापित करने के लिए जान्तियाँ विकास की प्रक्रिया की

अपेक्षा सदा ही घटिया सिद्ध होती है। पहली बात तो यह है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि क्रान्ति सफल हो ही जाएगी। दूसरी बात यह है कि जहाँ क्रान्ति सफल हो भी जाती है वहाँ यह इस प्रकार के दबाव और तनाव उत्पन्न कर देती है कि उनसे कारण फिर और क्रान्तियाँ होती हैं। यह भी एक बड़ा कारण है कि सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए प्रजातन्त्रात्मक पद्धतियाँ क्यों सदैव अधिकाधिक प्रगतिशील आती हैं।

सब तो यह है कि कुछ और भाग बढ़कर यहाँ तक कहा जा सकता है कि वास्तविक और स्थायी प्रगति प्रजातन्त्र के सिवाय और किसी प्रणाली से हो ही नहीं सकती। सोचा में कुछ यह अविश्वास-सा फैला हुआ है कि कम से कम अल्पकालीन अवधि की दृष्टि से अधिनायकतन्त्र (तानाशाही) प्रजातन्त्र की अपेक्षा अधिक वायदाय होता है। परन्तु सारा का सारा इतिहास इस स्थापना का खंडन करता है। जब भी किसी एकतन्त्रात्मक समाज की किसी प्रजातन्त्रात्मक समाज से टक्कर हुई है तब सदा ही अन्त में जीत प्रजातन्त्र की ही हुई है। यह कोई भावस्मिक या सांयोगिक बात नहीं है अपितु यह तो मनुष्य और समाज की प्रकृति में स्वभावतः विद्यमान है। कोई भी महान् सामाजिक सत्य बिना जनता लोगों के सहयोग के प्राप्त नहीं हो सकता और सहयोग ही एसी वस्तु है जो प्राधिकारात्मक (औथोरिटेरियन) समाज में कभी सुनिश्चित रूप से पाई नहीं जा सकती। प्रजातन्त्र में आरम्भ में कुछ हिचक और विलम्ब अवश्य दिखाई पड़ता है परन्तु इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि यह कोई हानिकारक वस्तु नहीं है। हिचक और विलम्ब केवल इस कारण होता है क्योंकि प्रजातन्त्र में बहुत-से लोग ठीक-ठीक यह निश्चय नहीं कर पाते कि उन्हें कौन-सा पथ पकड़ना है या यहाँ तक भी कि वे एक-दूसरे के विचारों को ठीक-ठीक समझ भी पा रहे हैं या नहीं। विचार-विमर्श वा-विचार आसप-आसप और युक्ति प्रयुक्ति में समय अवश्य लगता है किन्तु इनसे सदेह और अनिश्चितता को हटान में सहायता मिलती है। अन्त में जब प्रजातन्त्र कारवाही करता है तो उसे निश्चय रहता है कि उसके सब भागीदार सत्य के सम्बन्ध में मोट तौर पर एकमत हैं।

अधिनायकतन्त्र (तानाशाही) में इस प्रकार के सांके सत्य का कोई स्वासन नहीं रहता। सब तो यह है कि उसमें इतना तक भी नहीं माना जा

सकता कि सब लोग न उस सत्य को समान रूप से समझ भी सके हैं या नहीं। इस कारण क्या धान्ति और क्या युद्ध, दाना ही जाता में अधिनायक तत्र प्रजातन्त्र से कम कार्यक्षम सिद्ध होता है। जब तक किना सामाजिक धान्तिमेन या सैनिक अभियान में सफलता मिलता रहती है तब तक अधिनायक तत्र के दोष दिये रह सकते हैं। इस प्रकार के विजय के दौरा में द्वितीय कोटि के नेता स्वयं भी किसी विषय में निभय करने को उद्यत रहत ह और अधिनायक भी उन्हें उपन्ता या रोकता नहीं है। परन्तु यदि कभी स्थिति बिगड़ जाय तो अधिनायक उसका दोष धन सहकारियों (मजदूरों) पर डालना चाहता है। वह कभी यह सहन नहीं कर सकता कि किना को यह संदेश भी हो कि असफलता का अधिनायक के साथ कोई सम्बन्ध है। अधिनायक को निभान्त होना चाहिए, भयभीत वह कि नहीं सकता। इसलिये सबट के समय उसका सहकारी स्वयं कोई नियम करने का हिम्मत नहीं करता। वस्तुतः कई बार तो वे अधिनायक के आदेश का स्पष्टीकरण तक करवात डग्न ह। स्पष्टीकरण के लिए किए गए उनका अनुग्रह का सरमता से यह मत धन सगाया जा सकता है कि वे उनका नीति का आलाचना कर रहे ह या यह कि उन्हें उसकी नियम-शक्ति पर विश्वास नहीं है। अधिनायक एक ही बात का नहीं सह सकता और वह बात है—उसका अधिकार के सम्बन्ध में नृजनाचीनी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनायक तत्र प्रारम्भिक निष्ठा में आन्ध्र जनक सफलता या लन के बाद भी क्यों मदक धन में प्रजातन्त्र का सम्मन्ध हात रह ह। विचार-विमर्श और बात-बिबा के अभाव का परिणाम धनि बाधत मानि मन्थ और मनुमावना का प्रभाव होता है।

अधिनायकत्व की दुबलता ठीक यहा है। धान्ति जारी कर लिए बात है और धान्ति हा किना धान्ति को इतना साहस होता है कि यह पूछ कि उस धान्ति का असली धनिप्राय क्या है। धनीनस्य कमधारियों के प्रत्येक स्तर पर इस प्रकार के धान्ति के अपने-अपने विचार के अनुसार अलग अलग धन निकाल बात ह और उनका यथाशक्ति धन्युस धन्युस धन से पासन करने का यत्न किया जाता है। परन्तु धन विचारों का दूसरा सब धन्युस मानवाय सम्बन्ध में से एक बठिनवम बाध है। इसलिये इस बात का धतरा सन बना रहता है कि धा नृध वस्तुतः किया गया हा वह उससे विस्तृत भिन्न हो जो कि उस



घाटेन से अभिप्रत था। अग्रणी भाषा में सायद अय किन्हीं धर्ने का इतना बारम्बार प्रयोग नही हाता जितना कि भाद मीन ट से (मेरा अभिप्राय यह है कि) या बूट भाद मीन इज दिस (मेरे कहने का मतलब यह है कि) का। सामान्य वार्तालाप में भी हमें अपने भाषण को समझाने के लिए अपनी बात को बार-बार स्पष्ट करना पड़ता है। यह हाल केवल अग्रणी का ही नहीं अपितु सभी भाषाभाषा का है। प्रजातन्त्र प्रणाली में होने वाला विमर्श तथा दूर से अनिश्चय जैसी दोष पड़न वाली दशा इस प्रकार की सम्भावित गलतफहमी को न होने देने का प्रयत्न मात्र होती है। विचार विमर्श और बाद-विवाद होने के कारण प्राधिकारात्मक समाज में कारवाई भले ही तीव्र गति से हो प्रतीत हो किन्तु यह सम्भव है कि वह सारी कारवाई गलतफहमी और समझ की गड़बड़ी पर आधारित हो।

शिक्षा का सार इस प्रकार का विचार विमर्श और वाद-विवाद ही है। अतः बार शिक्षा का अणन इस रूप में किया जाता है कि यह अतीत और वर्तमान के मध्य विभिन्न दृष्टिकोणों के मध्य तथा विभिन्न पृष्ठभूमियों तथा अन्तर्गत वाले मनव्यों के मध्य होता हुआ एक महान् आलाप है। जहाँ शिक्षा का लक्ष्य बीते युगों के संचित ज्ञान को व्यक्ति तक पहुँचाना है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का उसके अन्य सब साथियों के साथ तात्कालिक सम्पर्क स्थापित करना भी है। इस प्रकार अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों के विचारों को समझना शिक्षा का सार है और प्रजातन्त्र वह सर्वोत्तम माध्यम है जिसमें कि ऐसी शिक्षा पनप सकती है। अगणित व्यक्ति अपने अतिशुद्ध निष्कर्ष के भौतिक और मानसिक परिवर्ण (एनवायरनमेंट) में जीवन व्यतीत करता है। शिक्षा का प्रयोजन यह है कि ऐसे व्यक्ति को उसके परिवर्ण के बर्धना से मुक्त कर दिया जाए और साथ ही यह मुक्ति इस ढंग से हो कि उस परिवर्ण के साथ व्यक्ति के सम्बन्ध समाप्त भी न हो जाए। शिक्षा मनुष्य को विभिन्न प्रकार के समाजों और सम्प्रदायों का ज्ञान कराती है। यह उसे इस योग्य भी बनाती है कि वह अतीत के आशोक में वर्तमान का दान कर सके। शिक्षा का अर्थ मनुष्य को यह समझाना भी है कि पृष्ठभूमियों में अन्तर होने पर भादसों और परम्पराया में अन्तर क्यों पड़ जाता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्य मनुष्यों को उदार बनाना तथा कल्पना को शिक्षित करना है। ऐसा करने

गिम्मा का नियम बनाना

का अर्थ है कि मनुष्य के मन में यह भावना उत्पन्न कर दी जाए कि परिवर्तन अनिवार्य है और साथ ही वह उन महान् मन्त्रों का भाग्यमूल जो इन सब प्रवाहों के बीच में रहते हुए भी अपरिवर्तित बन रहे हैं। इस प्रकार के मन्त्रों का हृदयगत कर लेना ही आध्यात्मिकता का मार है। गिम्मा का लक्ष्य यह है कि व्यक्ति को सब जाना तथा सब लोगो के ज्ञान और अनुभव का उत्तराधिकारी बनकर जीवन की आध्यात्मिक धारणा पर आधारित सभ्यता और सृष्टि का विकास किया जाए।

● ● ●



का अर्थ है कि मनुष्य के मन में यह भावना उत्पन्न कर आ जाए कि परिवर्तन अनिवार्य है और साथ ही वह उन महान मयों का भाग समझे जो इन सब प्रवाहों के बीच में गहन रूप से परिवर्तित हो रहे हैं। इस प्रकार के मयों का हस्तगम करना ही आध्यात्मिकता का मार्ग है। गिम्मा का लक्ष्य यह है कि व्यक्ति का सब कानों तथा सब नासा के ज्ञान और अनुभव का उत्तराधिकारी बनाकर जीवन की आध्यात्मिक आत्मा पर आधारित सम्प्रदाय और सृष्टि का विकास किया जाए।

● ● ●